

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092023-248524 CG-DL-E-04092023-248524

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 2

PART II — Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं<sup>0</sup> 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2023/ श्रावण 6, 1945 (शक) No. 12] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2023/SRAVANA 6, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## लोक सभा

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

20 जुलाई, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

20 जुलाई, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जुलाई, 2023/आषाढ़, 1945 (शक)

#### **LOK SABHA**

## REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023

#### (SEVENTEENTH LOK SABHA)

Presented to Lok Sabha on the 20th July, 2023 Laid in Rajya Sabha on the 20th July, 2023

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

JULY, 2023/ASHADHA, 1945 (SAKA)

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

#### श्री राजेन्द्र अग्रवाल

### सभापति

## लोक सभा

- 2. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
- 3. श्री राजू बिष्ट
- 4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
- 5. श्री तापिर गाव
- 6. श्री अजय टम्टा
- 7. श्री सुरेश कुमार कश्यप
- 8. श्रीमती गोमती साय
- 9. श्री सुदर्शन भगत
- 10. श्री पल्लब लोचन दास
- 11. कुमारी दिया कुमारी
- 12. श्री टी.आर. बालू
- 13. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 14. श्रीमती साजदा अहमद
- 15. श्री कोटागिरी श्रीधर
- 16. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
- 17. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 18. श्री महेश साहू
- 19. श्री गिरीश चन्द्र
- 20. श्री प्रद्युत बोरदोलोई\*
- 21. सुश्री गीता कोडा\*

### राज्य सभा

- 22. डॉ. अशोक बाजपेयी
- 23. श्री अनिल बलूनी
- 24. श्री समीर उरांव
- 25. डॉ. सी. एम. रमेश
- 26. श्री जवाहर सरकार
- 27 डॉ. प्रशांत नंदा
- 28. श्री हिशे लाचुंगपा
- 29. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
- 30. श्री आर गिरिराजन +
- 31. श्रीमती फूलो देवी नेताम +

## सचिवालय

1.	श्री जे एम बेसाख	-	सयुक्त सचिव
2.	श्री कल्याणसुंदरम	-	निदेशक
3.	सुश्री माया मेनन	-	अवर सचिव
4.	श्री राजीव कुमार	-	कार्यकारी अधिकारी
5.	श्रीमती सोनिया गुप्ता	-	कार्यकारी अधिकारी

<sup>\*</sup> दिनांक 14.04.23 से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा नामनिर्देशित।

<sup>+</sup> दिनांक 19.04.23 से माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा नामनिर्देशित।

#### प्राक्कथन

- मैं, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त सिमिति का सभापित, जिसे 'वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023' सौंपा गया था, उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, विधेयक सिहत यह प्रतिवेदन, जैसा कि उससे संबद्ध संयुक्त सिमिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है, प्रस्तुत करता हूं।
- 2. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 को लोकसभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त सिमिति को सौंपने का प्रस्ताव दिनांक 29 मार्च, 2023 को श्री भूपेन्द्र यादव, श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था (देखिए परिशिष्ट-I) और उसी दिन राज्य सभा द्वारा इस पर सहमित व्यक्त की गई थी (देखिए परिशिष्ट-II)।
- 3. सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, संयुक्त समिति को मानसून सत्र, 2023 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।
- 4. विधेयक के महत्व और इसके व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, सिमित ने उपरोक्त विधेयक के प्रावधानों पर सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से विशेषज्ञों/हितधारकों/गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों से विचार प्राप्त करने के लिए ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में 03 मई, 2023 को उनसे ज्ञापन आमंत्रित करने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। सिमिति को 1309 ज्ञापन (देखिए परिशिष्ट III) प्राप्त हुए हैं। सभी ज्ञापन सिमिति के सदस्यों को परिचालित किए गए। उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी भेजा गया और प्रत्येक पर उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त की गईं। सिमिति ने बारह विशेषज्ञों/हितधारक संगठनों के विचारों/सुझावों को भी सुना, जो सिमिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। विशेषज्ञों/हितधारकों और लोगों द्वारा उठाए गए बिंदुओं के साथ-साथ नोडल मंत्रालय की टिप्पणियों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।
- 5. इसके साथ-साथ, सिमित ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों अर्थात् गृह मंत्रालय, रक्षा, जनजातीय कार्य, रेल (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, जल शक्ति (पेयजल और स्वच्छता विभाग), खान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विभाग (डीओ एनईआर) जिसमें नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी शामिल है, से सुझाव आमंत्रित किए और अपनी बैठकों में मंत्रालयों/विभागों के विचार/सुझाव सुने। सिमिति ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की तीन राज्य सरकारों को भी विधेयक पर उनकी टिप्पणियां जानने के लिए बैठक में आमंत्रित किया। सिमिति ने 02.06.2023 से 07.06.2023 तक श्रीनगर, गुवाहाटी और भुवनेश्वर का अध्ययन दौरा भी किया, जहां उन्होंने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और शेष वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों अर्थात् ओडिशा और आंध्र प्रदेश सिहत चौदह अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा की। उक्त अध्ययन-दौरे के दौरान, सिमिति ने विभिन्न अन्य हितधारक संगठनों और पीएसयू जैसे सेना उत्तरी कमान (XV कोर), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी (ओएनजीसी) (देखिए परिशिष्ट-IV) के साथ विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा की।
- 6. संयुक्त सिमिति ने आठ बैठकें कीं, जिनमें उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और विशेषज्ञों/हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार सुने (देखिए परिशिष्ट-V)। मौखिक साक्ष्य के लिए संयुक्त सिमिति के समक्ष उपस्थित होने वाले साक्षियों की बैठकवार सूची संलग्न है (देखिए परिशिष्ट-VI)।
- 7. इसके बाद संयुक्त समिति ने 26 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में विधेयक के सभी खंडों पर खंडवार विचार पूरा किया। संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया विधेयक प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।
- 8. संयुक्त समिति के 05 सदस्यों से 04 विमत टिप्पण/कार्यवाही सारांश प्राप्त हुए हैं **(देखिए परिशिष्ट-VIII)** ।
- 9. संयुक्त समिति ने 11 जुलाई, 2023 को हुई अपनी 09वीं बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया और सभापित को उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति की बैठकों की कार्यवाही की एक प्रति और विधेयक पर समिति को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्येक ज्ञापन की दो-दो प्रतियां प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु संसद ग्रंथालय में रखी जाएं।
- 10. संयुक्त समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहती है जो संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित हुए और विधेयक की जांच के संबंध में आयोजित बैठकों के दौरान संयुक्त समिति द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अपने सुविचारित विचार रखे। संयुक्त समिति अन्य केन्द्रीय

मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों/हितधारक संगठनों को भी धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होकर विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए और प्रस्तुत किए। संयुक्त समिति की सभी बैठकों के सुचारू संचालन को सुकर बनाने और संयुक्त समिति का प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किए गए ईमानदारीपूर्वक और समर्पित प्रयासों की भी संयुक्त समिति सराहना करती है।

नई दिल्ली; 11 जुलाई, 2023 20 आषाढ़, 1945 (शक) श्री राजेंद्र अग्रवाल सभापति, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति

#### प्रतिवेदन

#### अध्याय एक

### वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की उत्पत्ति और विशेषताएं

1.1 वन राष्ट्र के हरित फेफड़े हैं और स्वच्छ हवा, पानी, मिट्टी के कटाव को रोककर मिट्टी की नमी को बनाए रखना आदि जैसी विभिन्न पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वन पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हैं। वनस्पितयों और जीवों की विशाल विविधता वाले प्राकृतिक वन जैव विविधता का केंद्र हैं। वन प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन रेत के टीलों को बढ़ने से रोककर मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। देश में भिम क्षरण को रोकने के लिए स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक हैं।

## वन की परिभाषा

- 1.2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 9-क्योटो प्रोटोकॉल के निर्णय 19 के अनुसार, वन को किसी भी देश द्वारा देश के सामर्थ्य और क्षमताओं के आधार पर निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है:—
  - कवर प्रतिशत: ट्री क्राउन कवर 10 से 30%;
  - स्टैंड का न्यूनतम क्षेत्रफल: 0.05 और 1 हेक्टेयर के बीच का क्षेत्र; और
  - पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई: परिपक्व होने पर स्वस्थान पर 2 से 5 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता।
- 1.3 भारत के वन की परिभाषा केवल उपर्युक्त तीन मानदंडों के आधार पर ली गई है और उनकी रिपोर्टिंग/संप्रेषण के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा इसे पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। 'वो भूमि जो क्षेत्र में एक हेक्टेयर से अधिक, जिसमें स्वामित्व और कानूनी स्थिति के बावजूद 10 प्रतिशत से अधिक वृक्ष कैनोपी घनत्व है उसे वन क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी भूमि आवश्यक रूप से एक दर्ज वन क्षेत्र नहीं हो सकती। इसमें बाग, बांस और ताड़ भी शामिल हैं'। वन क्षेत्र को सभी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) और भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषणों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- 1.4 मंत्रालय द्वारा हाल ही में 13 जनवरी, 2022 को प्रकाशित आईएसएफआर 2021 में, वन क्षेत्र के आंकड़ों को 'इनसाइड रिकॉर्डेड फोरेस्ट एरिया' और 'आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया' के रूप में विभाजित किया गया है। वे 'इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया' मूल रूप से प्राकृतिक वन और वन विभाग के वृक्षारोपण हैं। 'आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया' के वन क्षेत्र में आम के बाग, नारियल के बागान, कृषि वानिकी के ब्लॉक वृक्षारोपण हैं। इस प्रकार आम के बागानों आदि के आंकड़े स्वतः अलग हो रहे हैं क्योंकि भारतीय वन सर्वेक्षण अलग से 'आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया' के आंकड़ों की रिपोर्ट कर रहा है।

#### भारतीय वन अधिनियम, 1927

1.5 भारतीय वन अधिनियम, 1927 वनों, वन-उपज के परिवहन तथा लकड़ी और अन्य वन-उपज पर लगाए जाने वाले शुल्क से संबंधित कानून को समेकित करता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति पूर्व युग के दौरान, स्थानीय अधिनियमों के अतिरिक्त, अधिकांश वनों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंधों के तहत प्रबंधित और संरक्षित किया जा रहा था।

#### वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

- 1.6 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन से पहले और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के युग की 1951 से 1975-76 की अविध के दौरान, लगभग 4.135 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि को पर्यावरणीय विचारों की परवाह किए बिना विभिन्न वनेतर प्रयोजनों के लिए परिवर्तित किया गया था। देश के तेजी से घटते वन संसाधनों का संज्ञान लेते हुए, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा वनों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। यह आवश्यक महसूस किया गया कि विभिन्न वनेतर उपयोगों के लिए वन भूमि के अनियंत्रित और अनियमित उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए नियामक तंत्र होना चाहिए। तदनुसार, 25-10-1980 को संसद द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को अधिनियमित करके वन भूमि के आरक्षण-मुक्त और वनेतर उपयोग के बारे में विनियमन प्रस्तुत किया गया था।
- 1.7 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 देश में वनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय परिनियम है। इसमें उपबंध है कि आरक्षित वनों का आरक्षण रद्द करने, वन भूमि का उपयोग वनेतर प्रयोजन के लिए करने, वन भूमि को पट्टे के रूप में या अन्यथा प्राइवेट सत्ता को सौंपने और पुनर्वनीकरण के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को हटाने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमित की आवश्यकता होती है। पिछले चार दशकों के दौरान, अधिनियम के अधिनियमन के बाद वन भूमि के अपवर्तन की औसत वार्षिक दर लगभग

22,000 हेक्टेयर तक कम हो गई है। पिछले 43 वर्षों के दौरान, पर्याप्त शमन उपायों के साथ लगभग 9.83 लाख हेक्टेयर वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों के लिए परिवर्तित किया गया था।

1.8 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई लिखित प्रस्तुति के अनुसार, 12-12-1996 तक सामान्य पद्धति यह थी कि राज्य सरकारें, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम को केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत अधिसूचित वनों या किसी अन्य स्थानीय विधि के अंतर्गत अधिसूचित वनों और वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण में आने वाले वनों पर लागू करते थे। यह अधिनियम केवल छिटपुट रूप से उन भूमियों पर लागू किया गया था जो राजस्व अथवा अन्य विभागों के नियंत्रण में थे।

#### माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- 1.9 माननीय उच्चतम न्यायालय ने टीएन गोडावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में पारित अपने दिनांक 12.12.1996 के निर्णय में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों की प्रयोज्यता के दायरे को स्पष्ट किया। निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित प्रकार के वनों/वन भूमि पर लागू होते हैं:—
  - (क) स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के बावजूद किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र। इसमें किसी भी कानून के तहत वन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र शामिल थे;
  - (ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों से भिन्न सभी क्षेत्र और 'वन के शब्दकोश अर्थ' के अनुरूप हैं; और
  - (ग) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुसरण में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा वन के रूप में पहचाने गए सभी क्षेत्रों और तदनुसार 1997 में उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

#### संशोधन किए जाने की आवश्यकता

- 1.10 इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि दिनांक 12-12-1996 के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों ने प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ समिति द्वारा 'वन' के रूप में पहचाने गए किसी अन्य क्षेत्र और वन के शब्दकोश अर्थ के अंतर्गत आने वाली भूमि पर भी इस अधिनियम को लागू करना शुरू कर दिया है। इसलिए, विभिन्न प्रकार की भूमि में अधिनियम की प्रयोज्यता गितशील रही है अर्थात शुरू में अधिनियम के उपबंध केवल अधिसूचित वन भूमि पर लागू किए जा रहे थे और बाद में, अधिनियम को राजस्व वन भूमि या उन भूमि पर लागू किया गया था जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया था। ऐसी कई भूमि का पहले से ही सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदन से वनेतर उपयोग जैसे कि आवास, संस्था, सड़क आदि किया जा रहा था। इस स्थिति के परिणामस्वरूप अधिनियम के उपबंधों की उनकी प्रयोज्यता के संबंध में विशेष रूप से दर्ज वन भूमि, प्राइवेट वन भूमि, वृक्षारोपण, आदि में गलत व्याख्या की गई। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया कि अस्पष्टताओं को दूर करना और विभिन्न भूमि में अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टता लाना आवश्यक है।
- 1.11 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में विभिन्न व्याख्याओं के कारण ऐसे वृक्षारोपण को वन माने जाने के बारे में व्यक्तियों, संगठनों और अधिकारियों के बीच आशंका के कारण वनेतर भूमि में वृक्षारोपण करने की घटती प्रवृत्ति देखी गई है, और यह मिथ्याबोध 2.5 से 3.0 बिलियन टन सीओ 2 समतुल्य कार्बन सिंक के सृजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र को बढ़ाने में एक बाधा बन रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महत्ता की सामरिक और सुरक्षा संबंधित परियोजनाओं के त्वरित निपटान की आवश्यकता है तािक महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं के विकास को विशेषकर अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ जैसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी), नियंत्रण रेखा (एलओसी), एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों में भी सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार, सड़कों/रेलमार्गों के समीप छोटे स्थापनों और बस्तियों को उन्हें मुख्य मार्गों ओर अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच और संपर्क उपलब्ध कराके सुकर बनाने की भी आवश्यकता है।
- 1.12 इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि 1988 में वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए प्राइवेट सत्ता को पट्टे पर वन भूमि के समनुदेशन को विनियमित करने के लिए धारा 2 का खंड (iii) अंत:स्थापित गया था। तथापि, हाल के दिनों में खनन और अन्य प्रयोजनों के लिए पट्टे पर वन भूमि को समनुदेशित करने के लिए राज्यों और प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा इस धारा के उपबंधों का उपयोग किया जा रहा है। उप-धारा के उपबंधों को उनकी मौजूदा अभिव्यक्ति में, सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन वाली सत्ताओं पर खनन के लिए सिहत लागू नहीं किया जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप एकरूपता की कमी होती है, और इसलिए उपबंधों में एकरूपता लाने के लिए, उपधारा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे पट्टे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार समनुदेशित किए जाएं।
- 1.13 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह भी बताया है कि विभिन्न वानिकी प्रबंधन गतिविधियों को पूरा करने और वनों में त्वरित प्राकृतिक विपत्तियों के निपटान के लिए, वन भूमि में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बनाए रखने की आवश्यकता है। अधिनियम में सामर्थ्यकारी उपबंधों के अभाव में, वन क्षेत्र में इस तरह की बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना कठिन है, जिससे वानिकी संचालन, पुनर्जनन गतिविधियों, निगरानी और पर्यवेक्षण, जंगल की आग की रोकथाम, आदि पर प्रभाव

पड़ता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों द्वारा वनों की उचित सुरक्षा और संरक्षण के लिए आजीविका के अवसरों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है जिसे इको-टूरिज्म, चिड़ियाघर और सफारी को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अत:, इस उप-धारा के अंतर्गत वानिकी प्रबंधन के लिए सहायक गतिविधियों को स्पष्ट किया गया है। 'स्पष्टीकरण' शब्द को उन गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तृत बनाया गया है जो वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए किए जाते हैं। इसलिए, प्रस्तावित उप-धारा (1) के 'स्पष्टीकरण' में संशोधन किया गया है ताकि उन गतिविधियों को शामिल किया जा सके जो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए की जाती हैं।

- 1.14 वन क्षेत्र में अस्थायी सर्वेक्षण गतिविधियों जैसे जांच, अवीक्षण आदि से वन भूमि उपयोग में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वन वनस्पति में या भूमि के टूटने में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। ये अन्वेषण, अन्वेषणात्मक सर्वेक्षणों के अवीक्षण, आदि वन भूमि को प्रभावित किए बिना खनिजों की उपलब्धता निर्धारित करने के प्रभावी साधन हैं। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सर्वेक्षण आदि को वनेतर गतिविधि के रूप में न माना जाए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ नियमों और शर्तों के अधीन होगा।
- 1.15 अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पिछले चार दशकों से अधिक समय के दौरान वनों के परिरक्षण और विकास से संबंधित पारिस्थितिकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं और नीतियों में परिवर्तन हुआ है। अधिनियम के उपबंधों को देश की पारिस्थितिकीय, सामरिक और आर्थिक अभिलाषाओं में गतिशील परिवर्तनों के अनुरूप रखने के लिए विधेयक में निदेश जारी करने के लिए एक सामर्थ्यकारी उपबंध करने के लिए एक नई धारा 3ग के रूप में अंत:स्थापित की गई है।
- 1.16 अधिनियम मुख्य रूप से विभिन्न वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए प्रख्यापित किया गया था। बीच की अवधि के दौरान, अधिनियम के लागू होने के बाद, पारिस्थितिकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास से संबंधित नई चुनौतियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, वन कार्बन स्टॉक का अनुरक्षण या वृद्धि आदि। इसलिए, वनों और उनकी जैव-विविधता को संरक्षित करने की देश की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए, ऐसे मुद्दों को अधिनियम के दायरे में शामिल करना आवश्यक है।

## वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023

- 1.17 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 प्रस्तावित किया गया है। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:—
  - (i) देश के वनों के संरक्षण, उनकी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की देश की समृद्ध परंपरा को शामिल करने के लिए अधिनियम में प्रस्तावना को अन्तःस्थापित करना।
  - (ii) अधिनियम के संक्षिप्त नाम को संसोधित करके वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 करना ताकि अधिनियम के उपबंधों को वर्तमान परिदृश्य हेतु और प्रासंगिक तथा समावेशी बनाया जा सके।
  - (iii) विभिन्न भूमियों पर अधिनियम की प्रयोज्यता के दायरे को स्पष्ट करना ताकि अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके और स्पष्टता लाई जा सके।
  - (iv) अधिनियम के कार्यक्षेत्र से भूमियों की कतिपय श्रेणियों को छूट प्रदान करना—
    - (क) राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करना,
    - (ख) सार्वजनिक सड़कों और रेलवे के किनारे छोटे प्रतिष्ठानों, आवासों तक पहुंच प्रदान करना, और
    - (ग) गैर-वन भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना;
  - (v) अधिनियम के तहत प्रस्तावित छूट पर विचार करते हुए भूमि पर किए गए पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए पेड़ लगाने की शर्तों सहित नियम और शर्ते प्रदान करना।
  - (vi) अधिक गतिविधियों को शामिल करना, जो वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वानिकी गतिविधियों की श्रेणी में की जाती है।
  - (vii) सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के संबंध में अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता में एकरूपता लाना ।
  - (viii) केंद्र सरकार को, आदेश द्वारा, नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाना, जिसके अधीन भूकंपीय सर्वेक्षण सहित सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण जैसे किसी भी सर्वेक्षण को गैर-वन उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाएगा।
  - (ix) केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देना।

### वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति

1.18 वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को संसद द्वारा जांच और रिपोर्ट के लिए इस वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति को भेजा गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को लोकसभा ने 29 मार्च, 2023 को स्वीकार कर लिया था और उसी दिन राज्यसभा ने विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के गठन के संबंध में लोकसभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त की थी। प्रस्ताव के अनुसार समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संयुक्त समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य (लोक सभा) समिति के सभापति हैं। पहली बैठक में समिति को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो विधेयक के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है, के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई। दूसरी से पांचवीं बैठकों में, समिति ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों यथा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग), खान मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जो इस नोडल मंत्रालय अर्थात पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ इस विधेयक से मुख्य रूप से संबद्ध है तथा तीन राज्य सरकारों यथा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के प्रतिनिधियों के विचार सुने। छठी और सातवीं बैठक में समिति ने इस बिषय के संबंध में कुछ विशेषज्ञों और कुछ लोगों के भी विचार सुने, जिन्होंने समिति को अपने सुझाव सौप दिए। प्रथम बैठक में समिति ने विधेयक में निहित उपबंधों पर लोगों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का भी निर्णय लिया। इसकी प्रतिक्रिया में समिति को कुल 1309 ज्ञापन/सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने सभी पूर्वोत्तर राज्य और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित शेष राज्यों यथा ओड़ीशा और आंध्रप्रदेश सहित 15 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के विचार सुनने के लिए 2 जून से 7 जून, 2023 तक श्रीनगर, गौहाटी और भुवनेश्वर का अध्ययन दौरा भी किया। समिति ने इस अध्ययन दौरे के दौरान इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विभिन्न अन्य हितधारक संगठनों और पीएसयू यथा सेना उत्तरी कमान (XV कोर), बीआरओ, बीएसएफ,

डीआरडीओ, डीजीएच और ओएनजीसी के साथ चर्चा भी की। सातवीं बैठक में समिति ने इस विधेयक की खंड-वार चर्चा की। समिति ने 11.07.2023 को हुई अपनी आठवीं बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार्य किया।

1.19 निम्नलिखित अध्याय समिति द्वारा विधेयक की खंड-वार जांच से संबंधित हैं।

#### अध्याय – दो

### वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 की खंड-वार जांच

#### खंड 1

- 2.1.1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

#### खंड 2

## मूल अधिनियम के संगत उपबंध

### उद्देशिका:

2.2.1 मूल अधिनियम में ये उपबंध मौजूद नहीं हैं।

## संशोधन विधेयक में प्रस्तावित उपबंध

2.2.2 अधिनियम के पूरे नाम के पश्चात् और अधिनियमन सूत्र के पूर्व में निम्नानुसार उद्देशिका को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है:

"और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए और पारिस्थितिकीय रूप से संतुलित भरणीय विकास के माध्यम से वन कार्बन स्टॉक का अनुरक्षण या वृद्धि करने के लिए वनों की महता को अनुभव किया जाना है:

और देश के राष्ट्रीय रूप से अवधारित योगदान लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन सीओ₂, के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने की परिकल्पना करते हैं;

और देश अपने भूमि क्षेत्र के एक-तिहाई तक वन और वृक्ष आच्छदन में वृद्धि करने की परिकल्पना करता है, जिसे बढ़ी हुई वृद्धि प्रक्षेप्कता के साथ बल प्रदान किया जाना है;

और भारत की वनों को और उनकी जैव-विविधता को संरक्षित करने की समृद्ध परंपरा रही है और इसलिए वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय फायदों में वृद्धि की जा रही है जिसके अंतर्गत वनों पर निर्भर समुदायों के जीवनयापन में सुधार की परिकल्पना भी सम्मिलित की गई है;

और इसलिए, वनों के संरक्षण प्रबंधन और पुनः बहाली से संबंधित उपबंधों का उपबंध करने, पारिस्थितिकीय सुरक्षा, भरणीय संस्कृति और वनों की पारंपरिक महता का अनुरक्षण करने तथा आर्थिक आवश्यकताओं और कार्बन तटस्थता को बनाए रखने की आवश्यकता है।"

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण/ औचित्य

2.2.3 अधिनियम के उपबंधों को देश की पारिस्थितिकीय, रणनीतिक और आर्थिक महत्वकांक्षाओं में गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल में रखने और वन संरक्षण, बहाली, प्रतिपूरक तंत्र, शमन उपायों आदि के लिए उभरती पारिस्थितिकीय चुनौतियों के साथ इस अधिनियम के दायरे को प्रासंगिक बनाने के लिए, अधिनियम का नाम बदलने और अधिनियम में उद्देशिका को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

### समिति द्वारा जांच

2.2.4 विधेयक संबंधी ब्रीफिंग के दौरान पाया गया कि यदि उद्देशिका में निर्धारित लक्ष्यों को उल्लिखित वर्ष में पूरा नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम को पुन: संशोधित करना होगा। यदि लक्षित वर्ष के पूर्व भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है, तो भी अधिनियम को पुन: संशोधित करना होगा। इसलिए इन लक्ष्यों को उद्देशिका में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त अवलोकन के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में निम्नानुसार कहा है:—

"उद्देशिका में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों, कार्बन सिंक का निर्माण, ग्रीन कवर में वृद्धि, जैव-विविधता को संरक्षित करने और वन पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का उल्लेख किया गया है। सभी प्रस्तावित उपबंधों का संचालन वन प्रबंधन संवर्धन के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगा। इसमें शामिल उद्देशिका वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार के आशय को दर्शाती है।"

2.2.5 26 जून,2023 को इस विधेयक की खंड-वार चांच के दौरान जब यह मामला पुन: उठा तो वन महानिदेशक तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने स्पष्टीकरण दिया है कि प्रस्तावित उद्देशिका में उल्लिखित लक्ष्य भारत सरकार द्वारा जताई गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। इसे विस्तार से बताते हुए, उन्होंने विधेयक के खंडवार परीक्षण के दौरान निम्नलिखित बताया:—

"सर, उद्देशिका को चार भागों में पढ़ा जा सकता है। पहला भाग मुल रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं जिन पर हम नेट-जीरो और अतिरिक्त कार्बन सिंक के संबंध में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सहमत हए हैं। अतः, यह मूल रूप से नीति-निर्माताओं और न केवल नीति-निर्माताओं बल्कि राज्य सरकारों और उन अधिकारियों को भी दिशा-निर्देश प्रदान करना है जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार अपनी नीतियों और कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए क्षेत्र में हैं। अंततः, चूंकि इन प्रतिबद्धताओं को पूरे देश को पूरा करना था - सभी अधिकारियों, इन सभी नीति-निर्माताओं और सभी सरकारों को इस प्रतिबद्धता के लिए एक साथहाथ मिलाना चाहिए। भाग संख्या दो वन नीति के संबंध में है जो वर्तमान में प्रचलित है जिसमें हमें पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 भाग को वन के अंतर्गत लाना है। अतः, यह सभी नीति-निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों को यह भी याद दिलाता है कि सरकार ने नीति में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हमें वन क्षेत्र के एक तिहाई भाग को हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाहिए। यदि आप तीसरे भाग के साथ जाते हैं, तो यह अधिकांश माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी प्रतिध्वनित करता है। यह वन की समृद्ध परंपरा और आश्रित समुदायों के बारे में भी बात करता है। जैसा कि माननीय मंत्री ने किया है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि आश्रित समुदायों का क्या होगा, हमने उद्देशिका में इसके बारे में पहले ही उल्लेख किया है कि हम वे सभी उपाय करने जा रहे हैं जो सरकार को आश्रित समुदायों के हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं, जहां भी आश्रित समुदाय । मैंने पहले ही विभिन्न बैठकों में उल्लेख किया है कि एफआरए लागू होगा। इस प्रकार हम इस संशोधन के बाद किसी भी अधिनियम को कमजोर नहीं करने जा रहे हैं। आज की तारीख में लागू सभी अधिनियम इस संशोधन के बाद भी लागु होंगे। फिर अंतिम भाग में हम वन की विविधता के बारे में बात करते हैं। अत, यह केवल सरकार या वन विभाग के लिए नहीं है, बल्कि यह उन प्रयोक्ता एजेंसियों के लिए भी है जो वन अधिनियम के अंतर्गत स्वीकति प्राप्त करने जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए आ रही हैं। उन्हें इन सभी बातों के बारे में यह भी याद दिलाया गया है कि आश्रित समुदाय हैं और जब भी वे किसी गतिविधि की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें यह विचार करना होगा कि वन निर्भर सम्दाय हैं। वन विविध हैं। अत, उन्हें अपनी गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि इन सभी चीजों में व्यवधान न हो। यह मुल रूप से उद्देशिका रखने और उद्देशिका में इन सभी मुद्दों को उजागर करने का विचार है।"

2.2.6 ब्रीफिंग के दौरान यह भी पाया गया है कि इसकी उद्देशिका में आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में उल्लेख है किंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनकी आर्थिक आवश्यकताएं प्रस्तावित हैं। उद्देशिका और कार्बन स्टॉक तटस्थता में बताए गए राष्ट्रीय लक्ष्यों की सक्षम उपलब्धियों के संबंध में, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वृक्षारोपण की तुलना में प्राकृतिक वनों की कार्बन पृथक्करण क्षमता 40 गुना हरित है। इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में निम्नलिखत रूप में लिखित स्पष्टीकरण दिया है:—

"विधेयक में शामिल आर्थिक आकांक्षाएं स्थानीय समुदायों की आर्थिक आकांक्षाओं का प्रतीक है जो वास्तव में राष्ट्र की आकांक्षा है।"

## अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय

- 2.2.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समिति को निम्नलिखित बताया:—
  - "(i) 'वन आश्रित समुदाय' शब्द व्यापक है विशिष्ट नहीं है। यह सुझाव दिया जाता है कि हम वन निवासी अनुसूचित जनजाति (एफडीएसटी)/अन्य पारंपरिक वन निवासी (ओटीएफडी) को शामिल करके इस शब्द को स्पष्ट कर सकते हैं।
  - (ii) विशेष रूप से एफडीएसटी/ओटीएफडी की रक्षा करने के लिए 'वन के मूल्यों' के बाद यह अंत:स्थापित किया जाए: ''वन और रूढ़िगत अधिकारों के साथ-साथ एफडीएसटी/ओटीएफडी के संबंध में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण को शामिल करके।"

#### 2.2.8 राज्य सरकारें

राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी
मिजोरम सरकार:—	विद्यमान मूल अधिनियम में कोई उद्देशिका नहीं है और
उद्देशिका के विषय-वस्तु अधिनियम के विषय-वस्तु के अनुरूप	तदनुसार ही, मूल अधिनियम में एक उद्देशिका जोड़ी गई है।
होंगे। चूंकि इस अधिनियम के संशोधन में वन (संरक्षण)	प्रस्तावित उद्देशिका मूल अधिनियम के पूरे नाम को अतिछादित
	नहीं करता है। इस विधेयक की उद्देशिका इस अधिनियम के

रखना शामिल है, इसलिए उद्देशिका को उचित रूप में लिखे जाने की आवश्यकता है ताकि इस अधिनियम की उद्देशिका और इनके उपबंधों के बीच बिरोधाभास से बचा जा सके।

#### सिक्किम सरकार

इसकी उद्देशिका को युक्ति संगत बनाए जाने की आवश्यकता है। 'उद्देशिका' में बदलाव और स्पष्ट रूप में सरकार के लक्ष्य और वीजन को जोड़ना स्वागत योग्य है किंतु इन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, के बारे में स्पष्ट उपबंध होने चाहिए। विद्यमान पूरे नाम के अतिरिक्त है जिसमें वन संरक्षण और इससे संबद्घ गतिविधियां अथवा इसके सदृश्य कार्य का प्रावधान है।

समुदाय भागीदारी को बढ़ावा देने के अलावा इसके स्वास्थ्य, उतपादकता और सेवा प्रभाह में सुधार कर वन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए इस अधिनियम में उद्देशिका को अंतर्विष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त इस विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त समर्थकारी उपबंध का यथा आवश्यक आह्वान किया जाएगा ताकि इस अधिनियम की प्रयोज्यता स्पष्ट हो और यह सुनिश्चित हो कि वन भूमि का दुरुपयोग नहीं हो रहा हो।

इस विधेयक के उपबंध इसकी उद्देशिका में दिए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों की पृष्टि करते है।

प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंध निजी भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देता है जिससे कि देश के हरित क्षेत्र को बढ़ाने में जन भागीदारी को सुकर बनाया जा सके तथा कार्बन के प्रभाव को कम करने, कार्बन सिंक को बढ़ाने, बेहतर वन प्रबंधन आदि जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटा जा सके।

गैर वन भूमि में वनीकरण को बढ़ावा देने से वनों पर दबाव कम होने के अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित होगा।

संवर्धित उत्पादकता और पारिस्थितिकीय वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु वन प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होगा और वन संरक्षण को बढावा मिलेगा।

इस विधेयक की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण में वनों में प्राकृतिक संकटों की तत्काल प्रतिक्रिया तथा वन से जुड़े अग्रणी कर्मचारियों हेतु मूल भूत अवसंरचना के लिए समर्थकारी प्रावधान के माध्यम से प्रभावी वन प्रबंधन को सुकर बनाने की व्यवस्था है।

ये उपबंध ईको टूरिज्म और चिडियाघरों एवं सफारियों की स्थापना से भागीदारी करने वाले लोगों की आजीविका के अवसर मिलने के अलावा वन संरक्षण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन देते है।

# विभिन्न विशेषज्ञों/जनता द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव

2.2.9 समिति को प्रस्तुत लिखित ज्ञापन में, उद्देशिका को हटाने का सुझाव देने वाले हितधारकों ने निम्नानुसार कहा:—

- उद्देशिका अधिनियमन के कारणों की व्याख्या करते हुए शुरुआत में एक खंड है। वर्तमान अधिनियम में उद्देशिका नहीं है क्योंकि शीर्षक संक्षिप्त और स्वयं व्याख्यात्मक है।
- प्रस्तावित उद्देशिका को को पूरी तरह से हटा दिया जाए। प्रस्तावित संशोधन "वन संरक्षण की व्यवस्था करने" और "वन कटाई को रोकने" के वन संरक्षण अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य को उच्छेदित करता है। यह संशोधन विद्यमान अधिनियम के उपबंधों निष्प्रभावी बनाता है, 1995 के वी.पी. संख्या 202 के माध्यम से संरक्षण प्रदान करता है, वन संरक्षण अधिनियम के दायरे को कम करता है और पौध रोपण के नाम पर वनों के एक बड़े भाग को निजी हाथों में देता है।
- वर्तमान अधिनियम एक कठोर कानून है और इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे बेहतर व प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।

2.2.10 उपर्युक्त सुझाव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ध्यान में लाया गया। मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में जो कहा वह निम्नलिखित है:—

"प्रस्तावित विधेयक का प्रारम्भिक उद्देश्य विभिन्न भूमि पर इस अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना है। इस अधिनियम के दायरे को बढाए जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि वन संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित वैश्विक मुद्दे को शामिल और समाधान किया जा सके। गैर-वन भूमि पर वनीकरण को प्रोत्साहित करने के विचारार्थ इस विधेयक में एक स्पष्टता दी गयी है ताकि ऐसी भूमि को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके। इस विधेयक के वर्तमान उपबंधों में निजी क्षेत्रों को वन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं है बल्कि वन कार्यों की उत्पादकता और सुदृढ़ता को बढ़ाने का प्रोत्साहन है।"

2.2.11 अन्य विशेषज्ञों और लोगों ने अपने लिखित ज्ञापनों में इस अधिनियम की उद्देशिका और विषय-वस्तु में उल्लिखित उद्देश्यों के बीच अंतर के संबंध में चिंताएं व्यक्त की। इस संबंध में हितधारकों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:—

- इसकी उद्देशिका में उल्लिखित सहायता माध्यम और नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना, वनाच्छान को बढ़ाना, कार्बन न्युट्लिटी आदि विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।
- उद्देशिका में वनाच्छान के अंतर्गत देश के एक तिहाई क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने का उल्लेख है। तथापि, संशोधन विधेयक में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, राज्य को पर्याप्त शक्ति प्रदान की जाए ताकि वह उक्त भूमि को अधिसूचित कर सके जो भूमि वन के निकट नहीं है। इस संशोधन में उद्देशिका में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई तंत्र मौजुद नहीं है।"
- 2.2.12 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उपर्युक्त टिप्पणी की लिखित प्रतिक्रिया में निम्नवत् कहा:—

"प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों में निजी भूमि पर वनीकरण करने को बढ़ावा दिया गया है जिससे कि देश के हरित आच्छान को बढ़ाने में लोगों की भागीदारी को सुकर बनाया जा सके और कार्बन न्युट्रिलिटी, कार्बन सिंक को बढ़ाने, बेहतर वन प्रबंधन आदि जैस वैश्विक मुद्दे से निपटा जा सके।

इस विधेयक की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त स्पष्टीकरण में वनों में प्राकृतिक संकटों के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया तथा वन के अग्रीम पंक्ति के कर्मचारियों हेतु मूलभूत अवसंरचना हेतु उपबंधों को समर्थकारी बना कर प्रभावी वन प्रबंधन को सुकर बनाने के लिए एक समर्थकारी व्यवस्था है।

ये उपबंध इको-टूरिज्म के माध्यम से तथा चिड़िया घरों और सफारियों की स्थापना कर लोगों की आजीविका के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त वन संरक्षण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं।

अधिनियम के दायरे से गैर-वन भूमि को छूट देने से गैर-वन भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा जो अंततः प्राकृतिक वनों पर कम दबाव के कारण प्राकृतिक वनों की उत्पादकता में वृद्धि करेगा।"

#### 2.2.13 इसी आधार पर अन्य दो लोगों ने अपने लिखित ज्ञापनों के माध्यम से उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी दी:—

- "वर्तमान उद्देशिका वन भूमि के अन्यत्र उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है क्योंकि यह 'कार्बन सिंक के निर्माण द्वारा वन और वनाच्छान बढ़ाने'; 'वन समुदायों के जीवन और आजीविका में सुधार' और 'वनों का संरक्षण और प्रबंधन और बहाली' पर जोर देती है। ये पहले से ही भारतीय वन अधिनियम, 1927, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण) अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 जैसे अन्य अधिनियमों के तहत शामिल हैं।
- एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उद्देशिका संविधि के इस प्राथमिक उद्देश्य का उल्लेख करने में विफल रही है जो वनों के अपवर्तन को विनियमित और नियंत्रित करना है।
- उद्देशिका में कहा गया है कि यह विधेयक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने और कार्बन में कमी लाने के लिए पेश किया गया है, जिससे बचा जाना चाहिए। और उपर्युक्त दो कारणों से वनों को उद्यान/सम्पदा बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त लक्ष्यों को केवल वानिकी वृक्षारोपण गतिविधियों और हरित आवरण के क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- उद्देशिका शुद्ध शून्य उत्सर्जन, कार्बन सिंक के निर्माण, वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने, पारिस्थितिक सुरक्षा बनाए रखने, कार्बन तटस्थता आदि के संदर्भ में पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के महान उद्देश्य के बारे में बताती है। यह

विधेयक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के बजाय गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन की दिशा में अधिक सुविधा प्रदान करता है।

 प्रतिबद्धताओं के लिए एक अलग अधिनियम की आवश्यकता है क्योंकि भविष्य में हम और अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं करने जा रहे हैं। यह अधिनियम प्रस्तावना के साथ असंगत है।"

## 2.2.14 उपर्युक्त टिप्पणियों के एक लिखित उत्तर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने निम्नवत् कहा:

"मूल अधिनियम के मौजूदा उपबंधों यानी अधिनियम के पूरा नाम के अभिप्राय में संशोधन नहीं किया गया है और इसे अपने मौजूदा रूप में बनाए रखा गया है। इसलिए, अधिनियम के नियामक उपबंधों को बरकरार रखा गया है। विधेयक में प्रस्तावित उद्देशिका अधिनियम के मौजूदा उपबंध के अतिरिक्त है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के अलावा वन प्रबंधन के स्वास्थ्य, उत्पादकता और सेवाओं के प्रवाह में सुधार करके इसे मजबूत करने के लिए अधिनियम में प्रस्तावना जोड़ी गई है। इसके अलावा, अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो, विधेयक की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

इस विधेयक के उपबंध इस उद्देशिका में दिए गए लक्ष्य और उद्देश्य का समर्थन करता है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों में निजी भूमि पर वनीकरण करने को बढ़ावा दिया गया है जिससे कि देश के हरित आच्छान को बढ़ाने में लोगों की भागीदारी को सुकर बनाया जा सके और कार्बन न्युट्रिलिटी, कार्बन सिंक को बढ़ाने, बेहतर वन प्रबंधन आदि जैस वैश्विक मुद्दे से निपटा जा सके। गैर-वन भूमि में वनीकरण को बढ़ावा देने से वनों पर दबाव कम करने के अलावा अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण होगा। बेहतर उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के लिए वन का प्रबंधन भी जलवायु परिवर्तन और वनों के संरक्षण के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। इस विधेयक की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त स्पष्टीकरण में वनों में प्राकृतिक संकटों के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया तथा वन के अग्रीम पंक्ति के कर्मचारियों हेतु मूलभूत अवसंरचना हेतु उपबंधों को समर्थकारी बना कर प्रभावी वन प्रबंधन को सुकर बनाने के लिए एक समर्थकारी व्यवस्था है। ये उपबंध इको-टूरिज्म के माध्यम से तथा चिड़िया घरों और सफारियों की स्थापना कर लोगों की आजीविका के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त वन संरक्षण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं।"

#### 2.2.15 इसके अतिरिक्त लिखित ज्ञापनों में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई:—

- (i) यह देखा गया है कि उद्देशिका के पैरा 2 में 'ट्री कवर' शब्द को हटा दें क्योंकि पेड़ कवर का मतलब मोनोकल्चर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना हो सकता है। इसके बजाय, उसे केवल वन आवरण के तहत एक तिहाई भूमि क्षेत्र कहना चाहिए।
- (ii) उद्देशिका में वृक्ष आच्छादन में वृद्धि के माध्यम से वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की उपलब्धि पर जोर दिया जाना मूल अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध है।
- (iii) 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना सराहनीय है, हालांकि, पेड़, जंगल और कार्बन स्टैक जैसे शब्दों का उपयोग देश की पारिस्थितिक अखंडता के लिए खतरा है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे अल्पाइन घास के मैदान, घास की भूमि, बाढ़ प्रभावित वन क्षेत्रों, कम पेड़ घनत्व वाले क्षेत्रों के कार्बन स्टॉक उच्च कार्बन स्टॉक को बनाए रखते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को विधेयक के प्रस्तावित उपबंधों द्वारा अलग कर दिया गया है।

#### 2.2.16 इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत कहा:—

- (i) " इस संबंध में स्पष्टीकरण, यदि भविष्य में कोई आवश्यकता हो, विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत उपबंधित उपबंधों को लागू करके केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।
- (ii) वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की उपलब्धि मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है। विधेयक में परिकल्पित वृक्ष आच्छादन में वृद्धि से गैर-वन भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देने और वन के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने से वनों पर जैविक दबाव को कम करने के अलावा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार वन संरक्षण के उद्देश्य को पूरा किया जा सकेगा, जैसा कि मूल अधिनियम में परिकल्पित है।
- (iii) वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन की उपलब्धि में वन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ अन्य पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे घास भूमि, मरूभूमि, अल्पाइन घास के मैदान आदि की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए हमारे देश के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा कार्बन स्टॉक में संचयी वृद्धि की परिकल्पना की गई है। गैर-वन भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देकर और वन के स्वास्थ्य और

उत्पादकता में सुधार करके विधेयक में परिकल्पित वृक्ष वारण में वृद्धि से वनों पर जैविक दबाव को कम करने के अलावा उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार मूल अधिनियम में परिकल्पित वन संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा।"

#### समिति की टिप्पणी/सिफारिश

2.2.17 सिमिति ने विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझाव तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए अर्थपूर्ण उत्तर/स्पष्टीकरणों सिहत मूल अधिनियम की उद्देशिका को जोड़ने के लिए खंड में किए गए प्रस्तावों पर विचार किया और निर्णय लिया कि खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया जाए।

खंड 3

### मुल अधिनियम के संगत उपबंध

2.3.1 अधिनियम का नाम: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

#### संशोधन विधेयक में प्रस्तावित उपबंध

2.3.2 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980

## पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण/स्पष्टीकरण

2.3.3 अधिनियम के उपबंधों को देश की पारिस्थितिकीय, रणनीतिक और आर्थिक महत्वकांक्षाओं में गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल में रखने और वन संरक्षण, बहाली, प्रतिपूरक तंत्र, शमन उपायों आदि के लिए उभरती पारिस्थितिकीय चुनौतियों के साथ इस अधिनियम के दायरे को प्रासंगिक बनाने के लिए, अधिनियम का नाम बदलने और अधिनियम में उद्देशिका को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

#### समिति द्वारा जांच

2.3.4 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों के बारे में ब्रीफिंग के दौरान, यह बताया कि नाम बदलने के लिए प्रस्तावित संशोधन न तो इस कानून के महत्व को बढ़ाता है और न ही वर्तमान अधिनियम के दायरे और लक्ष्यों के संदर्भ में जरूरतों को पूरा करता है। इसे वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम कहना अधिक उचित होगा। इसके अलावा ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया गया कि विधेयक या अधिनियम का शीर्षक गैर-समावेशी है क्योंकि यह दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व दोनों में जनसंख्या के विशाल समूह को छोड़ देता है।... अत:, इसे समावेशी होने की आवश्यकता है। शीर्षक को बदला जाना चाहिए ताकि इसे ठीक से समझा जा सके और वास्तव में वन सुरक्षा या वन संरक्षण की प्रकृति को प्रतिबिंबित करे। इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

"नीतियों और कार्यक्रमों में गतिशील परिवर्तन हमारे वन संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके अधिक कुशल प्रबंधन की जरूरत हैं। इसके अलावा, वैश्विक चुनौतियों जैसे कार्बन तटस्थता, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) का सामना करने के लिए, हरित आवरण को बढ़ाना, पारिस्थितिक स्थिरता और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना आदि आवश्यक है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, अधिनियम को स्वत: स्पष्ट नाम दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है"।

2.3.5 विधेयक की खण्डवार जांच के दौरान, जब यह पूछा गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम का नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम किए जाने से क्या विशेषताएं प्राप्त होने वाली हैं, तो वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:—

"अब तक, इसका नाम वन संरक्षण अधिनियम है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे वन स्वीकृति अधिनियम के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के पास जो भी प्रयोक्ता एजेंसियां आ रही हैं, यहां तक कि विरष्ठ अधिकारियों को भी यह नहीं पता है कि यह एक विपथन है। वे बस सोचते हैं कि यह एक तरह की एनओसी या मंजूरी है। यह एक गलतफहमी है जिसे हम दूर करना चाहते हैं। संरक्षण के साथ-साथ संवर्धन शब्द का प्रयोग करके, हम सभी प्रयोक्ता एजेंसियों और राज्य सरकारों पर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह अधिनियम मूल रूप से केवल विकास कार्यों के लिए अनुमति देने के लिए नहीं है। विकास ता्मक कार्यों के साथ-साथ इससे इस तथ्य को भी बल मिलता है कि जहां विकासात्मक गतिविधियां आवश्यक हैं, वहीं वनों का संरक्षण और संवर्धन भी आवश्यक है। अन्यथा, जलवायु परिवर्तन के जो भी प्रभाव आज हम देख रहे हैं, वे और अधिक गंभीर हो जाएंगे और हम पहले से ही चक्रवात आदि देख रहे हैं, उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। हम विकास के लिए जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वह जरूरी है।"

## विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव

2.3.6 समिति के समक्ष उपस्थित होते समय, एक विशेषज्ञ ने अधिनियम के नाम में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं:—

"अगला मुद्दा हिंदी में नाम के बारे में है। मुझे लगता है कि हमें हिंदी और अंग्रेजी में इस अधिनियम के नाम के साथ द्विभाषीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वास्तव में यह कानूनी स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करता है। इसलिए, 'संवर्धन' को अंत:स्थापित करना और इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जो वास्तव में विकास कार्य से संबंधित हो, स्पष्टत: इसका फोकस संरक्षण पर है और हमें किसी प्रकार संदिग्घता उत्पन्न करने के लिए कमजोर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि इसे हटा दिया जाए। यह भी बताया गया कि एक आम आदमी को संरक्षण और संवर्धन शब्द बोलना आसान नहीं लगेगा। भाषा की विविधता भी है। विधेयक के शीर्षक में ही एक भाषा होने पर संदेह है कि क्या यह इस स्तर पर उपयुक्त है।"

- 2.3.7 समिति के समक्ष उपस्थित एक विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो यह सुझाव दे कि विधायिका इस संशोधन द्वारा वन भूमि का कोई विस्तार करना चाहती है । परियोजनाओं के कारणों के बारे में कोई संदेह नहीं है जो वास्तविक उद्देश्य के लिए हो सकते हैं, लेकिन अंतिम वास्तविकता यह होगी कि वन भूमि कवर कम हो जाएगा।
- 2.3.8 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि संवर्धन का अर्थ बेहतर प्रबंधन पद्धितयों को अपनाकर, फ्रंट लाइन स्टाफ की क्षमताओं को सुदृढ़ करके, वन आधारित आजीविका के अवसर प्रदान करके लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके वृक्ष वारण के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के अलावा स्वास्थ्य, उत्पादकता और सेवाओं में वृद्धि करना है।
- 2.3.9 दिनांक 16 मई, 2023 को हुई बैठक के दौरान इस अधिनियम के नाम को हिंदी में परिवर्तित किए जाने के प्रश्न पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:—

"महोदय, यदि आप धारा 4 को देखें तो इसमें वन शब्द को स्पष्ट किया गया है और वास्तव में इसमें वनीकरण को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण, वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और इन माध्यमों से देश में अधिक वनाच्छादन को बढ़ावा दिया जा रहा जो अधिक कार्बन वृक्षादन में योगदान देगा। यह उनमें से एक उपाय भी है जो देश के लिए आवश्यक है ताकि देश अपने कार्बन उदासीनता लक्ष्य को पूरा कर सके।"

2.3.10 16 मई, 2023 को हुई बैठक के दौरान विधेयक के नाम में 'संवर्धन' शब्द को जोड़े जाने के प्रश्न पर वन महानिदेशक तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने भी निम्नवत् सुपष्टीकरण दिया है:—

"यह भ्रांति है कि सड़कों या नहरों के किनारे पेड़ लागाएंगे तो कालांतर में वन विभाग इसे डीम्ड फोरेस्ट के रूप में मानेगा और जब भी लैंड ट्रांसफर या डाइवर्जन का कोई प्रपोजल आएगा तो एफसी एक्ट के उपबंध लागू होंगे। एनटीपीसी, यूनिवर्सिटीज़, पीएसयूज़ आदि खाली पड़े क्षेत्रों में प्लांटेशन करते थे। लेकिन 1996 के आदेश के बाद सभी ने प्लांटेशन बंद कर दिया क्योंकि उनको लगा कि अगर प्लांट का फ्यूचर एक्सपेंशन करेंगे तो इस अधिनियम के अधीन परिमशन लेनी पड़ेगी जबिक नियम में ऐसा नहीं था। इस भ्रांति को दूर करने के लिए हम धारा लाए हैं, जैसा छत्तीसगढ़ की ओर से कहा गयाधारा 1(क) में कहा गया है कि ऐसे वृक्ष वनस्पतियां, पुनर्वनीकरण जो उक्त भूमि पर किया गया जो धारा 1 के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं है। इसके अलावा जितनी भी प्लांटेशन रेज़ करेंगे, चाहे इंस्टीट्यूशनल एरिया में करें या सड़कों पर करें तो उस पर एफसी एक्ट लागू नहीं होगा। इससे आम जनता में सही संदेश जाएगा। इसलिए हमने इसमें संवर्द्धन शब्द जोड़ा है।

2.3.11 17 मई, 2023 को हुई बैठक के दौरान विधेयक के नाम में 'संवर्धन' शब्द को जोड़े जाने के एक अन्य प्रश्न पर वन महानिदेशक तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने आगे निम्नवत् स्पष्टीकरण दिया है:—

"पहले मोनोकल्चर रहा है, लेकिन अब मिक्स्ड कल्चर हो रहा है। कल आपसे बात हुई थी। करदई वगैरह भी लगा रहे हैं, एरियाज़ को क्लोज कर रहे हैं, पोटेटो लगा रहे हैं, तो हम नैचुरली रीजेनरेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा है कि हमने संवर्द्धन क्यों किया है। पिरभाषा में स्पष्टीकरण आ गया है, तो लोग एग्रोफोरेस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। जहां तक कार्बन क्रेडिट की बात है, उसके लिए डिफरेंट एजेंसीज़ ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। पिश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन मंडलों में कार्बन क्रेडिट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उनको कैसे इन्सेंटिवाइज करना है, कैसे मॉनीटाइज करना है, हम उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रीन क्रेडिट नामक योजना शुरू की है। कार्बन क्रेडिट के साथ-साथ अगर कोई पाल्यूशन कंट्रोल कर रहा है, तो ग्रीन क्रेडिट में कितना होगा, हम अभी वह डिसाइड करे रहे हैं। ग्रीन क्रेडिट की भी योजना बहुत जल्द शुरू होगी। इसको कैसे इन्सेंटिवाइज करेंगे, कैसे किसानों को लाभ मिलेगा, आगामी वर्षों में हम लोग अवश्य करेंगे।"

### 2.3.12 जनता से प्राप्त कुछ टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :—

- अंग्रेजी अनुवाद प्रदान किए बिना, केवल हिंदी में अधिनियम का नाम बदलना, समावेश और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के संवैधानिक प्रयोजन के विरूद्ध होने का तर्क दिया जा सकता है।
- एक द्विभाषी दृष्टिकोण, जिसमें अधिनियम का नाम हिंदी और अंग्रेजी में उनके संबंधित संस्करणों में प्रदान किया गया है,
   विधिक स्पष्टता और एकरूपता को बढ़ावा देता है। हिंदी संस्करण हमेशा राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।
- अधिनियम के नाम में 'संवर्धन' का अंत:स्थापन मूल अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन के प्रावधानों के साथ असंगत प्रतीत होता है।
- प्रस्तावित विधेयक में वन संवर्धन के उद्देश्य को कार्यान्वित करने का कोई उपबंध नहीं है।
- अधिनियम का मौजूदा नाम जारी रहना चाहिए। चूंकि नाम में बदलाव से देश की सामाजिक संरचना कमजोर होगी।
- अधिनियम के नाम में बदलाव इस बात की अनदेखी करता है कि समुदाय के विशाल हिस्से हैं जो विशेष रूप से दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में अलग-अलग भाषा बोलते हैं। इसलिए इसे हटा दिया जाना चाहिए और मूल शीर्षक को बनाए रखा जाना चाहिए।
- यह संविधान के भाषाई संघीय सिद्धांत के खिलाफ है।

## 2.3.13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सुझाव

राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी
सिक्किम राज्य सरकार ने कहा कि संवर्धन को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। एक स्पष्ट परिभाषा शामिल की जानी चाहिए क्योंकि यह संशोधन में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।	उत्तर में, मंत्रालय ने कहा कि विधेयक में कोई परिभाषा खंड नहीं है और यदि भविष्य में किसी की आवश्यकता होती है तो केंद्र सरकार द्वारा विधेयक की धारा 6 के तहत स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।
मेघालय ने सुझाव दिया कि अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक/नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होना चाहिए। मिजोरम ने कहा कि एफसीए को बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह पूरे देश में अच्छी तरह से समझा जाता है और सभी हितधारक इस शब्द से परिचित हैं।	नीतियों और कार्यक्रमों में गतिशील परिवर्तन हमारे वन संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके अधिक कुशल प्रबंधन की मांग करते हैं। इसके अलावा, कार्बन तटस्थता, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) जैसी वैश्विक चुनौतियों को पूरा करने के लिए, हरित आवरण को बढ़ाना, पारिस्थितिकीय स्थिरता और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इसलिए, उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, अधिनियम को एक स्वत: स्पष्ट नाम देने का प्रस्ताव किया गया है।

#### समिति की टिप्पणी/सिफारिश

2.3.14 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर/स्पष्टीकरण सहित अधिनियम के नाम को बदलने के लिए खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और खंड के तहत प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

#### खंड 4

#### मूल अधिनियम के संगत उपबंध

2.4.1 लागू नहीं (अधिनियम में उपबंध मौजूद नहीं हैं)।

### संशोधन विधेयक में प्रस्तावित उपबंध

2.4.2 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 1 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

#### 1क : कतिपय भूमि को समाविष्ट करने के लिए अधिनियम

- (1) निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात्:—
  - (क) वह भूमि, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबंधों या राज्य या स्थानीय कानून के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है;

(ख) वह भूमि, जो खंड (क) के अधीन नहीं आती है, किन्तु 25 अक्तूबर 1980 को या उसके पश्चात किसी भी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज की गई है, परंतु इस खंड के उपबंध ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस संबंध में राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर, 1996 को या उससे पहले वन से गैर-वन प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है;

स्पष्टीकरण- (i) इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, 'सरकारी अभिलेख' पद से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग या वन विभाग अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी प्राधिकारी, स्थानीय निकाय, समुदाय या परिषद द्वारा धारित अभिलेख अभिप्रेत है।

- (2) निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट नहीं होंगी, अर्थात्:—
  - (क) रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के समीप अवस्थित ऐसी वन भूमि जो आवास या रेल या सड़क के किनारे सुख-सुविधाओं के लिए, जो प्रत्येक मामले में अधिकतम 0.10 हेक्टेयर माप तक पहुँच प्रदान करती है;
  - (ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष, वृक्षारोपण या वनरोपण उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं है; और
    - (ग) ऐसे वन भूमि, —
  - (i) जो राष्ट्रीय महता की सामरिक लिनीयर परियोजना और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने के प्रयोजन हेतु यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित है; या
  - (ii) जो सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक है; या
  - (iii) जो रक्षा संबंधी परियोजना या अर्धसैनिक बलों के लिए कैंप या लोकोपयोगी परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित है, जो वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पांच हेक्टेयर एकड़ से अधिक नहीं है।
- (3) उप-धारा (2) के अधीन उपबंधित छूट, ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत भूमि से पेड़ों की कटाई के प्रतिकर के लिए वृक्षारोपण की शर्त भी है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन रहते हुए होगी।

## 2.4.3 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण/स्पष्टीकरण

- अधिनियम के दायरे पर स्पष्टता के अभाव में, "प्रयोज्यता" धारा पुरःस्थापित करना आवश्यक हो गया। यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1996 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप भी है।
- अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकारी अभिलेख में स्पष्टता की आवश्यकता है और तदनुसार स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सड़क के किनारे की सुविधाओं, आवास और रेल तक पहुंच प्रदान करने के लिए छूट का प्रस्ताव किया गया है।
- राष्ट्रीय वन नीति में यथा परिकल्पित वनेतर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए स्पष्टता प्रदान की जा रही है।
- राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि महत्वपूर्ण सुरक्षा बुनियादी ढांचे विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी), नियंत्रण रेखा (एलओसी) जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ अधिसचित वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

#### समिति द्वारा जांच

2.4.4 विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान यह टिप्पणी की गई कि सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी संभव नहीं है क्योंकि पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में यह भूमि के बड़े हिस्से को समाविष्ट कर सकता है और राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होगी। उपर्युक्त के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

"अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर छूट प्रदान करने वाले प्रस्तावित उपबंध सामान्य छूट नहीं हैं अर्थात प्रस्तावित छूट केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा पता लगाई जाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है। इसके अलावा, उक्त व्यवस्था ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें प्रतिपूरक शुल्क का भुगतान और पेड़ों का मुआवजा शामिल है, जो राज्यों के लिए 100 किलोमीटर के भीतर ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी होगा। रक्षा परियोजनाओं के लिए पूर्व में दिए गए अनुमोदनों के विश्लेषण से पता चला है कि गत 8 वर्षों में अपवर्तन किए गए कुल 80,408 हेक्टेयर क्षेत्र में से केवल 2480 हेक्टेयर वन भूमि को रक्षा परियोजनाओं हेतु अपवर्तित किया गया है, जिसमें सड़कें भी शामिल हैं, जो कुल क्षेत्र का 3% है। यह नोट करना भी

महत्वपूर्ण है कि गत 8 वर्षों के दौरान देश के सीमावर्ती राज्यों में सड़क के लिए अपवर्तन किए गए 19305 हेक्टेयर के कुल वन क्षेत्र में से केवल 3.5% को रक्षा सड़क परियोजनाओं के लिए अपवर्तन किया गया है।"

2.4.5 इसके अतिरिक्त, ब्रीफिंग के दौरान, एक और टिप्पणी की गई कि वन क्षेत्रों में रह रहे लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जैसे कि वहा आज स्कूल और पानी की सुविधा नहीं है, वहां संवादहीनता की स्थिति है क्योंकि उनके पास दूरसंचार सुविधाओं की कमी है। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

"वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जन उपयोगी परियोजनाओं के निर्माण के लिए 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे से छूट दी गई है।"

2.4.6 17 मई, 2023 को हुई बैठक में जब यह भी पूछा गया कि क्या रेल लाइन अथवा सड़क के किनारे 0.10 हेक्टेयर भूमि की प्रस्तावित छूट की अनुमित बायी ओर अथवा दायी ओर दी जाएगी, वन महानिदेशक एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने निम्नवत स्पष्टीकरण दिया:—

"महोदय, इसके बाद आपने कहा था कि 0.1 हैक्टेयर की अवधारणा है। वह थोड़ी अस्पष्ट है। 0.1 की जो अवधारणा है, हमने उसको अधिकतम कहा है कि 0.1 हैक्टेयर तक के इस तरह के मामले में हम एफसीए अधिनियम के उपबंधों को लागू नहीं करेंगे। जहां तक बायी ओर अथवा दायी ओर का संबंध है, चाहे यह बायी ओर है या दायी ओर है, अगर सड़क संपर्कता दायी ओर से है तो छूट बायी ओर मिलेगी। इन दोनों का संचयी नहीं है। दोनों अलग है। विशेष रूप से उदाहरण के लिए यदि प्रसंग 10.1 हेक्टयर तक है तो इस संशोधन के पश्चात् इस पर एफसीए अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

2.4.7 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में उक्त संशोधन को इस प्रकार स्पष्ट किया है:

"केंद्रीय सरकार द्वारा मंत्रालयों, राज्यों और जनता के साथ परामर्श करने के बाद इस विधेयक में प्रस्तावित छूट (वन भूमि का 0.10 हेक्टेयर) के विनिश्चय को समुचित माना गया है।

धारा 1क (2)(क) के तहत विचार की गई 0.10 हेक्टेयर वन भूमि की छूट, सड़क किनारे की बसावटों और संस्थानों को संपर्क-मार्ग प्रदान करेगी ताकि विकास की मुख्यधारा के साथ उनका संपर्क सुनिश्चित किया जा सके।

विधेयक की धारा 1क(3) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सुविधाओं, रणनीतिक सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं आदि को परिभाषित करने सहित निबंधन और शर्तें बाद में पूरी की जाएंगी।

"इस संबंध में यदि भविष्य में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हुई, तो विधेयक की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों को लागू करके केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।"

- 2.4.8 17 मई, 2023 को हुई समिति की बैठक के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा गौडा बर्मन मामले का भी संदर्भ दिया गया जिसमें यह टिप्पणी की गयी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी.एन. गौडा बर्मन मामले में कहा है कि जो भी भूमि सरकारी दस्तावेज में वन के रूप में दर्ज की गई है, उसके लिए वन स्वीकृति की जरूरत होगी लेकिन प्रस्तावित संशोधन विधेयक में केवल उस भूमि को वन माना गया है, जो 25 अक्तूबर, 1980 को या उसके बाद दर्ज की गई हो। इस विधेयक में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए।
- 2.4.9 उपरोक्त टिप्पणी के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समिति को दिए अपने लिखित उत्तर में बताया है:

"विधेयक के वाक्यांश*'.... 25.10.1980 को वन के रूप में दर्ज...'* से यह तात्पर्य है कि ऐसी सभी भूमि जो 25.10.1980 से पहले भी वन के रूप में दर्ज की गई हैं, उन्हें भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल किया जाएगा।

धारा 1 क में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान भारतीय वन अधिनियम, स्थानीय अधिनियम या कानूनों के तहत अधिसूचित भूमि और राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि पर लागू होंगे। इसके अलावा, किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्रकार की वन भूमि को शामिल करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड को भी परिभाषित किया गया है।

विधेयक की धारा 1क के तहत परिभाषित सरकारी रिकॉर्ड का तात्पर्य है कि अधिनियम की अनुप्रयोज्यता का दायरा उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुरूप है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहलेना नहीं हुई है। विधेयक की प्रस्तावित धारा 1क(1) के तहत प्रदान की गई व्याख्या स्पष्ट करती है कि सरकार, वन विभाग स्थानीय निकायों, या प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज अवर्गीकृत वनों सहित सभी वनों पर भी इस अधिनियम के प्रावधान लागृ होंगे। इसके अलावा, अधिनियम की अनुप्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो, धारा 6 के तहत प्रदान किए गए समर्थकारी प्रावधानों को, जब भी आवश्यक हो, लागू किया जाएगा।"

- 2.4.10 इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इस संबंध में सिमिति को निम्नलिखित बताया:—
  "वर्ष 1996 में टीएन गोडा वरमन का जो मानित वन मामला है, उसका कहीं न कहीं उल्लंघन होगा। टीएन गौडा बर्मन केस में जो उल्लंघन की बात है, ऐसा उसमें कहीं नहीं है। उस केस से जो भ्रांतियां आज की तारीख में उत्पन्न हैं कि उन्होंने कहा था कि सभी प्रदेश बैठ कर एक परिभाषा बना कर अपने-अपने मानित वन क्षेत्र को स्पष्ट कर दें। लेकिन कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने नहीं किया तो उससे भ्रांति यह बनी रही कि अगर कोई भी कहीं ग्रीन पैच होगा और कहीं भी कोई प्राईवेट आदमी फॉरेस्ट लगा लेगा तो उस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू हो जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने कृषि वानिकी को ही छोड़ दिया है। अब चूंकि यह भ्रांतियां दूर हो जाएंगी तो कृषि वानिकी का कॉन्सेप्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा और लोग उस ओर आकृष्ट होंगे और हमारा जो वन से बाहर जो वृक्ष क्षेत्र है, वह बढ़ेगा।"
- 2.4.11 16 मई, 2023 को हुई बैठक के दौरान यह भी देखा गया है कि चूंकि अनेक अवर्गीकृत भूमि को विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में मानित वन के रूप में वर्गीकृत किया गया जिससे वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विकास परियोजना रुक गई है।
- 2.4.12 इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

"विधेयक में प्रस्तावित अधिनियम की अनुप्रयोज्यता माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुरूप है। विधेयक की धारा 1क के तहत परिभाषित सरकारी रिकॉर्ड का तात्पर्य है कि इस अधिनियम की अनुप्रयोज्यता का दायरा उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुरूप है। इसके अलावा, राज्य की विशेषज्ञ समिति द्वारा पता लगाई गई मानित वन भूमि को रिकॉर्ड में लिया गया है और इसलिए अधिनियम का प्रावधान ऐसी भूमि पर भी लागू होगा।"

- 2.4.13 सिमिति द्वारा जांच के दौरान यह टिप्पणी की गई कि वन का प्रशासन संघी सूची का विषय है। यह केंद्रीय विषय नहीं है। इसलिए इस विधेयक में जहां भी ऐसा कहा गया है कि, केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे या निर्णय ले, उसे संशोधित किया जाए।
- 2.4.14 यह भी टिप्पणी की गई कि इस विधेयक की सभी धाराएं केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। राज्य पुलिस वलों की सुरक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर, भूमि की उपलब्धता के संबंध में उपबंध करना राज्य सरकार के दायरे में आना चाहिए क्योंकि मूल योजनाओं के मूर्तरूप नहीं दिए जा सकने पर वह भूमि संबंधी समझौते और वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था में स्थानीय और जनजातीय लोगों के साथ जुड़ी होती है।
- 2.4.15 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:—

"विधेयक की धारा 1क (3) के तहत छूट पर विचार करते समय निबंधन और शर्तें निर्धारित करने हेतु समर्थकारी प्रावधान किए गए है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के तहत विचार की गई छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए। प्रभाव आकलन, न्यूनीकरण उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को जहां कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकार के परामर्श से संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छूटों पर विचार करते समय, ऐसे सुरक्षा उपायों को हमेशा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी दिशा-निर्देश जारी करने से पहले मंत्रालय द्वारा सामान्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राय ली जाती हैं। मौजूदा मामले में भी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा।"

2.4.16 इसके अतिरिक्त, विधेयक की खंडवार जांच के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और विधेयक में किए गए प्रावधानों के संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देते हुए निम्नवत् बताया—

"महोदय, जहां भी अधिनियम लागू होता है मूल रूप से, यह खंड वन के दायरे से संबंधित है और यह माननीय उच्चतम न्यायालय के 12-12-1996 के निर्णय से उत्पन्न होता है। मैं निर्णय की विषय-वस्तु पढ़ना चाहता है। निर्णय में कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को वनों की कटाई को रोकने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिक असंतुलन होता है और इसलिए वन के संरक्षण और उससे संबंधित मामलों के लिए इसमें किए गए प्रावधान सभी वनों पर लागू होते हैं, भले ही उनके स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति कुछ भी हो। 'वन' शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। यही निर्णय था। इसमें आगे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो (i) उन क्षेत्रों की पहचान करे जो वन हैं, भले ही वे किसी भी कानून के तहत अधिसूचित, मान्यता प्राप्त या वर्गीकृत हों, और ऐसे वन की भूमि के स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना; (ii) उन क्षेत्रों की पहचान करना जो पहले वन थे लेकिन अवक्रमित, उजड़े हुए या साफ हो गए हैं; (iii) सरकार से संबंधित वृक्षारोपण

और निजी व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्रों की पहचान करना। अत. यही निर्णय था। इससे पहले. इस अधिनियम में वन के दायरे में कछ नहीं कहा गया था। इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है कि 12-12-1996 के इस निर्णय के बाद यह अधिनियम कहां लागू होना चाहिए। अत, न केवल आम जनता द्वारा बल्कि वन अधिकारियों द्वारा भी एक सामान्य वक्तव्य दिया गया था कि यह उन क्षेत्रों पर लागु होता है जो वन दिखते हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में नहीं है। अतः, यह स्पष्ट करने के लिए कि यह अधिनियम कहां लागू होगा और निर्णय की भावना के अनुसार, हमने उल्लेख किया है कि यह उस भूमि पर लागू होगा जिसे भारतीय वन अधिनियम या इस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है। उदाहरण के लिए, पीएलपीए जो पंजाब और हरियाणा के लिए प्रासंगिक है, भूमि खंड क के अंतर्गत शामिल नहीं है लेकिन 25 अक्तूबर, 1980 को या उसके बाद वन के रूप में सरकारी रिकार्ड में दर्ज की गई है। हमने कहा है कि इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, 'सरकारी रिकॉर्ड' शब्द का अर्थ राजस्व विभाग या वन विभाग द्वारा रखे गए रिकॉर्ड से है। कई राज्यों में, वन रिकॉर्ड को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए, हमने यहां कहा है कि अभिलेख या तो राज्य सरकार के वन विभाग या राजस्व विभाग, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समदाय या परिषद के पास हैं। जैसा कि मैडम संगमा ने मेघालय के वन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेघालय में 90 प्रतिशत वन इस समुदाय के स्वामित्व में हैं और ये सभी अभिलेख हैं। संशोधन के बाद यह अधिनियम उन भूमि पर भी लागू होगा। यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू होगा। इस भाग को स्पष्ट करने के लिए, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने मानित वन होने की बात कही है, अभी भी एक भ्रम है कि यह महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल एक महीने की समय-सीमा दी है। मैं इस बात से सहमत हुं कि इसे एक महीने के भीतर कवर नहीं किया गया था और इसमें लगभग एक वर्ष लग गया और लगभग सभी राज्यों ने इस संबंध में अपने हलफनामे दायर किए हैं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिनकी पहचान वन के रूप में की गई है, वन क्षेत्र की तरह दिखते हैं और अवक्रमित वन हैं, जो कभी वन थे और अब वे अवक्रमित हो गए हैं आदि। इस निर्णय के बाद गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। ये भी रिकॉर्ड में हैं। इन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी दायर किया गया है। इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। आगे स्पष्ट करने के लिए, हमारे पास पहली बार प्रावधान हैं। हम दिशानिर्देशों के प्रावधान ला रहे हैं। माननीय समिति की भावनाओं के अनुरूप गलती होना मानवीय है। हमसे जरूर कोई गलती हुई होगी. मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सही रहा है। यदि हमसे कुछ छुट रहा है तो मैं आपको आश्वस्त करता हुं कि हम दिशानिर्देशों में इसका ध्यान रखेंगे। "

2.4.17 निम्नलिखित विवरण सदस्यों द्वारा की गई लिखित टिप्पणियों/सुझावों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर को दर्शाता है:—

## सदस्य के सुझाव/टिप्पणियाँ

इस विधेयक की प्रमुख चिंता यह है कि 2023 का संशोधन संभवतः उच्चतम न्यायालय के 1996 के ऐतिहासिक गोडावर्मन फैसले को कमजोर कर देगा, जिसने एफसीए के दायरे को सरकार द्वारा वन के रूप में दर्ज किसी भी भूमि पर लागू करने के लिए बढ़ा दिया था, भले ही उसका स्वामित्व कुछ भी हो; हालांकि मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन उच्चतम न्यायालय के आदेश को अस्वीकार नहीं करेगा।

यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो अरावली का बड़ा हिस्सा, तराई और मध्य भारत के बाघों के आवास, पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्व के जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट, अब 'वन' नहीं माना जा सकता हैं और संभवतः इसे संभावित रूप से बिना किसी नियामक निरीक्षण के बेचा, डायवर्ट, साफ़, क्राय, उपयोग, दोहन किया जा सकता है।

नया विधेयक उस भूमि के लिए अस्पष्टता पैदा करेगा जो पहले राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं है क्योंकि राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों के रिकॉर्ड में वन

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तर

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को कमजोर नहीं किया गया है। विधेयक की प्रस्तावित धारा 1 क (1) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि सरकार, वन विभाग, स्थानीय निकायों या प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज अवर्गीकृत वनों सहित सभी वनों पर भी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इसके अलावा, अधिनियम की अनुप्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो, जब भी जरूरत होगी, धारा 6 के तहत प्रदान किए गए समर्थकारी प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

विधेयक की धारा 1क(1) के तहत किया गया स्पष्टीकरण सरकारी रिकॉर्ड के दायरे को न केवल राजस्व विभाग और वन विभाग के रिकॉर्ड तक सीमित करता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण या यहां तक कि स्थानीय निकाय को भी सम्मिलित करता है।इसके अतिरिक्त, दिनांक 12-12-1996 के आदेश के अनुसरण में विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित और माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित किए गए वन जैसे क्षेत्रों को भी रिकार्ड में लिया गया है।

धारा 1क(1) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि राजस्व विभाग या वन विभाग द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होंगे।

भूमि हो सकती है। प्रस्तावित विधेयक यह स्पष्ट करने में विफल रहता है कि ऐसे मामलों में अस्पष्टता से कैसे निपटा जाएगा और इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि वर्ष 1996 से पहले बिना किसी औपचारिक कागजी कार्रवाई के वन घोषित की गई भूमि पर प्रबंधन और नियंत्रण अधिकारों को तय करने के लिए स्पष्टता लाई जाए।

राजस्व विभाग अपने अभिलेखों में वन भूमि की स्थिति को अद्यतन करें और स्पष्ट रूप से उन्हें वन भूमि के रूप में चिन्हित करें। इससे इन क्षेत्रों के भीतर पट्टे या अन्य कोई अधिकार जारी करने पर रोक लगेगी और राजस्व विभाग की प्रतिबंधात्मक आदेश पुस्तिका में वन भूमि को शामिल करने से उनकी संरक्षित स्थिति और सुदृढ़ होगी।

विधेयक में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि वन ब्लॉकों की लंबित अधिसूचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एक निश्चित अविध के भीतर तुरंत हल किया जाना चाहिए क्योंकि कई वन भूमि भूमि की अस्पष्ट श्रेणियों के अंतर्गत रहती है, जिससे अतिक्रमण की संभावना होती है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि विधेयक में आरओएफआर (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2008 के तहत सौंपी गई भूमि का सीमांकन करने का भी प्रावधान है ताकि आदिवासियों द्वारा अतिक्रमण को रोका जा सके, जो अक्सर पेड़ों की कटाई करके अपने मूल पट्टा स्थल से अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वन बिनाश और आगे अतिक्रमण होता है।

विधेयक में वन भूमि के अनिवार्य सीमांकन के लिए एक मजबूत तंत्र की व्यवस्था भी की जाए। सीमा स्तंभों का निर्माण या खाई खोदने से स्पष्ट भौतिक सीमांकन मिल सकता है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भ्रम और अतिक्रमण के प्रयासों को कम किया जा सकता है। वन भूमि की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, एकल वन रक्षक को सौंपे गए क्षेत्राधिकार क्षेत्र को भी कम करने का प्रावधान किया जाए।

'<u>4झ क</u>(1)(ख) में 'सरकारी रिकॉर्ड' के स्थान पर 'सरकारी भूमि रिकॉर्ड' अन्तःस्थापित किया जाए।

उपखंड (1) (क) और (ख) के बाद धारा 1क में एक अतिरिक्त प्रावधान यह है कि आरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर मौजूद बस्तियों वाले क्षेत्रों को बाहर रखा जाए. भले ही ऐसे आरक्षित वन

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तर

केंद्र सरकार को निदेश जारी करने का अधिकार देने वाले विधेयक की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए समर्थकारी प्रावधानों को भविष्य में इस तरह के स्पष्टीकरण जारी करने के लिए जब भी जरूरत होगी, लागू किया जाएगा।

धारा 1 क (1) (क) के प्रावधानों में प्रावधान है कि भारतीय वन अधिनियम या स्थानीय अधिनियम के तहत अधिसूचित भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे में आएगी। इसलिए, जिस भूमि को अधिसूचित करने का इरादा किया गया है, जैसे कि धारा 4 आईएफए के तहत भूमि या किसी स्थानीय अधिनियम के तहत इसी तरह की भूमि, पर भी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

केंद्र सरकार को निदेश जारी करने का अधिकार देने वाले विधेयक की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए समर्थकारी प्रावधानों को भविष्य में इस तरह के स्पष्टीकरण जारी करने के लिए जब भी जरूरत होगी, लागू किया जाएगा।

इस संबंध में दिशानिर्देश/अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। केंद्र सरकार को निदेश जारी करने का अधिकार देने वाले विधेयक की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए समर्थकारी प्रावधानों को भविष्य में इस तरह के स्पष्टीकरण जारी करने के लिए जब भी जरूरत होगी, लागू किया जाएगा।

सरकारी रिकॉर्ड को माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुरूप परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुप्रयोज्यता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अधिनियम में परिभाषित सरकारी रिकॉर्ड सरकारी और गैर-सरकारी भूमि से संबंधित है।

ऐसे क्षेत्रों को आम तौर पर निपटान अधिकारी द्वारा अधिकारों के निपटान सहित उचित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 या स्थानीय वन अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाता है। धारा 1क के खंड (ख) में जोड़े गए परंतुक में ऐसी राजस्व वन भूमियों को छट प्रदान करने का प्रावधान है, जिन्हें

और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख कुछ भी हो।"

"0.1 हेक्टेयर" के स्थान पर 1 हेक्टेयर" अन्तःस्थापित किया जाए।[पैरा 4झ क (2)(क)].

एफसीए के दायरे से निजी वनों की श्रेणी को छूट देने से भूस्वामियों और किसानों को लाभ हो सकता है और उन्हें अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, हालांकि यह उनकी भूमि को विकास प्रक्रियाओं के लिए लेने से रोकेगा या वास्तव में इसकी सुविधा प्रदान करेगा। इस का जलवायु परिवर्तन शमन संबंधी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और दायित्वों पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

"एक सौ किलोमीटर" के स्थान पर" एक सौ पचास किलोमीटर" अन्तःस्थापित किया जाए [पैरा 4 झ क (2)(ग)(झ)].

भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भारी निर्माण हमारे वन्य जीवन को खतरे में डाल सकता है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर के वनों को अब राजमार्गों, जल विद्युत परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए किसी वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह बहुत समस्याग्रस्त है।

भारत की 15,100 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा में समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं - घास के मैदान, रेगिस्तान, आर्द्रभूमि, तराई के जंगल, सदाबहार वर्षावन - जो ज्यादातर अपनी दूरस्थता के कारण अछूते हैं। यह हमारे देश के लिए एक प्राकृतिक रक्षा कवच है। किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। पशु-पक्षियों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती। सीमाओं के पार इसकी मृक्त आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तर

25-10-1980 से पूर्व की अवधि के मामलों सिंहत 12-12-1996 से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा गैर-वानिकी उपयोग के लिए रखा गया है। यह आईएफए या स्थानीय अधिनियमों/कानूनों के तहत अधिसूचित भूमि के संबंध में लागू नहीं है।

विधेयक के प्रावधान मुख्य रूप से विभिन्न भूमि में अधिनियम की अनुप्रयोज्यता को स्पष्ट करते हैं और यह कानूनी स्थिति को बदलने या स्थानीय अधिनियम के आईएफए के तहत अधिसूचित किसी भी वन भूमि को डी-रिजर्व करने का प्रावधान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13-11-2000 के आदेश में वनों और राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों के डी-रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है।

0.10 हेक्टेयर की छूट सड़क/रेल किनारे की बस्तियों और प्रतिष्ठानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जैसा कि गहन परामर्श के बाद निर्णय लिया गया, प्रस्तावित व्यवस्था को इष्टतम माना गया है।

प्रस्तावित विधेयक की धारा 4(2)(ख) के प्रावधान निजी भूमि में वनीकरण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे लोगों की भागीदारी के माध्यम से देश के हरित आवरण को बढ़ाने और कार्बन तटस्थता, कार्बन सिंक बढ़ाने, बेहतर वन प्रबंधन आदि जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने में सहायता मिलेगी। गैर-वन भूमि में वनीकरण को बढ़ावा देने से वनों पर दबाव कम होने के साथ-साथ अतिरिक्त कार्बन सिंक भी बनेगा।

एलएसी और एलओसी सहित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 100 किमी की दूरी के भीतर स्थित रैखिक परियोजनाओं की छूट कोई व्यापक छूट नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के परामर्श से इसका प्रस्ताव किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर प्रस्तावित छूट सामान्य छूट नहीं है अर्थात प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की विशिष्ट रैखिक परियोजनाओं के लिए है जिनकी पहचान केंद्र सरकार द्वारा की जानी है। उक्त छूट निजी संस्थाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। 100 किमी की दूरी अधिकतम स्वीकार्य दूरी है। छूट का उपयोग आवश्यकता आधारित होगा यानी 5 किमी या 10 किमी के भीतर उपयोग किया जा सकता है।

विधेयक की धारा 1ए (3) के तहत प्रदत्त शक्ति छूट पर विचार करते समय निबंधन और शर्तें निर्धारित करने के बारे में है। केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के तहत विचार की गई छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए। प्रभाव आकलन, न्यूनीकरण उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरिक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां भी आवश्यक हो, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छुटों पर विचार करते समय,

जाना चाहिए। वन्यजीवों पर प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। यह गलत धारणा है कि वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (पीए) तक ही सीमित हैं। भारत के एक तिहाई से अधिक बाघ, 70% हाथी और भेड़िया, बस्टर्ड, तेंदुए की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पीए के बाहर के क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह के भूकंपीय और भूगर्भीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण न केवल दुर्लभ वन्यजीवों और देश की जल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इन क्षेत्रों को भूकंप और भूस्खलन के लिए भी संवेदनशील बनाता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पहले से ही संरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों जिसमें बाघ रिजर्व, राष्टीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व के साथ-साथ वन्यजीव गलियारों जैसे अन्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों द्वारा स्व-घोषित सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं. अनसचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी विपथन से सख्ती से संरक्षित किया गया हैं। स्थानीय लोगों या पर्यावरण की सुरक्षा के बिना किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए इन क्षेत्रों का अंधाधुंध उपयोग और वनों की कटाई का वास्तविक डर है। रैखिक परियोजनाएँ पहले से ही जैव विविधता और वन्यजीव आंदोलनों के लिए सबसे हानिकारक साबित हुई हैं।

इस तरह की छूट से वन संसाधनों का अनियंत्रित दोहन और पारिस्थितिक क्षति हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी परियोजनाओं से होने वाले पारिस्थितिक नुकसान को रोकने के लिए प्रस्तावित विधेयक में एक खंड शामिल किया जाए।

इस खंड के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि कोई भी रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजना जो पूर्व अनुमोदन से छूट चाहती है, उसे परियोजना के संभावित पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) से गुजरना होगा। इस ईआईए को प्रभावित होने वाली वन भूमि की सीमा, वन्यजीव आवासों पर प्रभाव और मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण की संभावना जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तर

ऐसे रक्षोपायों को हमेशा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले निबंधन और शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उक्त व्यवस्था ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें प्रतिपूर्ति शुल्क और पेड़ों के मुआवजे का भुगतान, वन्यजीव प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, आवश्यकता के अनुसार मृदा और नमी संरक्षण योजना शामिल है, जो राज्यों के लिए छूट के तहत ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी होगी। इस विधेयक के प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

विधेयक के प्रावधान वन अधिकार अधिनियम, 2006, पीईएसए या एलएआरआर अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन या निरसन नहीं करते हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अजा और ओटीएफडी की सहमति सहित इन कानूनों में परिकल्पित प्रक्रियाओं को प्रस्तावित संशोधन द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया है।

इसके अलावा, नियम 9(6) (ख) (ii) के तहत दिए गए प्रावधान यह कहते हैं कि उपयोगकर्ता एजेंसी को भूमि सौंपने से पहले राज्य द्वारा एफआरए, 2006 का अनुपालन पूरा किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर प्रस्तावित छूट सामान्य छूट नहीं है अर्थात प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की विशिष्ट रैखिक परियोजनाओं के लिए है जिनकी पहचान केंद्र सरकार द्वारा की जानी है। उक्त छूट निजी संस्थाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। 100 किमी की दूरी अधिकतम स्वीकार्य दूरी है। छूट का उपयोग आवश्यकता आधारित होगा यानी 5 किमी या 10 किमी के भीतर उपयोग किया जा सकता है।

विधेयक की धारा 1क (3) के तहत प्रदत्त शक्ति छूट पर विचार करते समय निबंधन और शर्तें निर्धारित करने के बारे में है। केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के तहत विचार की गई छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए। प्रभाव आकलन, न्यूनीकरण उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरिक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां भी आवश्यक हो, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छूटों पर विचार करते समय, ऐसे रक्षोपायों को हमेशा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उक्त व्यवस्था ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें प्रतिपूर्ति शुल्क और पेड़ों के मुआवजे का भुगतान, आवश्यकता के अनुसार वन्यजीव प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, मिट्टी और नमी संरक्षण योजना शामिल

प्रस्तावित विधेयक वनों में रहने वाले समुदायों को बेदखल कर सकता है और उनकी पारंपरिक आजीविका को खतरे में डाल सकता है, खासकर वन क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा-संबंधी परियोजनाओं की तेजी से निगरानी के साथ प्रस्तावित विधेयक में वन वासी समुदायों के अधिकारों और उनकी पारंपरिक आजीविका की रक्षा के लिए एक प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रावधान के लिए आवश्यक हो सकता है कि वन क्षेत्र में स्थित राष्टीय महत्व की कोई भी रणनीतिक या सुरक्षा-संबंधी परियोजना एक व्यापक सामाजिक प्रभाव मृल्यांकन (एसआईए) से गुजरे, जो वन में रहने वाले समुदायों पर परियोजना के संभावित प्रभाव पर विचार करती है, इसके अलावा, प्रावधान के लिए आवश्यक हो सकता है कि कोई भी परियोजना जो वन में रहने वाले समुदायों और उनकी पारंपरिक आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, उसे पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के अधीन होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित समुदायों को आजीविका के किसी भी नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, और आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान किए जाएं। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना प्रभावित समदायों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए और किसी भी परियोजना गतिविधियों के शुरू होने से पहले लागू की जानी चाहिए।

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तर

है, जो राज्यों के लिए छूट के तहत ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी होगा। इस विधेयक के प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन या बेदखली, यदि कोई शामिल हो, राज्य की प्रासंगिक आर एंड आर नीति के प्रावधानों के अनुसार और वन अधिकार अधिनियम, 2006, पीईएसए अधिनियम, 1996 और एलएआरआर अधिनियम, 2013 या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या नियमों के तहत दिए गए प्रावधानों का पालन करते हुए किया जाएगा।

विधेयक का कोई भी प्रावधान एफआरए, पीईएसए या एलएआरआर अधिनियमों के किसी भी प्रावधान में बाधा नहीं डालता है। इसके अलावा, नियम 9 (6) (ख) (ii) के तहत दिए गए प्रावधानों यह कहते है कि उपयोगकर्ता एजेंसी को भूमि सौंपने से पहले राज्य द्वारा एफआरए, 2006 का अनुपालन पूरा किया जाए।

पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के प्रावधानों, जहां भी लागू हो, एजेंसी द्वारा पालन किया जाएगा। विधेयक की धारा 1 क (3) के तहत प्रदत्त शक्ति छूट पर विचार करते समय निबंधन और शर्तें निर्धारित करने बारे में है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के तहत विचार की गई छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए। प्रभाव आकलन, न्यूनीकरण उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां कहीं आवश्यक हो, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छूटों पर विचार करते समय, ऐसे रक्षोपायों को हमेशा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले निबंधन और शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए।

# विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव

## <u>जनजातीय कार्य</u> मंत्रालय

2.4.18 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस प्रस्तावित संशोधन के संबंध में समिति को दी अपनी प्रस्तुति में निम्नवत् बताया है:—

"एफआरए की धारा 2 (घ) के अनुसार 'वन भूमि' से "िकसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है। एफआरए के तहत वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) के गारंटीकृत अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कृपया यह उल्लेख करते हुए व्यावृत्ति खंड अन्तःस्थापित करने पर विचार करे कि "वन भूमि" की उक्त परिभाषा एफआरए, 2006 की अवहेलना नहीं करेगी।"

- 2.4.19 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कृपया एक व्यावृत्ति खंड अन्तःस्थापित करें कि "जिस भूमि पर वन अधिकारों को मान्यता दी गई है या एफआरए के तहत मान्यता की प्रक्रिया में है, उसे वन भूमि के रूप में माना जाएगा।
- 2.4.20 17 मई, 2023 को हुई बैठक के दौरान वन महानिदेशक एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने निम्नवत् स्पष्टीकरण दिया:—

"महोदय, आप एफआरए के बारे में बात कर रहे थें, अभी हम सभी क्षेत्रों में एफआरए को ले रहे हैं, 100 किलोमीटर (अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ छूट) के क्षेत्र में हम लोग एफआरए को तो रखेंगे ही। इस अधिनियम में हम उसको छूट नहीं दे रहे हैं। एफआरए अधिनियम तो उसमें भी लागू रहेगा। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए लागू होता है। यह हमारी विकास परियोजनाओं पर भी लागू होता है।"

#### ग्रामीण विकास मंत्रालय

- 2.4.21 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि धारा 1(क) की प्रस्तावित उपधारा (2) में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए सम्चित संशोधन किया जाए:—
- "क. पीएमजीएसवाई के तहत बस्तियों/ग्रामीण बुनियादी ढांचे (सड़कों और पुलों) के उन्नयन के लिए नई कनेक्टिविटी।
- ख. सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण/उन्नयन और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित या सुरक्षा या सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाने वाले अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करना।"
- 2.4.22 उपर्युक्त सुझाव के संबंध में, वन महानिदेशक एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने दिनांक 17 मई, 2023 को हुई समिति की बैठक में समिति के समक्ष निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:—

"जहां तक कनेक्टिविटी का संबंध है, पीएमजीएसवाई की सड़कों के संबंध में हमने सड़क के किनारे सुख-सुविधाओं और जन सुविधाओं के लिए प्रावधान किया है और इस संबंध में 0.1 हेक्टेयर भूमि के बारे में संशोधन का प्रस्ताव किया है। पीएमजीएसवाई की अधिकांश सड़कें आंतरिक क्षेत्रों में बनाई जाती है और हमारे प्रतिबंधित क्षेत्र इन सड़कों के निकट हैं। अत: उनकी कनेक्टिविटी रूक जाती है। हमने 0.1 हेक्टेयर की जो छूट दी है उससे 70-80 प्रतिशत मामले निपटाए जाएंगे। मामला निपटाया जाएगा क्योंकि जहां कहीं सुविधा है, हम इसे मार्ग निर्देशों के माध्यम से प्रदान करेंगे। हमने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी यह छूट प्रदान की है। यदि कोई और आवश्यकता है तो हम इसे अलग से देखेंगे।"

#### जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग

2.4.23 जल शक्ति मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि धारा (2) उपधारा (ग)(i) के प्रस्तावित पैरा 4 को निम्नलिखित को शामिल करने के लिए उपयुक्त तरीके से संशोधित किया जाए:—

"एलओसी, एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी तक प्रस्तावित रणनीतिक परियोजनाओं हेतु छूट के अनुसरण में ऐसी परियोजनाओं (वाइब्रेंट विलेज़ कार्यक्रम के मद्देनजर) हेतु जलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित कार्यों की अनुमति भी वन संबंधी स्वीकृति के बिना दी जाए।"

2.4.24 उपर्युक्त सुझाव के संबंध में वन महानिदेशक एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने दिनांक 17 मई, 2023 को हुई समिति की बैठक में समिति के समक्ष निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:—

"पेयजल पाइपलाइन के मुद्दे के संबंध मे यह पूछा गया है कि यदि कोई रणनीतिक सड़क हो तो पेयजल की व्यवस्था का क्या होगा। सभी आरओडब्ल्यू जो राज मार्गों के अंतर्गत आएंगे उन पर पेयजल पाइप लाइन बिछाई जा सकती है। विद्वमान दिशानिर्देशों में भी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि पहले से ही कोई सड़क वन से गुज़र रही है, और यदि मंत्रालय पाइपलाइन बिछाने के लिए आरओडब्ल्यू का उपयोग करना चाहती है तो शुरुआत में इसका दायरा एक-एक मीटर था और अब इसका दायरा बढ़ा कर दो-दो मीटर कर दिया गया है क्योंकि पाइप का आकार इसमें प्रवाहित किए जाने वाले जल की मात्रा को ध्यान में रखकर बढ़ा दिया जाता है।"

## 2.4.25 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

- (i) **1क (2) में** : उपखंड (घ) का संयोजन कृपया निम्नानुसार समझा जाए: (घ) पहले से ही विपथित वन भूमि से आगे ड्रिलिंग गतिविधियां शुरू करना, जिसके लिए ड्रिलिंग गतिविधि के लिए वन स्वीकृति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।
- (ii) वन क्षेत्र के बाहर तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं में विस्तारित रीच ड्रिलिंग (ईआरडी) प्रौद्योगिकी पर एफसी अधिनियम के लागू न होने के संबंध में एफसी विधेयक, 2023 में खंड को शामिल करने की आवश्यकता।

#### राज्य सरकारें

#### छत्तीसगढ़ सरकार

2.4.26 छत्तीसगढ़ सरकार ने समिति को दी गई अपनी प्रस्तुति में कहा है कि सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के प्रकार और उपयोग एजेंसियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया है कि प्राइवेट लोगों और अन्य कंपनियों द्वारा वन भूमि के उपयोग के लिए बच कर भागने के रास्तों को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। अतः निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है:—

### 1क(2)(ग)(iii)

"(iii) जैसा कि रक्षा संबंधी परियोजना या अर्धसैनिक बलों/राज्य पुलिस के लिए कैंप या जन सुविधा परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में यह *छह हेक्टेयर* से अधिक नहीं है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।"

स्पष्टीकरण:— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "जन सुविधा परियोजनाओं" में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगी:—

- (क) मोबाइल टावर
- (ख) ओएफसी केबल
- (ग) अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के कैंपों को जोड़ने वाली सड़क और बलों के लिए हेलीपैड
- (घ) अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय छात्रावास और आश्रम
- (ड) एकलव्य विद्यालय की स्थापना (जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना)
- (च) ऐसे क्षेत्र जहां वन भूमि में प्रति एकड़ 50 से कम पेड़ हों या जो पहाड़ियों और चट्टानों के रूप में प्राकृतिक रूप से रिक्त हों वहाँ 5 किमी तक सौर संयंत्र।

#### महाराष्ट्र सरकार

2.4.27 महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित करने का सुझाव दिया है:—

"बशर्ते कि इस खंड में वर्गीकृत भूमि उन मामलों में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंध को आकर्षित नहीं करेगी जहां (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 के अंतर्गत आरक्षण-हटाने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 से पहले भूमि का गैर-वानिकी उपयोग किया गया है। (ख) निजी स्वामित्व वाली भूमि जिन्हें महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के तहत आरक्षित वन माना जाता है और वर्ष 1978 में संशोधित उसी अधिनियम की धारा 22-क के तहत आजीविका के उद्देश्यों के लिए भूमि मालिकों को लौटा दी गयी है।"

2.4.28 इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"विधेयक में प्रस्तावित अधिनियम की अनप्रयोज्यता माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुरूप है। धारा 1क के तहत परिभाषित सरकारी रिकॉर्ड स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम के प्रावधान भारतीय वन अधिनियम, स्थानीय अधिनियमों या कानूनों और राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि के तहत अधिसूचित भूमि पर लागू होंगे। इसके अलावा, सरकारी रिकॉर्ड को किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्रकार की वन भूमि को अधिकार में लेने के लिए भी परिभाषित किया गया है।

इसके अलावा, राज्य की विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचान की गई मानव वन भूमि को रिकॉर्ड में लिया गया है और इसलिए अधिनियम का प्रावधान ऐसी भूमि पर भी लागू होगा।"

## 2.4.29 <u>असम सरकार</u>

	राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी
1.	इस तरह की छूट को वन की लंबाई के बावजूद विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए जहां से रैखिक अवसंरचना गुजरती है। अधिकतम 0.1 हेक्टेयर के ऐसे अपवर्तन को उपनगर, पर्यटन केंद्रों के नजदीक के क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए, लेकिन पूरे वन में नहीं फैला होना चाहिए। शेष वन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सुविधाओं में जन स्वास्थ्य केंद्र आदि जैसी जन सुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिए।	धारा 1ए(2)(ए) के तहत विचार की गई वन भूमि के 0.10 हेक्टेयर की छूट, विकास की मुख्यधारा के साथ उनका संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सड़क / रेल किनारे की बस्तियों और प्रतिष्ठानों को संपर्क प्रदान करेगी। अनुमत छूट 0.1 हेक्टेयर तक है अर्थात वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2, 3, 4, या 5 मीटर चौड़ी सड़क जिसमें 0.1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र शामिल नहीं है, के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।
2.	छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजना अर्थात केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए विचार की जानी चाहिए। 'महत्व' और 'संबंधित' के बीच 'और' शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। संशोधित पंक्ति को इस प्रकार पढ़ा जाए " राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजना के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव; अथवा	अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रस्तावित छूट सामान्य छूट नहीं है अर्थात प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है जिनकी पहचान केंद्रीय सरकार द्वारा की जानी है। 100 किमी की दूरी अधिकतम स्वीकार्य दूरी है। छूट का उपयोग आवश्यकता आधारित होगा यानी 5 किमी या 10 किमी के भीतर उपयोग किया जा सकता है।

# 2.4.30 जम्मू एवं कश्मीर सरकार

	राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी
(i)	धारा 1क(1)(1) के तहत दिए गए प्रावधानों में, "25 अक्तूबर, 1980 को या उसके बाद" के संदर्भ को हटाया जा सकता है क्योंकि यह अनावश्यक प्रतीत होता है।	वाक्यांश " 25 अक्तूबर, 1980 को या उसके बाद 25.10.1980 से पहले या बाद में वन के रूप में दर्ज की गई भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता पर अस्पष्टता की गुंजाइश को समाप्त करना।
(ii)	वाक्यांश " राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजना के निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। "धारा कि की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i) में वाक्यांश " राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक रैखिक परियोजना के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए है" के साथ प्रतिस्थापित किया जाये।	राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए छूट पर विचार किया गया है यानी छूट का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों होने की आवश्यकता है। छूट ऐसी अर्हक रैखिक परियोजनाओं पर लागू होगी, जिनकी पहचान रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा की जाए। इसके अलावा, धारा 1क (3) के तहत दिए गए प्रावधानों का उपयोग ऐसी छूट के लिए नियम और शर्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
(iii)	वाक्यांश "जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए है" धारा 1क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में जोड़ा जाए।	छूट ऐसे अर्हक अवसंरचना पर लागू होगी, जिसकी पहचान रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा की जाए। इसके अलावा, धारा 1क(3) के तहत दिए गए प्रावधानों का उपयोग ऐसी छूट के लिए नियम और शर्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

#### 2.4.31 नागालैंड सरकार

#### राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी 1. राज्य के अधिकांश वन क्षेत्रों को वनों के रूप में दर्ज नहीं किया विधेयक की प्रस्तावित धारा 1क (1) के तहत प्रदान किए जाता है और कोई भूमि रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इस बात का गए स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार, उल्लेख नहीं है कि राज्य में निजी और सामुदायिक स्वामित्व वाले वन विभाग के स्थानीय निकायों या प्राधिकरण के रिकॉर्ड क्षेत्रों के साथ विशेष रूप से कैसा व्यवहार किया जाएगा। यह में दर्ज अवर्गीकृत वनों सहित सभी वन भी अधिनियम के बताया गया है कि किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए निजी प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा, अधिनियम (प्राकृतिक रूप से उगे) वन क्षेत्रों को अधिनियम के दायरे से बाहर की अनुप्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो। धारा 6 रखते हुए एक विशिष्ट धारा अंतःस्थापित की जा सकती है। के तहत प्रदान किए गए समर्थकारी प्रावधानों को, जब भी आवश्यक हो, लागू किया जाएगा, 100 किमी की छूट के संबंध में, यह बताया गया है कि पूरे नागालैंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रस्तावित छूट सामान्य छूट नहीं राज्य को शामिल नहीं किया जाएगा। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर है अर्थात प्रस्तावित छुट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है के विशिष्ट आकार को देखते हुए लगभग सभी राज्यों को इससे बाहर रखा गया है। 100 किलोमीटर की एकरूपता को हटाने की जिनकी पहचान केंद्रीय सरकार द्वारा की जानी है। 100 आवश्यकता है, क्योंकि भारत-म्यांमार सीमा भारत-चीन या किमी की दूरी अधिकतम स्वीकार्य दूरी है। छुट का भारत-पाकिस्तान सीमा की तरह संवेदनशील नहीं है। इसके उपयोग आवश्यकता आधारित होगा अर्थात् 5 किमी या 10 किमी के भीतर उपयोग किया जा सकता है। अलावा. परी 100 किलोमीटर की बेल्ट इंडो-बर्मा जैवविविधता हॉटस्पॉट में आती है- जो पूरी दुनिया में जीन पूल विविधता के मामले में समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। 3. एक नई धारा अंतःस्थापित की जाए जिसमें निजी क्षेत्र में प्राकृतिक विधेयक की धारा 1क(3) में छुट पर विचार करते समय रूप से उगे वन को अधिनियम के दायरे से बाहर रखें जाए लेकिन निबंधन और शर्तों का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार यह जहां तक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और जैव विविधता के नुकसान सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के तहत विचार की गई का संबंध है, उन्हें वन क्षेत्रों के बराबर रखें जाए है। पुन: इस बात छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते पर बल दिया जाता है कि पूर्वोत्तर में निजी वन क्षेत्र अत्यंत समृद्ध हुए लागू की जाती है। प्रभाव आकलन, न्यूनीकरण हैं और नुकसान की भरपाई समुदाय के साथ समझौते में एनपीवी उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट की वसुली के माध्यम से समकक्ष क्षेत्रों के पुनःस्थापन या योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां कहीं आवश्यक हो, दीर्घकालिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। इस तरह की छुटों पर विचार करते समय, ऐसे सुरक्षा उपायों को हमेशा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, ये प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

## 2.4.32 हिमाचल प्रदेश सरकार

	राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी
i.	राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में ऐसी परियोजनाओं को प्रमाणित करने/विनिर्दिष्ट करने के लिए सक्षम प्राधिकरण को अधिनियम में परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है;	ऐसी अर्हक रैखिक परियोजनाओं पर छूट लागू होगी, जिनकी पहचान केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा की जाए।
ii.	यह समझा जाता है कि 100 किमी की दूरी हवाई दूरी है।	100 किमी की दूरी हवाई दूरी है।
	<ol> <li>धारा 1क (2) (ग) (ii) के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित 10 हेक्टेयर तक की भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत</li> </ol>	नियम और शर्तें, जिनमें सुविधाओं, रणनीतिक सड़कों, सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि को परिभाषित करना शामिल है। बाद में, विधेयक की धारा 1क(3) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा,

शामिल नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में, यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे अवसंरचना की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करके 'सुरक्षा संबंधी अवसंरचना' को विस्तृत करने की आवश्यकता है और यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण भी है कि किस प्रकार के अवसंरचना को सुरक्षा से संबंधित घोषित किया जाएगा।

दिशानिर्देशों में मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं को पहले ही विनिर्दिष्ट किया जा चुका है।

2. राष्ट्रीय महत्व की परियोजना, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी अवसंरचना के लिए अनुमोदन (वन मंजूरी) प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का प्राधिकार और एनपीवी और सीए की प्रभार राशि

विधेयक के तहत विचार की गई छूट पूर्ण छूट नहीं है। ऐसी परियोजनाओं को अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से छूट दी जाएगी, जबिक सीए और एनपीवी के भुगतान और विधेयक की धारा 1क(3) के प्रावधानों के अनुसार नियम और शर्तों को तय करते समय केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य शमन उपायों सहित राज्य स्तर पर प्रक्रियाएं की जानी हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ 100 किमी की दूरी, ज्यादातर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को कवर करती है, जो जनजातीय लोगों के अधिकारों को प्रभावित करेगी। अत: जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संशोधन की धारा 4(3) के अनुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित ग्राम सभा की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद वन भूमि का उपयोग करने का प्रावधान किया जाए।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित प्रावधान अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, पीईएसए अधिनियम, 1996 और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित अन्य समानांतर कानूनों के संचालन पर रोक या उल्लंघन नहीं करते हैं जिसके लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

#### 2.4.33 सिक्किम सरकार

राज्य सरकार की टिप्पणी/सुझाव	नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी
<ul> <li>1. 1क (किसी भूमि विशेष को कवर करने के लिए अधिनियम)</li> <li>(i) इस शर्त के तहत कट ऑफ तिथि को 25.10.1980 से बदलकर 12.12.1996 करने से वनेतर उद्देश्यों के लिए परिवर्तित दर्ज वन भूमि को नियमित किया जाएगा, जहां रिकॉर्ड में सुधार उचित परिश्रम के साथ-साथ वन विभाग की सहमति के बिना किया गया है;</li> <li>(ii) इससे वन भूमि में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को भी बढ़ावा</li> </ul>	12.12.1996 को या उससे पहले जिन भूमियों के भूमि उपयोग को वनेतर उपयोग में बदल दिया गया है, उन्हें छूट देने वाले विधेयक के प्रावधान उन दर्ज (राजस्व) वन भूमि पर लागू होंगे जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा वनेतर उपयोग के लिए रखा गया है।
मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ तिथि को स्थानांतरित करने की वरीयता बनाई गई है;	निर्देश को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा, धारा 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जब भी आवश्यकता होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो।
(iii) इसमें वे वन शामिल नहीं होंगे जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या सिक्किम वन, जल मार्ग और सड़क आरक्षित (परिरक्षण और संरक्षण) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है;	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अधिसूचित क्षेत्र, धारा 4 (अधिसूचित किए जाने के लिए प्रस्तावित) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों सहित, विधेयक के प्रावधान के तहत कवर किए जाएंगे।
(iv) उपधारा की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी एन गोधवर्मन मामले में 12 दिसम्बर, 1996 के 1995 के डब्ल्यूपी (सी) 202 में जारी आदेश के अनुरूप नहीं है।	अधिनियम के प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हैं। विधेयक की प्रस्तावित धारा 1क (1) के तहत प्रदान किए गए 'स्पष्टीकरण' में स्पष्ट किया गया है कि सरकार, वन विभाग के स्थानीय निकायों या प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज अवर्गीकृत वनों सहित सभी वन भी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, धारा 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जब भी आवश्यक हो,

2. पहाड़ी राज्य होने के नाते सिक्किम में खड़ी पहाड़ी ढलानों के साथ सड़कों का निर्माण किया गया है जो कटाव और स्लाइड से ग्रस्त हैं। 0.1 हेक्टेयर के बड़े खुले क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया ढलान स्थिरता में बाधक होगा। 12 मीटर आरओडब्ल्यू के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 0.1 हेक्टेयर या 1000 वर्ग मीटर के खुले क्षेत्र से 83 मीटर की लंबाई का खुले क्षेत्र होगा जो एक पहाड़ी राज्य के लिए दुर्गम और अनुचित है। छूट की सीमा दो-लेन पहुंच मार्ग की चौड़ाई या लगभग 10 मीटर तक सीमित हो सकती है।

अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो।

अनुमत छूट 0.1 हेक्टेयर तक है यानी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2, 3, 4, या 5 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए पहुंच मार्ग पर विचार किया जाए जिसमें 0.1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र शामिल नहीं है।

- 3. 7096 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ सिक्किम तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण तक 114 किमी और पूर्व से पश्चिम तक 64 किमी की सीमा है। इस प्रकार, एफसीए, 1980 के नियमों से एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी की छूट पूरे राज्य को समाहित कर देगी और एफसीए विनियमन के बिना वनेतर उपयोगों के लिए अपनी जैव विविधता के साथ प्राचीन वन क्षेत्रों को खोल देगी। सिक्किम के भौगोलिक संदर्भ में, प्रस्तावित छूट को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर से घटाकर 2 किलोमीटर किया जाए;
- 4. सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक की भूमि काफी बड़ी है। सुरक्षा से संबंधित अच्छी तरह से परिभाषित और सूचीबद्ध अवसंरचना के लिए अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि की अनुमति दी जा सकती है।
- 5. सिक्किम के लिए विशिष्ट एफसीए से संबंधित आंकड़ों के अनुसार; आज की तारीख तक वनेतर प्रयोजनों के लिए 3015 हेक्टेयर की कुल वन भूमि के डायवर्सन में से रक्षा प्रयोजनों के लिए 1529 हेक्टेयर है जो कुल डायवर्सन का लगभग आधा है;

छूट को विशुद्ध रूप से देश के सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में प्रस्तावित छूट सामान्य छूट नहीं है अर्थात प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है जिनकी पहचान केंद्र सरकार द्वारा की जानी है। कहा कि निजी संस्थाओं के लिए छूट उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, वन भूमि के विचलन के बाद भी, वन भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है, इसलिए, वन क्षेत्र में कोई कमी नहीं होगी।

इसके अलावा, उक्त व्यवस्था ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें प्रतिपूरक शुल्क का भुगतान और पेड़ों का मुआवजा शामिल है, जो राज्यों के लिए छूट के तहत ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी होगा।

## त्रिपुरा सरकार

2.4.34 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ 100 किमी तक की छूट त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य पर लागू नहीं हो सकती है और इसे घटाकर 10 किमी किया जाए। उपर्युक्त सुझाव के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है -

"अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रस्तावित छूट एक सामान्य छूट नहीं है यानी प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पहचाना जाना है। 100 किमी की दूरी अधिकतम स्वीकार्य दूरी है। छूट का उपयोग आवश्यकता आधारित होगा यानी 5 किमी या 10 किमी के भीतर उपयोग किया जाए।"

### 2.4.35 अरुणाचल प्रदेश सरकार

राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी
1. 0.1 हेक्टेयर की छूट को 1 हेक्टेयर तक बढ़ाया जाए	विधेयक में प्रस्तावित छूट का निर्णय केन्द्र सरकार ने मंत्रालयों, राज्यों और जनता के साथ परामर्श प्रक्रिया करने के बाद लिया है। धारा 1क (2) (क) के अंतर्गत विचार की गई 010 हैक्टेयर वन भूमि की छूट को सड़क किनारे की बसावटों और प्रतिष्ठानों को सड़क के किनारे की बसावटों और प्रतिष्ठानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपयुक्त माना जाता है ताकि विकास की मुख्यधारा के साथ उनकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।

#### 2. 100 किमी की दूरी को 150 एलएसी और एलओसी सहित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित रैखिक परियोजनाओं की छुट एक व्यापक छुट नहीं है। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के किमी तक बढ़ाया जाए। परामर्श से किया गया है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के विकास में तेजी लाई जा सके। अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (i) में पुनरुत्पादन कार्यकलापों 3. औषधीय पौधों के पुनर्जनन और कृषि को भी वानिकी के प्रावधानों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। गतिविधि के रूप में शामिल प्रधान अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल वाले किया जाए। पौधों, बागवानी फसलों या औषधीय पौधों की कृषि जैसी गतिविधियों को वनेतर गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये गतिविधियाँ वाणिज्यिक और गैर-साइट-विशिष्ट हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए वनों की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वन भूमि में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं जो कृषि के लिए वन भूमि के उपयोग को हतोत्साहित करती हैं।

### 2.4.36 मिजोरम सरकार

### राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव

इस उद्देश्य के लिए स्वीकार्य सरकारी रिकॉर्ड के प्रकार पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। चूंकि अधिसूचित वनों के अलावा अन्य वन भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर करने से प्रस्तावना के विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वे वन क्षेत्र इसका लाभ उठाते हुए विलुप्त/साफ़ हो सकते हैं।

2 (क) के संबंध में, सामग्री बिलकुल स्पष्ट नहीं है, इसका क्या अर्थ है। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि यदि ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित वन या दर्ज वन हैं, तो क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रावधान धारा 1क के विपरीत होगा।

3. (2) (ख) इस प्रावधान का फिर से विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वन विभाग द्वारा उन भूमियों पर कई वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, जो न तो अधिसूचित वन हैं और न ही दर्ज वन हैं। इस प्रकार, कोई भी उन बागानों को साफ करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसे क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. (2) (ग) (i) (ii) (iii) और (3) यह प्रावधान किसी भी एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किमी के भीतर स्थित किसी भी आरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी कार्य करने की खुली छूट देता है। किसी भी एजेंसी द्वारा रैखिक परियोजना की परिभाषा के तहत आने वाली किसी भी गतिविधि को राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय सुरक्षा की परियोजना का उल्लेख करते हुए लिया जाए क्योंकि सभी कार्य किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय महत्व के हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों में किसी भी काम को कार्य एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में कहा जाए। यह रक्षा परियोजनाओं में शामिल सभी एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर स्थित किसी भी आरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करने की खुली छूट देगा, जो इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, जो

### नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी

विधेयक की प्रस्तावित धारा 1 क (1) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि सरकार, वन विभाग के स्थानीय निकायों या प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज अवर्गीकृत वनों सहित सभी वन भी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो, जब भी आवश्यक हो, धारा 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

वनेतर भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ऐसी भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के लिए विधेयक में एक स्पष्टता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, विधेयक के प्रावधान राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं। यह ऐसी भूमि पर अधिनियम की गैर-प्रयोज्यता पर स्पष्टता लाकर वनेतर भूमि पर वनीकरण को बढावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में प्रस्तावित छूट सामान्य छूट नहीं है अर्थात प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है जिनकी पहचान केंद्र सरकार द्वारा की जानी है। कहा कि निजी संस्थाओं के लिए छूट उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, उक्त व्यवस्था ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें प्रतिपूरक शुल्क का भुगतान और पेड़ों का मुआवजा शामिल है, जो राज्यों के लिए छुट के तहत ऐसी

मानव के अस्तित्व के लिए एक विनाशकारी कार्य होगा। क्योंकि पूरा पारिस्थितिक संतुलन नष्ट हो जाएगा। चूंकि लगभग पूरा मिजोरम राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा (म्यांमार और बांग्लादेश सीमा) की हवाई दूरी के 100 किलोमीटर के भीतर आता है और इसलिए, इसके सभी वन और वन्यजीव क्षेत्र इस तरह के प्रावधान के साथ नष्ट हो जाएंगे। इस प्रावधान पर कड़ी आपत्ति है और यह स्वीकार्य नहीं है और इसे हटा दिया जाएगा।

परियोजनाओं पर विचार करते समय उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी होगा।

ये प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

### 2.4.37 <u>पंजाब सरकार</u>

# राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव एफसीए के तहत अनुमोदन की मंजूरी के लिए शक्ति राज्य सरकार को उन मामलों में प्रत्यायोजित की जाए जहां उपयोगकर्ता एजेंसी पीडब्ल्यूडी, रेलवे, सिंचाई विभाग आदि जैसी भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी है। और इसमें शामिल क्षेत्र 5 हेक्टेयर तक है।

## नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी

चूंकि सामान्य अनुमोदन के प्रावधान मूल अधिनियम के उपबंधों द्वारा समर्थित नहीं हैं, इसलिए मंत्रालय द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया।

वन (संरक्षण) नियम, 2022 को अधिसूचित करके अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, जिसमें 40 हेक्टेयर तक के क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को संसाधित करने और अनुमोदित करने के लिए आईआरओ को स्पष्ट प्रतिनिधिमंडल दिया गया है। प्रस्ताव की जांच के मौजूदा रैखिक तरीके के स्थान पर प्रस्ताव की सहभागी और समानांतर जांच को सुकर बनाने के लिए परियोजना अनुवीक्षण समिति शुरू करके राज्य सरकार में प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कई अन्य पहलें की हैं जैसे प्रत्येक आईआरओ में पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठकें आयोजित करना, महीनों में दो बार आरईसी बैठकें आयोजित करना आदि। ऐसे प्रस्तावों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को सुगम बनाना।

#### अन्य संगठन

### सीमा सड़क संगठन

2.4.38 बीआरओ ने सुझाव दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा/नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किमी की छूट सीमा को बढ़ाकर 150 किमी किया जाना चाहिए क्योंकि टनलिंग, ब्रिजिंग और सड़क अवसंरचना के कई कार्यों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जो सीमावर्ती क्षेत्रों को रणनीतिक गहराई प्रदान करेगा।

2.4.39 सड़कों, पुलों, सुरंगों, आवासों, स्थायी सुरक्षा, हवाई क्षेत्रों आदि के संदर्भ में चीन के साथ "अवसंरचना के अंतर" को कम करने के लिए, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को अधिसूचित करने की पुरजोर सिफारिश की जाती है तािक एलएसी/एलसी/आईबी से 100 किमी तक रक्षा अवसंरचना परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण किया जा सके। सीमा सड़क संगठन के उपर्युक्त सुझाव के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लिखित में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

"उन्होंने कहा, "एलएसी और एलओसी सहित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित रैखिक परियोजनाओं को छूट देना कोई व्यापक छूट नहीं है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के लिए रक्षा मंत्रालय के परामर्श से प्रस्तावित किया गया है।"

# विशेषज्ञों/हितधारकों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

2.4.40 हितधारकों ने समिति के समक्ष अपने लिखित निवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:—

- i. संशोधन विधेयक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12-12-1996 के आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार वन भूमि की परिभाषा को सीमित करने का प्रयास किया गया है।
- ii. धारा 1क की उपधारा (1) के खंड (ख) को शामिल करने से उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12-12-1996 के निर्णय को पलट दिया जाएगा।
- iii. धारा 1 (क) (1) (ख) में दिए गए प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार वनों के शब्दकोश अर्थ को भी शामिल किया जाना चाहिए।

2.4.41 उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

"विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के 12.12.1996 के आदेश के अनुरूप हैं। प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ समिति द्वारा उन सभी भूमियों, जो उनके शब्दकोष में वन थीं, की पहचान की गई है और उन्हें रिकार्ड में लिया गया है। विधेयक के प्रस्तावित प्रावधान विभिन्न भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की प्रयोज्यता को और स्पष्ट करते हैं।"

2.4.42 हितधारकों ने समिति को प्रस्तुत अपने लिखित ज्ञापनों में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"धारा 1 (क) (1) (ख) में दिया गया परंतुक माननीय सुप्रीम कोर्ट के 12.12.1996 के आदेश के प्रावधानों को कमजोर करता है क्योंकि यह 1980 से 1996 तक वन भूमि के डायवर्सन को वैध बना देगा।"

2.4.43 उपर्युक्त के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार स्पष्ट किया:—

"यह केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उन वन भूमि पर लागू होता है जहां राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 12.12.1996 से पहले भूमि उपयोग बदल दिया गया है, उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अर्थात परंतुक के प्रावधान केवल राजस्व वन भूमि पर लागू होते हैं, न कि आईएफए या स्थानीय अधिनियमों के तहत अधिसूचित वन भूमि पर। परंतुक में ऐसी राजस्व वनभूमियों को छूट प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें राज्य द्वारा 12-12-1996 से पहले वनेतर उपयोग के लिए रखा गया है, जिसमें 25-10-1980 से पहले की अविध के मामले भी शामिल हैं। इसलिए, परंतुक के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर नहीं करते हैं।

2.4.44 इसके अलावा एक हितधारक ने पाया कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कई जंगलों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया था जो अधिसूचित नहीं हैं। नए संशोधन न केवल उस संरक्षण को कमजोर करेंगे, बल्कि इसे तेजी से नष्ट करने में भी मदद करेंगे। विधेयक में "केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक उपयोगिता" जैसे कई अस्पष्ट क्षेत्र हैं, जो अस्पष्ट हैं और हमें जंगलों के विनाश के लिए इसका दुरुपयोग करने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ते हैं। इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

"विधेयक के प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए कानूनी संरक्षण को कमजोर नहीं करते हैं। गैर-अधिसूचित वन भूमि पर अधिनियम की प्रयोज्यता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, स्थानीय निकाय स्तर तक सरकारी रिकॉर्ड के दायरे का विस्तार करते हुए एक विस्तृत स्पष्टीकरण। विधेयक की धारा 1क(3) के सक्षम प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं को स्पष्ट किया जाएगा।"

- 2.4.45 इसके अलावा, सिमित को प्रस्तुत लिखित ज्ञापन में हितधारकों ने कहा कि धारा 1क (1) एफसीए के दायरे को सीमित करती है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश को पलट देती है। ऐसी भूमि यां हैं जहां केवल अधिसूचना जारी की जाती है, नारंगी भूमि का बड़ा हिस्सा, पूर्वोत्तर राज्यों में अवर्गीकृत वन हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि अधिनियम के प्रावधान ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विधेयक के प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12-12-1996 के आदेश को नहीं पलटते हैं और विधेयक की प्रस्तावित धारा 1क (1) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि सरकार, वन विभाग के स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड में दर्ज अवर्गीकृत वनों सहित सभी दर्ज वन, या प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों को भी आकर्षित करेगा। इसके अलावा, धारा 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जब भी आवश्यक हो, अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो।
- 2.4.46 एक अन्य लिखित ज्ञापन में यह देखा गया कि प्रस्तावित विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह अधिनियम 12 दिसम्बर, 1996 को या उससे पहले वनेतर प्रयोजनों के लिए बदली गई वन भूमि पर लागू नहीं होगा। हमारा मानना है कि इस खंड का वन संरक्षण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अतीत में, वन भूमि को कई वनेतर उपयोगों जैसे नकदी फसलों के रोपण, अवसंरचना के विकास, खनन पट्टे आदि के लिए परिवर्तित किया गया है। एफसीए (1980) कहता है कि वन भूमि के ऐसे किसी भी डायवर्जन या ऐसे क्षेत्रों पर पट्टों के विस्तार के लिए उचित पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वन मंजूरी प्राप्त करने से इन गतिविधियों के स्पेक्ट्रम को छूट देना एफसीए (1980) के संरक्षण उद्देश्यों के अनुपालन में नहीं होगा। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

"12.12.1996 को या उससे पहले जिन भूमि के उपयोग को वनेतर उपयोग में बदल दिया गया है, उन्हें छूट देने वाले विधेयक के प्रावधान केवल दर्ज / राजस्व वन भूमि पर लागू होंगे यानी धारा 1क के खंड (बी) में जोड़ा गया परंतुक ऐसी राजस्व वन भूमि को छूट प्रदान करता है, जिन्हें 12.12.1996 से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा वनेतर उपयोग के लिए रखा गया है।"

### 2.4.47 इसके अलावा, जनता से निम्नलिखित लिखित टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं:—

- 1. 25 अक्तूबर, 1980 से पहले किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किए गए वनों को प्रिंसिपल एक्ट के तहत विनियमित या संरक्षित नहीं किया जाएगा।
- 2. पश्चिमी घाट, वन्यजीव गलियारों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र से समझौता किया गया है क्योंकि वे अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं। 25.10.1980 की कट ऑफ तारीख से बड़ी मात्रा में वन भूमि खुल जाती है जो अन्य विभागों के पास केवल उपयोग के अधिकारों के साथ पट्टे पर है।
- इस तारीख से पहले भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अधिसूचना के लिए भूमि के कई क्षेत्र प्रस्तावित हैं, और अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में वैधता पर गौर करने और उसे स्पष्ट करने की जरूरत है।
- 4. नई धारा 1क उप-धारा 1 अरावली, तराई, मध्य भारत, पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्व में जैव विविधता से समृद्ध वनों के बड़े हिस्से को खतरे में डालती है. जिन्हें अब प्रिंसिपल एक्ट के उद्देश्य के लिए 'वन' नहीं माना जाए।
- 5. कुल वन क्षेत्र में से हमारे वनों का लगभग 2762% (दर्ज वन) अधिनियम के दायरे से बाहर होगा।
- 6. प्रस्तावित संशोधन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का घोर उल्लंघन है।
- पेड़ों की कटाई के लिए मुआवजा, एक प्रतिस्थापन नहीं होगा। किसी भी तरह से एक प्राकृतिक आवास का पुनर्वास नहीं किया जाए।
- 8. प्रस्तावित धारा 1क में 'भूमि' को चित्रित करने का प्रयास किया गया है जो एक तरफ एफसीए द्वारा कवर की जाएगी, और 'भूमि' जो एफसीए द्वारा कवर नहीं की जाएगी। इस तरह के वर्गीकरण के लिए कोई तर्क नहीं है, न ही इस तरह के वर्गीकरण और एफसीए के उद्देश्य और उद्देश्य के बीच कोई सहसंबंध है, जो वन संरक्षण है। ऊपरी तौर पर, इस प्रस्तावित प्रावधान में वन भूमि का वर्गीकरण तर्कहीन और असंवैधानिक है।
- 2.4.48 उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—
  - 1. विधेयक के वाक्यांश '25.10.1980 को वन के रूप में दर्ज...' का तात्पर्य है कि 25.10.1980 से पहले भी वन के रूप में दर्ज की गई सभी भूमि भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर की जाएगी।
  - 2. धारा 1क स्पष्ट करती है कि अधिनियम के प्रावधान भारतीय वन अधिनियम, स्थानीय अधिनियमों या कानूनों के तहत अधिसूचित भूमि और राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि पर लागू होंगे। इसके अलावा, सरकारी रिकॉर्ड को सभी प्रकार की वन भूमि पर कब्जा करने के लिए भी परिभाषित किया गया है।
  - 3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अधिसूचित क्षेत्र, धारा 4 (अधिसूचित किए जाने के लिए प्रस्तावित) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों सहित, विधेयक के प्रावधान के तहत कवर किए जाएंगे।
  - 4. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को कमजोर नहीं किया गया है। विधेयक की प्रस्तावित धारा 1क(1) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि सरकार, वन विभाग के स्थानीय निकायों या प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज अवर्गीकृत वनों सहित सभी वन भी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, धारा 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जब भी आवश्यक हो, अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो।
  - 5. भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत की वन स्थिति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत के लगभग 5,16,630 वर्ग किमी वन दर्ज वन क्षेत्रों (अधिसूचित वन क्षेत्रों) के भीतर हैं, जबिक 1,97,159 वर्ग किमी वन दर्ज वन क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं जिसमें राजस्व वन, निजी वन, कृषि वानिकी वृक्षारोपण आदि शामिल हैं। अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज राजस्व वन भूमि, निजी वन भूमि एवं अन्य भूमि पर अधिनियम के प्रावधान लागू हैं। इसलिए, यह टिप्पणी कि 2762% वन अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे, तर्कसंगत नहीं है।
  - 6. संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा "वन" को समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17क के रूप में जोड़ा गया था। इसलिए, प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को प्रदान की गई शक्तियों के दायरे में आता है। इसके अलावा, विधेयक का प्रस्तावित संशोधन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करता है।

- 7. इस बात से सहमत हैं कि डायवर्सन से लुप्त हुए प्राकृतिक वनों को वृक्षारोपण से प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। तथापि, नुकसान की प्रतिपूत करने और समय-समय पर खोई हुई सेवाओं की भरपाई करने के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण और इसी प्रकार की अन्य शर्तों, जैसा कि केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करे, के प्रावधान विधेयक में प्रस्तावित किए गए हैं।
- छूट पर विचार करते समय नियम और शर्तें निर्धारित करने के लिए विधेयक की धारा 1क(3) के तहत सक्षम प्रावधान प्रदान किए गए हैं। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के तहत विचार की गई छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए। प्रभाव आकलन, न्यूनीकरण उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां भी आवश्यक हो, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। इस तरह की छूटों पर विचार करते समय, ऐसे सुरक्षा उपायों को हमेशा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों में शामिल किया जाएगा।
- 2.4.49 समिति को प्रस्तुत लिखित ज्ञापनों में निम्नलिखित टिप्पणियां भी की गई थीं :--
  - 12-12-1996 से पहले वनेतर उपयोग के लिए पहले से ही रखी गई वन भूमि को छूट देने वाला परंतुक अशुभ है क्योंकि वन क्षेत्र में खनन जैसी गतिविधियों की अनुमित दी जाएगी।
  - यह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना 12.12.1996 से पहले वनेतर उपयोग के लिए रखी गई सभी वन भूमि को वैध बना देगा।
  - एनपीवी के भुगतान के बिना और वन मंजूरी की प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि उपयोग को बदला जाए।
  - 12 दिसंबर, 1996 से पहले वन उपयोग से वनेतर उपयोग में बदलने वाली भूमि की छूट उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत हो सकती है।

2.4.50 उपर्युक्त टिप्पणियों के उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:—

"प्रावधान केवल दर्ज (राजस्व) वन भूमि के लिए लागू होते हैं यानी धारा 1क के खंड (बी) में जोड़े गए परंतुक में ऐसी राजस्व वनभूमि को छूट प्रदान की जाती है, जिन्हें 12.12.1996 से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा वनेतर उपयोग के लिए रखा गया है, जिसमें 25.10.1980 से पहले की अविध के मामले भी शामिल हैं।

12.12.1996 के बाद की अवधि से संबंधित अन्य सभी मामलों को एनपीवी और सीए के भुगतान सहित मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

चूंकि प्रावधान 12.12.1996 से पहले की अवधि से संबंधित मामलों पर लागू होंगे, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।"

2.4.51 एक विशेषज्ञ ने समिति को सौंपे गए अपने लिखित ज्ञापन में कहा है कि वनों के विनाश के लिए 0.10 हेक्टेयर की छूट का दुरुपयोग किया जाए खंड "सीए और एनपीवी की शर्त के बिना राज्य सरकार/अधिकृत अधिकारी से अनुमित" को अंतःस्थापित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त टिप्पणी के संबंध में, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समिति को दिए अपने लिखित निवेदन में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

"धारा 1क की उप धारा (3) में प्रावधान है कि इस तरह की व्यवस्था ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें पेड़ों के नुकसान की भरपाई भी शामिल है, जैसा कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है। केंद्र सरकार जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के उपायों सहित नियम और शर्तें निर्धारित करेगी, जो राज्य में अधिकारियों के साथ-साथ उपयोगकर्ता एजेंसी के लिए भी बाध्यकारी होगी।"

2.4.52 जनता से प्राप्त लिखित ज्ञापनों में यह भी देखा गया कि प्रस्तावित संशोधन एफआरए, 2006, एलएआरआर अधिनियम, 2013, पीईएसए अधिनियम और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों को कमजोर करता है। अधिनियम के तहत विचार की गई छूट एफआरए, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संबंध में, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विधेयक में कोई गैर-बाध्यकारी खंड या धारा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित प्रावधान अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, पीईएसए अधिनियम, 1996 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता सहित अन्य समानांतर कानूनों के संचालन पर रोक या उल्लंघन नहीं करते हैं, जिसमें ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

2.4.53 इस विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में दिनांक 17 मई, 2023 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान एक हित धारक ने निम्नलिखित बातें कहीं:—

"उदाहरण के लिए कृपया पूर्वोत्तर क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशाल वन क्षेत्रों को देखें। यदि आप देश की प्रत्येक सीमा से 100 किलोमीटर के क्षेत्र को छूट प्रदान करेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्या बचेगा? यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसा है कि हम समस्याएं देख रहे है जो कतिपय समुदायों के कारण उत्पन्न हुई हैं जिन समुदायों का संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत वन पर परम्परागत अधिकार और रूढ़िजन्य अधिकार है जो मेरे विचार से अपर्याप्त है। मैं मानता हूं कि यदि आप सुरक्षा के नाम पर इसमें छूट देंगे तो इससे समस्या उत्पन्न होगी। यह ऐसा खंड है जिस पर समिति को बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। विभिन्न श्रेणियों वाली परियोजनाओं के लिए भारत के वनों के बड़े हिस्से के लिए भी अन्य छूटें दी जा रही हैं। इसलिए जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यह व्यवस्था जिसमें किसी बाधा के बिना छूट देने की बात कही गई है, एक स्वाभाविक छूट व्यवस्था है जो बहुत खतरनाक और जोखिम भरी है। मैं आश्वस्त हूं कि सरकारें काफी जिम्मेदार हैं और कि वे संरक्षण के प्रति चिंतित है। किंतु जैसे ही आप इसे सांविधिक रूप देंगे तो इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी और आपके लिए इसे ठीक कर पाना कठिन हो जाएगा। जहां तक छूट देने का मामला है मैं इस मामले में यही बात कहना चाहती हूं।" अन्य विशेषज्ञ/हितधारक ने छूट और छूट के मामले में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणी की:

"विधेयक के तहत विचार की गई छूटें पूर्ण छूट नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में राज्य द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अनुमोदन से विचार किया जाना चाहिए।"

2.4.54 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

"रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श कर 100 किलोमीटर के दायरे पर निर्णय लिया गया है और विभिन्न रक्षा संगठनों की अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतने दायरे को ईष्टतम माना गया है।

इस छूट पर पूर्णत: जनिहत तथा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की दृष्टि से विचार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के साथ प्रस्तावित छूट सामान्य छूट नहीं है अर्थात् प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा वाले रणनीतिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ही है जिसकी पहचान केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। उक्त छूट प्राइवेट सत्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, वन भूमि के अन्यत्र उपयोग के बाद भी इसकी कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और इसलिए वन क्षेत्र में कोई कमी नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, उक्त व्यवस्था ऐसी निबंधन व शर्तों के अध्यधीन होंगे जिसमें प्रतिकर लेवी और वृक्षों की क्षतिपूर्ति का भुगतान शामिल होगा जो राज्यों पर बाध्यकारी होगा कि वे छूट के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

रक्षा परियोजनाओं में, जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना होता है, अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल दुरूह प्रक्रिया और प्रलेखीकरण के कारण प्राय: देरी हो जाती है।"

2.4.55 इसके अलावा, दिनांक 30 मई, 2023 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए दो हितधारकों ने समिति के समक्ष निम्नवत बातें कहीं:—

"यह देश में विशाल वन भूमि पर इस अधिनियम की जागू किए जाने को सीमित करता है जिसे गोदावर्मन आदेश लागू होने के बाद से संरक्षण प्राप्त है। इसलिए वन भूमि के ऐसे अपवर्जन से बिना किसी वन मंजूरी के इन्हें बेचा जा सकता है, अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है, इसकी कटाई की जा सकती है, वृक्षों को काटा जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है अथवा दोहन किया जा सकता है। सभी वन भूमि जो संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है किंतु 1980 से पहले सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध है, इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएगीं। यह उच्चतम न्यायालय के 1996 के निर्णय से अलग है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि सरकारी अभिलेखों में उल्लिखित प्रत्येक वन भूमि को काटने से बचाने के लिए कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए।"

(i) "खंड 1क में ख के पश्चात् हमें एक उपखंड जोड़ने की आवश्यकता है कि '12.12.1996 के गोदावर्मन निर्णय में परिभाषित भूमि' को सम्मिलित किया जाए। इसी खंड के प्रथम परंतुक में दो ऐसे पहलू हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। हमें अधिसूचना रद्द करना और अपवर्जन के बीच अंतर करना चाहिए। इसलिए हम इसमें अंतर लाएं और जिन भूमियों का अन्यत्र उपयोग किया गया है उन्हें इस अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं रखा जाए। यह एक बडी़ खामी होगी जिसका दोहन किया जाएगा। जिस भूमि की अधिसूचनाएं रद्द कर दी गई हैं, केवल उस भूमि को कानून के दायरे से बहार रखे जाने पर विचार किया जाए।"

2.4.56 उपर्युक्त के विषय में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने दिनांक 30 मई, 2023 को हुई समिति की बैठक के दौरान निम्नवत उत्तर दिया:—

'जिन नए मुद्दों को उद्धृत किया गया है उनमें से एक मुद्दा तिथि अर्थात् 12 दिसंबर, 1996 की प्रयोज्यता से संबंधित है और कि उक्त तिथि से पूर्व किए गए सभी कानूनी कार्यों को विधि सम्मत माना जाएगा या नहीं। मैं माननीय समिति के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जिस भाषा का हमने प्रयोग किया है वह यह है: ''परंतु इस खंड के उपबंध ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे जिनका उपयोग राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रसाशन द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा उनकी ओर से जारी आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर, 1996 को अथवा उसके पूर्व वन उपयोग से बदल कर वनेतर प्रयोजन के लिए कर दिया गया है।" यदि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य शासन द्वारा किसी बात को प्राधिकृत नहीं किया गया है, वह अवैध होगी और इस उपबंध के अंतर्गत भी अवैध माना जाएगा। इस उपबंध को उन गतिविधियों को सुकर बनाने के लिए ही अंत:स्थापित किया गया था जो 12 दिसंबर, 1996 से पूर्व हुई हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यालय का निर्माण हो चुका है और अब वे एक शौचालय अथवा कमरा जोडना चाहते हैं तो यह गतिविधि वन संरक्षण अधिनियम के दायरे के अंतर्गत नहीं आएगी।"

2.4.57 एक आमंत्रित सदस्य ने दिनांक 30 मई, 2023 को समिति के समक्ष निम्नलिखित बातें कहीं:—

"अन्य पहलू जो मैं जोर देकर कहना चाहती हूं वह यह है कि बहुत संघर्षों के बाद हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कानून मिला है। मैं खुद भी उस कमेटी में थी। मुझे याद है कि बहुत बाधाएं थीं। मेरा मुद्दा यह है कि हमने इसके लिए साथ मिलकर कितने दिनों तक संघर्ष किया है ऐसे संघर्ष के पश्चात् हमें कुछ व्यवस्था मिली है जिसमें कम से कम तीन बातें हैं। पहला जनजातीय समुदायों और परंपरागत वन निवासियों हेतु सुरक्षा है। दूसरा, वन के अंतर्गत आने वाले हमारे क्षेत्रों हेतु लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अब हम इन सभी चीजों को छोड रहे हैं। ये सारे फॉरेस्ट हमारे औद्योगीकीकरण के लिए इस्तेमाल करें, क्योंिक जिक्र नहीं है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पेसा (पीईएसए) का रूल्स में भी जिक्र नहीं है कि यह भी अधिकार है। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि इसमें ट्राइबल्स का कंजर्वेशन में क्या रोल है। आप अमेंडमेंट्स को लाएंगे और इन कम्युनिटीज को मेंशन भी नहीं करेंगे तो मैं समझती हूं कि यह बहुत ही गलत है। अगर किनारे करके ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकारों को आप इस प्रकार से करेंगे, यह बहुत ही गलत होगा। अंत में यह कहूंगा कि जनजातीय समुदायों और वन निवासियों हेतु पीईएसए एवं अन्य संवैधानिक गारंटियों के साथ वन अधिकार अधिनियम का संदर्भ दिए बिना और इन्हें संबद्ध किए बिना ये संशोधन अन्याय पूर्ण होगा। इसलिए मैं समिति से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों को इन संशोधनों में अंत:स्थापित करते हुए हमारे संरक्षण अधिनियमों में नियमों से जोड़ा जाए।"

2.4.58 उपर्युक्त के संदर्भ में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नवत कहा:—

"जहां तक एफआरए का संबंध है, मैंने पहले ही यह स्पष्ट किया है यह अधिनियम एफआरए का उल्लंघन नही करता है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं इसे पुन: पढ़ता हूं:

"राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यथास्थिति अधिनियम की धारा-2 के अधीन केंद्रीय सरकार का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी और वन अधिकारियों की मान्यता, जो एफआर एक्ट है, के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन को सुनिश्चित करने सिहत यथा लागू अन्य सभी अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति और अनुपालन करने के पश्चात यथास्थिति अभियोजन पट्टा निर्धारित करने व निरीक्षण के संबंध में आदेश जारी करेगा" इसलिए संबंधित क्षेत्र की ग्राम सभा द्वारा लिखित रूप में अनुमित दिए जाने के बाद ही राज्य सरकार अंतिम अनुमित जारी करेगी।"

- 2.4.59 इसके अलावा. समिति को प्रस्तत किए गए लिखित ज्ञापनों में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :—
  - (i) विधेयक वन में रहने वाले स्थानीय समुदायों की पूरी तरह से अनदेखी करके वन संरक्षण का एक संकीर्ण दृष्टिकोण लेता है, और वास्तव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निहित "वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सुरक्षा" के उनके मौजूदा अधिकारों को दरिकनार करता है। वन विपथन से पहले स्थानीय समुदायों की सहमित के प्रावधानों को प्रधान अधिनियम के खंड 2 और प्रस्तावित विधेयक के खंड 4 में पर्याप्त रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए।
  - (ii) वन भूमि की छूट जहां व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की प्रयोज्यता से मान्यता दी गई है।
  - (iii) प्रस्तावित अधिनियम के रूप में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 जनजातियों के कल्याण के लिए तैयार किए गए वन अधिकार अधिनियम-2006 और पीईएसए अधिनियम-1996 दोनों को कमजोर करेगा और विशेष रूप से भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और धीरे-धीरे उपरोक्त दो अधिनियमों के तहत किए गए कल्याणकारी उपायों को कम कर देगा। इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रस्तावित विधेयक को वापस

लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन निवासी समुदायों के अधिकारों को कम किया गया है। एफआरए के तहत ग्राम सभा को दी गई शक्तियों को शामिल करने के लिए किसी भी प्रावधान को विशेष रूप से शामिल करने में विफलता। पीईएसए अधिनियम 1996 का उल्लंघन।

- (iv) नए विधेयक को यह स्वीकार करने में आ रही विफलता की मूलभूत समस्या का समाधान करना चाहिए कि स्थानीय समुदाय वनों के वास्तविक संरक्षक और रक्षक हैं। तथापि वन अधिकार अधिनियम ने ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन एफसीए में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय समुदायों को वनों की रक्षा और बचाव के अधिकार दिए जा सकें, यह सुनिश्चित करके कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना किसी भी वन को गैर-वन उद्देश्यों के लिए विचलन या उपयोग नहीं किया जाता है।
- (v) विधेयक वन से संबंधित किसी भी अन्य कानून का कोई संदर्भ नहीं देता है: वन अधिकार अधिनियम, 2006; जैव विविधता अधिनियम, 2002 में न तो विधेयक के पाठ में और न ही उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कोई संदर्भ पाया गया है। तथ्य यह है कि वन खाली स्थान नहीं हैं, बिल्क ऐसे क्षेत्र हैं जहां कानून के तहत दिए गए अधिकार हैं, विधेयक में कोई संदर्भ नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 2,95,000 जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई है और वे कार्यात्मक हैं। वन में रहने वाले समुदायों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रदान किए गए हैं और ग्राम सभाओं को इन सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करने के लिए अनिवार्य किया गया है। फिर भी, विधेयक विभिन्न आधारों पर जंगल को विपथन का अधिकार देता है। इन वन क्षेत्रों की रक्षा और पुनरुत्पादन में समुदायों द्वारा किए गए प्रयासों की कोई मान्यता नहीं है।
- (vi) हालांकि, वर्ष 2023 विधेयक भारत के संविधान के प्रावधानों, कानूनों और न्यायिक मिसालों के बारे में ज्ञान की चिंताजनक कमी को प्रदर्शित करता है जो भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को एक विशेष संवैधानिक दर्जा देते हैं। संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद 244, जो इन क्षेत्रों के विशेष शासन से संबंधित है, को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। वर्ष 2023 विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 243एम के जनादेश के तहत अधिनियमित पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की भी अनदेखी करता है, जिसके तहत पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सामान्य रूप से अपने प्राकृतिक संसाधनों पर और विशेष रूप से खिनज, वन और जल संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अधिकार दिया गया है। ग्राम सभाओं के साथ उचित परामर्श किए बिना विकासात्मक परियोजनाओं के लिए इन संसाधनों के उपयोग को इस कानून द्वारा निषिद्ध किया गया है।

### 2.4.60 इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय ने लिखित में निम्नानुसार बताया है:—

"विधेयक के प्रावधान वन अधिकार अधिनियम, 2006, पीईएसए या एलएआरआर अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन या निरस्त नहीं करते हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत एसटी और ओटीएफडी की सहमति सहित इन कानूनों में परिकल्पित प्रक्रियाओं को प्रस्तावित संशोधन द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया है।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित प्रावधान अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, पीईएसए अधिनियम, 1996 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता सहित अन्य समानांतर कानूनों के संचालन पर रोक या उल्लंघन नहीं करते हैं, जो ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का आदेश देता है।

विधेयक में कोई गैर-बाध्यकारी खंड प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, विधेयक के प्रावधान वन अधिकार अधिनियम, 2006 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों में बाधा नहीं डालते हैं। उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ग्राम सभा/समिति को प्रदत्त अधिकार ग्राम सभा/समितियों अथवा अन्य सांविधिक निकाय को प्राप्त होते रहेंगे।

संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा "वन" को समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17क के रूप में जोड़ा गया था। अतः, प्रस्तावित संशोधन केन्द्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के दायरे में है। इसके अलावा, विधेयक का प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करता है।"

### 2.4.61 जनता से प्राप्त आगे की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:—

(i) संशोधन में प्रस्तावित छूट वनों की कटाई की जांच और वनों की सुरक्षा में अधिनियम की भूमिका को कमजोर करेगी। "अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित" भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर रखना खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के बड़े इलाकों जैसे रेगिस्तान, अर्ध-शुष्क सवाना घास के मैदानों, चट्टानी आउटक्रॉप्स और आर्द्रभूमि के संरक्षण से गंभीर रूप से समझौता है।

- (ii) छूट के परिणामस्वरूप वन आवरण का विनाश होगा और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये क्षेत्र, अर्थात् नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा, और "वामपंथी उग्रवाद" से प्रभावित क्षेत्र अत्यंत नाजुक पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र हैं। वन क्षेत्र के इस तरह के विनाश से जनजातीय आवासों और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की प्रस्तावित छूटों की भरपाई वृक्षारोपण और वनीकरण से नहीं की जा सकती है।
- (iii) 100 किमी की मनमानी सीमा देने के बजाय, एक वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाए, जैसे कि 'सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र', जिसे समय-समय पर अधिसुचित किया जा सकता है।
- (iv) सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के निर्माण के लिए 100 किमी की दूरी को घटाकर 50 किमी किया जाना चाहिए क्योंकि 100 किमी उच्च और मध्य हिमालय के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर देगा।
- 2.4.62 उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है :—

"अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में छूट प्रदान करने वाले प्रस्तावित प्रावधान सामान्य छूट नहीं हैं अर्थात प्रस्तावित छूट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है जिनकी पहचान केंद्रीय सरकार द्वारा की जानी है। उक्त छूट निजी संस्थाओं सिहत क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, उक्त व्यवस्था ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें प्रतिपूरक शुल्क का भुगतान और पेड़ों का मुआवजा शामिल है, जो राज्यों के लिए छूट के तहत ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी होगा।

रक्षा मंत्रालय के परामर्श से 100 किमी की सीमा तय की गई है। भूमि की कुछ श्रेणियों को विशुद्ध रूप से देश के सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है।

अतः, प्रस्तावित विधेयक की धारा 1क की उपधारा (3) में सक्षम प्रावधान किए गए हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसी व्यवस्था ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें पेड़ों के नुकसान की प्रतिपूत भी शामिल है, जैसा कि केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे। छूटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा।"

2.4.63 जनता के एक अन्य लिखित ज्ञापन में यह देखा गया है कि शोला घास के मैदान, मिरिस्टिका दलदल, लेटराइट पहाड़ियों पर घास का मैदान, निजी स्वामित्व वाले मैंग्रोव वन जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अपने उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

"प्रस्तावित विधेयक मुख्य रूप से विभिन्न भूमि में अधिनियम की प्रयोज्यता में अस्पष्टता को समाप्त करने का इरादा रखता है। अधिनियम की प्रयोज्यता अभिलेखों में दर्ज भूमि की स्थिति से तय की जाती है जिसे विधेयक की धारा 1क(1) के तहत समझाया गया है। भूमि राज्य का विषय है और यदि राज्य सरकार चाहे तो पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/पारितंत्रों को वनों की श्रेणी में शामिल करने के लिए भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जा सकता है।"

2.4.64 समिति को सौंपे गए एक अन्य ज्ञापन में, एक हितधारक ने सुझाव दिया है कि आईए (2)(क) के तहत विचार की गई छूट के संबंध में, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए इको-ब्रिज के निर्माण के प्रावधान प्रदान किए जा सकते हैं। इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है:—

"धारा 1क की उपधारा (3) में प्रावधान है कि ऐसी व्यवस्था ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें पेड़ों के नुकसान की क्षतिपूत भी शामिल है, जैसा कि केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। केंद्रीय सरकार जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के उपायों सहित नियम और शर्तें निर्धारित करेगी, जो राज्य में अधिकारियों के साथ-साथ उपयोगकर्ता एजेंसी के लिए बाध्यकारी होंगी।"

- 2.4.65 विधेयक के 1क2(क) में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में हितधारकों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां/सुझाव दिए गए थे:—
  - अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए 01 हेक्टेयर की छूट को बढ़ाकर 10 हेक्टेयर किया जाना चाहिए।
  - 01 हेक्टेयर की छूट अनुचित है और इससे पर्यावास संपर्क और जंगली जानवरों के फैलाव/प्रवास में दीर्घकालिक चुनौतियां पैदा होंगी और इसलिए इसे उक्त विधेयक से हटा दिया जाना चाहिए।
  - बसावट, सड़क और रेलवे और 0.10 की छूट शब्द परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट हैं।
  - 0.10 की छूट को उन वन क्षेत्रों को बाहर करने के लिए अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है जो पट्टी रोपण नहीं हैं।
  - विधेयक में सड़क/रेल स्विधाओं से बसावटों की पहंच के लिए छट की व्याख्या नहीं की गई है।

2.4.66 उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नानुसार स्पष्ट किया हैं:—

- "इस विधेयक में प्रस्तावित छूट का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा मंत्रालयों, राज्यों और जनता के साथ परामर्श प्रक्रिया करने के बाद यथा उपयक्त रूप में लिया गया है।
- धारा 1क(2)(क) के तहत विचार की गई वन भूमि के 0.10 हेक्टेयर की छूट, सड़क के किनारे की बस्तियों और प्रतिष्ठानों को संपर्क प्रदान करेगी ताकि विकास की मुख्यधारा के साथ उनका संपर्क सुनिश्चित हो सके।
- नियम और शर्तें, जिनमें सुविधाओं, रणनीतिक सड़कों, सार्वजिनक उपयोगिताओं आदि को परिभाषित करना शामिल है। बाद में, विधेयक की धारा 1 क(3) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- इस संबंध में स्पष्टीकरण, यदि भविष्य में कोई आवश्यकता होती है, तो विधेयक की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों को लागू करके केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।
- संबंधित धारा अर्थात् 1 क(2)(क) के प्रावधान स्पष्ट रूप से 0.1 हेक्टेयर की छूट के उद्देश्य की व्याख्या करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 'सरकार द्वारा बनाए गए रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे स्थित ऐसी वन भूमि, जो प्रत्येक मामले में अधिकतम 0.10 हेक्टेयर के आकार तक बसावट, या ऐसी रेल और सड़क के किनारे की सुविधा तक पहुंच प्रदान करती है।'

इसके अतिरिक्त, उक्त प्रावधानों को उद्देश्यों के ब्योरे में भी स्पष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि विधेयक में छोटे प्रतिष्ठानों, सड़कों और रेलवे के किनारों पर बसावटों तक पहुंच प्रदान करने के लिए भूमि की कुछ श्रेणियों को छूट देने की परिकल्पना की गई है।"

2.4.67 1क(2)(ग)(i) में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में जनता से प्राप्त उनके लिखित ज्ञापनों में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं :—

- (i) "सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए विचार की गई छूट के संबंध में, इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई डाटा नहीं है कि वन मंजूरी ने वन क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को रोक दिया है। ऐसे परिदृश्य में प्रस्तावित संशोधन अतार्किक और मनमाना है।
- (ii) सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा परियोजनाओं और सुरक्षा संबंधी अवसंरचना से संबंधित छूट को हटा दिया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत विचार की गई छूट विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों, वनों, पहाड़ों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट कर देगी, जिससे रेल और सड़कों के किनारे बसावट और प्रजातियों का नुकसान होगा।
- (iii) सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं की छूट के संबंध में, पूर्व में अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र (काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीिक बाघ रिजर्व, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, आदि) के मामले में क्या प्रक्रिया और रुख होना चाहिए। । क्या वन विभाग की राय की आवश्यकता वाले किसी भी अनुमित या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी? ऐसे मामलों में नियंत्रण और संतुलन क्या होगा? क्या यह एक मुफ्त पास होगा? किसी दिए गए क्षेत्र में वन भूमि के ऐसे उपयोग के क्षेत्र पर कोई सीमा या सीमा नहीं है।"

2.4.68 उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

- (i) "जिन रक्षा परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना होता है, उनमें अक्सर अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल लंबी प्रक्रियाओं और प्रलेखन के कारण देरी हो जाती है। रक्षा परियोजनाओं के लिए पूर्व में दी गई अनुमोदनों के विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 8 वर्षों में विपथित किए गए 80,408 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में से केवल 2480 हेक्टेयर वन भूमि को रक्षा परियोजनाओं के लिए विपथित किया गया है, जिसमें सड़कें भी शामिल हैं, जो कुल क्षेत्र का 3% है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान देश के सीमावर्ती राज्यों में सड़कों के लिए विपथित 19305 हेक्टेयर के कुल वन क्षेत्र में से केवल 35% का उपयोग रक्षा सड़क परियोजनाओं के लिए किया गया है। इसके अलावा, ये छूट केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन हैं जिसमें विधेयक में उल्लिखित प्रतिपूरक संरक्षण अनुपालन शामिल होंगे।
- (ii) छूट पर विचार करते समय नियम और शर्तें निर्धारित करने के लिए विधेयक की धारा 1 क(3) के तहत सक्षम प्रावधान प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के तहत विचार की गई छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाए। प्रभाव आकलन, न्यूनीकरण उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां भी आवश्यक हो, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित

- एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छूटों पर विचार करते समय, ऐसे रक्षोपायों को हमेशा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियमों और शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए।
- (iii) प्रस्तावित छूट वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में लागू नहीं होगी। सड़कों/रेलों के लिए निर्माण गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए, क्षेत्र को हरा-भरा करने के अलावा, वनस्पतियों और जीवों के अलावा स्थानीय स्थलाकृतिक व्यवस्थाओं के संरक्षण, सुरक्षा और स्थिरीकरण के लिए अन्य उपाय करना आवश्यक है। निर्माण गतिविधियों के दौरान मौजूदा शमन उपायों का अनुपालन जारी रखा जाएगा। इसलिए, प्रस्तावित विधेयक की धारा 1क की उपधारा (3) में सक्षम प्रावधान किए गए हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसी व्यवस्था ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसमें पेड़ों के नुकसान की प्रतिपूत भी शामिल है, जैसा केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे। छूटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा।"
- 2.4.69 इसके अलावा, जनता से प्राप्त लिखित ज्ञापनों में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई है :—
  - (i) बहुत व्यापक अवधि की सार्वजनिक उपयोगिता जो वस्तुतः वन भूमि पर किसी भी परियोजना के निर्माण की अनुमित देगी।
  - (ii) विधेयक में रेल/सड़क के किनारे की सुविधा, सार्वजनिक उपयोगिता, रणनीतिक परियोजनाओं, सुरक्षा से संबंधित और रक्षा संबंधी परियोजनाओं जैसे शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है।
  - (iii) सामान्य समझ में, 'सड़क के किनारे की सुविधाओं' में पेट्रोल पंप, शौचालय आदि जैसे कई अवसंरचना शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 'राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे सुविधाओं के विकास के लिए नीतिगत दिशानिर्देश' अनिवार्य और अनुमेय सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दिशानिर्देश में फूड कोर्ट/रेस्तरां, 1000 वर्ग फुट क्षेत्र तक स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित क्षेत्र, भूनिर्माण और अन्य को अनिवार्य सुविधा श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्पष्टीकरण में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़क के किनारे सड़क के किनारे सुविधाओं के संबंध में 'सड़क के किनारे की सुविधाओं' का वर्णन किया गया है, जिसमें ढाबा, कारों, बसों और ट्रकों के लिए अलग-अलग पार्किंग, बेंच और टेबल के साथ खुली हवा में आराम क्षेत्र, ड्राइवरों/ट्रक चालकों और अन्य के लिए शयनगृह आदि शामिल हैं। ये सुविधाएं वास्तव में राजमार्गों के साथ टाउनिशप प्रदान करती हैं और ऐसी रैखिक परियोजनाओं के साथ इन सुविधाओं की आवृत्ति के संबंध में विशिष्टताओं की कमी विशाल वन क्षेत्रों को अतिसंवेदनशील बनाती है। इसलिए, विधेयक से धारा 1क(2)(क) को हटा दिया जाना चाहिए।
- 2.4.70 उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं:—
  - (i) मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक उपयोगिताओं को पहले ही विनिर्दिष्ट किया जा चुका है। प्रस्तावित छूटों के तहत सरकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की केवल निर्दिष्ट श्रेणी की अनुमित दी जाएगी। इसके अलावा, ये छूट 10 या 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के विपथन के लिए है, न कि 10 या 5 हेक्टेयर के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए, जैसा कि समझा जा रहा है। इसके अलावा प्रावधान को उपधारा (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि ऐसी छूट केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
  - (ii) नियम और शर्तें, जिनमें सुविधाओं, रणनीतिक सड़कों, सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि को परिभाषित करना शामिल है। बाद में, विधेयक की धारा 1 क(3) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों में सार्वजनिक उपयोगिताओं को पहले ही विनिर्दिष्ट किया जा चुका है।
  - (iii) धारा 1क(2)(क) के तहत विचार की गई वन भूमि के 0.10 हेक्टेयर की छूट, विकास की मुख्यधारा के साथ उनका संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सड़क/रेल किनारे की बस्तियों और प्रतिष्ठानों को संपर्क प्रदान करेगी। स्थानीय अधिकारियों, छुट प्रदान की जाएगी।
    - प्रस्तावित व्यवस्था का उपयोग सड़क और रेलवे के किनारे स्थित सड़क और अन्य सुविधाओं के साथ बस्ती को संपर्क प्रदान करने के लिए किया जाएगा। वितरण का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा अर्थात जहां भी स्थानीय अधिकारियों के आकलन के अनुसार ऐसे संपर्क की आवश्यकता होगी, वहां छूट प्रदान की जाएगी।
- 2.4.71 1क(2)(ख) में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में जनता से निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं :—
  - वृक्षारोपण का बिहिष्करण अनुचित है।
  - गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण की छूट से बहिष्कृत वन भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में खोला जाएगा।

- प्रस्तावित संशोधन राष्टीय वन नीति, 1988 के विरुद्ध है।
- भारत में, सरकार के नियंत्रणाधीन वन क्षेत्रों के अलावा, ऐसे वन क्षेत्र जो निजी लोगों के स्वामित्व में हैं और जिन क्षेत्रों में गैर-वन गतिविधियां/पिरयोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकती हैं। यह विधेयक अब वृक्षारोपण और निर्माण कार्य करने के लिए छूट देने की कोशिश कर रहा है। इन वन क्षेत्रों में वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत। तिमलनाडु में संरिक्षित वन क्षेत्रों और बाघ और हाथी अभयारण्यों में निजी लोगों से संबंधित कई हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध है। यदि उन क्षेत्रों को वन (संरक्षण) अधिनियम के नियंत्रण से छूट दी जाती है, तो इससे उन क्षेत्रों में नकदी फसलों की खेती होगी और पेड़ काटे जाएंगे। जब संरिक्षत वन क्षेत्र के पास या केंद्र में निजी स्वामित्व वाले जंगल में ऐसी गतिविधियां की जाती हैं, तो इससे मिट्टी का क्षरण हो सकता है, और वर्षा के मौसम के दौरान मिट्टी के क्षरण के कारण वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा।
- 2.4.72 उपर्युक्त टिप्पणियों के उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए हैं :—
  - गैर-वन भूमि में अधिनियम की प्रयोज्यता में अस्पष्टता को समाप्त करने और देश के वन आवरण को बढ़ाने और वन संरक्षण और प्रबंधन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।
  - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को भारतीय वन अधिनियम या स्थानीय अधिनियम के तहत हमेशा वनों के रूप में अधिसुचित किया जाता है। अतः, अधिनियम के प्रावधान ऐसी भूमि पर लागू होंगे।
  - विधेयक के प्रावधान राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं। यह ऐसी भूमि पर अधिनियम की गैर-प्रयोज्यता पर स्पष्टता लाकर गैर-वन भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देता है।
  - प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के प्रावधान निजी भूमि में वनीकरण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे देश के हरित आवरण को बढ़ाने और कार्बन तटस्थता, कार्बन सिंक बढ़ाने, बेहतर वन प्रबंधन आदि जैसे वैश्विक मुद्दों का मुकाबला करने में लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। गैर-वन भूमि में वनीकरण को बढ़ावा देने से वनों पर दबाव कम करने के अलावा अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण होगा। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और संशोधन विधेयक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं।

### समिति की टिप्पणी/सिफारिश

2.4.73 सिमिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर/स्पष्टीकरण सिहत खंड में किए गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया और खंड के तहत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

#### खंड 5

### मुल अधिनियम के संगत उपबंध

2.5.1 धारा 2 के मौजूदा उपबंध निम्नानुसार हैं:—

### वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बंधन

- 2.5.2 किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं देगा:
  - i. कि कोई आरक्षित वन (उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में "आरक्षित वन" पद के अर्थ में) या उनका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा:
  - ii. कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए;
- iii. कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को *जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध या नियंत्रण के अधीन नहीं है*, समनुदेनित किया जाए;
- iv. कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग से पुनर्वनरोपण के लिए उनका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वृक्षों को, जो उन भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं. काट कर साफ किया जाए।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए वनेतर प्रयोजन में:—

(क) चाय, काफी, मसाले, रबड़, पाम तेल वाले पौधे, उद्यान कृषिलो वा यौधे की खेती के लिए;

(ख) पुनर्वनरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए;

किसी वन भूमि या उसके प्रभाग को तोड़ना वा काट कर साफ करना अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत वनों और वन्य-जीवों के संरक्षण विकास और प्रबंध से संबंधित या उनमें आनुषंगिक कोई कार्य अर्थात्, चौिकयों, अनि लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाड़ पुल और पुलियों, बांधों, वाटरहोल्, खाई चिह्नों, सीमा चिह्नों पाइप लाइनों का निर्माण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं है।

### संशोधन विधेयक में प्रस्तावित उपबंध

### 2.5.3 अधिनियम की धारा 2 का संशोधन

मूल अधिनियम में, धारा 2 में,—

- (क) उक्त धारा को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-धारा (1) में—
- (I) खंड (iii) में, "सरकार के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (II) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के पश्चात आने वाली लंबी पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"र्कितु इसके अंतर्गत वनों और वन्य-जीवों के संरक्षण विकास और प्रबंध से संबंधित या उनमें आनुषंगिक कोई कार्य शामिल नहीं है, जैसे कि :–

- (i) पुनर्जनन कार्यों सहित वनसंवर्धन कार्य;
- (ii) फ्रंट लाइन वन कर्मचारियों के लिए चौकियों और बुनियादी ढांचे की स्थापना;
- (iii) अग्नि लाइनों की स्थापना और रखरखाव;
- (iv) वायरलेस संचार;
- (v) बाड़, सीमा चिह्न या खंभे, पुल और पुलिया, चेक डैम, वाटरहोल, खाई और पाइपलाइनों का निर्माण;
- (vi) संरक्षित क्षेत्रों से भिन्न अन्य वन क्षेत्रों में, सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 में बताए गए चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना;
- (vii) वन कार्य योजना या वन्यजीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या उस क्षेत्र की कार्य योजना में शामिल पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधा; और
- (viii) कोई अन्य ऐसे प्रयोजन, जो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।":

# 2.5.4 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण/औचित्य

- 1. अधिनियम की धारा 2(iii) के मौजूदा उपबंध, जो पट्टे पर वन भूमि के समनुदेशन से संबंधित हैं, सरकारी सत्ताओं पर लागू नहीं होते। इसलिए एकरूपता लाने के लिए धारा 2(iii) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- 2. 'वनेतर प्रयोजन' पद को अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण को उन कार्यकलापों को शामिल करने के मामले के लिए विस्तृत बनाया गया है जो वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए किए जाते हैं।

#### समिति द्वारा जांच

2.5.5 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को विधेयक पर अपनी ब्रीफिंग के दौरान प्रमुख अधिनियम की धारा 2 के खंड (iii) में किए गए प्रावधान को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लिखित टिप्पण में निम्नानुसार बताया: –

"वर्ष 1988 में, धारा 2 की प्रस्तावित उपधारा (1) के खंड (iii) को वाणिज्यिक वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए निजी संस्थाओं को पट्टे पर वन भूमि के समनुदेशन को विनियमित करने के लिए अंत:स्थापित किया गया था। उक्त उप-धारा के उपबंध सरकारी सत्ताओं पर लागू नहीं किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एकरूपता का अभाव है। अतः, उपबंधों में एकरूपता लाने के लिए अधिनियम की धारा 2 की प्रस्तावित उप-धारा (1) के खंड (iii) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।"

2.5.6 विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान, आगे यह बताया गया कि प्रस्तावित विधेयक में उल्लेख किया गया है कि वन भूमि पर चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना से वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और वन पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला और खाद्य चक्र प्रणाली बाधित होगी जिससे वन खराब हो जाएंगे। इस संबंध में सुझाव है कि गैर वन भूमि पर चिड़ियाघर और सफारी स्थापित की जानी चाहिए, ताकि जनजाति लोग परेशान न हों।

- 2.5.7 इसके अलावा, जनता से प्राप्त लिखित ज्ञापनों में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:—
- (क) चिड़ियाघरों और सफारी को छूट देने से वन क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा और सड़क नेटवर्क बन सकता है।
- (ख) चिड़ियाघरों और सफ़ारी को अब वानिकी गतिविधि के रूप में माना जा रहा है, यह असंगत पृष्ठभूमि पर आधारित है कि यह वन और वन्यजीवों के संरक्षण का सहायक है।
- (ग) गैर-वन गतिविधियों के दायरे में चिड़ियाघरों और सफ़ारियों को अनुमित देने से वन परिनर्भर रहने वाले लोगों, वन्यजीव आवासों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अधिकारों पर विचार किए बिना वनों और वन्यजीवों का असंगत रूप से व्यावसायीकरण हो सकता है।
- (घ) वन संवर्धन गतिविधियों, चिड़ियाघर, इकोटूरिज्म और इसी तरह के उद्देश्यों जैसी वानिकी गतिविधियों को शामिल करने के प्रावधान अस्पष्ट हैं और अतिविचित्र हैं।
- (ङ) ऐसे समय में जब चिड़ियाघर, इको-टूरिज्म और सफारी का निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, यह संशोधन केवल निजी निगमों के हित में होगा।
- (च) इकोटूरिज्म सुविधाओं, चिड़ियाघरों और सफारी और बुनियादी ढांचे के नाम पर प्रतिष्ठान देशी वनस्पति और वन्यजीव आवास पर बनाए जाते हैं।
- (छ) चिड़ियाघर और सफारी को वानिकी गतिविधियों के रूप में शामिल करना वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए एक अलग तरीका है।
- (ज) विधेयक को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों को बहिष्कृत संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था के तहत जंगल की बढ़ती मात्रा को अपने दायरे से हटाना चाहिए और इकोटूरिज्म के माध्यम से छोटे वैश्विक लेजरयुक्त वर्ग की बढ़ती खर्च आय पर लार टपकाने का विरोध करना चाहिए, भले ही यह अफ्रीकी जंगली से वन्यजीवों को उनके देखने के आनंद के लिए आयात करके हो।
- (झ) विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों से संभवतः वाणिज्यिक पारिस्थितिकी की एक नई प्रणाली तैयार होगी जो संरक्षण और टिकाऊ भविष्य में निवेश करने के बजाय कॉर्पोरेट उद्यम को पूरा करेगी।
- (ञ) भारत में 2019 से कुछ निजी संस्थाओं ने चिड़ियाघरों की स्थापना शुरू कर दी है और बाद में 2020 में केंद्रीय पर्यावरण और वन विभाग ने कई चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए निजी लोगों के साथ समझौता किया है। इस प्रकार, इस बात का खतरा है कि अधिनियम में इस संशोधन के माध्यम से, चिड़ियाघरों और वन्य जीवन/ईको-टूरिज़्म को समझौते के माध्यम से निजी संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा जो जंगल की प्रकृति को खराब कर देगा।
- 2.5.8 उपरोक्त टिप्पणियों पर अपने लिखित स्पष्टीकरण में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नवत कहा:—
  - "चिड़ियाघर और सफारी एक गतिविधि है जो वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए सहायक है। राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार चिड़ियाघर और सफारी स्थापित किए जाएंगे। इसलिए, यह वनों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा नहीं देता है। इसी प्रकार, अनुमोदित कार्य योजना अथवा वन्यजीव प्रबंधन योजना अथवा बाघ संरक्षण योजना के अनुसार वन क्षेत्रों में ईको-टूरिज़्म शुरू किया जाएगा। वन क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं स्थानीय आबादी की मनोरंजक और सौंदर्य संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के अलावा, वन भूमि और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा करती हैं। ऐसी सुविधाएं आम तौर पर अधिवास के निकट बनाई जाती हैं ताकि वन पारिस्थितिकी तंत्र में न्युनतम गड़बड़ी सुनिश्चित की जा सके। जंगलों में चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना से लोगों को संवेदनशील बनाने के अलावा, स्थानीय समुदायों की आजीविका के स्रोतों में भी वृद्धि होगी और इस तरह उन्हें विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। विधेयक की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने और इन गतिविधियों से दुरुपयोग, यदि कोई रिपोर्ट की गई है, को रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए किया जाएगा। जंगलों में प्राकृतिक खतरों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और प्रभावी वन प्रबंधन की सुविधा के लिए, विधेयक में वन फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचे के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के साथ-साथ संशोधन विधेयक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अलावा, चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी। विधेयक के कोई भी प्रावधान वनों में कारपोरेट उद्यमों को बढ़ावा नहीं देते हैं। सरकारी संस्थाओं के लिए सभी छुटों पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, विधेयक में

शामिल नई वानिकी गतिविधियां पहले से ही दिशानिर्देशों के माध्यम से लागू थीं और ऐसी गतिविधियों जैसे इको-टूरिज़्म, चिड़ियाघर और सफारी को सरकारी विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा।."

2.5.9 इसके अलावा, ब्रीफिंग बैठक के दौरान, यह सुझाव दिया गया कि राजस्थान जैसे राज्यों में ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों को छूट दी जानी चाहिए, जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड में रखा गया है जो वन भूमि में भी हैं। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नानुसार कहा है: –

"विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, 'इको-टूरिज़्म' को वानिकी गतिविधियों की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए, वन भूमि में स्थित स्मारक, जो प्रकृति के पर्यटन का आंतरिक हिस्सा हैं, को भी पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया जाए।

2.5.10 विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान, यह भी बताया गया कि अधिनियम की धारा 2 के खंड 5 के तहत, चिड़ियाघरों, सफारी और इकोटूरिज्म सुविधाओं को शामिल करना संभावित रूप से विनाशकारी हो सकता है और देशी वनस्पति और वन्यजीव आवास पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि स्थानिक प्रजातियां हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें संरक्षित किया जाना है। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नवत कहा है: –

"विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान न तो किसी अन्य कानून का उल्लंघन करते हैं और न ही वन्यजीवों सहित वनों के संरक्षण को बाधित करते हैं।"

- 2.5.11 ब्रीफिंग के दौरान यह भी देखा गया कि कई आदिम जनजातियाँ और जनजातीय लोग हैं, वे वनों पर निर्भर हैं। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान भी होना चाहिए ताकि जो लोग वनों पर निर्भर हैं उनकी जीवन स्थितियों में सुधार हो सके।
- 2.5.12 विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान, यह भी देखा गया कि प्रस्तावित शर्तें जैसे कि इको-टूरिज्म सुविधा भूमि और गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जंगल जनजातियों के आजीविका का साधन है। अधिनियम की वर्तमान स्थिति में पुलिया और सड़क बनाने में समस्या आ रही है, इसे सरल बनाया जाए ताकि गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा हो सके।
- 2.5.13 उपरोक्त टिप्पणियों के उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नवत कहा:—

"इसके अलावा, विधेयक में ईको-टूरिज़्म, चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना आदि जैसी गतिविधियों को वानिकी कार्यकलापों के रूप में शामिल किया गया है। इस तरह की सुविधाएं, वन भूमि और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में संवेदनशील और जागरूकता पैदा करने के अलावा, स्थानीय समुदायों की आजीविका के स्रोतों को भी जोड़ेंगी और इस तरह उन्हें विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के अवसर प्रदान करेंगी। वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित प्रावधान अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सिहत अन्य समानांतर कानूनों के संचालन पर रोक या उल्लंघन नहीं करते हैं।"

2.5.14 निम्नलिखित विवरण में सदस्यों से लिखित रूप में प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर को दर्शाया गया है:—

सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियाँ	नोडल मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर
"औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों के पुनर्जनन और खेती" को वानिकी उद्देश्य के रूप में माना जाए और तदनुसार इस पैरा में मदबद्ध उप-पैरा में अन्तःस्थापित किया जाए। [पैरा 5(क)(॥)]	अधिनियम की धारा 2 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (i) में पुनर्जनन गितविधियों के प्रावधान पहले से ही शामिल किए गए हैं।  मूल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार चाय, कॉफी, मसाले, रबर, ताड़, तेल वाले पौधे, बागवानी फसलें या औषधीय पौधों की खेती जैसी गितविधियों को गैर-वानिकी गितविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये गितविधियाँ व्यावसायिक और गैर-स्थलविशिष्ट हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते प्रवाह के लिए वनों की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वन भूमि में ऐसी गितिविधियों की अनुमित नहीं है। इसके अलावा, ऐसी गितविधियाँ राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं जो खेती के लिए वन भूमि के उपयोग को हतोत्साहित करती हैं।
प्रस्तावित विधेयक में 'वन', 'सार्वजनिक उपयोगिता', 'ईको-टूरिज़्म सुविधाएं' और 'किसी भी अन्य उद्देश्य'	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ वन शब्द को विधेयक की धारा 1क में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, इस खंड में 'सार्वजनिक उपयोगिता', 'ईको-टूरिज़्म सुविधाएं' और 'किसी भी अन्य उद्देश्य' जैसे

सहित उपयोग किए गए सभी शब्दों को गलत व्याख्या से बचने के लिए परिभाषित करने की आवश्यकता है।

वनों का उपयोग "केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य उद्देश्यों" के लिए करने की अनुमित देने निर्णय। अस्पष्ट रूप से परिभाषित यह शब्द संभावित रूप से लौकिक बाढ़ के द्वार खोल सकता है, जिससे जंगलों को खदान से मॉल और बीच में किसी भी उद्देश्य के लिए मोड़ने का रास्ता आसान हो सकता है।

प्राचीन क्षेत्रों को अक्षुण्ण रखने और एक विशिष्ट अविध के लिए विपथन के अधीन न करने के प्रस्ताव की भी बहुत आवश्यकता है। हालांकि, ऐसे क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए और पीईएसए, एफआरए और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों के सीमांकन का मतलब यह नहीं होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों के सीमांकन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों को अलग नहीं किया गया है, उन्हें अधिक आसानी से मोड़ दिया जाएगा। यदि वनों के डायवर्जन की प्रक्रिया में ढील दी जाती है और सहमति के खंडों सहित वन मंजूरी की कठोर प्रक्रिया को सभी मौजूदा वन क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जाता है, तो देश की पारिस्थितिक सुरक्षा से अत्यिधक समझौता होगा।

वन भूमि पर खोजपूर्ण ड्रिलिंग और सर्वेक्षण गतिविधियों की छूट खतरनाक मिसाल है। यह हवा, पानी और भूमि की गुणवत्ता पर कई सिद्ध प्रभाव डालता है और वन्यजीवों के लिए गंभीर अशांति का कारण बनता है। शब्द भविष्य में विधेयक की धारा 1 क (3) और धारा 6 के प्रावधानों को लागू करते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट/परिभाषित किए जाएंगे।

वाक्यांश "...कोई अन्य समान उद्देश्य" पहले से ही मूल अधिनियम में मौजूद है।

विधेयक के प्रावधान वन अधिकार अधिनियम, 2006, पीईएसए या एलएआरआर अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन या उन्हें निरस्त नहीं करते हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत एसटी और ओटीएफडी की सहमति सहित इन कानूनों में परिकल्पित प्रक्रियाएं प्रस्तावित संशोधन द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं हैं।

इसके अलावा, नियम 9(6) (ख) (ii) के तहत दिए गए प्रावधान यह अधिदेशित करते हैं कि उपयोगकर्ता एजेंसी को भूमि सौंपने से पहले राज्य द्वारा एफआरए, 2006 का अनुपालन पूरा किया जाता है।

वन क्षेत्र में जांच, पैमाइश आदि जैसी सर्वेक्षण गतिविधियां अस्थायी होती हैं और इसके परिणामस्वरूप वन वनस्पित में या भूमि के टूटने में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। विधेयक के तहत विचार की गई छूट केवल सर्वेक्षण और जांच तक सीमित है, इसके परिणामस्वरूप वन भूमि का डायवर्जन नहीं होगा जिसके लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। इसके अलावा, हाइड्रोकार्बन के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग जिसमें वन भूमि के भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन शामिल है, विधेयक में प्रस्तावित छूट के अंतर्गत शामिल नहीं है।

केंद्र सरकार वन भूमि में सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा पालन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित करेगी। विधेयक के प्रावधान वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों में लागु नहीं होंगे।

# विभिन्न हितधारकों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

### जनजातीय कार्य मंत्रालय

2.5.15 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक व्यावृत्ति खंड यथा "एफआरए के तहत एफडीएसटी और ओटीएफडी को गारंटीकृत अधिकार संरक्षित रहेंगे" अन्तःस्थापित करने पर विचार करे"

### छत्तीसगढ़ सरकार

2.5.16 छत्तीसगढ़ सरकार ने मूल अधिनियम की धारा 2(iii) के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं—

"िकसी पट्टे विशेष के लिए सम्बंधित राज्य सरकार से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अध्याधीन किसी भी वन क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को किसी व्यक्ति या अधिकारी, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संगठन को पट्टे पर दिया जा सकता है"

# 2.5.17 सिक्किम सरकार

राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय के उत्तर/टिप्पणी
वन क्षेत्रों में 'किसी प्राधिकरण' के स्वामित्व वाले चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना से संबंधित उप-खंड (vi) स्पष्ट नहीं है और पूरी संभावना है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। 'किसी अन्य प्राधिकरण के स्वामित्व वाले' चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना के संदर्भ में स्पष्टता होना आवश्यक है। इस संशोधन में 'किसी अन्य प्राधिकरण' के स्वामित्व वाले चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया या तंत्र प्रदान किया जा सकता है।	चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना आदि जैसी गितिविधियाँ सरकार के स्वामित्व में होंगी और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार स्थापित की जाएगी। इसलिए, इससे वनों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसी प्रकार, अनुमोदित कार्य योजना अथवा वन्यजीव प्रबंधन योजना अथवा बाघ संरक्षण योजना के अनुसार
	वन क्षेत्रों में ईको-पर्यटन शुरू किया जाएगा।  ये सुविधाएं आम तौर पर वन पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूनतम गड़बड़ी सुनिश्चित करने के लिए आवास स्थान के समीप बनाई जाती हैं, ऐसी सुविधाएं, वन भूमि और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में संवेदनशील और जागरूकता पैदा करने के अलावा, स्थानीय समुदायों के आजीविका स्रोतों को भी इनसे जोड़ेंगी और इस प्रकार उन्हें विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के अवसर प्रदान करेंगी। इस संबंध में दिशा- निर्देश पहले से ही मौजूद हैं।
	विधेयक के खंड 6 के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और संशोधन विधेयक, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं।
ईको-पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों की विस्तृत प्रकृति और इनमें विभिन्न प्रकार जिन्हें अनुमति दी जानी है और चिड़ियाघरों और सफारी के विकास के लिए क्षेत्र की अधिकतम सीमा का विवरण देने की आवश्यकता है।	इस संबंध में दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। तथापि, यदि भविष्य में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो वह केन्द्र सरकार द्वारा विधेयक के खंड 6 के उपबंधों को लागू करके प्रदान किया जाएगा।

# 2.5.18 <u>मिजोरम सरकार</u>

राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव	नोडल मंत्रालय के उत्तर/टिप्पणी
5. 5. (क)(I) : केंद्र सरकार को सभी शक्तियां देना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन समवर्ती सूची का विषय है।	समय निबंधन एवं शर्ते निर्धारित करना है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अंतर्गत विचारित छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित की जाए। प्रभाव आकलन, निवारक उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां भी आवश्यक हो, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा
	राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छूटों पर विचार करते समय, उक्त सुरक्षा उपायों को सदैव केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों में शामिल किया जाएगा।

धारा 2 (तीन) के अंतर्गत प्रस्तावित उपबंध सामान्य शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित करने वाली विशिष्ट शक्तियां हैं, जो केवल वन भिम को पट्टे पर देने के सीमित उद्देश्य के लिए है. न कि वन भिम के अन्यत्र उपयोग के लिए है। ये उपबंध वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। स्पष्टीकरण के खंड (आठ) के अंतर्गत दिए गए उपबंध "..किसी अन्य सामान्य उद्देश्य जोकि.."मूल अधिनियम में पहले से ही विद्यमान हैं। विधेयक की धारा 5(2) के अंतर्गत प्रदत्त उपबंध वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए विशिष्ट हैं और ये केन्द्र सरकार को वन भूमि का सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और संबंधित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले कतिपय निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनातें हैं। विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त उपबंधों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के वैध उपयोग को सनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। विभिन्न वानिकी प्रबंधन कार्यकलापों को करने और वनों में त्वरित प्राकृतिक 6. 5. (क) (II): कार्यकलापों को विनिर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती खतरों से निपटने के लिए, वन भूमि में अवसंरचना सम्बंधित मूलभूत सुविधाओं है। इसमें केवल इतना बताया जाना चाहिए को बनाए रखना आवश्यक है। अधिनियम में सक्षमकारी उपबंधों के अभाव के कि "वन संरक्षण, विकास और वनों और कारण, वन क्षेत्र में ऐसी मूलभूत अवसंरचना का सृजन करना कठिन है जिससे वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए सहायक कोई भी वानिकी प्रचालनों, पुनरूद्धार कार्यकलापों, निगरानी और पर्यवेक्षण, वनों में लगने कार्यकलाप"। इसके अतिरिक्त, किसी भी वाली आग की रोकथाम आदि पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, स्थानीय मामले से संबंधित सभी शक्तियां केंद्र सरकार समुदायों द्वारा वनों की समुचित सुरक्षा और संरक्षण के लिए आजीविका के के पास निहित नहीं होंगी क्योंकि वन समवर्ती अवसरों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है जिसे इको-पर्यटन, चिड़ियाघरों सुची का विषय है और राज्यों में सभी वन और सफारी के संवर्धन के माध्यम से प्रभावी ढंग से सक्षम बनाया जा सकता है। केवल राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं। इसलिए, इस उप-धारा के अंतर्गत वानिकी प्रबंधन में सहायक कार्यकलापों को स्पष्ट किया गया है। 'स्पष्टीकरण' शब्द को ऐसे कार्यकलापों को शामिल करने के लिए विस्तार से स्पष्ट किया गया है जो वन और वन्य जीवन के संरक्षण के प्रयोजन से आरम्भ किये जाते हैं।

#### 2.5.19 मेघालय सरकार

### राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव

1. विधेयक की धारा 5 के स्पष्टीकरण के तहत दिए गए खंड (viii) के संबंध में, अर्थात् "कोई अन्य ऐसे प्रयोजन जिन्हें केंद्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।" राज्य सरकार से उन मामलों पर भी परामर्श किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के विषयों पर निर्भर करते हैं।

#### नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी

विधेयक की धारा 5 में प्रस्तावित उपबंध "ऐसे अन्य प्रयोजन, जिन्हें केन्द्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे", मूल अधिनियम में पहले से ही विद्यमान हैं और वनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित नीतियों में गतिशील बदलावों को ध्यान में रखते हुए इन्हें और सुदृढ़ किया गया है।

भविष्य में जब कभी स्पष्टीकरण के खंड (viii) या विधेयक के अन्य समान उपबंधों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावी किया जाएगा, तो आवश्यकता के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पूर्व परामर्श किया जाएगा।

#### 2.5.20 हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य सरकार का सुझाव

विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि वन कार्य योजना अथवा
वन्यजीव प्रबंधन योजना अथवा बाघ संरक्षण योजना अथवा
उस क्षेत्र की कार्य योजना में शामिल इको-पर्यटन सुविधाओं को

गैर-वानिकी प्रयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा। यह सुझाव

### नोडल मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर

इस संबंध में दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। तथापि, यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो केन्द्र सरकार द्वारा विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त उपबंधों के अनुसार और स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। दिया जाता है कि बेहतर स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए अधिनियम में इको-पर्यटन को परिभाषित किया जाए।

### विशेषज्ञों/जनता द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

2.5.21 समिति को सौंपे गए ज्ञापन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने निम्नलिखित सुझाव दिया हैं:—

"विधेयक के खंड 5 (II) (vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए – "संरक्षित क्षेत्रों के सिवाय वन क्षेत्रों में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संदर्भित, सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाले चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना।

विधेयक के खंड 5 (II) (vii) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए - "स्पष्टीकरण: वन क्षेत्र में 'इको- पर्यटन सुविधाओं' में विनियमित इको- पर्यटन के प्रयोजनार्थ आधारभूत अवसंरचना शामिल हैं जैसे कि बिना तारकोल वाले और बिना – कंक्रीट वाले मार्ग, आगंतुकों और इको- पर्यटन प्रबंधकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए अस्थायी ठहराव और प्रकृति प्रेक्षण झोपड़ियां, लेकिन इसमें पर्यटकों के लिए आवासीय स्थान, होटल परिसर, हवाई पट्टियां और कंक्रीट संरचनाएं, जो स्थल के मुल वन / प्राकृतिक वातावरण को बदल देती हैं, शामिल नहीं है।"

2.5.22 समिति के समक्ष अपनी उपस्थिति के दौरान, एक विशेषज्ञ ने कहा, "मुझे लगता है, वन भूमि पर चिड़ियाघर और सफारी की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए। वनों में इको-पर्यटन के नाम पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नानुसार उत्तर दिया है—

"दूसरा मुद्दा चिड़ियाघरों, सफारी और इको – टूरिज्म संबंधी सुविधाओं के बारे में उठाया गया। मैं माननीय समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि हम एफसी अधिनियम पर बात कर रहे हैं तो उन्हें दो बार सरकार की स्वीकृति मिल रही थी। किसी भी चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना के लिए, भारत सरकार की पूर्व अनुमित की आवश्यकता होती है क्योंकि वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा शासित होते हैं। फिर वे एफसी अधिनियम के तहत अनुमित की मांग कर रहे हैं। व्यापार में सुगमता के लिए, यदि उन्हें सीजेडए की अनुमित मिल रही है, तो हमें उन्हें फिर से आने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी। उनका उपयोग केवल उस कार्यकलाप के लिए किया जाना है जो सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा की जाती है। फिर इको-टूरिज्म संबंधी कार्यकलापों के संबंध में, यदि हम भाषा पढ़ें, तो इको-टूरिज्म सुविधाओं को वन कार्य योजना या वन्यजीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। मैं समिति को यह बताना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश के द्वारा कहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही इन क्षेत्रों का प्रबंधन कार्य-योजना अथवा वन्यजीव प्रबंधन योजना द्वारा किया जाएगा। इसलिए, हमारे आईआरओ जो 11 क्षेत्रों में तैनात हैं, उस विशेष क्षेत्र की कार्य योजना और प्रबंधन योजना को मंजूरी देते हैं। यदि इको-टूरिज्म सुविधा उस कार्य योजना का हिस्सा है, तो केवल उन्हें अनुमित दी जाएगी और एफसी अधिनियम के अंतर्गत अनुमित की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। अतः, यह सही नहीं है कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। भारत सरकार पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बहुत चिंतित है और हम वह सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं।"

- 2.5.23 इको-पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:—
  - (i) इको टूरिज्म के परिणामस्वरूप वन क्षेत्रों और वन्यजीवों का विनाश हो सकता है।
  - (ii) खंड 5 (क) (II) (vii) में इको टूरिज्म को वानिकी कार्यकलाप मानने का भी प्रावधान है। होटल, सड़क, हवाई पट्टी और अन्य वाणिज्यिक निर्माण जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बढ़ने से रोकने के लिए 'सुविधाओं' शब्द को विस्तार से समझने की आवश्यकता है।"
  - (iii) इको टूरिज्म संबंधी सुविधाओं के सूजन के लिए वन भूमि में निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- 2.5.24 पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में एक लिखित नोट में निम्नलिखित बात स्पष्ट की है: -

"विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत प्रदान किए गए सक्षमकारी उपबंधों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। 'सुविधाएं' शब्द को सक्षमकारी खंड के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा।"

2.5.25 एक लिखित ज्ञापन में दो हितधारकों ने सुझाव दिया, "सर्वेक्षण और जांच से संबंधित खंड 5 के खंड (ख) में, वाक्यांश "... जिसमें ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग सहित जंगल को साफ करना या पेड़ों को काटना या सड़कों या रास्तों का निर्माण शामिल नहीं है ..." जोड़ा जाना चाहिए। उपर्युक्त सुझाव के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर प्रस्तुत किया:—

"इस धारा में उल्लिखित निबंधन और शर्तों को लागू करने के उपबंधों को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा और आवश्यकतानुसार उपशमन उपायों सहित अतिरिक्त एहतियाती शर्तों को निर्धारित किया जाएगा।"

2.5.26 एक हितधारक द्वारा यह भी टिप्पणी किया गया कि विधेयक की धारा 5 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत उल्लिखित कार्यकलापों का वन्यजीव की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह अधिक मानव हस्तक्षेप और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करेगा और मानव गतिविधियों से पशुओं के वास स्थान अस्त व्यस्त होंगे। उपर्युक्त टिप्पणी के लिखित उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया है:—

"विभिन्न वानिकी प्रबंधन कार्यकलापों को करने और जंगलों में त्वरित प्राकृतिक खतरों का जवाब देने के लिए, वन भूमि में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बनाए रखना आवश्यक है। अधिनियम में सक्षम प्रावधानों के अभाव के कारण, वन क्षेत्र में ऐसी बुनियादी अवसंरचना का सृजन करना किठन है जिससे फॉरेस्ट्री ऑपरेशन्स, पुनरूद्धार कार्यकलाप, निगरानी और पर्यवेक्षण, वनों की आग की रोकथाम आदि प्रभावित होती है। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों द्वारा वनों की उचित सुरक्षा और संरक्षण के लिए आजीविका के अवसरों की आवश्यकता होती है जिसे वन क्षेत्रों में इको-पर्यटन, चिडियाघरों और सफारी को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रभावी ढंग से सक्षम बनाया जा सकता है।"

- 2.5.27 इसके अलावा, हितधारकों ने लिखित ज्ञापनों में निम्नलिखित बातें कही हैं:
  - (i) किसी भी सर्वेक्षण, सैन्य सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, जांच, अन्वेषण और भूकंपीय सर्वेक्षण को छूट देने से वनों और वन्यजीव वास पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं में पेड़ों को काट दिया जाता है और उपकरणों के परिवहन के लिए अस्थायी सड़कों का निर्माण किया जाता है।
  - (ii) विधेयक में प्रस्तावित सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए विचार की गई छूट से हमारे सभी वनों में खनन और इसी तरह की वाणिज्यिक गतिविधियां आरंभ हों जाएंगी।
  - (iii) सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए छूट मनमानी हैं और अंतर्निहित परियोजना और वन तथा संबंधित वन्यजीवों पर इसके प्रभाव पर निर्भर होना चाहिए। हाल ही में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जैव विविधता प्रभाव आकलन के नहीं होने के कारण डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में सात स्थानों पर हाइड्रोकार्बन के लिए विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग के माध्यम से अन्वेषण और ड्रिलिंग के संबंध में ऑयल इंडिया लिमिटेड को पर्यावरण मंजूरी पर रोक लगा दी।
- 2.5.28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लिखित रूप में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—

"वन क्षेत्र में सर्वेक्षण गतिविधियाँ जैसे जांच, टोही आदि प्रकृति में अस्थायी स्वरुप की हैं और इसके परिणामस्वरूप वन वनस्पति में या वन क्षेत्रों में कमी नहीं होती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार वन भूमि में सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा पालन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित करेगी। इसके अलावा, ये छूट वाले उपबंध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में लागू नहीं होंगे।"

2.5.29 जनता के एक लिखित ज्ञापन में यह पाया कि वन संवर्धन गतिविधियों को वन संबंधी गतिविधियों के रूप में माना जाना प्रस्तावित है, हालांकि इसमें वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पेड़ों की कटाई शामिल है। इस प्रेक्षण के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में स्पष्ट किया है कि वनों से पारितंत्र वस्तुओं और सेवाओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता और प्रवाह को बनाए रखने के लिए वनसंवर्धन प्रचालन किए जाते हैं।

### प्रधान अधिनियम के प्रासंगिक उपबंध

2.5.30 लागू नहीं (अधिनियम में उपबंध मौजूद नहीं हैं)।

#### संशोधन विधेयक में प्रस्तावित उपबंध

2.5.31 **(ख)** उपधारा (1) के बाद, जैसा कि इस प्रकार पुनर्संख्यांकन किया गया है, निम्नलिखित उप-धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातु:—

"(*2)* केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके अधीन भूकंपीय सर्वेक्षण सहित कोई सर्वेक्षण, जैसे टोही, पुर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण को गैर-वन उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाएगा।

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण/औचित्य

2.5.32 यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें वन वनस्पति में कोई बोधगम्य परिवर्तन नहीं होता है।

#### समिति द्वारा की गई जांच

### विभिन्न हितधारकों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

#### <u>छत्तीसगढ़ सरकार</u>

2.5.33 छत्तीसगढ़ सरकार ने उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं -

"केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के बाद नियम और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसके अधीन भूकंपीय सर्वेक्षण सहित कोई सर्वेक्षण, जैसे टोही, पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण को गैर-वन उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाएगा।"

### विशेषज्ञों/जनता के महत्वपूर्ण सुझाव

2.5.34 एक हितधारक ने समिति को सौंपे गए एक लिखित ज्ञापन में कहा कि विधेयक का उद्देश्य भूकंपीय सर्वेक्षण सहित सर्वेक्षण, टोही, पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण जैसी गैर-वन गतिविधियों की परिभाषा को भी सीमित करना है, जिसके लिए वर्तमान में वन मंजूरी की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त अवलोकन के लिखित स्पष्टीकरण में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा है:—

"वन क्षेत्र में जांच, टोही आदि जैसी सर्वेक्षण गतिविधियाँ प्रकृति में अस्थायी स्वरुप की हैं और इसके परिणामस्वरूप वन वनस्पति में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है या वन क्षेत्रों में कमी नहीं होती है। केंद्र सरकार वन भूमि में सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नियम और शर्तें निर्धारित करेगी।"

- 2.5.35 इसके आगे हितधारकों द्वारा लिखित ज्ञापनों में निम्नानुसार पाया गया:-
  - (i) धारा 2 (iii) का संशोधन केंद्र सरकार को नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है।
  - (ii) केन्द्र सरकार को बिना किसी सुरक्षोपाय के उन नियमों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देना जिनके अधीन भूकंपीय सर्वेक्षण सहित किसी भी सर्वेक्षण, जैसे टोही, पूर्वेक्षण, अन्वेषण या अन्वेषण को गैर-वन उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाएगा।
  - (iii) उपभाग (1) (iii) 'सरकार के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं' शब्दों के स्थान पर ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें केन्द्र सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, यह निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि करता है कि किन भूमियों का अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है या उन्हें पट्टे पर दिया जा सकता है। इस प्रकार, राज्य सरकारों या वन अधिकारियों या स्थानीय समुदायों की संरक्षण चिंताएं जो ऐसी भूमि का प्रबंधन करती हैं, इस तरह के निर्णय लेने में अप्रासंगिक हो जाएंगी।
  - (iv) विधेयक को भविष्य में तनुकृत किए जाने का रास्ता खुला रखने हेतु यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार ऐसे नियम और शर्तें ला सकती है जिनके अधीन सर्वेक्षण और अन्वेषण को गैर-वनीय उद्देश्य नहीं माना जाएगा।
  - (v) वनों की शुचिता बनाए रखने के लिए वनों को किसी निजी व्यक्ति अथवा किसी अन्य एजेंसी (सरकारी, गैर-सरकारी या निजी) को पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए।
  - (vi) एफआरए, 2006 के उपबंधों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
  - 2.5.36 इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है:—
  - (एक) उक्त धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित शक्तियां सामान्य शक्तियां नहीं हैं बल्कि निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने हेतु विशिष्ट शक्तियां हैं जो वन भूमि को पट्टे पर सौंपने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं, न कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों हेतु हैं।
  - (दो) इसके अतिरिक्त, उपबंधों में सरकारी संस्थाओं को पट्टे पर वन भूमि के आवंटन के उद्देश्य से अधिनियम के दायरे में शामिल करके एकरूपता लाने का प्रस्ताव है, जो अब तक केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना किया जा सकता था।
  - (तीन) विधेयक की धारा 5(ख) के अंतर्गत किए गए उपबंध वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण हेतु विशिष्ट हैं और केन्द्र सरकार को वन भूमि में सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और संबध्द प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले कतिपय निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।
  - (चार) उपबंध 1988 में लागू किए गए थे और अब सरकारी कंपनियों को भी विनियमन के अंतर्गत लाने हेतु इन्हें उन पर लागू किया जा रहा है।
  - (पांच) चूंकि इस धारा के उपबंधों में वन भूमि का व्यपवर्तन शामिल नहीं है, इसलिए यह वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उपबंधों का खंडन नहीं होगा। तथापि, संबद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्राधिकारी वन भूमि को पट्टे पर आवंटित करने से पहले एफआरए, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

#### समिति द्वारा टिप्पणी/सिफारिश

2.5.37 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर/स्पष्टीकरण सहित खंड में किए गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

#### खंड 6

### मुल अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

2.6.1 प्रयोज्य नहीं है (अधिनियम में प्रावधान मौजूद नहीं हैं)।

### संशोधन विधेयक में प्रस्तावित उपबंध

2.6.2 मूल अधिनियम में, धारा 3ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतर्विष्ट की जाएगी, अर्थात्:—

**"3ग.** केन्द्र सरकार, समय-समय पर, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र के अधीन किसी प्राधिकारी अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संगठन, संस्था या निकाय को, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगी।"

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण/औचित्य

2.6.3 अब तक निदेश जारी करने की शक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न आदेशों अथवा जैसा भी मामला हो, उसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से प्राप्त की जाती थी। इसलिए, गतिशील पारिस्थितिक परिवर्तनों के साथ तालमेल रखते हुए निदेश जारी करने के लिए समर्थकारी उपबंध का प्रस्ताव किया गया है।

### समिति द्वारा की गई जांच

2.6.4 उपर्युक्त प्रावधान के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में निहित उपबंधों पर बैठक के दौरान यह बताया गया था कि वन प्रबंधन अब संघीय आधार पर किया जाता है। कितपय राष्ट्रीय आरक्षित वनों को छोड़कर अधिकांश वनों का अनुरक्षण राज्य करते हैं। यह कुछ-कुछ एकपक्षीय प्रतीत होता है। उपर्युक्त टिप्पणी के प्रत्युक्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उक्तर में निम्नानुसार बताया गया है:—

"वर्तमान में, अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में ऐसे कोई समर्थकारी उपबंध नहीं किए गए हैं, जिससे केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों पर स्पष्टीकरण अथवा निदेश जारी करने में सक्षम बनाया जा सके। विधेयक में जलवायु परिवर्तन और कार्बन तटस्थता जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए वन प्रबंधन प्रथाओं के संवर्धन हेतु रोड मैप की आवश्यकता होगी। अतः, अधिनियम में सक्षम उपबंध सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है जो केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।"

2.6.5 निम्नलिखित ब्यौरा सदस्यों द्वारा की गई लिखित टिप्पणियों/सुझावों तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में है:—

#### सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणी

प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्राधिकार केन्द्र सरकार को दे दिया गया है। यह सुझाव है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक समान एजेंसी स्थापित की जाए ताकि उसमें जांच और संतुलन लानेवाली प्रणाली तैयार हो।

संशोधन के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर बेल्ट में स्थित वन भूमि की पारिस्थितिक सुरक्षा बनाए रखने, उसकी जैव विविधता को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए विशेष देखभाल और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

#### नोडल मंत्रालय द्वारा दिया गया जवाब

विधेयक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां सामान्य शक्तियां नहीं बल्कि केवल इस धारा के अधीन प्रावधान के लिए हैं जो केंद्र सरकार को वनों के बेहतर संरक्षण, प्रबंधन और विकास के लिए उक्त उपबंध के प्रावधानों को लागू करने में सक्षम बनाएँगे। विधेयक की धारा 1क (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का अर्थ है छूटों पर विचार करते हुए नियम और शर्तें निर्धारित करना । केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अंतर्गत विचारित छूटें सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाएगी । संबंधित एजेंसियों द्वारा परिणामी आकलन, न्यूनीकरण उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का यथावश्यक कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को राज्य सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छटों पर विचार करते समय उक्त रक्षोपायों को

हमेशा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियमों और शर्तों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। धारा 2 (iii) के अंतर्गत प्रस्तावित प्रावधान सामान्य शक्तियां नहीं हैं, बल्कि नियम और शर्तों को निर्धारित करने के लिए दी जा रही विशिष्ट शक्तियां हैं जिनका प्रयोजन केवल वनभूमि को पट्टे पर देने के सीमित उद्देश्य के लिए है न कि वन भृमि के विपथन के लिए। ये प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीनवर्ती संरक्षित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। स्पष्टीकरण के खंड (viii) के तहत किया गया प्रावधान "... *कोई अन्य समान प्रयोजन* ..." पहले से ही मुल अधिनियम में मौजूद है। विधेयक की धारा 5(2) के अंतर्गत उपबंधित प्रावधान वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए हैं और केन्द्र सरकार को वनभिम में सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और संबंधित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले कतिपय निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनाते है। विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रावधानों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार अधिनियम में कोई भी संशोधन करने से पहले वनाश्रित समुदाय, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, के साथ एक पूर्व-विधायी परामर्श बैठक आयोजित करे। सरकार को अधिनियम में कोई संशोधन करने से पूर्व वनवासी समुदायों के साथ पूर्व-विधायी परामर्श बैठक का प्रयास करना चाहिए।

इस विधेयक के कार्यान्वयन से वनवासी समुदायों की आजीविका और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यापक स्तर पर परामर्श किए जाने की आवश्यकता है। विधेयक के उपबंधों का उन भाषाओं में अनुवाद किया जाए जिन्हें वे समझ सकें और यह अनुवाद उन्हें उपलब्ध कराया जाए और इस तरह के परामर्श के लिए पर्याप्त समय अविध भी प्रदान की जाए।

लोक सभा सचिवालय की मानक प्रथा के अनुसार हिन्दी और अँग्रेजी में जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इस विषय में जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों के साथ साथ जनता से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उनका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की पूर्व-विधायी परामर्श नीति के प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परामर्श भी किया गया था और अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला एक अवधारणा पत्र स्थानीय भाषाओं में परिचालित किया गया था और इस विषय में स्थानीय भाषाओं सहित जनता से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

लोक सभा सचिवालय की मानक प्रथा के अनुसार हिन्दी और अँग्रेजी में जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इस विषय में जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों सहित जनता से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उनका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदान किया गया हैं। इसके अलावा, भारत सरकार की पूर्व-विधायी परामर्श नीति के प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परामर्श भी किया गया था और अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला एक अवधारणा पत्र स्थानीय भाषाओं में परिचालित किया गया था और इस विषय में स्थानीय भाषाओं सहित जनता से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

### विभिन्न हितधारकों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

### जनजातीय कार्य मंत्रालय

2.6.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या जारी किए गए अनुदेश वन अधिकारों के संरक्षण को यथोचित महत्त्व देते हैं, इसमें एक खंड जोड़ा जा सकता है जो कहता हो कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी विद्यमान अधिनियम की अवहेलना नहीं करेंगे।

### सिक्किम सरकार

2.6.7 किसी मामले से संबंधित सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास निहित नहीं होंगी क्योंकि वन समवर्ती सूची का विषय है और राज्यों में सभी प्रकार के वन केवल राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और इसलिए, सभी निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से लिए जाने का प्रस्ताव है।

### मेघालय सरकार

#### राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव नोडल मंत्रालय का उत्तर/टिप्पणी निम्नलिखित पर भी विचार किया जाना चाहिए: इस धारा के प्रावधान राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। समय-समय पर दिशा-निर्देश (i) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में राज्य सरकार की और स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्रावधान प्रधानता को शायद समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित किए गए हैं जिनकी न केवल राष्ट्रीय बल्कि यह देखते हए कि वन एक समवर्ती विषय है और संविधान (ii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियों में गतिशील परिवर्तनों की VIIवीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार भूमि राज्य का को देखते हुए विभिन्न पदाधिकारियों को आवश्यकता विषय (प्रविष्टि-45) है, केन्द्र सरकार के पक्ष में ऐसा कोई हो सकती है। प्राधिकार नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए इसी प्रकार, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत प्राधिकरण, (iii) नियमों में कोई सक्षमकारी प्रावधान नहीं किया गया संगठन. संस्थाएं या निकाय केवल राज्य सरकार के है जो केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों पर प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं जो पूरी तरह से राज्य सरकार स्पष्टीकरण या निर्देश जारी करने के लिए सक्षम बनाता के निर्देशों से बंधे हैं। हो। जैसा कि विधेयक में जलवायु परिवर्तन और कार्बन तटस्थता जैसे वैश्विक मृद्दों का मुकाबला करने के लिए संविधान की VIIवीं अनुसूची में उन विषयों का प्रावधान (iv) अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है. किया गया है जो क्रमशः राज्य सूची, केंद्रीय सूची और जिसके लिए वन प्रबंधन तरीकों को बेहतर बनाने के समवर्ती सुची के अंतर्गत आते हैं। सुची ॥ और ॥ के अंतर्गत लिए रोड मैप की आवश्यकता होगी। इसलिए, आने वाले मामलों में राज्य सरकार को दी गई स्वायत्तता को अधिनियम में सक्षमकारी प्रावधान करने का प्रस्ताव शायद संरक्षित किया जाए। किया गया है जो केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है. जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकता है।

### 2.6.8 ओडिशा सरकार

राज्य सरकार की टिप्पणियां/सुझाव नोः	
और इसे जारी रखा जाए। स्प जैस तट आ जि	वर्तमान में, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई ऐसा सक्षमकारी प्रावधान नहीं किया गया है जो केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण या निर्देश जारी करने में सक्षम बनाता हो। जैसा कि विधेयक में जलवायु परिवर्तन और कार्बन तटस्थता जैसे वैश्विक मुद्दों का मुकाबला करने के लिए अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वन प्रबंधन के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए रोड मैप की आवश्यकता होगी। इसलिए,

अधिनियम में सक्षमकारी प्रावधान प्रदान करने का
प्रस्ताव किया गया है जो केंद्र सरकार को निर्देश जारी
करने का अधिकार देता हो, जो अधिनियम के प्रावधानों
के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकता है।
, ,

### विशेषज्ञों/हितधारकों के महत्वपूर्ण सुझाव

2.6.9 एक लिखित ज्ञापन में टिप्पणी की गई है, कि 'धारा 3ग के प्रावधान एफसीए के तहत किसी भी राज्य सरकार या प्राधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने की असीमित शक्ति देते हैं.' अपने लिखित उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है :—

"अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का कोई दुरुपयोग न हो, जब भी आवश्यकता होगी, उक्त धारा के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।"

### 2.6.10 लिखित ज्ञापन में इस संबंध में की गई आगे की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:—

- ं।. किसी भी अधिनियम के कार्यान्वयन को उपयुक्त नियम बनाकर सुगम बनाया जाता है। इस खंड-6 को शामिल करने से केन्द्र सरकार को अपने 'निदेशों' को लागू करने की अनियंत्रित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वे कितनी भी न्यायोचित (गैर-न्यायोचित) प्रतीत होती हों। इससे बचा जा सकता है।
- ii. धारा 3 ग राज्य सरकार की प्रधानता को निरस्त कर सकती है। केन्द्र सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
- 2.6.11 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में क्रमशः निम्नानुसार स्पष्ट किया है:
  - i. वर्तमान में अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कोई समर्थकारी उपबंध नहीं किए गए हैं, जो केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण अथवा निदेश जारी करने में समर्थ बनाते हों। इस विधेयक में जलवायु परिवर्तन और कार्बन तटस्थता जैसी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अधिनियम के दायरे को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए वन प्रबंधन प्रथाओं के संवर्धन हेतु रूपरेखा की आवश्यकता होगी। इसलिए, अधिनियम में समर्थकारी उपबंध किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार को निदेश जारी करने हेतु सशक्त बनाता है।
  - ii. इस धारा के उपबंध राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। समय-समय पर दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण जारी करने के लिए उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं जिनकी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियों में गतिशील परिवर्तनों को देखते हुए विभिन्न पदाधिकारियों को आवश्यकता हो सकती है।

### 2.6.12 इसके अलावा हितधारकों ने लिखित ज्ञापन में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

- "संशोधन विधेयक केंद्र सरकार में संशोधन विधेयक की धारा 5 और धारा 6 के अंतर्गत वनों में किए जा सकने वाले अनुमेय कार्यों की संख्या को बढ़ाने और संशोधित करने की पूर्ण शक्तियां सुरक्षित रखता है। इसलिए, केंद्र सरकार धारा 2 (1), धारा 2 (2) धारा 3 (ग) के स्पष्टीकरण खंड (आठ) के अंतर्गत पुर:स्थापित की जाने वाली अपनी नई पूर्ण शक्तियों को लागू करके वन भूमि में लगभग किसी भी परियोजना अथवा कार्यकलाप को सही ठहराने में समर्थ होगी। केंद्र सरकार में इस प्रकार की अत्यधिक और गैर-निर्देशित शक्तियां निहित करने से वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- धारा 4 (2) में किया गया उपबंध, जिसमें केंद्र सरकार को अनियंत्रित विवेकाधिकार दिया गया है और धारा 4 (3) में प्रदान की गई कुछ राहत की प्रकृति अस्पष्ट है तथा इसे केंद्र सरकार की दया और इच्छा पर छोड़ दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद-13 के साथ-साथ पीईएसए-1996, एफआरए-2006, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम-2013 में प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दिशानिर्देश तैयार कर सकती है।"
- 2.6.13 उपर्युक्त के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है:—
  - "विधेयक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां सामान्य शक्तियां नहीं हैं बल्कि वे केवल उस धारा के लिए विशिष्ट हैं जो वनों के बेहतर संरक्षण, प्रबंधन और विकास के लिए उक्त धारा के प्रावधानों को लागू करने में केंद्र सरकार को समर्थ बनाती हैं। विधेयक की धारा 1क (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का कार्य छूट पर विचार करते समय निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करना है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अंतर्गत विचारित छूट सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित की जाए। प्रभाव आकलन, निवारक उपाय, वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग, स्थल-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन, जहां भी आवश्यक हो, निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न पहलुओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा राज्य

सरकार के परामर्श से कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी छूटों पर विचार करते समय, उक्त सुरक्षा उपायों को सदैव केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों में शामिल किया जाएगा।

धारा 2 (तीन) के अंतर्गत प्रस्तावित उपबंध सामान्य शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित करने वाली विशिष्ट शक्तियां हैं, जो केवल वन भूमि को पट्टे पर देने के सीमित उद्देश्य के लिए है, न कि वन भूमि के अन्यत्र उपयोग के लिए हैं। ये उपबंध वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संरक्षित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण के खंड (आठ) के अंतर्गत दिए गए उपबंध *"..किसी अन्य सामान्य उद्देश्य जोकि.."* मूल अधिनियम में पहले से ही विद्यमान हैं।

विधेयक की धारा 5(2) के अंतर्गत प्रदत्त उपबंध वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए विशिष्ट हैं और ये केन्द्र सरकार को वन भूमि का सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और संबंधित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले कतिपय निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनातें हैं।

विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त उपबंधों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्था के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।"

### समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.6.14 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर/स्पष्टीकरण सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

नई दिल्ली; 11 जुलाई, 2023 20 आषाढ़, 1945 (शक) श्री राजेंद्र अग्रवाल सभापति, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति

<u>परिशिष्ट-I</u>

### विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का लोक सभा में प्रस्ताव

बुधवार, 29 मार्च, 2023/ 8 चैत्र, 1945 (शक)

श्री भूपेन्द्र यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"िक वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को सभाओं की संयुक्त सिमति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा से निम्नलिखित 19 सदस्य होंगे:—

- 1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- 2. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
- 3. श्री राजू बिष्ट
- 4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
- श्री तापिर गाव
- 6. श्री अजय टम्टा
- 7. श्री सुरेश कुमार कश्यप
- 8. श्रीमती गोमती साय
- 9. श्री सुदर्शन भगत
- 10. श्री पल्लब लोचन दास
- 11. कुमारी दिया कुमारी
- 12. श्री टी.आर. बाल
- 13. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 14. श्रीमती साजदा अहमद
- 15. श्री कोटागिरी श्रीधर
- 16. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
- 17. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 18. श्री महेश साहू
- 19. श्री गिरीश चन्द्र

तथा राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

विधेयक को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## <u>परिशिष्ट-॥</u>

# विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का राज्य सभा में प्रस्ताव

बुधवार, 29 मार्च, 2023/ 8 चैत्र, 1945 (शक)

#### राज्य सभा से संदेश:

"िक सभा लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह यह सभा वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सिम्मिलित हो और संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्निलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त सिमिति में सेवा के लिए नामित किया जाए :—

- 1. डॉ. अशोक बाजपेयी
- 2. श्री अनिल बलूनी
- 3. श्री समीर उरांव
- 4. डॉ. सी. एम. रमेश
- 6. श्री जवाहर सरकार
- 6. डॉ. प्रशांत नंदा
- 7. श्री हिशे लाचुंगपा
- 8. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य

और दो सदस्यों को माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा द्वारा नामित किया जाएगा।

उपरोक्त प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा बुधवार, 29 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में पारित किया गया था।"

# <u>परिशिष्ट-III</u>

विशेषज्ञों/हितधारकों/गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं और जन सामान्य की सूची जिन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किए

Sl. No.	Name
1.	1. Shri Achyut Das, Social worker, Agragamee, Kashipur Odisha,
	2. Dr.Aurobindo Behera, IAS, Ex- Principal Secretary, Department of Forest and Environment Government of Odissha
	3. Dr. Sanjaya Kumar Panda, IAS, Ex-Chief Secretary, Government of Tripura
	4. Shri G.V. Venugopala Sarma, IAS , Ex-Member, Board of Revenue, Govt. of Odisha
	5. Shri Anil Pradhan, Sikshasandhan, Bhubaneswar
	6. Shri Gouranga Mohapatra, BGVS Odisha
	7. Shri Sandeep Patnaik, Social Worker, AtPo - Dimirisena, Via - Brahamagiri, Dt - Puri, Odisha Pin -752011
	sandeepkumar.pattnaik@gmail.com
2.	23venkatesan@gmail.com
3.	Shri A Cardoso, Vasco Mormugao Goa-403712, Vasco, info@jhatkaa.org
4.	Shri A K Varma, avanivarma413@gmail.com
5.	Shri A. Chanru, cspallavicspallavi@gmail.com
6.	Shri A. K. Johari, IFS (Retd.), Ex Principal Chief Conservator of Forests-Assam, johari60@yahoo.com
7.	Shri A. Karthikeyan, karthikthamizhan@gmail.com
8.	Shri A. Mohamed Elahi, Tamilnadu, mohdi552@gmail.com
9.	Shri A. Murugan, muruganpitchu@gmail.com
10.	Shri A. Punitharaj, punitharaj11873@gmail.com
11.	Shri A. Ram Rexahan, ramrexahan7@gmail.com
12.	Shri A. Sahul Hameed, sahul75hameed@gmail.com
13.	Shri A. Thamilselvan, tamilmeena644@gmail.com
14.	Shri A.Akbar Basha, Cheyyaru, akbarnizam.ab@gmail.com
15.	Shri A.C. Raj, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, jasu1440@gmail.com
16.	Shri A.C. Zonunmawia, Chairman, Centre for Environment Protection (CEP), Aizawl, Mizoram. cep earth@yahoo.com
17.	Shri A.Pandurangan, hepsiba.0506@gmail.com
18.	Shri A.R. Meghna Bhandari Saklecha
	meghnarbhandari@gmail.com
19.	aakashchandru2003@gmail.com
20.	Shri Aan Priya C Philip, Parappallill Pathirappally Junction, Alappuzha-688081
21.	Shri Aasic Raja aasicparveen69@gmail.com
22.	Shri Abani Kumar Kanhor, Secretary, Kui Samaj Seba Samiti, Phulbani, kuisamajss.plb@gmail.com
23.	Shri Abdul Hameed Mohamed Anvar, New St. Vellayapuram -623315 mdanvar2013@gmail.com info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
24.	Shri Abdul Hameed, hameedabdul21934@gmail.com
25.	Shri Abdul Kalam BS, acekalam@gmail.com
26.	Shri Abdul Majeed, 3, Chennai- 600013 info@jhatkaa.org
27.	Shri Abdul Nayeem, 11-38, Godavari Road, Lakshettipet-504215 mohammad03081991@gmail.com, info@jhatkaa.org
28.	abdulraja6843@gmail.com
29.	Shri Abdur Rahman MA veeraezhil1432@gmail.com
30.	Shri Abhi Sabar, padmalaya103@gmail.com
31.	Shri Abhijit Prabhudesai, General Secretary, Federation of Rainbow Warriors, rainbowwarriors2014@gmail.com
32.	Shri Abhijit Thengodkar, Thengodkar, abhijit.thengodkar@googlemail.com
33.	Shri Abhimanyu Sabar, padmalaya103@gmail.com
34.	Shri Abhinand, abhinandmspld@gmail.com
35.	Shri Abhinav Gaur, Advocate, Allahabad High Court, abhinav.cgaur@gmail.com
36.	Shri Abhinav Prasad, RR nagar, Bangalore, Bangalore-560098 abhinavpblr@gmail.com info@jhatkaa.org
37.	Shri Abul Fazal, Yari Road, Mumbai- 400095 abulf3@gmail.com, info@jhatkaa.org
38.	adhiasaithambi@gmail.com
39.	Shri Adhithyan. V, adhithyanvenkatesan@gmail.com
40.	Shri Aditi Kale, Pune, India blueski122@gmail.com
41.	Shri Aditya L, No D 81, Dhanishka Allegria Gardens, Plot No.23, Vengadamangalam Main Road, Kandigai, Kanchipuram-600127
42.	Shri Aditya Prasad, 35 Mutthiganj-700053, Allahabad aditya.prasad332@gmail.com info@jhatkaa.org
43.	Adv. Nithianandan Balagopalan Flat 8/1201, Nerio Building, Kesar Exotica CHS Ltd., Plot No. 264, 265, 266, Sector-11, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra- 410210
44.	Shri Agadesh Waran, G, 641603 Tiruppur info@jhatkaa.org
45.	Shri Aganathavenkatesh. M, aganvenkateshbe@gmail.com
46.	Shri Ahamed Ali, 9C, Pathu Nonbu Chavadi Str, 1st Lane, Goripalayam, Madurai-625002
47.	Shri Ahmad Bin muhammmad, Darul khairath, Kuttur-670306 670306 ahmadktr3@gmail.com, info@jhatkaa.org
48.	Shri AIKMKS Sabha Kisan Mazdoor Khet India LLA, Bengal West Purrup, Village Post-731236
49.	Shri Aishwarya Kammili, Noida-201305, kammiliaish88@gmail.com, info@jhatkaa.org
50.	Shri Aishwarya, 92aishwarya.s.iyer@gmail.com
51.	Shri Ajay C, No:27E, Poonthotta Street, Krishna Puram, Kadayanallur, Tenkasi-627759
52.	Shri Ajay Dsouza, Benson Town, Bangalore-560046 ajayd81@yahoo.com info@jhatkaa.org
53.	Shri Ajay Phatak, phatak.ajay@gmail.com
54.	Shri Ajay Shah ajayh.shah@yahoo.in
55.	Shri Ajay Shah F-403, Parmeshwar 7, near Godrej Garden city, Jagatpur, Ahmedabad
56.	Shri Ajin Mon, aajinmon1994@gmail.com

Sl. No.	Name
57.	Shri Ajith, ajith13040@gmail.com
58.	Shri Ajith Kumar ajithkumardae2225@gmail.com
59.	Shri Ajith Kumar S, Dharmapuri, aeroajith143@gmail.com
60.	Shri Ajith Kumar. A, ajithkumardae2225@gmail.com
61.	Shri Ajith R, 2/32, Kongavembu, Dharmapuri-636902
62.	Shri Akash. K, olukumaresan@gmail.com
63.	akashjos88@gmail.com
64.	akdinesh85@gmail.com
65.	Shri Akhilesh Chipli, General Secretary, SWAN & Man (Save-Wild-Atmosphere-Nature & Man), Chipli-Lingadahalli, Post: Varadamoola, Sagar Taluk-577417, Shivamogga-Karnataka
66.	Shri Akilan Balaguru, Vriddhachalam-606001, Tamilnadu info@jhatkaa.org
67.	Shri Akruara Luha, AT Budhibahal, P.O., Turekela, Dist. Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
68.	Shri Akshaya Raj, Ashoknagar, Chennai-600083 info@jhatkaa.org
69.	Shri Alisha Pereira, bournetapereira03@gmail.com
70.	Shri N. Alaguponnirul, alaguthamilan74@gmail.com
71.	Shri Along Longkumer, Convenor, The Naga Rising & Khriezodilhou Yhome, Secretary, The Nagar Rising. nagarisingoffice@gmail.com
72.	Shri Aman Bharti, Begusarai Bihar-851101, Begusarai amanbharti995@gmail.com, info@jhatkaa.org
73.	Shri Amar Ghosalkar, Bhandup, Mumbai-421306 amarghosalkar@gmail.com, info@jhatkaa.org
74.	Shri Ameen, ameenmeister@gmail.com
75.	Shri Ameet Singh, economist & farmer, ameetgsingh@gmail.com
76.	Shri Amer Jaleel, (Indian Citizen), amerswork@yahoo.com
77. Shri Amit Lahiri, AE 520, Bidhannagar, Kolkata-700064	
	lahiriamit07@gmail.com info@jhatkaa.org
78.	Shri Amit Nagwanshi, Guna-473001, Toriua, M.P. amit.nagputraaimbscs@gmail.com, info@jhatkaa.org
79.	ammaanpillai@gmail.com
80.	Ms. Ammu, TamilNadu ammukutty318@gmail.com info@jhatkaa.org
81.	Shri Ammulu D, 77 indra Nagar, Thiruninravur -602024
82.	Shri Ana Gracias, Near SFX Cross, Chinchwadda chimbel graciasana123@gmail.com
83.	Shri Anand Paramasivam haiaanand@gmail.com
84.	anandhraj6362@gmail.com
85.	anandhsugumaran@gmail.com
86.	anandjob1706@gmail.com
87.	Shri Anantharaman, anandharaman.s@gmail.com
88.	Shri Ananthi Ponnusamy, IIT Madras- 600036 Chennai ponnusamyananthi@gmail.com info@jhatkaa.org
89.	Shri Anbarasan Kannan, Naam Tamilar Katchi District Organizer, Cuddalore West, anbarasankannan1993@gmail.com

Sl. No.	Name
90.	Shri Anbazhagan Palanichamy, Aratt Premier Apartment, Bangalore-560048 panbu2000@gmail.com, info@jhatkaa.org
91.	anbumuni25@gmail.com
92.	anbushangami@gmail.com
93.	Shri Anden Mesmar, andenmesmar123@gmail.com
94.	Shri Aniket J, P 7/1, NAD Colony, Navi Mumbai-410206
95.	Shri Anil kumar H A, 97 7 th cross lpo, Bangalore 560003
96.	Shri Anil Xalxo AT/PO-Ratakhandi , Dist-Sundergarh Odisha, Pin code-770039 aniroxalxo25@gmail.com
97.	anithaanitha27078@gmail.com
98.	Ms. Anju, avtarharsana0056@gmail.com
99.	Shri Antaraa Vasudev, Founder, Civis, antaraa@civis.vote
100.	Shri Antonio Vital Luis, Carmona , south Goa,
	antoniovitalluis@yahoo.co.in.
101.	Shri Antony, jantonysmp@gmail.com
102.	anudharma1623@gmail.com
103.	Shri Anuj Mishra, Gwalior-474011, M.P.,
	anujmishra1955@gmail.com, info@jhatkaa.org
104.	Shri Anujan Prabhakaran, anuxtz@gmail.com
105.	anuragureti.asu@gmail.com
106.	Ms. Anusha B, Nayandahalli, 560039 Bengaluru,
	anu151829@gmail.com, info@jhatkaa.org
107.	Ms. Anuviya Anbuselvam, Chetpet, Chennai-600031
	anuviyanbuselvam@gmail.com, info@jhatkaa.org
108.	aramthirumalainnpl@gmail.com
109.	Shri Arasakumar, arasakumarntk@gmail.com
110.	Shri Aravind beckham2391@gmail.com
111.	Shri Aravind Kathiravan, Tamilnadu Social Media Division In-charge, Naam Tamilar Katchi.Tamilnadu, aravindkathiravan26@gmail.com
112.	archananarasimman29@gmail.com
113.	Shri Arikrishnan, ppmuthu02@gmail.com
114.	Shri Aril Krishnappa Sugandhini, S/O. Sri Krishnappa Poojary, Kalnayabagh, Andinje Post & Village, Belthangady Taluk, 574242, D.K. District, Karnataka.
115.	Shri Arka Roychoudhury, P86 Green View Baoshmabghata-700084, Kolkata
116.	Shri Arnab Dutta, Dr BC Roy Road Shyamnagar, North 24 Parganas-743127 arnabduttamusic@gmail.com, info@jhatkaa.org
117.	Ms. Aruthi, tamildivakar007@gmail.com
118.	Shri Artheeswaran S, 2/25, perumal koil Street, Then puthur village , Viluppuram-604306
119.	Shri Arul Prasath M, Aranganal street, Chennai-600113 arulmech404@gmail.com info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
120.	arulmani.ski@gmail.com
121.	Shri Arulprasath M, arulprasathm76@gmail.com
122.	Shri Arumugam K, No 44, Kannagi ST, Rajeshwari Nagar, Chennai-603202
123.	Shri Arun Anthony Raj S., arunanthony2803@gmail.com
124.	Shri Arun Chakaravarthy, No.3 middle street, Vadakurumboor-607201
125.	Shri Arun Kumar, im.arunofficial@gmail.com
126.	Shri Arun N, aarounn@gmail.com
127.	Shri Arunabh Dev Sharma, For Hope & Care Foundation, kokrajharhopecarefoundation@gmail.com
128.	arunjunai.selvan@gmail.com
129.	Shri Ash M, Jayamahal Extension Benson Town, Bangalore-560092 the9colors@gmail.com info@jhatkaa.org
130.	Shri Ashay Chaware, Flat no. 007, Sai Sadan Apt, Sugwekar Ali , Neral-410101
131.	Shri Ashish Kotamkar ashkot@yahoo.com
132.	Shri Ashok Kumar asokkumar83@gmail.com
133.	ashok20292@gmail.com
134.	ashrafdigital2006psm@gmail.com
135.	Shri Ashwinkumar Rangasamy, Padhirikuppam, Cuddalore-607401 ashwinranga95@gmail.com, info@jhatkaa.org
136.	Shri Ayush Sahoo, Shreekhetra Vihar, Bhubaneswar-751003 ayush.ronu@gmail.com
137.	azeesfarmer@gmail.com
138.	Shri Azharudeen, deensocial.2020@gmail.com
139.	Shri B K Singh, Retired PCCF (Head of Forest Force), Karnataka, <a href="mailto:bksinghretiredpccf@gmail.com">bksinghretiredpccf@gmail.com</a>
140.	Shri B. Babusandar, babusandar706@gmail.com
141.	Shri B. Girija, Director, info@cpf.in
142.	Shri B. Prabhakaran Hospitality Supplies & Services, prabha010356@yahoo.in
143.	Shri Babu, penpencil662@gmail.com
144.	Shri Babu S, prancisbabu@gmail.com
145.	babukannan1994@gmail.com
146.	Shri M. Siva, shivaram2007@gmail.com
147.	Badapalli Gramsabha At-Badapalli, Po-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
148.	Shri Badnaran Majhi, Trustee, (Simlipal Trust for Ecology & Economic Development), <a href="mailto:durgaprosadmajhi@gmail.com">durgaprosadmajhi@gmail.com</a>
149.	Shri Baibaraj Majhi, on behalf of Bagbel Gram Sabha, AT- Bagbel , P.O. / Via- Turekela District Balangir, Odisha , Pin 767060 zindabadsangathanbgr@gmail.com
150.	Baidipada Nuasahi Gramsabha At- Baidipada Nuasahi, Po-Jagilipadar, Via-Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032 padmalaya103@gmail.com
151.	Shri Baidyanath Sing, General Secretary (Org.) of Bahujan Mukti Party (BMP), District Unit Mayurbhanj, Odisha

Sl. No.	Name
152.	Shri Baishanb Hans, At- Malibahali, Po Mahakhand, Via- Bangomunda, dist. Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
153.	Shri Bakiyaraj rarayaraudo@gmail.com
154.	Shri Bala Murugan, Pachapalayam, Coimbatore-641010 mail2thaai@gmail.com, info@jhatkaa.org
155.	Shri Balachandran Chinnaiyan, 1109, V. O. C. Nagar , Pudukkottai-622004
156.	Shri Balaji Chitravel, kuttyb40@gmail.com
157.	Shri Balajee T E krishbala.raghul@gmail.com
158.	Shri Balaji balajie3@gmail.com
159.	Shri Bala Mukundhan Vysar Moorthy, 5/817 c Sriram Nagar Kunnur Road Krishnan Kovil- 626138
160.	Shri Balamurugan T NTK Environmental Wing balamnc23@gmail.com
161.	Shri Balamurugan. Mu, balamurugankani02@gmail.com
162.	Shri Banadhikar O Prakriti Banchao Adivasi Mahasabha, Garbeta, Paschim Medinipur, West Bengal-721127 banadhikar.adivasimahasabha@gmail.com
163.	Banadhikar O Prakriti Banchao Adivasi Mahasabha, Paschim Medinipur, Garbeta, Tigar House, West Bengal
164.	barkavi131@gmail.com
165.	barockiasamy64@gmail.com
166.	Shri Baskar Pandiyan, No.4, 3rd Street, Kamarajar Nagar, Avadi-600071
167.	Shri Baspet Bag, On behalf of Bagdor Gram sabha , zindabadsangathanbgr@gmail.com
168.	Bayasahi Gramsabha At-Bayasahi, Po-Mundula, Via-Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032 padmalaya103@gmail.com
169.	Beherakhai, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
170.	bestonecommunication2022@gmail.com
171.	Shri Bhagaban Putel, AT/P.O., Turekela, Dist. Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
172.	Shri Bhagvan Shiv, sivajudo1990@gmail.com
173.	Shri Bhagyashree Pancholy, Add Pancholy House, PP Singhal Marg, Udaipur - 313004, Rajasthan
174.	Shri Bhaja Majhi, AT-Tikrapada P.O Salemudhanga, Via- Bangomunda Dist. Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
175.	Shri Bharath Kumar R, 50, Vettavalam Road, Tiruvannamalai-606602
176.	Shri Bharathi Raja Pandi, Sivaganga-630561 info@jhatkaa.org
177.	bhubalan@gmail.com
178.	Shri Bijay Kumar Hembram, Rastriya Adivasi Ekta Parishad (RAEP), hembram.bijaykumar@gmail.com
179.	Shri Bijaya Jani ( Village President), padmalaya103@gmail.com
180.	Shri Biju Sabar, padmalaya103@gmail.com
181.	Shri Biram Soren, Mayurbhanj Hanat Paranik, biramsoren83@gmail.com
182.	Shri Bisambar Mura, General Secretary, All India Jan Adhikar Suraksha Committee, jascommittee@gmail.com
183.	blueski122@gmail.com
184.	Shri Boobathi Raja.V, S/O.K.Veerappan, Samiyarpudur, Oddanchatram, Dindigul boobathi2599@gmail.com

Sl. No.	Name
185.	Shri Boopathi, Naam Thamizhar Party, Tamil Nadu, imjust4u4ever@gmail.com
186.	bose.chandraleka@icloud.com
187.	Shri Brian Lobo lobobrian41@gmail.com
188.	Shri Brijesh CS, brijesh4architect@gmail.com
189.	Ms Brinda Karat, Member, Polit Bureau, CPI(M), Former Member, Rajya Sabha, cc@cpim.org
190.	Shri B.vijayaprabakaran vijayaprabakaran.b@gmail.com
191.	Shri C. Kugan shyamkugan@gmail.com
192.	Shri C.M. Kartik Kumar, cmvsk82@gmail.com
193.	Shri C.R Bijoy, cr.bijoy@gmail.com
194.	Shri C. Suresh, NTK Environmental Wing
195.	Shri C.V. Anandan, cvanandan16@gmail.com
196.	career.dhasthaa@gmail.com
197.	cd.murugan79@gmail.com
198.	Shri Cedric Savio Dsouza
199.	Shri CH Varte, Joint Secretary, Hmar Inpui (Hmar Supreme House), Assam Hills Region, Assam, India
200.	Shri Chambra Munda, AT –Kusumdihi, PO-Kalta, Dist-Sundargarh, Odisha, 770052
201.	Shri Chanchara Sahi Gramsabha At-Chanchara Sahi, Po-Mundula, Via-Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032
202.	Shri Chandru Chawla, cchawla123@gmail.com
203.	chandruksubash@gmail.com
204.	Shri Charles Ebinezer, ebijebi@gmail.com
205.	Shri Charles Teunissen, Botterland, Zevenaar
	teunissencharles@gmail.com, info@jhatkaa.org
206.	Shri Chetan Agarwal, chetan_agarwal1@hotmail.com
207.	Chhattisgarh Bachao Andolan, Conveners – Shri Sudesh Tikam, Shri Manish Kunjam, Shri Bijay Bhai, Ms. Shalini Gera, Shri Ramakant Banjare, Shri Nandkumar Kashyap, Shri Alok Shukla, cbaraipur@gmail.com
208.	Shri Chiranjit Roy, Durgapur-713212, West Bengal royfire007@gmail.com, info@jhatkaa.org
209.	Shri Chitra Iyer Sah, Headingly Cottage, Nainital-263002 chitraiyer@gmail.com, info@jhatkaa.org
210.	Shri Chitrakar Majhi, on Behalf of Mahulmunda Gram sabha zindabadsangathanbgr@gmail.com
211.	Shri Clara Vaz Goa 67writers@gmail.com
212.	Shri Cleo Wendy, <u>DENISEJACKIE@hotmail.com</u>
213.	Col CP Muthanna [Retd], Hon Secretary, Environment and Health Foundation [India], colmuthanna@gmail.com
214.	Concerned Punekars, C/o Sarang Yadwadkar, A-10 Pradnyangad, Sr. No. 119/3, Sinhgad Raod, Pune- 30
215.	Shri Cuz Judas S. Barreto, judas.barreto1967@gmail.com
216.	Shri D. Ajith Kumar, aaji37503@gmail.com
217.	Shri D. E. Asokan, asokan.de@gmail.com
218.	Shri D. Manokaran, manokaranduraisamy2@gmail.com

Sl. No.	Name
219.	Shri D. Raja, rajad617746@gmail.com
220.	Shri Dadio Podar, Gram Sabha, GP-Haldi, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
221.	Dahu Gramsabha, Dahu, Hatmunda, PS- Brahmanigon, Dist-Kandhamal, 762021, Odisha, nuangabalanhadra@gmail.com
222.	Shri Dakshina Ranjan Kisku, West Bengal-713209, Bardhaman, drkisku@gmail.com, info@jhatkaa.org
223.	Shri Daman Kumar, Pahari Gate Hariana -144208 V.P.O Hariana
224.	Shri Dandasi Sabar (Village President), padmalaya103@gmail.com
225.	Shri Danny R., Anand Park, Pune-411007 dee.rau@gmail.com, info@jhatkaa.org
226.	Shri David Rodrigues, H.No.191, Murmo Vaddo, Tamsheriem, Borim. Ponda, Goa - 403401
227.	Shri Dayasagar Patil, Savali, Plot No 476/A 2nd Cross Bhagyanagar, Belgaum-590006
228.	Shri Debadityo Sinha, Lead, Climate & Ecosystems, Vidhi Centre for Legal Policy, A-232, Defence Colony, New Delhi - 110024
229.	Shri Debaraj Budek, on Behalf of Masina Gram Sabha zindabadsangathanbgr@gmail.com
230.	Shri Debi Goenka, Executive Trustee, Conservation Action Trust, 5 SahakarBhavan, 1st Floor, LBS Marg, Narayan Nagar, Ghatkopar (West), Mumbai 400086
231.	Shri Deekshith N, 428 5th Main Road Domlur Village Domlur, Bengaluru-560071 deekshith.n@honeysys.com, info@jhatkaa.org
232.	Shri Deepak, allisdeepak@gmail.com
233.	Shri Deepak Gogate, thandademag@gmail.com
234.	Shri Deepak Holkar, Bhigwan-413105 holkardd24@gmail.com, info@jhatkaa.org
235.	Shri Deepak kumar, 4th block, Koramangala, Bangalore-560034
236.	deepakevr@gmail.com
237.	deepakperiyasamy23@gmail.com
238.	Shri Deivasigamani R., Bryant nagar, Thoothukudi-628008
239.	Shri Denis Fernandes, House No. 405, Agas, Loliem, Canacona, Goa.
240.	Shri Devaki Kunte devaki.kunte@gmail.com
241.	Shri Dhanasekar. K, dhana81@gmail.com
242.	Shri Dhanraj Karthikeyan, Thiruvarur, Tamilnadu -613701, gkkdraj@gmail.com
243.	Shri Dhanush Chandra, Water Tank Road, Bengaluru-560085 dhanushfenix@gmail.com, info@jhatkaa.org
244.	Shri Dharmaraj C S, Our Own Nature, Reg.No.68/10,
	P.O.Krishnagiri, Meenangadi, Wayanad Dist, Kerala-673591
245.	Dharma Babu, No. 2/5, First floor, Sardar colony first street, Ek 600032 Chennai babudharma1007@gmail.com, info@jhatkaa.org
246.	dhaya44m@gmail.com
247.	Shri Dheeran Mukesh, mukesh2k1@rediffmail.com
248.	Shri Dhinakaran V dinakarandina12233@gmail.com
249.	dhineshporchilai@gmail.com

Sl. No.	Name
250.	Shri Dhiraj U Mirajkar, B.Sc., LL.M., Legal Advisor to Sanjay Gandhi National Park (2000 - 2023), Legal Advisor to Mangrove and Marine Biodiversity Foundation of Maharashtra (2020 - 2023), 405-406 Kanchan Holy Cross Road, Borivali West, Mumbai 400103
251.	Dhobapadar Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com
252.	Shri Dhruvang Sunil Hingmire, 4, Vrindavan society, Near Mhatre bridge, Pune - 411030
253.	Shri Dhuruvan Selvamani, Spoke Person, Naam Tamilar Katchi parisalkaran@gmail.com
254.	Shri Diamond D Fernandes (Indian Citizen) diamond1827f@gmail.com
255.	Shri Dickson Agnelo Pereira (Indian Citizen) dicksonsail79@rediffmail.com
256.	Shri Dileep Kumar Yadav (I.F.S.), Divisional Forest Officer, Garhwa North Forest Division, Van Bhawan, Kutchery Road, Garhwa, Jharkhand-822114
257.	Shri Dilip Chakma, Executive Director, Indigenous Rights Advocacy Centre (IRAC), indigenousrightsadvocacy@gmail.com
258.	Shri Dilip Gode, Executive Director, <i>VNCS</i> , Vidarbha Nature Conservation Society,B-401, Gondawana-Dhruv Apartments, KT Nagar, Katol Road, Nagpur-440013
259.	Shri Dilli Rajan, dillirajan95972@gmail.com
260.	Ms. Dimple Asha, 4-280/2A, Balaji Nagar-517002 Chittoor
261.	Shri Dinesh Kumar Agrawal, S/o Late Moti Lal Agrawal, 1/24, First Floor, Charmwood Village, Eros Garden, Suraj Kund, Faridabad-121009.
262.	Shri Dinesh Kumar G, gdineshkumar065@gmail.com
263.	Ms. Dipti Arora, diptiarora60@gmail.com
264.	District Forest Right Group Member, 15 Ward Member, Vettaikaranpudhur, Dapslip, Coimbatore, Tamil Nadu
265.	divanaslan1432@gmail.com
266.	Ms. Divya Sree, Jettypalem, Venkatagiri-524132 divyasree92159@gmail.com, info@jhatkaa.org
267.	Ms. Dolly Pandya, Mangal Bagh Street No. 1, Gurudwara Road, Jamnagar-361001
268.	domnicraja1996@gmail.com
269.	Domturunji Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com
270.	Dr Arvind Kumar Jha, PCCF & DG (SFD), Maharashtra, Member (Bar Council of High Court of Bombay and Goa)
271.	Dr Ashok Kaushal akaushal1960@yahoo.co.in
272.	Dr Bhushi Venkata Rao. Convenor, Visakha Dalit Unity Forum, Bhushi Bhavan, Ashok Nagar, Desapalrunipalem, Nea Check Post, Parawada(M), Visakhapatnan-531021
273.	Dr D K Sriwastwa IFS Rtd, Secretary, SILVAN, silvansociety@gmail.com
274.	Dr H.S Gupta, Ranchi -834002., Jharkhand (India)
275.	Dr Thimmappaiah G, Vijayanagar, Bangalore-560040 info@jhatkaa.org
276.	Dr. A. Simon Justin, simjus6@gmail.com
277.	Dr. Balathandayuthabani P, PhD (Sweden) Environmental Science balapselvam@gmail.com
278.	Dr. Fr. Bolmax Fidelis Pereira, Convenor, Diocesan Commission For Ecology Goa (DCE), goaecology@gmail.com
279.	Dr. Kalpana S Gupte gupte.sankalp@gmail.com

Sl. No.	Name
280.	Dr. Kishor Moghe 19, Vishalnagar, Moha, Dhamangaon Road, Yavatmal- 445001
281.	Dr. M. Saren, Paranik/President (B.J.M, P.M.),Barsarsa, P.O. Itachuna,Block- Pandua, District- Hooghly, W.B.
282.	Dr. M.P.Singh, IFS, Director, Institute of Wood Science and Technology, 18Cross, Malleshwaram Bengaluru- 560 003
283.	Dr. Mailaraaj, tamilantamayilraai@gmail.com, 13.05.2023 08.37
284.	Dr. Mairee Chet, selvamselvammv@gmail.com 13.05.2023 08.27
285.	Dr. N M Saran MD Physician (Russia & Armenia),
	nmsaran2040@gmail.com
286.	Dr. Sejal Worah, Programme Director, WWF India, vuppal@wwfindia.net
287.	Dr. T. Santhosh Raj, t.santhose@gmail.com
288.	Shri Durai, themotherkpn6@gmail.com
289.	Shri Durairaj durairaj242@gmail.com
290.	Shri Durga M, Adyar, Chennai-600020
291.	Shri Durgacharan Hembram, (vice president, Mayurbhanj Surakhya Manch) BadNaran Majhi, (Advisor Mayurbhanj Surakhya Manch) <u>durgaprosadmajhi@gmail.com</u>
292.	Shri Durgacharan Singh, Working President of Bahujan Mukti Party (BMP), District Unit Mayurbhanj Odisha At:— Kanchanpal, PO:— Orachandabilla, PS:— Betnoti, Dist:— Mayurbhanj, State:— Odisha Pin: 757103
293.	Shri E Sathish Kumar, sathishbharathy88@gmail.com
294.	Shri E Tamilselvan, ts0582020@gmail.com
295.	Shri E. Batsha, Naam Tamilr Katchi, yuvanbatsha@gmail.com
296.	Shri A. Manikanandan, manimalai00315@gmail.com
297.	Shri E. Rasaiya, rasaiyae@gmail.com
298.	Shri E. Tamilselvan, ts0582020@gmail.com
299.	Shri E.A.S.Sarma, 14-40-4/1 Gokhale Road, Maharanipeta, Visakhapatnam- 530002
300.	Ms. R Kanagapriyaa, kanagapriyamsc@gmail.com
301.	elaiyarasan1989@gmail.com
302.	elangovanselva@gmail.com
303.	Shri Eliel D'Souza, Panaji 403002, North Goa, Panaji mrlel96@gmail.com info@jhatkaa.org
304.	elilkrasa90@gmail.com
305.	Ms. Elisabeth Bechmann, Neugebäudeplatz 4 / 67, St. Pölten, elisabeth.bechmann@kstp.at, info@jhatkaa.org
306.	Er. Royson E. Da Costa Consultant Civil Engineer, royson24@gmail.com
307.	erodevpg@gmail.com
308.	Shri Eswar M, 250, Santhiyakinatru Street, Srivilliputhur-626125
309.	Shri Eswara, eswara7@gmail.com
310.	ethirmuttu@gmail.com

Sl. No.	Name
311.	Shri Fahad CV, #202 Sri Ram NIIaya Apartments, 145, AECS B Block, Wellington Paradise, Begur, Bengaluru, Karnataka-560068, Bangalore
312.	Ms. Fatima M Noronha fmn2011@gmail.com
313.	Shri Felix Furtado, H. No. 330, Cavorim, Chandor, Salcete, Goa-403714
314.	Shri Felix Pereira, H. No. 642, Moll ward, Sao Jose de Areal, Salcete Goa 403709
315.	Forest Rights Committee, Distt Bayurbhanj, Odisha
316.	Shri Francis, francismmvdj@gmail.com
317.	Shri Francis Selvaraj, francismmvdj@gmail.com
318.	Shri Fred Hamilton Hamilton, Hiranandani Gardens Powai, Mumbai-400076 hamilton.fred@gmail.com info@jhatkaa.org
319.	Shri G Dhayalan, dhaya4144@gmail.com
320.	Shri G Maharajan, maharajangurunath@gmail.com
321.	Shri G. Munisamy, munisamy0401@gmail.com
322.	Shri G. Prasanna, prasanna.g89@gmail.com
323.	Shri G. Prasannavenkatesh, prasan4p@gmail.com
324.	Shri G. Rajasekar., rajasekardhileepan@gmail.com
325.	gaganshetty047@gmail.com
326.	Shri Ganesan Pazhani, 25/162 Kali Amman koil Street Virugambakkam-600092 Chennai
327.	Shri Ganesh G, Chennai-600019 ganeshg@duck.com, info@jhatkaa.org
328.	Shri Ganesh Sabar, padmalaya103@gmail.com
329.	Shri Ganesh Veluswami, Thilagar Street, Chennai-600091 gunnniboy@yahoo.com, info@jhatkaa.org
330.	ganeshtamil9789@gmail.com
331.	Shri Ganga Majhi, on Behalf of Rautmunda Gram sabha, District- Balangir, Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
332.	Shri Gangadhar Majhi, At- Ganjaudar Po /via Turekela, Dist- Balangir (Odisha) Pin 767060, zindabadsangathanbgr@gmail.com
333.	Shri Gaurish Angawalkar, 25/C/104, Green Hill Goregaon East Near NNP 1&2, Mumbai-400065
334.	Shri Gehla Charan Munda, AT-Birtola, P.ODarjing, Via-lahunipara, PS-Chandiposh, Pin-770040, State-odisha gelhamunda@gmail.com
335.	Shri Gerald C, 44 Bajanai Madam Street, Pondicherry- 605003 info@jhatkaa.org
336.	Shri Ghana Majhi, on Behalf of Barakani gram sabha zindabadsangathanbgr@gmail.com
337.	
338.	ghostofjustice2@gmail.com  Gilinda Gramsabha At-Gilinda, Po-Angaragaon, Via-Sumandal, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761035
	padmalaya103@gmail.com
339.	gmsaibalaji@gmail.com
340.	gnanamtech85@gmail.com
341.	Shri Gnanamuthu, gnanamuthutvl@gmail.com
342.	Shri Gnanamuthu. T, gnanamuthu.t@sfl.co.in

Sl. No.	Name
343.	gnanaseelan98@gmail.com
344.	Shri Gnanasekar, gnanasekarsudararaj@gmail.com
345.	Shri Gobinda Majhi, on Behalf of Jharani gram sabha
	zindabadsangathanbgr@gmail.com
346.	Shri Gogulan. S, gogulan4648@gmail.com
347.	Shri Gokul KR, 16 Brindavan Road Salem-636016
348.	Shri Gopal, gopal.cse2007@gmail.com
349.	Shri Gopalakrishnan Srinivasan, 1-1/438, Rasi Nagar, Mohan Nagar P.O., Salem – 636030
350.	Shri Gopi Vijayakumar, gopivijayakumar24@gmail.com
351.	Shri Gopikrishnan N, krish.kannan89@gmail.com
352.	Shri Gopinath K, 36/47, Nachiappa Street, Chennai-600004
353.	Shri Goutam Rana, AT Pandaren P.O Kuibahal, Via- Turekela, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
354.	Shri Govindarasu, govindarasu292@gmail.com
355.	Shri Gowri Shankar Manimuthu, Senganoor, boominaikenpatty, 636304 Salem mgssalem@gmail.com, info@jhatkaa.org
356.	Shri Gowtham M, Environmentalist, gowthamvedha26@gmail.com
357.	Shri Gowthamraj Kandasamy, Tamil Nadu, gowthamrajkandasamy65@gmail.com
358.	gowthamvedha26@gmail.com
359.	Gramasabha Samuha, Dadapalla Block, Nayagarh Odisha, Odisha. muduli.trilochan143@gmail.com
360.	Gudikia Gramasabha, P.O. Gudikia, PS-Brahmanigam, District Kandhamal, Odisha sauravbaliarsingh2@gmail.com
361.	Gumandi Gramasabha, nuangabalanhadra@gmail.com
362.	Shri Gura Singh, Member of Rashtriya Adivasi Ekta Parishad, District Unit, ayurbhanj, Odisha At:—Kandaliasole, PO:—Sankerko, PS:—Badasahi, Dist:—Mayurbhanj State:—Odisha, Pin:—757024
363.	Shri Gurudas Nulkar gurudasn@gmail.com
364.	Shri Hamza Tariq, Kanuni Lok Sahayta Kendra-Mandvi hamza.csj@gmail.com
365.	Shri Hannan Mollah, bhumiadhikarandolan@yahoo.com
366.	Haraguda Gramasabha, saratmalick306@gmail.com
367.	Shri Harald Nixon C C, haraldnixon0225@gmail.com
368.	Shri Haraprasad Raut, on behalf of Dumermunda Gramsabha zindabadsangathanbgr@gmail.com
369.	Shri Hari Krish, 620 Bharathi Road, Chennai-600050
370.	Shri Hariharan. K, k.hariharan25@gmail.com
371.	harinimlr64@gmail.com
372.	Shri Hariprasad G, harikalam@gmail.com
373.	Shri Haripriya Haridasan, Eliyan House , illipuram, PO: Irinave, District Kannur-670301
374.	Shri Harish N, Mahadeshwarnagar, Bangalore-560091 info@jhatkaa.org
375.	harishgmogaveera810@gmail.com

Sl. No.	Name
376.	Shri Haritha M, Meledath House, Thaliparamba-670581
377.	harithesmart6@gmail.com
378.	harshith2701@gmail.com
379.	harshshah9990@yahoo.com
380.	Ms. Hema Chari, kandalahema@gmail.com
381.	Hema Chari, hema 05@rediffmail.com
382.	Ms. Hema Ramani, Campaigns Director info@beag.in
383.	Shri Hemant Kumar Lodhi, Middle High Teacher, Gram+Post- Kundli, Tehsil- Hilwani, District- Raisen (MP)
384.	Shri Hemanth, hemanthinmail@gmail.com
385.	Shri Hemasagar Dharua, At Khutulumunda, Po Kantabanji, Dist Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
386.	Shri Himanshu Singh, Bijliasi, 226003 Lucknow
387.	Shri Hussain Ahamed. madhusathya0806@gmail.com, Software Engineer. hussainahamed107@gmail.com
388.	Shri I. Jayaraman, jeyechange304@gmail.com
389.	imsadiq12@gmail.com
390.	Shri Inamdar Tabussum S., Advocate, Mumbai High Court
391.	Shri Inder Jit Singh, D 383, Defence Colony-110024, New Delhi
392.	Indigenous Lawyers Association of India C3/441, Top Floor, Janakpuri, New Delhi -110058
393.	indrakumar7063@gmail.com
394.	Shri Infant Prakash, infantprakashl@gmail.com
395.	info.kuums@gmail.com, Kachchh Camel Breeder's Association
396.	Initiative for Social Inclusion & Change, Silchar, Cachar, Assamm, mail.ourmedia@gmail.com
397.	Shri Iniyan PK, Ayothidhasar Nagar, Madurai-625514 iniyaa10@gmail.com, info@jhatkaa.org
398.	iniyangeorge0767@gmail.com
399.	Shri Iona Yvette Fernande, Goa ionayvette@gmail.com
400.	Shri J Chandralega, Advocate, Thiruppullani, Ramanathapuram 623532 advchandralega2016@gmail.com
401.	Shri J Johnwesly, kingsj604@gmail.com
402.	Shri J. Loganathan, 4u.logu@gmail.com
403.	Shri J. Richard Amalraj traditionalcnr@gmail.com
404.	Shri J.F. Jino (President), Mountainside Farmers Association, Kamarajapuram, Thadikkarankonam (Post) Kanniyakumari Dist629851
405.	jabezduke95@gmail.com
406.	Shri Jacob Raja, kittanmani@gmail.com
407.	Shri Jadelin Athena, 3 51 24 Arokia Nagar Muthalakurchy Thuckalay Post Kanyakumari Dist. Kanyakumari 629175, Tamil Nadu
408.	Shri Jaffer Li, jaffersara786@gmail.com
409.	Shri Jaffer Ali, jaffersara786@gmail.com
410.	Shri Jagadeesh S, 24/31, Perumal 1st Street, Purasaiwalkam Chennai-600007

Sl. No.	Name
411.	Shri Jagadish G Shet, Nagara-577425, Hosanagara Tq, Shivamogga Dist jagga.nagar@gmail.com
412.	Shri Jagan Shekhar, jekansekhar@icloud.com
413.	jaganratnam@gmail.com
414.	Shri Jainam Sheth, Mulund west-400080, Mumbai jsrock2004@gmail.com, info@jhatkaa.org
415.	Shri James Zacharias, Former Forest Officer, Kerala james.zacharias@gmail.com
416.	Ms Janaki Gandhi, #6 Shivalik Apartment, 88 Anand Park , Pune-411007
417.	Ms Janani, Parisar Pune janani@parisar.org
418.	Shri Janardan Nayak, Milita Adibasi Kalyan Monch, Keonjhar, Odisha-758001
419.	Shri Janarthanan Mani vellorejana@gmail.com
420.	Shri Janarthanan Mohan, 269 new Street Kedambur, Ambur-635808
421.	Janibili Gramsabha At-Janibili, Po-Mardamekha, Via-Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032 padmalaya 103@gmail.com
422.	Jarapalli Gramsabha At-Jarapalli, Po-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
423.	Ms Jaya Sabar (Village President) At- Telimal, Po- Jagilipadar, Via- Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032
424.	jayakarthickofficial@gmail.com
425.	Shri Jayakumar, jayaguru84@gmail.com
426.	Ms Jayanti K. Ramani (Lakdawala) jklakdawala@gmail.com
427.	Shri Jayapal Balaji, balaji211190@gmail.com
428.	jayaprakash2071975@gmail.com
429.	jayaprakashkarthick28@gmail.com
430.	jayasamy57@gmail.com
431.	jeba.embassy600100@gmail.com
432.	jebajulians@gmail.com
433.	Shri Jeferry Rebello, President, United Planters Association of Southen India (UPASI), Coonoor, Nilgiris, Tamil Nadu
434.	Shri Jegan Raj, jegannivash0007@gmail.com
435.	Shri Jeganathan S., jeganathan 1170@ gmail.com
436.	Jesufair Environmental Activist, jesufair@gmail.com
437.	Shri Jeya S, jeyasribalan@gmail.com
438.	jeyagopal784@gmail.com
439.	Shri Jeyaraj, jeyamjeyaraj1999@gmail.com
440.	Shri Jodi Rodar, 223 North Valley Road, Pelham
441.	Shri John Mark Pena, President, Hmar Students' Association, HSA Campus, Muolhoi, Haflong, Dima Hasao, Pin-788819
442.	Shri John paul, johnpaulmaria0@gmail.com
443.	Shri John Peppin, johnpeppin1974@gmail.com

Sl. No.	Name
444.	Shri Jon Botham, bothamj50@gmail.com
445.	Shri Jose Carlos Da Veiga Gracias, 54 Borda Fatorda Goa 403602 zecarlos@rediffmail.com
446.	Shri Joseph D'costa (Indian Citizen) joseph.dcosta@3i-infotech.com
447.	Shri Joseph Hoover, Former member, State Board for Wildlife, Karnataka, Independent Senior Journalist joehoover60@gmail.com
448.	joshuajackrio@gmail.com
449.	Ms. Jothimageswari R, prasan4p@gmail.com
450.	jsugumaran7@gmail.com
451.	Shri Jubaraj Dharua, AT Barakani, P.O. Jamkhunta, Via- Sindhekela, Dist-Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
452.	Shri Juheb Jhony, Barak, Assam juheb5@gmail.com
453.	juliyamass@gmail.com
454.	Ms. Jyoti Pande Lavakare pande.jyoti@gmail.com
455.	Jyoti Pande Lavakare, pchopra@dpncglobal.com
456.	Shri Jyotiraditya Chillal, Gandhinagar-411041, Narayanpet jyotiradityachillal2020@gmail.com, info@jhatkaa.org
457.	Shri K .Jagadeesan Dhana jagadeesan.jd0804@gmail.com
458.	Shri K Suresh Nayak, Member, NECF, Mangaluru, Karnataka ksureshnayak@rediffmail.com
459.	Shri K. Elumalai, elumalai.logu@gmail.com
460.	Shri K. Johnson, kjohnson1101990@gmail.com
461.	Shri K. Murugesan, mchellathambi@gmail.com
462.	Ms. K. Rajalakshmi, mahamahalakshmi953@gmail.com
463.	Shri K. Silamabarasan, gurutraders75@gmail.com
464.	Shri K. Silamabarasan, simbustr9629@gmail.com
465.	Shri K. Silambarasan, saisimbu4450@gmail.com
466.	Shri K. Venkatesh, k1995@gmail.com
467.	Shri K. Venkatraman, General Secretary – Thamizh Thesiya Periyakkam, (Thamizh National Movement), SP – 10 / 34, First Sector, Third Street, First Floor, Kalaignar Karunanithi Nagar, Chennai – 600 078.
468.	Shri K. Vijayakumar, vijaysha79@gmail.com
469.	Shri K. Yuvaraj, yuvrajuv591@gmail.com
470.	Shri K.A.S.S.Rahman shafiq7441@gmail.com
471.	Shri K.M. Kajendiran, NTK MEMBER, kajendiran2114@gmail.com
472.	Shri K.Nuagan Gramsabha, PS-Brahmanigam, District Kandhamal, Odisha sauravbaliarsingh2@gmail.com
473.	k.u.guru8897@gmail.com
474.	Shri Kaartikeyan, Vellore, novanavkarthik@gmail.com
475.	Shri Kailash. S, kailash.gold@gmail.com
476.	Shri Kalaigukan Mathivanan, kalaigukan33@gmail.com
477.	Shri Kalaimani, kalai19641992@gmail.com

478. Shri Kalaimaran A, 302 A Harihar Residency, Tiruchi-620020 479. Shri Kalaivendan J, kalaivendan/2323@mail.com 480. Shri Kalidadan, kalidasanthamizhan@gmail.com 481. Shri Kalimuthu S esskayashok147@gmail.com 482. kaliyappanansk@gmail.com 483. Shri Kalimuthu S esskayashok147@gmail.com 484. Shri Kamal Rathi, Naturalist and Conservationist, kamalrathi20@yahoo.co.in 485. Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com 486. kamankathir944@gmail.com 487. kamarajmugesh@gmail.com 488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com 489. kanagagomathi9@gmail.com 490. Shri Karnan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karna Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karn Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthick, J.Karthick9500787385@gmail.com 496. Shri Karthick, J.Karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick, Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick, Noungpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik, Noungpolitician7@gmail.com 501. Shri Karthik, Noungpolitician7@gmail.com 502. karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 503. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kashida277@gmail.com 509. Shri Karthikamalanda95@gmail.com 509. kathistandio1990.kk@gmail.com 500. Shri Karthikamalanda95@gmail.com 501. Shri Karthikamalanda95@gmail.com 502. Shri Karthikamalanda95@gmail.com 503. Shri Karthikamalanda95@gmail.com 504. Shri Karthikamalanda95@gmail.com 505. Shri Karthikamalanda95. Shri Karthikamalanda95. Smri Kardilanda95. Smri Kardilanda95. Smri Kardilanda95. Smri Kardilanda95. Smri Kardilanda95. Smri Kardilanda95. S	Sl. No.	Name
480. Shri Kalidadan, kalidasanthamizhan@mail.com  481. Shri Kalimuthu S esskayashok147@gmail.com  482. kaliyappannsk@gmail.com  483. Shri Kalpavriksh kalpavriksh.info@gmail.com  484. Shri Kanal Rathi, Naturalist and Conservationist, kamalrathi20@yahoo.co.in  485. Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com  486. kamankathir944@gmail.com  487. kanarajmugesh@gmail.com  488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com  489. kanagagomathi9@gmail.com  480. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha  481. kapadavel@gmail.com  492. Shri Karna Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org  483. Shri Karn Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org  484. Kartas Gramasabha, OP-Gudighat, District Balangir, Odisha  485. Shri Karthiakeshahdharua@gmail.com  486. Shri Karthick Jakarthick@gmail.com  487. Shri Karthick, j.karthick900787385@gmail.com  488. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com  489. Shri Karthick R, karthick988@gmail.com  500. Shri Karthick M, mpkarthikec@gmail.com  501. Shri Karthick, youngpolitician?@gmail.com  502. karthikeyan, S, Kanchipuran, karthikiyammal@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthikamilanda95@gmail.com  505. Shri Karthik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  karunatattooartist@gmail.com  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  509. kashvankasvan20@gmail.com  501. Shri Karthictudio1990.kk@gmail.com  502. kashvankasvan20@gmail.com  503. Karthikamilanda95@gmail.com  504. Shri Karthickungrist@gmail.com  505. Shri Karthik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  kashvankasavan20@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. Shri Karthik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  kashvanakathatana kanda kanda kanda kanda Choolai-600112, Chennai  511. Shri Kavidasan P, I, Govin	478.	Shri Kalaimaran A, 302 A Harihar Residency, Tiruchi-620020
481. Shri Kalimuthu S esskayashok147@gmail.com 482. kaliyappamsk@gmail.com 483. Shri Kalpavriksh kalpavriksh.info@gmail.com 484. Shri Kamal Rathi, Naturalist and Conservationist, kamalrathi20@yahoo.co.in 485. Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com 486. kamankathir944@gmail.com 487. kamarajmugesh@gmail.com 488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com 489. kanagagomathi9@gmail.com 489. kanagagomathi9@gmail.com 490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 494. Kartaa Gramasabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartaa Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthick9500787385@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 499. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 500. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 501. Shri Karthikyoun.gpolitician7@gmail.com 502. karthikevan.s, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Karthik M. mpkarthikece@gmail.com 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathistudio1990.kk@gmail.com 509. kathistudio1990.kk@gmail.com 501. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com 502. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	479.	Shri Kalaivendan J, kalaivendan2323@gmail.com
482. kaliyappanmsk@gmail.com  483. Shri Kalpavriksh kalpavriksh.info@gmail.com  484. Shri Kamal Rathi, Naturalist and Conservationist, kamalrathi20@yahoo.co.in  485. Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com  486. kamankathir044@gmail.com  487. kamarajmugesh@gmail.com  488. Shri Kameswar Majhi, At. Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com  489. kanagagomathi9@gmail.com  489. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha  491. kapadavel@gmail.com  492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org  493. Shri Karn Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com  494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057  495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com  496. Shri Karthick, Jikarthick9500787385@gmail.com  497. Shri Karthick Manickam, No. 4652 Valluvan Street, Chennai -600012  498. Shri Karthick Manickam, No. 4652 Valluvan Street, Chennai -600012  498. Shri Karthik, wangpolitician7@gmail.com  500. Shri Karthik, wangpolitician7@gmail.com  501. Shri Karthik, mpkarthikee@gmail.com  502. karthikeyan, S. Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com  503. karthikpheonixx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Karthikanianda95@gmail.com  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kasha277@gmail.com  509. kathistudio1990.kk@gmail.com  509. kathistudio1990.kk@gmail.com  501. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com  502. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	480.	Shri Kalidadan, kalidasanthamizhan@gmail.com
483. Shri Kalpavriksh kalpavriksh.info@gmail.com  484. Shri Kamal Rathi, Naturalist and Conservationist, kamalrathi20@yahoo.co.in  485. Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com  486. kamankathir944@gmail.com  487. kamarajmugesh@gmail.com  488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com  488. Shri Kamswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com  489. kanagagomathi9@gmail.com  490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha  491. kapadavel@gmail.com  492. Shri Karan Bbure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org  493. Shri Karan Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha  keshabdharuakeshabdharua@gmail.com  494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057  495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com  496. Shri Karthick, Ji.sarthick9500787385@gmail.com  497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012  498. Shri Karthick R, karthick298&@gmail.com  500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com  501. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com  502. karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Karthi Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  karunatattooartix@gmail.com  506. karunatattooartix@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  501. Shri Kavidasan P, I, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavimuthusamy2003@gmail.com	481.	Shri Kalimuthu S esskayashok147@gmail.com
484. Shri Kamal Rathi, Naturalist and Conservationist, <a href="mailto:kamalrathi20@yahoo.co.in">kamalrathi20@yahoo.co.in</a> 485. Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com 486. kamankathir944@gmail.com 487. kamarajmugesh@gmail.com 488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com 489. kanagagomathi9@gmail.com 490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 500. Shri Karthik, youngpolitician @gmail.com 501. Shri Karthik, mpkarthikee@gmail.com 502. karthikeyan.cs, Kanchipuram, karthikjammal@gmail.com 503. karthikpeonixxx@gmail.com 504. karthikpeonixxx@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 606. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 500. Shri Karvik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 501. Shri Kavikasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavimuthusamy2003@gmail.com	482.	kaliyappanmsk@gmail.com
485. Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com 486. kamankathir944@gmail.com 487. kamarajmugesh@gmail.com 488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com 489. kanagagomathi9@gmail.com 490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 500. Shri Karthik M. mpkarthikee@gmail.com 501. Shri Karthik M. mpkarthikee@gmail.com 501. Shri Karthik M. mpkarthikee@gmail.com 503. karthikpan.cyk18@gmail.com 504. karthikpan.cyk18@gmail.com 505. Shri Karthik M. mpkarthikee@gmail.com 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 500. Shri Karuna Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavin kavinmuthusamy2003@gmail.com	483.	Shri Kalpavriksh kalpavriksh.info@gmail.com
486. kamankathir944@gmail.com  487. kamarajmugesh@gmail.com  488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com  489. kanagagomathi9@gmail.com  490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha  491. kapadavel@gmail.com  492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org  493. Shri Karn Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com  494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057  495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com  496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com  497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012  498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com  500. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com  501. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com  502. karthikeyan.r2k18@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  501. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, I, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	484.	Shri Kamal Rathi, Naturalist and Conservationist, kamalrathi20@yahoo.co.in
487. kamarajmugesh@gmail.com 488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com 489. kanagagomathi9@gmail.com 490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick R, karthick9500787385@gmail.com 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com 501. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com 502. karthikeyan, S, Kanchipuram, karthikiyanmal@gmail.com 503. karthikeyan, Zk18@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 500. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	485.	Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com
488. Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com 489. kanagagomathi9@gmail.com 490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 501. Shri Karthikyan, S. Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan, S. Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 500. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	486.	kamankathir944@gmail.com
489. kanagagomathi9@gmail.com 490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 501. Shri Karthikyan, S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan.r2k18@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 500. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	487.	kamarajmugesh@gmail.com
490. Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha 491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com 501. Shri Karthikeyan, S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan, S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, I, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	488.	Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
491. kapadavel@gmail.com 492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karan Bebara, Gram Sabba, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com 501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan.rzk18@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, I, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	489.	kanagagomathi9@gmail.com
492. Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org 493. Shri Karn Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com 494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com 496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com 501. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com 502. karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 503. karthikhehonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartti Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	490.	Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha
493. Shri Karn Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com  494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057  495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com  496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com  497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012  498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com  499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com  500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com  501. Shri Karthikyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com  502. karthikeyan.rzk18@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  500. Shri Kaushalenda Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	491.	kapadavel@gmail.com
keshabdharua@gmail.com  494. Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057  495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com  496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com  497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012  498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com  499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com  500. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com  501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com  502. karthikeyan.r2k18@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  510. Shri Kavidasan P, I, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	492.	Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org
495. Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com  496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com  497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012  498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com  499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com  500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com  501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com  502. karthikeyan.r2k18@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	493.	
496. Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com 497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com 501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan.r2k18@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	494.	Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057
497. Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012 498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com 501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan.rzk18@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	495.	Shri Karthi, karthipoonga2001@gmail.com
498. Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com 499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com 501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan.r2k18@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	496.	Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com
499. Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com 500. Shri Karthik M, mpkarthikee@gmail.com 501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan.r2k18@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	497.	Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012
500. Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com 501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com 502. karthikeyan.r2k18@gmail.com 503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	498.	Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com
501. Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com  502. karthikeyan.r2k18@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	499.	Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com
502. karthikeyan.r2k18@gmail.com  503. karthikpheonixxx@gmail.com  504. karthiktamilanda95@gmail.com  505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	500.	Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com
503. karthikpheonixxx@gmail.com 504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	501.	Shri Karthikeyan. S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com
504. karthiktamilanda95@gmail.com 505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060 506. karunatattooartist@gmail.com 507. kasavankasavan20@gmail.com 508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	502.	karthikeyan.r2k18@gmail.com
505. Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060  506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	503.	karthikpheonixxx@gmail.com
506. karunatattooartist@gmail.com  507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	504.	karthiktamilanda95@gmail.com
507. kasavankasavan20@gmail.com  508. kash4277@gmail.com  509. kathirstudio1990.kk@gmail.com  510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh  511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai  512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	505.	Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060
508. kash4277@gmail.com 509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	506.	karunatattooartist@gmail.com
509. kathirstudio1990.kk@gmail.com 510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	507.	kasavankasavan20@gmail.com
510. Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh 511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	508.	kash4277@gmail.com
511. Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai 512. Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com	509.	kathirstudio1990.kk@gmail.com
512. Shri Kavin, <u>kavinmuthusamy2003@gmail.com</u>	510.	Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh
	511.	Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai
513. <u>kavinkumark242003@gmail.com</u>	512.	Shri Kavin, kavinmuthusamy2003@gmail.com
	513.	kavinkumark242003@gmail.com

Sl. No.	Name
514.	kavisathya.65@gmail.com
515.	Ms. Kavita Mehta, Executive Director, Sahjeevan, 175-Jalaram Society, B/h. Vishwamangal Apartment, Vijaynagar, Bhuj 370 001 Kachchh, Gujarat, INDIA
516.	Ms. Kavitha Devi Anbazhagan, Radhanagar Main Road, Chennai-600044 drkavitha20188@gmail.com, info@jhatkaa.org
517.	Shri Kaviyarasan N., kaviyarasann6150eee@gmail.com
518.	kayalyaal@gmail.com
519.	Shri Kaza Ramana Prasad, Yapral, Hyderabad-500087 info@jhatkaa.org
520.	Shri Keerthivasan T, New Colony Street Keezh Edaiyalam, Tindivanam -604302 keerthivasan1209@gmail.com, info@jhatkaa.org
521.	Shri Kesar Singh, Social worker and resident Village Kot, Dist. Faridabad, Haryana
522.	Shri Keshav Jangid, Near Neelkanth public school, khari kothi mohalla, Dausa-303303
523.	Ms. Ketaki Patil, kvp.ketaki@gmail.com
524.	kezhi.kavai@gmail.com
525.	Khadakpada Adivasi Gaothan Main Pump House, Aarey Milk Colony, Goregaon East, Mumbai- 400065, Maharashtra.khadakpada65@gmail.com
526.	Khajuri Sahi Gramasabha At-Khajuri Sahi, Po-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya 103@gmail.com
527.	Khandyanal Gramsabha At-Khandyanal, Po-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
528.	kidjeeva@gmail.com
529.	kishoremidas43@gmail.com
530.	koretikoya750@gmail.com
531.	Kovilpatti Forest Rights Committee, Nilgiris Dist. Masinagudi Post-643223, Tamil Nadu
532.	kpramod249@gmail.com
533.	Shri Krishna Chandra Chattar, Rastriya Adivasi Ekta Parishad, District President/Co-ordinator, District-Keonjhar, Odisha
534.	Shri Krishna Kumar D, Periyar Nagar- 626203, Sattur krish97.jsaa@gmail.com, info@jhatkaa.org
535.	Shri Krishna Prasath G, Naam Thamizhar Katchi – Chennai, krisnaa.san@gmail.com
536.	Shri Krishna Raj, Jeeva Nagar, 605602 Villupuram, krishna.ishna81@gmail.com, info@jhatkaa.org
537.	Ms. Krishna Valli M, rkff542@gmail.com
538.	krishnagunal51@gmail.com
539.	Shri Krishnan Nimmathi, 889, Malligai St, Anbarasu Nagar, Poonamallee-600123
540.	Ms. Kriti Mehra, Malad W, Mumbai-400064 info@jhatkaa.org
541.	Shri Krunal Bhagat, Achole Road, Nalasopara East, Maharashtra -401209 Vasai
542.	Shri Kshetramohan Majhi, AT Pingalmunda, P.O. Ghunasar, Via- Khaprakhol Dist Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
543.	Shri Kuldip Singh, Member of Rashtriya Adivasi Ekta Parishad (RAEP), District Unit Mayurbhanj, Odisha At:— Kukudakhumpi, PO:— Kuchei, PS:— Kuliana, Dist:— Mayurbhanj, State:— Odisha, Pin: 757105
544.	kumar7477@gmail.com
t .	1

Sl. No.	Name
545.	kumarmanikandan270@gmail.com
546.	kumarsuresh85952@gmail.com
547.	Kutani Jhoran Gramsabha, GP-Gudighot, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
548.	Shri Kuttalam, kuttalam07@gmail.com
549.	Shri L J Raj, blesstou2014@gmail.com
550.	Shri L Kumar, Vyasar Nagar 6th Street, Vyasarpadi, Chennai -600039 sannathkumar49471@gmail.com info@jhatkaa.org
551.	Shri L. Senthilkumar, senthilkumar15433@gmail.com
552.	Shri Lakapati Bag, AT-Gudramunda, P.O. Kuibahal, Via- Turekela, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
553.	Shri Lakhia Sabar, padmalaya103@gmail.com
554.	Shri Lakshmanakumaran Kumaran, 175/176, Radhakrishnan Nagar, Avaniapuram Byepass Road, Madurai-625012
555.	Shri Lakshmanan R, vnslaxman@gmail.com
556.	lakshmipathi111995@gmail.com
557.	lal392283@gmail.com
558.	Ms. Lalita Premsila Lakra, Block-lathikata, Vill-Birkera, District -Sundagarh (Odidhsa) lalitalakra236@gmail.com
559.	Shri Lalringhnem Pulamte, Secretary, Hmar Women's Association, Assam Hills Region, Hqr Muolhoi, Haflong, Assam
560.	Shri Lalrothang Thiek, General Secretary,Hmar Youth Association N. Chills Joint Headquarters Muolhoi,Haflong, <a href="https://hyanchithqrs@gmail.com">hyanchithqrs@gmail.com</a>
561.	Shri Latasahada, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
562.	Shri Laxmidhara sahoo, ddtcoordinator@gmail.com
563.	leelaa1234@gmail.com
564.	Ms. Leona Delphi, leonadelphi@gmail.com
565.	lokendrasoren4699@gmail.com
566.	Shri Lochan Bariha, on Behalf og Barla Gram Sabha, AT - Barla , P.O. Ghunesh PS-Turekela , Dist. Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
567.	loguraja302@gmail.com
568.	lokakavi@gmail.com
569.	lokendrasoren4699@gmail.com
570.	Shri Lokesh P., No. 6/2, Ashok Nagar, 600083 Chennai
571.	Ms. Lona Yvette Fernande, Goa
572.	Shri S. Shiva, sivajudo1990@gmail.com
573.	lurthulaisington@gmail.com
574.	Shri M Karthik, karthikmsk76@gmail.com
575.	Shri M Kavin, naamtamilaryoungsters@gmail.com

Sl. No.	Name
576.	Shri M Nishar Ahamed, thennurnishar@gmail.com
577.	Shri M. Palaniswami, nandhinistudioslm@gmail.com
578.	Shri M. Antony Stephen antonystephen9610@gmail.com
579.	Shri M. Anand, joypremanand@gmail.com
580.	Shri M. Baskaran, bossmani750@gmail.com
581.	Shri M. Gopalsami, Muthumari Amman, Kovil Keela, Velipalaoam, Nagapatinam
582.	Shri M. Isai Desan isaithesam@gmail.com
583.	Shri M. Jeeva, selvamselvammv@gmail.com
584.	Shri M. Kaja kajavrs1@gmail.com
585.	Shri M. Kathiresan, msamykathir@gmail.com
586.	Shri M. Kesavan newqueensmobiles@gmail.com
587.	Shri M. Lakshamanan, lakshmananl685@gmail.com
588.	Shri M. Mohamed Kani, kanisfi1012@gmail.com
589.	Shri M. Muthukrishnan, muthukrishnanmmuthu@gmail.com
590.	Shri M. Muthukrishnan, muthukrishnan501@gmail.com
591.	Shri M. Pandian, Presidient, Theni District Farmers Union, Periyakulam, Tamil Nadu mvetrivelformer1984@gmail.com
592.	Shri M. Prabaharan, prabakarandhilipan@gmail.com
593.	Shri M. Prabhakaran, mprabhasurya333@gmail.com
594.	Shri M. Sathish, sathish4181@gmail.com
595.	Shri M. Sathishkumar, sathishkumar_tms@yahoo.in
596.	Shri M. Subramanian, Secretary, Maramalai Planters Association, Vivekanandan Street, K.P. Road, Nagarcoil-629001
597.	Shri M. Venkatesan, venkatesanmurugaiah73@gmail.com
598.	Shri M. Antony Stephen antonystephen9610@gmail.com
599.	Shri M. Asisa mafil8745@gmail.com
600.	Shri M. Kesavan
601.	Shri M. Deepan, deepan90ns@gmail.com
602.	Shri Madan Sharma, madanlal.sharma92@gmail.com
603.	Shri Mahesh Kumar BN mahesh.kumarbn61@gmail.com
604.	Shri Maheswar Dharua, on behalf of Sanbanki Gram sabha, District- Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
605.	Shri Malarvizhi Ekambaram, 10/17A, 8th Street, B.V. Nagar, Pazhavanthangal Chennai -600114, Tamil Nadu
606.	Shri Maneck Kapadia, Havelock Rd., Camp, Belgaum-590001
607.	Shri Mangilal Gujjar, Jangal Jamin Jan Andolan, mlgurjar@gmail.com
608.	Shri Mani, tamilgooogle@gmail.com
609.	Shri Manian NTK, k.maniyan64@gmail.com

Sl. No.	Name
610.	manickakandasamy@gmail.com
611.	manieie.maran@gmail.com
612.	Shri Manika Sabar ( Village President), padmalaya103@gmail.com
613.	Shri Manikandan K K, maniajith8582@gmail.com
614.	Shri Manikandan Kuppusamy, kpm.manikandan@gmail.com
615.	Shri Manikandan S, r15.manikandan05@gmail.com
616.	Shri Manikandan M, manimahi006@gmail.com
617.	manimalai00315@gmail.com
618.	Shri Maninder Singh seekerstrail@gmail.com
619.	Shri Manish Ghurde, Amravati-444607 ghurdemanish50@gmail.com, info@jhatkaa.org
620.	manisuku07@gmail.com
621.	Ms. Manjushri mranjushrisavadi@gmail.com
622.	Shri Manohar chauhanmanohar@gmail.com
623.	Shri Manoj Negi, Brothers Apartment, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092 negi2u@gmail.com, info@jhatkaa.org
624.	Shri ManojKumar, manojindian912@gmail.com
625.	Shri Mansoor Ali, ma8648950@gmail.com
626.	manuelkr66@gmail.com
627.	Marad Gramasabha, Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com
628.	Shri Marcos Agostinho dos Santos marcosdossantos@yahoo.com
629.	Shri Margaret Viegas, (Indian Citizen) margaretviegas10@gmail.com
630.	Shri Maria do Carmo Fernandes mariadocarm@hotmail.com
631.	Shri Maria Jacinta de Silva (Indian Citizen) jacintasmseducator@gmail.com
632.	Shri Maria Jegan, Estimation Supervisor, ZIMIPCO Dammam, K.S.A., jegan.susai@icloud.com
633.	Shri Mariappa T, mariappanadar 1@gmail.com
634.	Shri Mariappan, bestjoy321@gmail.com
635.	Shri Mariya Bakiya Raj, rarayaraudo@gmail.com
636.	Shri Mariya Mary Joseph, Mundoor h, Panathady. P.O., Cherupanathady, Kasaragod-671532
	mariyamaryjoseph888@gmail.com info@jhatkaa.org
637.	Shri Mariyamuthu M, mmathan8@gmail.com
638.	massmano604@gmail.com
639.	Shri Mathan Kumar, Jailaniyastreet 6th Cross, Subramaniapuram -620020, Trichy
640.	Shri Mathan Muthuswamy, 22-12, Ananthapadmanabhapuram-629901, Nagercoil
641.	Shri Mathavan M, mathavanngo@gmail.com
642.	Shri Mathumitha Sathiyamoorthy, MCA, madhusathya0806@gmail.com
643.	Shri Mayank Mikhail Mukherjee, Advocate, Chambers of Mayank Mikhail Mukherjee, B6/58, Terrace, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110 029

Sl. No.	Name
644.	Mayurbhanj Jungle Manch, AT-Jyotipur, P.O. Goudadiha, Baripada, Mayabhan-757003, Odisha onlinecentre7@gmail.com
645.	Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Village - Devdungri, Post - Barar, District - Rajsamand, Rajasthan, India - 313341, mkssrajasthan@gmail.com
646.	Ms. Meenakshi Kapoor and Ms. Krithika A Dinesh, Independent Environmental Researcher <a href="meenakshi.em@gmail.com">meenakshi.em@gmail.com</a>
647.	Ms. Meenal Tatpati, Salisbury Park, Pune-411037 meenaltatpati@gmail.com info@jhatkaa.org
648.	Ms. Meera meera.rajesh@gmail.com
649.	Shri Melvi Fernandes, (Indian citizen) melvifernandes@gmail.com
650.	Shri Mervin, mervinjsm@gmail.com
651.	Shri Mervyn Vales, merwynvales@gmail.com
652.	Minapur Gramsabha At-Minapur, Po-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya 103@gmail.com
653.	Minjapanka Gramasabha, saratmalick306@gmail.com
654.	Shri Mirona Afonso (Indian Citizen) maura711afonso@gmail.com
655.	Shri Misbah Qureshi, 403/A Wing Kshitij Building, Mumbai-400016
656.	Shri Mo Haroon, 4, Kasturi Bai Street, Chennai-600094
657.	Shri Mohamed Shareef, mohamedshareef0128@gmail.com
658.	Mohamed Shareef, mohamedshareef1995@gmail.com
659.	Shri Mohamed Siddiq, tamilann1976@gmail.com
660.	Shri Mohamed Thajudeen, taj987@gmail.com
661.	Shri Mohan M, mohan.m909@gmail.com
662.	Shri Mohanam, mohanamhema@gmail.com
663.	mohenkumar1961@gmail.com
664.	Ms. Monisha V, kanchiseemanadhithyan@gmail.com
665.	Shri C. Lalaji, lalaji84@gmail.com
666.	Shri Durai themotherkpn6@gmail.com
667.	Shri Edwin Jayakumar, edvinj92@gmail.com
668.	Shri Joseph Sequeira Calangute joseph.sequeira@casaseverina.com
669.	Shri D.A. Narayanan ( Serve a Tribe ) ADVOCATE, Coimbatore 312, Lawyers Chambers District Coucomplex, Gopalapuram, Coimbatore – 641018, Tamilnadu State
670.	Ms. Fatima Fernandes, Siolim-Bardez, Goa fatimasiolim@gmail.com
671.	Ms. Peruma, Naam Tamilar Party, Tamilnadu, perumasekar24@gmail.com
672.	1. Ms. Prerna Singh Bindra, Former member, Standing Committee, National Board for Wildlife, Form member, State Board for Wildlife, Uttarakhand, PhD Scholar, University of Cambridge.
	2. Ms. Prakriti Srivastava, IFS, Principal Chief Conservator of Forests, Kerala bindra.prerna@gmail.comprakritii_2000@yahoo.com
673.	Ms. Bhagyashree Panchaly, Pancholy House, PP Singhal Marg, Udaipur, Rajasthan

Sl. No.	Name
674.	Ms. Qaneez Sukhrani, Convenor - Association of Nagar Road Citizens Forum, A/3 Hermes Drome CHS Ltd. S.no.211/3/1B Viman Nagar, Pune 411 014
675.	Ms. Shubhda Deshmukh, Dr Satish Gogulwar, Convener, Amhi Amchya Arogyasatharogyasathi@gmail.com
676.	msrinidpintk@gmail.com
677.	mukesh2k1@rediffmail.com
678.	Shri Mukilan Manikandan, Thelepan Street, P. Vadugapalayam, Palladam-641664 mukilanjm@gmail.com info@jhatkaa.org
679.	Shri Mukund V Mavalankar, mukund.mavalankar@gmail.com
680.	Shri Munindra, IFS (retd) munindra47@gmail.com
681.	Shri Murali Kumar K, T.N, Ranipet, kmurali.ind@gmail.com
682.	muralidharanemail@gmail.com
683.	muruganmuruga5659@gmail.com
684.	murugesansantha3@gmail.com
685.	mushroommahe@gmail.com
686.	musicaddict286@gmail.com
687.	musicianjabezrio2001@gmail.com
688.	Ms. Muskan Agarwal, Malviya Nagar Delhi, Delhi-302017 muskanagarwal2615@gmail.com, info@jhatkaa.org
689.	Shri Muthu, muthusamy1593@gmail.com
690.	Shri Muthu Kumaran, muthu.mk4@gmail.com
691.	Shri Muthu Veerasamee, itsmeveera8@gmail.com
692.	Shri Muthukrishnan Uthaman, Thirunagar-625006, Madurai
693.	Shri Muthukumar Gurusamy Kadavur, Mayilampatti-621301 info@jhatkaa.org
694.	Shri Muthukumar S, sivasamymdr@gmail.com
695.	Shri Muthukumar V, muthukumar.v96@gmail.com
696.	Shri N Alagu Ponnirul, alaguthamilan74@gmail.com
697.	Shri N K, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 knatesa@gmail.com info@jhatkaa.org
698.	Shri N.K., 560082 Bengaluru raghavnk@gmail.com, info@jhatkaa.org
699.	Shri N. Udaya, Member of NECF, Mangalore udeeachar@gmail.com
700.	naamtamilar.sam@gmail.com
701.	Shri Nagaraj H Shettar, 1st cross, park extension, Durgigudi, Shivamogga, Karnataka -577201
702.	Shri Nagaraja Koove, Ganapathikatte, Koove Post MudigereTaluk, Chickamgalur District
703.	Shri Nagesh S.V., 'Navyasgree', 100ft Road, Vinayaka Nagara, Shivamogga-577201
704.	Shri Nakul Bariha, AT -Khuripani, P.O Rengali, Via- Khaprakhol, District Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
705.	Ms. Namrata Das, J-78/2, Pandav Nagar, Opposite Mother Dairy, New Delhi-400061
706.	Shri Nandha Kumar, Asf3 Barathi Avenue 1st cross street New Perungalathur Tamilnadu, Chennai-600063

Sl. No.	Name
707.	Shri Narasimma, officialnarasimma@gmail.com
708.	Shri Narendra Armor, President, Forest Right Committee, Village- Morga, Post- Morga, Tahsil- Podi, District- Korba, Chhattisgarh
709.	Shri Naresh B, Thiruvanmaiyur- 600018 Chennai naresh.endless@gmail.com, info@jhatkaa.org
710.	Shri Naresh Jamatia, President, Radhacharan Debbarma, General Secretary, GMP, Tripura. <a href="mailto:nareshjamatia@gmail.com">nareshjamatia@gmail.com</a>
711.	Ms. Natarajanjothi, M.Com, nata6ajan777@gmail.com
712.	Shri Nathiya Raman, 16/27 Meenakshipuram-629301, Aralvoimozhi
713.	National Alliance on CFR and MFP, C/o Dr. Kishor Moghe, 19 Vishal Nagar, Moha, Dhamangaon Road, Yavatmal, Maharashtra- 445001
714.	Shri Navaneethakrishnan S, navakrish@outlook.com
715.	Shri Naveen Kumar H C, Hadinaru Village and Post Chatra Hobli Nanjangud, Thaluk Mysore, district, Mysore-571302 naveenkumarhc333@gmail.com info@jhatkaa.org
716.	naveenkumarnk1712@gmail.com
717.	naveensivakumars6120@gmail.com
718.	Shri Navin, navin774433@gmail.com
719.	Shri K. Navinrajan, k.navinrajan23@gmail.com
720.	Shri Nawinrajtamiz, nawinrajtamizha@gmail.com
721.	Ms. Neela Dhavale neela.dhavale@gmail.com
722.	Ms. Neelam Ahluwalia Nakra, Co-Founder and Trustee, Aravalli Bachao Citizens Movement aravallibachao.team@gmail.com
723.	Shri Neenu Somaraj, Sreevalsam, Parippu, P.O. Kottayam, Kerala
724.	Ms. Nelisha Trindade, Goa ,Candolim, Mapusa-403515
725.	nilavucomputers@gmail.com
726.	Shri Niruban Chakaravarthy, No.8/30A Mettu Street Agraharam Korattur Chennai - 600076
727.	Shri Nishikant Jadhav, Nishikant Bhaskar Jadhav At post shirgaon tehsil Deogad District Sindhudurg-416610. Maharashtra spredlove.999@gmail.com info@jhatkaa.org
728.	Shri Nithin K M, Prestige Willow Tree, Vidyaranyapura, Bangalore-560097 nitkm88ster@gmail.com info@jhatkaa.org
729.	Shri Nitin Shinde, neetinlic@gmail.com
730.	Shri Nityan and Shri Jayaraman, S45, 35th Cross, Besant Nagar, Chennai-600090
731.	Shri Nivaas Sudhan, C403, Coimbatore-641041 shrinivaasanln@gmail.com info@jhatkaa.org
732.	nramarvijay@gmail.com
733.	Shri NTK Ranipet, naamtamilarkatchiranipettai@gmail.com
734.	ntkssptupnorth@gmail.com
735.	Shri Nu Nizaam Ahmad, nijamfirtho999@gmail.com
736.	Nuapalli Gramsabha At-Nuapalli, PO-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya 103@gmail.com
737.	Shri Om Rane, 12, Raigad Society, Mumbai-400078

Sl. No.	Name
738.	on behalf of Area Sabha Association of Pune (ASAP) asapcitizens@gmail.com
	1. Ms. Swapna Narayan, Co-ordinator
	2. Shri Ravindra Sinha, Member
	3. Ms. Vaishali Patkar, Member
	4. Shri Makarand Shende, Member
	5. Ms. Hema Chari, Member
	6. Shri Akhilesh Bhandari, Member
	7. Shri Satya Natarajan, Member
739.	oneshotphotographysvks1@gmail.com
740.	Our Race, visinaa048@ gmail.com
741.	Shri Oviyan K, 1 ayothidhasar nagar, Madurai-614154
	oviyankanna@gmail.com info@jhatkaa.org
742.	Shri P Mallikharjuna Rao,Hyderabad pmkrao72@gmail.com
743.	Shri P. Pasupathy, agpasupathy@gmail.com
744.	Shri P. Prakash, prakasharasu123@gmail.com
745.	Shri P. Raghuveer, it4dss@gmail.com info@jhatkaa.org
746.	Shri P. Raghuveer, Flat No. 205, Sri Tirumala Prestige Apartments, Hill Top Colony, Erramanzil, Hyderabad - 500 082
747.	Shri P. Tamilselvam., Rtd. PSU officer, Vellore,
	selvamtamil.bsnl@gmail.com
748.	Shri P. Thiruvalluvan, p.thiruvalluvan1@gmail.com
749.	Shri P. Thiruvalluvan, pthiruvalluvan9@gmail.com
750.	Shri P. Vasanth Raj, Salem, Tamilnadu, vrgarlands@gmail.com
751.	Shri Pa. Bharatirajaa, bharathirock37@gmail.com
752.	Shri P.A. Kalidhasan palaiyankalidhasan@gmail.com.
	kalidhasanpalaiyan@gmail.com
753.	Shri Padmanagarajan, cobraking1993@gmail.com
754.	Shri Pagala Prudhvi, Ganganagunta- 517507, Tirupati
	prudhvipower.pp@gmail.com info@jhatkaa.org
755.	palanisamy.mayavan1953@gmail.com
756.	pandieswaran186@gmail.com
757.	Shri Pandiyan, pandiyanindiacyr@gmail.com
758.	Shri Pankaj Singh, A Narayanapura, Bengaluru-560016
	pankajking04@gmail.com info@jhatkaa.org
759.	Shri Partha Sarathy, Mylapore- 600004, Chennai
	ramcinema9@gmail.com, info@jhatkaa.org
760.	Shri Pasupathy, tpasupathy1@gmail.com

Sl. No.	Name
761.	Patiasil Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com
762.	Shri Pavan Kumar, #21,1st Cross Kenchenahalli, Rajarajeshwari Nagar-560098
763.	Shri Pavan Kumar, Electronic City-560100, Bangalore,
	pavangrandhi123@gmail.com
764.	periyasamypsy@gmail.com
765.	Shri Peruamal, Gram Sabha, GP-Haldi, District Balangir, Odisha, keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
766.	perumallakshmana67@gmail.com
767.	perumasekar24@gmail.com
768.	Phasikhol Gramsabha AT-Phasikhol, P.OBadapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029, padmalaya103@gmail.com
769.	Shri Phuduku Sabar, on behalf of Mudakani Gram Sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
770.	pkpratna@gmail.com
771.	Shri Ponnuppandian, ponnaiyathevan457@gmail.com
772.	Shri Ponnusamy S, 32, Kannimar Kovil Pudur-638661 Tiruppur
773.	ponraja3007@gmail.com
774.	Shri Poonam Saini, Landscape Architect and Research Scholar, poonam.phd261la20@spa.ac.in
775.	Shri Pounvel, velpounvel@gmail.com
776.	powerparasu2@gmail.com
777.	Shri Prabakaran Veera Arasu, Poovulagin Nanbarkal (Friends of Earth), 12th Street, Vaigai Colony, Ashok Pillar, Chennai-600083
778.	prabakarandhilipan@gmail.com
779.	prabakarankannan881@gmail.com
780.	Shri Prabhakar Thayumanavan, pat.rawlinsons@gmail.com
781.	Shri Prabhakaran Veeraarasu, Ramakrishna Nagar-600048, Chengelpet, prabhakaranenvi@gmail.com info@jhatkaa.org
782.	Shri Prabuddha Gaikwad, Solapur-413004,
	prabuddhagaikwad01@gmail.com info@jhatkaa.org
783.	Shri Pradeep Arjunan, Denalai, Coonoor-643102,
	pradeeparjunan.nk@gmail.com info@jhatkaa.org
784.	Shri Pradeep Ghumare p_ghumare@yahoo.co.in
785.	Shri Pradeep Kumar G, urspradeep86@gmail.com
786.	Shri Pradeep Mokardkar, President, Poinguinkarancho Ekvott judas.barreto1967@gmail.com
787.	Shri Pradeep S, pradee.sp.94@gmail.com
788.	Shri Pradeep Singh, Advocate, District Bar Association, Chamoli (Gopeshwar), Gram- Sagar, Post- Gwad Devaldhar, District – Chamoli, Pin- 206401.
789.	Shri Pradip Chatterjee, National Convener, NPSSFW
	npssfw@smallscalefishworkers.org

Sl. No.	Name
790.	Shri Pradip Kumar Mahapatra, General Secretary, Paschimbanga Vigyan Mancha, 162-B, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata – 700 014
791.	Shri Pradyumna Behera, on behalf of Community Network Against Protected Areas (CNAPA)
792.	Shri Prakaran Veeraarasu, on behalf of Poovulagin Nanbargal
793.	Shri Prakash Manivel, Thular east street, Sendurai-621719, Ariyalur
794.	Shri Prakash Shrivastava, D-270, Old Minal Residency, Bhopal-462023 <u>prakritii 2000@yahoo.com</u>
795.	prakashking561@gmail.com
796.	Prakriti Banchao Adivasi Banchao Mancha, Ajodhya Hill, District - Purulia West Bengal, prakritibanchaoadivasibanchaom@gmail.com
797.	Ms. Prakriti Srivastava, I.F.S, PCCF, Kerala Forest Department
798.	Shri Pranab Doley, Assam, JA Shivu, Karnataka, Pradyumna Behera, Odisha, Sharanya Nayak, Odisha, OSR Rajaraman, Tamil Nadu
799.	Shri Pranav Kalra, 4, Bamroli Road, Godhra-411045, pranavkalra66@gmail.com info@jhatkaa.org
800.	Shri Pranav Takkar, Pandit Parth Extension, Delhi-110051, pranavtakkar510@gmail.com info@jhatkaa.org
801.	Ms. Praneti Lawange, pranetilawange@gmail.com
802.	Shri Prasadkumar GM, Byndoor Udupi District
803.	Shri Prasanna Hial, on Behalf of Gadagada bahal Gram sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
804.	Shri Prasanth D, prasanthdeep8@gmail.com
805.	Shri Prasanth Muthuraman, 1/680, Sivasakthi Nagar, Pamban-623521
806.	prasanth1601n@gmail.com
807.	Shri Prasath Renganathan, Manjanviduthy, Pudukkottai-622303
808.	Ms. Pratibha R, pratibha.rk@gmail.com
809.	Shri Praveen, romalan.june@gmail.com
810.	Shri Praveen Bhargav, Trustee - Wildlife First, Former Member - National Board for Wildlife, Author-Wildlife Law for Rangers wildlifefirst@gmail.com
811.	Shri Praveenkumar R, praveen.r608612@gmail.com
812.	Shri Pravin Mathew, Plot No. 326/327,G2, Baba Nagar 2nd Main Road, Villivakkam- 600049, Chennai
813.	Shri Pravin Mote, pravin.mote.cpc@gmail.com
814.	Shri Pravinsingh Shedgaonkar, pravinsingh03@gmail.com
815.	Shri Premkumar D, Oomerabad, Ambur-635808,
	premkumar19be@gmail.com
816.	Shri Premkumar R premkumarnellai@gmail.com
817.	President, Jangle Adhikar Committee, Bandhabhuin, Jhillimili,
	mundakande40@gmail.com
818.	President/Secretary, National Environment Care Federation (NEFC), Mangalore, Karnataka
819.	Shri Prince Nadar, chelliahv7@gmail.com
820.	prithiselva@gmail.com
821.	Ms. Priya Kumari, Dharamapuri-636906, Tamil Nadu,
	ranipriya9745@gmail.com, info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
822.	priyaalemane@gmail.com
823.	Ms. Priyadarshini J, 560085 Bangalore, info@jhatkaa.org
824.	Ms. Priyanka Gunjikar, 4, Vrindavan society, Near Mhatre Bridge, Pune -411030
825.	Ms. Priyanka Verma, Delhi-110001, info@jhatkaa.org
826.	Prof. Richard Hay, Ex MP, Asset Rangoli, 12 B, Maradu, Kochi-682304.
827.	Prof. (Dr.) Tejbir Singh Rana, Department of Geography, Shivaji College, University of Delhi, Delhi-110027
828.	Shri Pugal Suriya, suryapugal619@gmail.com
829.	Shri Pugal, suryapugal619@gmail.com
830.	Shri Pugazhanthi. M, ponp51593@gmail.com
831.	Pullikata Gramsabha, Odisha, phinyalata143@gmail.com
832.	Shri Purushothaman. N, Kumbakonam, Tamil Nadu,
	kelvin.purushoth@gmail.com
833.	Shri Pushkar Kulkarni ramanm764@gmail.com
834.	Shri Pushkar.V.Kulkarni D-901, Kapil Aasamant, Near Shivshakti chowk Pashan Sus road, Pashan, Pune – 411 021
835.	Shri Pushpa Lingam Padmaraj, padmarajpushpalingam@gmail.com
836.	pushparajdme6@gmail.com,
837.	pushparajr715@gmail.com
838.	R J Travels, No.1 MGR Street, 2nd Cross, Padhuvanchery, Chennai – 126, rraja.sekaran@rediffmail.com
839.	Shri R Prabakaran, prabakaranbsms@gmail.com
840.	Ms. R Swarnalatha <u>r.swarnalatha@gmail.com</u>
841.	Shri R. Anbarasan, aanbarasan552@gmail.com
842.	Shri R. Anbarasan, Naam Tamilar Party, Thanjavur District Secretary, anbuyalinianbu@gmail.com
843.	Shri R. Bhuvanendran Tirunelveli, nellainanban@gmail.com
844.	Shri R. Elango, r.elango125@gmail.com
845.	Shri R. Gopinathan, srvgopi@gmail.com
846.	Shri R. Gowtham, gowtham.pr002@gmail.com
847.	Shri R. Hariprasath, hariprasath985@gmail.com
848.	Shri R. Kannan, abrezbuilding@gmail.com
849.	Shri R. Sanjiv, Deputy State Secretary, Anti Bribe Wing, Naam Tamilar Party, kaiyootuolippu13@gmail.com
850.	Shri R. Siva, rsiva4407@gmail.com
851.	Shri R. Srinivasan, Sales Officer North Arcot Zone, SKM Siddha and Ayurvedics Pvt. Ltd., Vellore, s.srini1992@gmail.com
852.	Shri R.Mohan, Tamil Nadu, rm.mohan2010@gmail.com
853.	Shri R.Murugananatham, shavanshavan349@gmail.com

Sl. No.	Name
854.	Shri R.Sivaramakrishnan, sivanithe@gmail.com
855.	Shri R. A. Murugananda, shavanshavan349@gmail.com
856.	Shri Rabi Sabar, padmalaya103@gmail.com
857.	radhakrishnan662003@gmail.com
858.	raghu011989@gmail.com
859.	Shri Raj Kumar, 8/1, 13 solaiamman Kovil Street, Purasawalkam-600007
860.	Shri Raja C., poovairaja2012@gmail.com
861.	Shri Raja. M, North kattur, Trichy 19, rajaharini5050@gmail.com
862.	rajangreenaqua@gmail.com
863.	Shri Rajaram, rajacomputer2018@gmail.com
864.	Shri Rajaselvam M, South Boag Road, Chennai-600017
865.	Shri Rajavel. R, rajavel328@gmail.com
866.	Shri Rajeev Savant rajeev savant@yahoo.com
867.	rajejayamani@gmail.com
868.	Shri Rajen Tudu, President, Bharat Jakat Majhi Pargana Mahal Juwan Mahal Purulia District rajentudu1973@gmail.com
869.	Shri Rajendra Thilahar, Chengalpet-603101, info@jhatkaa.org
870.	rajendranlic1964@gmail.com
871.	Shri Rajesh Gosalia, C- 314 Antophill Warehouse, Wadala East-400037 Mumbai
872.	Shri Rajib Baskey, Raghunathpur, Dahijuri, Binpur, Jhargram-721504, rajibbaskey 62@gmail.com
873.	Shri RajiniKanth B, rajini.rkn@gmail.com
874.	Shri Rajiv Gandhi, rajivgrk@gmail.com
875.	Shri Rajkumar Vellore, rajbhava10@gmail.com
876.	Shri Rajmohan Jegatheesan, 199, Lakeview Road West mambalam-600033, Chennai
877.	Rajpur Gramasabha, nuangabalanhadra@gmail.com
878.	Shri Raju K, 255, 5th cross st, Yeshwanth nagar, Madambakkkam, Tambaram- 600126
879.	Shri Ram Kumar. M, ram447495@gmail.com
880.	ramalingamsk86@gmail.com
881.	Shri Ramamoorthy, ramamoorthyabi3042@gmail.com
882.	Shri Raman, ramanm764@gmail.com
883.	Shri Raman
884.	Shri Ramanan Ganapathy, rini_4444@yahoo.com
885.	Rambuli Gramasabha, saratmalick306@gmail.com
886.	Shri Ramesh Sabar, padmalaya103@gmail.com
887.	rameshlp001@gmail.com
888.	Shri Ramkumar, sbramkumar1@gmail.com
889.	Shri Ramkumar B, s.b.ramcivil2828@gmail.com

Sl. No.	Name
890.	Shri Ranen Bhadra , 4/C Dhrubesh Chatterjee Lane, PO: Uzarpara, Pin: 712258 Dist: Hooghly
891.	Shri Ranjan Sabar (Village President), padmalaya103@gmail.com
892.	Ranpudi Gramsabha AT-Rampudi, Po-Pandiripada, Via-Polasara, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761105 padmalaya103@gmail.com
893.	Shri Rans, ranscatb@gmail.com
894.	rarayaraudo@gmail.com
895.	Rasaiya Rasa, rasaiyae@gmail.com
896.	Rastrya Advasi Ekta Parisad, Rourkela
897.	Shri Ravi Palanisamy, Mondipalayam, Bhavani-63831, mailravipkumar@gmail.com info@jhatkaa.org
898.	ravi.sankartheni@gmail.com
899.	Shri Ravichandran k, kraviad05@gmail.com
900.	Shri Ravina Raj Kohli ravinakohli13@gmail.com
901.	Shri Ravindra Nath Saxena IFS (Retd.), Former Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh Bhopal – 462026 (M.P.)
902.	Shri Ravindra Sinha, Flat no C-703, Camellia Apartments, Baner Pashan Link RoadPashan, Pune – 411 021
903.	Shri Ravindra Velip, H.No. 39/04, Velipwada Caurem Quepem, Goa
904.	Shri Ravivarma Kumarasamy, Kuruvikkarambai, Post Petavurani Taluk-614802, ravivarma.lk@gmail.cominfo@jhatkaa.org
905.	Shri Raymond, raymond.aj@icloud.com
906.	rganesh6196@gmail.com
907.	Shri Richardson Colaço, H. No 1545, Udden Shiroda, Ponda Goa
908.	Shri Rishabh Karade, Bibwewadi, Pune-411037,
	karadekailasmamta@gmail.com info@jhatkaa.org
909.	Shri Rishabh Pardeshi, House no 1165, Olkaiwadi, Lonavala-41040,
	ritzmillan@gmail.com, info@jhatkaa.org
910.	Shri Rishi Kant Chaudhary, Durg -491001, Chhattisgarh
911.	Shri Rishi Senthil, Karamadai, Chikkarampalayam-641104,
	senvai96@gmail.com info@jhatkaa.org
912.	Shri Rishi senvai96@gmail.com
913.	Ms. Ritanya, ddharan410@gmail.com
914.	Shri Ritwick, N-73 Lower Ground Floor, Greater Kailash 1,New Delhi
915.	rockfortnarayanan@gmail.com
916.	rocksampath84412@gmail.com
917.	Shri Rohit M, Tirupur-641652, info@jhatkaa.org
918.	Shri Rohit Menon, Mulund-West-400080, Mumbai,
710.	funkyduderohit@gmail.com_info@jhatkaa.org
919.	Shri Rohit Pandit, Secretary General, Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), PHD House (3 <sup>rd</sup> Floor), 4/2 Siri Institutional Area (Opposite AsianGames Village), New Delhi – 110 016 (India).

Sl. No.	Name
920.	Shri Rohith, Udupi, Karnataka rohithworkstuff@gmail.com
921.	rohithdevaraj1@gmail.com
922.	ronikasm1102@gmail.com
923.	Shri Rooban, Coimbatore district Secretary, Naam Tamil Party, Environmental Wing, roobancbe@gmail.com
924.	Ms. Rosaria Pimenta, Convent of Jesus and Mary, Palanpur-385001, cjmv2009@gmail.com info@jhatkaa.org
925.	Roseipadar Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057, deepakgonda68@gmail.com
926.	Shri RP Ganesan BE, 268/2B2, Thennamplayam, Arasur PO, Sulur TK, Coimbatore DT, Tamil Nadu - 641407
927.	Ms. Rupa Majhi, on Behalf of Lahumunda Gram Sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
928.	Shri Rupadhar Bag, AT/PO Kuibahal, Via- Turekela, Dist. Balangir , Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
929.	Shri S Jothimani, Member of Parliament, Karur, Tamil Nadu jothimanimpoffice@gmail.com
930.	Shri S Karthick, karthick740@gmail.com
931.	Shri S Lohith, Vyasar Nagar 6th Street , Vyasarpadi , Chennai -600039, lohithkumar.s.1008@gmail.com info@jhatkaa.org
932.	Shri S Nagaraj, nr761982@gmail.com
933.	Shri S Srikanth, sricbi12@gmail.com
934.	Shri S. Arun, Subsistence Farming, arunkumar22077@gmail.com
935.	Shri S. Edward Xavier, sedxavi93@gmail.com
936.	Shri S. Jaya Prakash, sjayaprakash219@gmail.com
937.	Shri S. Kanojkumar, dawankanoj92@gmail.com
938.	Shri S. Kumar, natlinthara@gmail.com
939.	Shri S. Kumaresa Moorthy, s.kumaresan85@gmail.com
940.	Shri S. Kurlanda Gram Sabha, Post- Tarangada, District- Gajapati, Odisha
941.	Shri S. Mohith, home2office2016@gmail.com
942.	Shri S. Murugapandi, murugapandi877@gmail.com
943.	Shri S. Nandakumaar, nanthuanil9596@gmail.com
944.	Shri S. Prabakar, arulyps@gmail.com
945.	Shri S. Radhakrishnan, ntk148nakkambadi@gmail.com
946.	Shri S. Rajan, vnselvar17@gmail.com
947.	Shri S. S. Karthik, sskarthikmech@gmail.com
948.	Shri S. Sarathraj, rrksarathraj@gmail.com
949.	Shri S. Sharmi, sathishkumar_tms@live.in
950.	Shri S. Siva, sivajudo1990@gmail.com
951.	Shri S. Varun, State Joint Secretary of Environmental Wing in NTK, sssvarun22@gmail.com

Sl. No.	Name
952.	Shri S. Vetriselvi, Assistant Commissioner of GST Retired, Thanjavur, pranilathayus@gmail.com
953.	Shri S.Gnana Prathaban, killer.prathap@gmail.com
954.	Shri S.Gunasekaran, right2work6@gmail.com
955.	Shri S.Kumaran, Naan Tamilar Katchi (NTK), (Environmental Wing), Chennai, aquagreen2011@gmail.com
956.	Shri S.M. Selvakumar, selvakumarsm92@gmail.com
957.	s.u.madan1974@gmail.com
958.	Shri SA Arulraj Selvamarry, Sriperumbudur -602105, Vallam, arulfuel81@gmail.com info@jhatkaa.org
959.	Ms. Saanvi Roshan kurunji, Mangalore-574142, saanvikurunji5@gmail.com info@jhatkaa.org
960.	sabari.in.heaven@gmail.com
961.	sabarishbala420@gmail.com
962.	Ms. Sabita D'costa, (Indian Citizen), sabitadcosta24@gmail.com
963.	Sachin Dave, Shardanahar Society, Paldi-400058, Ahmedabad sachin.dave9@gmail.com info@jhatkaa.org
964.	Sachin Yadav, C-101, Tivoli ,Godrej City, Ahmedabad-380054 sachinbyadav@gmail.com info@jhatkaa.org
965.	Sadat Khan, Subedarpalya Yeshwantpur, Bangalore-560022 sadatkhan411@gmail.com info@jhatkaa.org
966.	Shri Sadhu Charan Jarika, dharambirhembram76@gmail.com
967.	Vetri, jaya98411@gmail.com
968.	Shri Sagnik Sengupta, Director, Stripes And Green Earth Foundation sagnik@sagefoundation.in
969.	Shri Sahadev S H, Paschima Ghatta Jaagruti Vedike, Shivapura, Koppa Taluk, Chickamgalur District
970.	Shri Sahadev Shivapura, Shivapura, Suryadevasthana Post, Chickmagalur District-Koppa-560062
971.	sahitya9750mathurkar@gmail.com
972.	saikailasam@gmail.com
973.	Shri Sajjan Bhajanka, President, Federation of Indian Plywood & Panel Industry, 404, Vikrant Tower 4, Rajendra Place, New Delhi – 110008
974.	Shri Sakani Podar, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha, keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
975.	Shri Sakshi Khare, Banjara hills, Navi Mumbai-410206, itsmesakshi.khare@gmail.com info@jhatkaa.org
976.	Shri Sakthivel, shakthivelsjs@gmail.com
977.	Shri Sakthivel Duraisamy, Kamaraj Nagar-638301 Bhavani, dsvelavan@gmail.com info@jhatkaa.org
978.	Shri Samara Tudu, Manjhi Pargana Mahal, Keonjhar, Odisha-758001
979.	Shri Sambhav Jain, Nirman Vihar-110092, East Delhi, jainsambhav227@gmail.com info@jhatkaa.org
980.	Shri Samuel L Khobung, President, The Hmar Student Association, New Delhi.
981.	Shri Samy, adaikkalasamy@gmail.com
982.	Ms. Sandhiya Murugan, murugansandhiya087@gmail.com
983.	Ms. Sandra Fernandes, Sarpanch, Village Panchayat, Carmona, Goa
984.	Shri Sanjay Bramhane sanjaybramhane1968@gmail.com
985.	Shri Sanjay Kumar Srivastava, IFS (Retd) &, Praveen Chandra Tyagi, IFS (Retd), Formerly PCCFs (HoFF), Tamil Nadu
986.	Shri Sanjay. G, 21cs144@kpriet.ac.in

Sl. No.	Name
987.	Shri Sanjay. G, sanjay.gopalsamy2003@gmail.com
988.	Shri Sanjeev Gaur, IFS, CGM (Planning), Forest Development Corporation of Maharashtra Limited, Nagpur, Maharashtra
989.	Shri Sanjeev Gawade, Pune Maharashtra India, sanjeevgawade1@gmail.com
990.	Shri Sanjeev Gawade, Shantisheela Soc Plot No 18, Law College Road Pune -411016, Maharashtra State
991.	Shri Sanjeev Jagtap, Pune, jagtapsanjeev@gmail.com
992.	sanjeevbl9@gmail.com
993.	Shri Sankar Sabar, padmalaya103@gmail.com
994.	Shri Sankaran C, sankarcsurvey@gmail.com
995.	Shri Sankaran Lakshmanan, slakshman28@gmail.com
996.	sankarmari00@gmail.com
997.	santhosh190183@gmail.com
998.	santkola438@gmail.com
999.	Shri Santosh Shintre, samadhan,prabhat road 9th lane,Pune-411004
1000.	Shri Saran, dssaran14122002@gmail.com
1001.	Shri Saran Subramaniam, 17, Gandhinagar-641024, Coimbatore, saran.s87@gmail.com, info@jhatkaa.org
1002.	Shri Saranya Inbaa, 2/182, Mel Theru, Neikkarapatty, Salem-636010
1003.	Shri Saranya kumaresan, KGM Hospital, Coimbatore- 641062, drsaranyadeepak@gmail.com, info@jhatkaa.org
1004.	Shri Saranya Raghavan, sahaatravels2014@gmail.com
1005.	Shri Saravana Kumar, 1/110/51-A ,Sri Senthil Nagar ,Iduvai P.O. Tirupur -641687
1006.	Shri Saravana Kumar, 3/90-A, Avalchiinampalayam- 642123
1007.	Shri Saravanan, sstamizh19@gmail.com
1008.	Shri Saravanan, abcsaravanan@gmail.com
1009.	Shri Saravanan Moorthi, Ramadoss Street, Cuddalore-607001, saravanansame84@gmail.com, info@jhatkaa.org
1010.	saravannak@gmail.com
1011.	Shri Sasikumar G, sasikumar.g90@gmail.com
1012.	Shri Sastha, sasathasastha1996@gmail.com
1013.	Shri Satheesh S, 1/280 Gadambur,oomerabad Post, Ambur Taluk, Ambur-635808
1014.	Shri Satheeshkumar S, kings1318sks@gmail.com
1015.	Shri Sathishkumar, thamizhsathish2106@gmail.com
1016.	sathishkumartamil13@gmail.com
1017.	sathiyavenkatesan2425@gmail.com
1018.	Shri Sathya. V, tamilanaraciyal@gmail.com
1019.	sathya83.r@gmail.com
1020.	savariraj2003@gmail.com

Sl. No.	Name
1021.	Shri Saviola Fernandes <u>iteng.sferns@yahoo.co.in</u>
1022.	Ms.Savitha Nagabhushan, Nagabhushansavitha, Mysuru-570009, info@jhatkaa.org
1023.	Shri Seeman Thambi, udayatamizhan@gmail.com
1024.	Shri Seenivasan M, seenimsenthil@gmail.com
1025.	Shri Seenuvasan V, vaseenuvasan@gmail.com
1026.	Shri SeKi, sskrishnan9582@yahoo.com
1027.	Shri Selin Paulraj, Tamilnadu, selinpaulraj.civil@gmail.com
1028.	Shri Selva Kumaran, Palaya Thottam- 638505 Gobichettipalayam, dravidkumaran.19@gmail.com info@jhatkaa.org
1029.	selvainge@gmail.com
1030.	Shri Selvakumar, selvam17781@gmail.com
1031.	Shri Selvakumar. P, selvadmech@gmail.com
1032.	selvakumarsm92@gmail.com
1033.	selvam17781@gmail.com
1034.	selvam2035@gmail.com
1035.	Shri Selvendran A, khallaas123@gmail.com
1036.	sengelsoren@gmail.com
1037.	Shri Senthamil selvan MP, 16 akr 3rd Street, Valasaravakkam-600083
1038.	Ms. Serena Chopra, New Delhi serenachopra31@gmail.com
1039.	Shri Seshadri Vasu, Sobhitha seshadri, Sai Sunayana, Sai Chanasya, Lakshmidevamma seshadri.vasu@gmail.com
1040.	Shri Sethupathy. M, sethupathyse10@gmail.com
1041.	Shri Shahbaz Ahmad IFS Retd., Ex-Principal Chief Conservator of Forests & Chief Wildlife Warden, MP, 81/3, North Malaka, Prayagraj, UP- 211001
1042.	Ms. Shailaja Deshpande, on behalf of Jeevitnadi Living River Foundation, jeevitnadi@gmail.com
1043.	Ms. Shailaja Deshpande shailajadesh@gmail.com
1044.	Shri Shailender Singh, Vpo Kolar, Teh. Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.), 173001
1045.	Shri Shailesh Dathe, Shailesh Sathe, Datta Nagar , Panchavati Nashik-422003 , shailesh.7021@gmail.com info@jhatkaa.org
1046.	shajakhan.executive@gmail.com
1047.	Ms. Shalini, shalininetpark@gmail.com
1048.	Shri Shamsher Singh on behalf of the Residents of Villages
	residentsofvillages@gmail.com
1049.	Shri Shankar Prakash, aspmajaa@gmail.com
1050.	shankarr.1986@gmail.com
1051.	shanmugatamizhar9@gmail.com
1052.	Shri Shanu Charan Murmu, Rastriya Adivasi Ekta Parishad, District President/Co-ordinator, District- Mayurbhanj, Odisha, karanhansdah21@gmail.com
1053.	Shri Sharad Paliwal, President, Paryavaran Prerna Maharashtra, paliwalsharad10@gmail.com

Sl. No.	Name
1054.	Ms. Sharmila Deo, Pune. sharmiladeo@gmail.com
1055.	sheikabdulla7383@gmail.com
1056.	Shri Shekhar Phatak (Indian Citizen), shekhar.phatak@gmail.com
1057.	Shri Sheriff Mohamed Nagoore Mohideem, West Street, Achanputhur -627803
1058.	Ms. Sherlin Pinto, Amtady, Bantwal T.Q., Karnataka-574211, Bantwal, sherlinneil@gmail.com info@jhatkaa.org
1059.	Shri Shirish Kanitkar, Ecologist, Consultant, shirishkanitkar@yahoo.com
1060.	Shri Shiv Ka Bhandar, sivapaed@gmail.com
1061.	Shri Shiva Kumar, sivakumarlee20@gmail.com
1062.	Shri Shivam Kushawah, Etawah, Uttar Pradesh-206120 Bakewar , Etawah, shivamindald@gmail.com info@jhatkaa.org
1063.	Shri Shogun Fernandes , President , Chicalim Youth Farmers Club, cyfarmersclub@gmail.com
1064.	Ms. Shomona Khanna, Advocate, Supreme Court of India shomona@gmail.com
1065.	Shri Shree Arun Kumar, arunkagitham05@gmail.com
1066.	Shri Baijnath Pandey, S/o Late Shri Baikunth Nath Panday, 127/317 W Block, Kesav Nagar, Kanpur-208014
1067.	Shri D.A. Narayanan, Advocate, 312, Lawyers Chambers, District court complex, Gopalapuram, Coimbatore-641018, Tamil Nadu
1068.	Shri Dinesh Kumar Agrawal, S/o Late Moti Lal Agrawal, 1/24, First Floor, Charmwood Village Eros Garden, Suraj Kund, Faridabad-121009
1069.	Shri Jitendra Chaudhary, Formar MP, National Convener, Aadivasi Adhikar Rashtriya Manch
1070.	Shri K.K. Singh Lohali Jalal, Nainital, Uttrakhand
1071.	Shri Lalaji P., Secretary, Blackrock Hill Planters Association, Nagercoil,
1072.	Shri M.S. Selvaraj, Campaign for Survival and Dignity-Tamil Nadu, Vyavasaayikal Thozhilalarkal Munnetra Sangam, Tamilnadu Pazhangudi Makkal Sangam
1073.	Shri Rajan Singh, R/o Lane No. 5, Lower Tathar, Pooja Colony, Bantallab, Jammu-J&K UT
1074.	Shri. L Kuki President, Shri S. Jeme, Working President, Shri L. Hlima Keivom, General Secretary, Indigenous People Forum's, HQ- Haflong, N.C. Hills, Assam, Pin-788819.
1075.	Shri. Sanjay Deshpande, Shrushti Parayavaran Mandal, Nagpur
1076.	Ms. Shristy Mukherjee, Shristy, Bangalore-560032, shristymukherjee9@gmail.com info@jhatkaa.org
1077.	Ms. Shriya M, Laburnum, Gurgaon-400069, shriyam@gmail.com info@jhatkaa.org
1078.	Ms. Shruti Mahajan, 699, Saraswati Vihar, MG Road, Gurgaon -122002
1079.	Ms. Shweta Vernekar, shweta@parisar.org
1080.	Shri Shyam K, shyam.kamaraj@gmail.com
1081.	Ms. Shyamala Das, Bengaluru-560066, shdas.athashri@gmail.com info@jhatkaa.org
1082.	sinivasaperumal@gmail.com
1083.	Siunapadar Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057, deepakgonda68@gmail.com
1084.	Shri Siva, sivaoct2k@yahoo.com
1085.	Shri Siva R, Ozone Greens, Chennai-600100, sivarajantrgml@gmail.com info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
1086.	siva999494@gmail.com
1087.	Shri Sivabalan Chidhambaram, Journalist, Dream T amilnadu-(Junior Vikatan).
1088.	Shri Sivabalan Chidhambaram, No.14/A, Sakthi Nagar, Nerkundram, Chennai-600107
1089.	Shri Sivasakthivel, sivasakthi0981@gmail.com
1090.	Shri Skanda, skandaprasad93@gmail.com
1091.	Shri SL Kumar, Vyasar Nagar 6th Street, Chennai-600039, lohithkumar.1008@gmail.com info@jhatkaa.org
1092.	Ms. Smitha Naik, smithasanjeevnaik@gmail.com
1093.	snaveen.nn@gmail.com
1094.	Ms. Sneha C, Kannur-670142, Kerala
1095.	Shri Snehasis Sarkar, Silchar-781011 Guwahati, snehasis056@gmail.com info@jhatkaa.org
1096.	Ms. Sobha Royyuru IFS Retd, Advisor to Govt.of Telangana , Forestry Affairs, Hyderabad, Telangana , India.
1097.	Shri Soma Shekhar Venugopal, 475, 9th Cross BSK 3rd Stage, Bengaluru-560085
1098.	Ms. Soniya DE, magadi road, Bengaluru-560091
1099.	Ms. Soniya Tadvi, Jalgaon, Jalgaon - 425002, info@jhatkaa.org
1100.	soulnathan37@gmail.com
1101.	Shri Soundarraj M, soundarrajmurugan44@gmail.com
1102.	Shri Sourav Mukherjee, Howrah, West Bengal, prakritibadi@gmail.com
1103.	Shri Sourav Paul, Electronic City, Bengaluru-560100, souravpnccs@gmail.com info@jhatkaa.org
1104.	sowkathali23@gmail.com
1105.	Shri Sreekanth sreekanthsv8@gmail.com
1106.	Shri Sri Blr, Bengaluru-560027, sri4blr@gmail.com info@jhatkaa.org
1107.	Shri Sri Gopinath Majhi, Convenor, Campaign for Survival and Dignity, Odisha <u>csdorissa@gmail.com</u>
1108.	Shri Srichandra Mallik, on behalf of Khujen Gram Sabha, AT Khujen P.O. Ghunesh, Via H.S.Road, District Balangir, Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1109.	Shri Srikant Verma srikantjaraikela@outlook.com
1110.	Shri Srikant Verma, Divisional Forest Officer, Ranchi Forest Division, Ranchi, Block- F, Van Bhawan, Doranda
1111.	Shri Srikanthan V, 32, 14th Cross New Colony, Chromepet-600044
1112.	Srikrushnasara Gramsabha At-Srikrushnasara, Po-Sankuda, Via-Sumandal, Dist- Ganjam, Odisha, Pin-761035, padmalaya103@gmail.com
1113.	Shri Srikumaran, For Karnada Estate- Melta Div., Gunumalai House, Virudhunagar-6260001
1114.	Shri Srimuralidharan, srimuralidharan03@gmail.com
1115.	Shri Srinivasan.M, msrinidpintk@gmail.com
1116.	srivi.lingam@gmail.com
1117.	sspandiyan9124@gmail.com
1118.	Shri Stalin, stalinsg100.sm@gmail.com
1119.	Shri Stanley Balasingh.S D, stanleybalasingh@gmail.com

Sl. No.	Name
1120.	stylethiru4@gmail.com
1121.	Shri Su. Ranjith Kumar, ranjithraj1991143@gmail.com
1122.	subashl35072129@gmail.com
1123.	Shri Subir Mario Chowfin, Gadoli House,Gadoli Fee Simple Estate,Pauri,District Pauri Garhwal,Uttarakhand - 246001.
1124.	Shri Subodh Bansal, 3, North Idgah Colony, Agra 282010, UP, subodh5050@gmail.com
1125.	Shri Subramani Kandasamy, 8 and 9, Tulips Sherwood, Thuthipattu-632011, Vellore
1126.	Shri Sudam Bhoi, H.S. Road, District- Balangir, Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1127.	Shri Sudarshan Ramakrishnan, 3/1/148, T.Kallupatti-625702
1128.	Shri Sudhansu Sekhar Mishra, Retd Forest Officer, Govt of Odisha, Flat no c 203, PDN Exotica Apartment, Panchasakhanagar, Dumduma, Bhubaneswar, Odisha, Pin 751019
1129.	Shri Sudharsanam Subramani, 268, AV salai, Veerapuram, Ch - 55, Avadi-600055
1130.	Shri Sudip Birade, Nashik-422001, sudipbirade7@gmail.com info@jhatkaa.org
1131.	suhailrasith1996@gmail.com
1132.	Sujanith Shetty, Vijayanagar , Bangalore-560072, info@jhatkaa.org
1133.	Shri Sujit Vetal, Manjinagar, Narhe-411041, Pune
1134.	sujitlomga7@gmail.com
1135.	Shri Sukumar, Chennai, Thamilnadu, plsugu116@gmail.com
1136.	Shri Suman Sabar, padmalaya103@gmail.com
1137.	Shri Sumathikabilan, sumathikabilan81@gmail.com
1138.	Ms. Sumi Munda, At-Birtola, Po-Darjing, Ps-Lahunipara, Dist-Sundargarh, Pin-770040, State-Odisha, punampurty0502@gmail.com
1139.	Ms. Sumitha, bayamariyaan.nt@gmail.com
1140.	sunai1990126@gmail.com
1141.	Shri Sundar Mohan Soren, Mayurbhanj Hanat Pargana, Shri Biram Soren, Mayurbhanj, Shri Hanat Paranik, Bharat Jakat Majhi Pargana Mahal, Majhi Pargana Mahal Bakhul, Pawra, Ghatsila, District- East Singbhum, Jharkhand biramsoren83@gmail.com
1142.	Shri Sundararajan P., Thambu Chetty Street, Chennai-600001, 600001 lawyersundar@gmail.com info@jhatkaa.org
1143.	Shri Sundermohan Soren and Biram Soren, Bharat Jakat Majhi Pargana Mahal, biramsoren83@gmail.com
1144.	Shri Sunil Chhabra, Aamgam Road, Sanjan-396150, chhabra.sunil.58@gmail.com info@jhatkaa.org
1145.	Shri Sunil Harsana, Independent researcher and conservationist, Resident of Mangar Village, Faridabad, Haryana -121004
1146.	Ms. Sunita Dhairyam (Jayapathy) (Indian Citizen), sdhairyam@gmail.com
1147.	Ms. Suparna Sankaran, Flat GB, Sivedha Apartments, New no 27, 3rd Avenue, Chennai-600090
1148.	Shri Suresh, sanjur707@gmail.com
1149.	Shri Suresh Kumar Vadivel, sureshsince82@gmail.com
1150.	sureshaachimuthu@gmail.com

Sl. No.	Name
1151.	Shri Sureshbabu R, Karavalimathappur, Coimbatore-641668, 641668 rsureshbabu101@gmail.com info@jhatkaa.org
1152.	sureshdivya43@gmail.com
1153.	sureshtanishq29@gmail.com
1154.	Shri Suru Sing Majhi , on behalf of Gunchijor Gram sabha , zindabadsangathanbgr@gmail.com
1155.	Shri Susan Sharma, C-2490, Sushantlok-122009, Gurgaon
1156.	Ms. Suwathy Venugopal, S.V.Puram, Venkatesa Mills, Udumalpet-642128, suwathyvenugopal@gmail.com info@jhatkaa.org
1157.	Swacch Association, swacchnagpur@gmail.com
1158.	Shri Swaminathan E, Nathapattu Housing Board, Cuddalore-607001, swaminathansnp@gmail.com info@jhatkaa.org
1159.	Shri Swaminathan G L, 37/63, Kala Complex, 4th Avenue, Ashok Nagar, Chennai- 600083
1160.	Shri Swapnil Gupta, 302 Tower 3 ILD Greens Sector 37C, Gurgaon-122001
1161.	Ms. Swathilakshmi S, swathisekar0308@gmail.com
1162.	Ms. Swati M, Indiranagar, Bangalore-560008, am.i.swati@gmail.com info@jhatkaa.org
1163.	Shri Swayambar Majhi , on behalf Phulakimunda Gram sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1164.	Shri Syed Naqvi, Jaipur-302004, smoiz123@gmail.com info@jhatkaa.org
1165.	Shri T .Franklin, 17 A, Henry Road, Nagercoil, T amilnadu.
1166.	Shri T Deiva Arul, deiva.t@hap.in
1167.	Shri T Deivaarul , deivaarul98@gmail.com
1168.	Shri T Deivaarul, ntdarul333@gmail.com
1169.	Shri T Pandiyan cheyyar pandiyanindiacyr@gmail.com
1170.	Shri T. Mayilraj, tamilantamayilraai@gmail.com
1171.	Shri T. Mohanta, General Secretary, Society of Geoscientists & Allied Technologists, Plot No. ND-12 (Part), V.I.P. Area, P.O.: IRC Village, Bhubaneswar - 751 015, Odisha, India
1172.	Shri T. Vinmeen Pandian, kperipandian@gmail.com
1173.	Tabhabania Gramsabha At-Tabhabania, Po-Mardamekha, Via-Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032, padmalaya 103@ gmail.com
1174.	Tamil Ulagan Sanjay, sanjaisagu321@gmail.com
1175.	Tamil, ghostofjustice2@gmail.com
1176.	tamilan.photography@gmail.com
1177.	Tamilnadu Tribal peoples Assn, 103 / 4, Kannappan Kinatru Veethi, Anthiyur - 638501, erodevpg@gmail.com
1178.	tamizharasanr600@gmail.com
1179.	Shri Tamizharvan Thandayuthapany, Tamil Nadu, tamizharvan1991@gmail.com
1180.	Ms. Tannistha Lahiri, 396/9 Becharam Chatterjee Road, Kolkata-700034
1181.	Ms. Tanuja Aundhe, Raheja Gardens, Thane-400604
1182.	Ms. Tara Misra, Binny Crescent Rd, Benson Town, Bangalore-560046
1183.	Ms. Tatum Ghosh, Amrapali Silicon City, Noida-201304, tatumghosh@gmail.com info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
1184.	Shri Tej Vohra, Bangalore, Karnataka telltej@gmail.com
1185.	tejasvita.malhotra@gmail.com
1186.	Shri Tejaswi Kumar Pradhan, Advocate, S/o Late Muralidhar Pradhan, Chamber No. 5 (R.K. Garg Block), Supreme Court of India New Delhi, tejaswipradhan@gmail.com
1187.	Shri Teju Rana, At Semla, Po Kuibahal , Via- Turekela, Dist. Balangir Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1188.	Shri Thamilum Aramum, kollywooddaily2022@gmail.com
1189.	thanigaikarthika96@gmail.com
1190.	thanrajj848@gmail.com
1191.	Shri Thasarathan V, svtdass@gmail.com
1192.	Shri Theeran Thirumurugan,S/o Ganesan,Morepannai Fishing Village,Uppoor post, Thiruvadanai Taluk,Ramanathapuram District.
1193.	thillai97nathan@gmail.com
1194.	Shri Thiru, thirukumar732@gmail.com
1195.	Shri Thiru ragava Krishna, Thiruporur, Chennai-600001
1196.	Shri T Thirumalaikumar Thangaiah, Gandhi street, 2/107, Vedanthankal Nagar, Arasan kazani, Chennai 600126 Chennai, karthikumarmsd007@gmail.com info@jhatkaa.org
1197.	Shri Thiruvalluvan, p.thiruvalluvan1@gmail.com
1198.	Shri Tiak Bariha, AT/PO - Ghunesh, Via Harishankar Road, Dist. Balngir , Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
1199.	Shri Tommy Lobo, 53, Coconut Grove, Behind Deva Matha School, Horamavu, 560043 Bangalore
1200.	Shri Tony AR, E-503 Santha Towers Paruthipattu, Avadi Chennai-600071
1201.	Shri Toshesh Daulta, AFNOE, Sec-7, Plot-11, Dwarka-400095, New Delhi
1202.	Shri Trilochan Punji, Zindabad Sangathan, Balangir, Odisha
1203.	ts0582020@gmail.com
1204.	Shri Uday Kumar, Thanjavur-614205, Papanasam uday_tj@rediffmail.com info@jhatkaa.org
1205.	udayakmr5@gmail.com
1206.	Shri Udhayakumar TS, No 1c, 3rd Street, Jothy Nagar, West Tambaram, Chennai-600045.
1207.	Uhavan Art Gallery, tamilanvicky007@gmail.com
1208.	Shri Uma Shanker Singh IFS (Retd.), Director Vanashakti, 3/184, VibhavKhand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
1209.	Shri Umesh Athavia, Pune uathavia@gmail.com
1210.	United Conservation Movement priyaalemane@gmail.com
1211.	United Conservation Movement, rajukidoor@gmail.com
1212.	United Conservation Movement, sahajaputtur@gmail.com
1213.	United Conservation Movement, dheerajsalian333@gmail.com
1214.	United Conservation Movement, united conservation movement @gmail.com
1215.	United Conservation Movement, danielsukumar@gmail.com

Sl. No.	Name
1216.	Shri Ushnish Chattopadhyay, Dy. General Manager (Raw Materials), JK Paper Ltd, 2 <sup>nd</sup> Floor, Nehru House,4, Bahadur Shah Zafar Marg,New Delhi - 110002
1217.	Shri V. Thirumurugan, rvtmurugan1980@gmail.com
1218.	Shri V G Srikara BE Convener, Shimoga District Westernghat Conservation, Committee R/o Channappa layout, Ist Cross, Shimoga, Karnataka
1219.	Shri V. Muruga Anand murugananand7305@gmail.com
1220.	Shri V. Sathish Kumar, venkatsathish12@gmail.com
1221.	Shri V. Selva Kumar selvam17781@gmail.com
1222.	Shri V. Subash, subashmenaka1980@gmail.com
1223.	Shri V. Thampi vijigish@gmail.com
1224.	Shri V. Vignesh M.Sc Biotechnology, vigneshk984@gmail.com
1225.	Shri V. Vimalraj, vimalraj.dgl@gmail.com
1226.	Shri Vaarthai, mervinjsm@gmail.com
1227.	Shri Vaibhav Shettar, 1st cross, Park Extension, Durgigudi, Shivamogga, Karnataka -577201
1228.	Ms. Vaira Meenakshi, vyshi5979@gmail.com
1229.	zohanandco@gmail.com
1230.	Ms. Vaishali Nikam, B/403, Mumbai-400092
1231.	Ms. Vaishali Rawat, Writer and wildlife conservationist, M.Sc. Biodiversity, Conservation and Management, University of Oxford <a href="mailto:vaishali.rawat@gmail.com">vaishali.rawat@gmail.com</a>
1232.	Ms. Vaisshali J Patkar, President, Aundh Mohalla Committee, Director, CCP, Environmental Foundation, Trustee, Bhujal Abhiyan, Convener, Pune Texas-Austin Sister city International, Area Sabha Association of Pune, Ramnadi Restoration Mission vpshali25@gmail.com
1233.	Ms. Vaitheeswaran, mpvaitheeswaran@gmail.com
1234.	vallarasugk001@gmail.com
1235.	Shri Valluvan Valai, priyakumaran182@gmail.com
1236.	Ms. Vanisri K, Chennai-600015 vanisrikalpana@gmail.com info@jhatkaa.org
1237.	Ms. Vanya Jain, 31 Tramoo Street, Lalor-110076
1238.	varith034@gmail.com
1239.	Shri Varun savarun@gmail.com
1240.	Shri Vasuki Tamilselvam, B.A history, Vellore, selvamtamil.bsnl@gmail.com
1241.	Ms. Vasumati Kale, Pune, India vasumatikale@gmail.com
1242.	Vayagam Amar Rahen, manofattitude408@gmail.com
1243.	Veeramani, veera1607.mani@gmail.com
1244.	Shri Veeramuthu A, vamprats@gmail.com
1245.	velganesh326@gmail.com
1246.	Velkum55555@gmail.com
1247.	Shri Velkumar Satchidanandam, Kandaswami koil street, Kosapet-600012 velkumar_61@yahoo.in, info@jhatkaa.org
1248.	Shri Vellian Giri, Kudlu, Bangalore-560068 vellian3156@gmail.com, info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
1249.	Shri Velmurugan, vr8019783@gmail.com
1250.	Shri Velmurugan R, velmuruganraja.t@gmail.com
1251.	Shri Vembuselvam M, vembuselvamm@gmail.com
1252.	venkataraj01@gmail.com
1253.	Shri Venkatesan. D, kanchiadhithyan@gmail.com
1254.	venkatesanmurugaiah73@gmail.com
1255.	Shri Venkatesh Nagarajan, 4/233, Mullukurichi, Namakkal-636142
1256.	Shri Venkatesh Pandi B, #697, Thanthai Periyar Nagar 4th street, Burma Colony Karaikudi-630002
1257.	venkisumathi@gmail.com
1258.	Ms. Vennila Thayumanavan, vennithayumanavan@gmail.com
1259.	verbindenkarthick@gmail.com
1260.	vetri6006@gmail.com
1261.	Shri Vetriselvi Thayumanavan, Assistant Commissioner of GST Retired, pranilathayus@gmail.com
1262.	vetrivelmayavel@gmail.com
1263.	Ms. Viana Fernandes, H.No.268/A, Arossim Bandar , Cansaulim Mormugao, Goa
1264.	Vibrant India Economic Council,Shri Manoj Patil, Shri MaheshTapase, Shri Pawan Kolte info@viecglobal.com
1265.	Shri Shri Vignesh B., vignesh.subramaniam1511@gmail.com
1266.	Shri Vignesh Kumar G, 8/16,palathumarriamman street, Musiri-621215
1267.	Shri Vignesh Rajendran, Norton Road, Mylapore-600028
1268.	Shri Vigneshwaran RK, 4/82, Annai Nagar, Visuwasapuram -641035 Coimbatore
1269.	Shri Vihaan Vee, Kasavanahali - 560035, Bangalore vihaan0vee@gmail.com info@jhatkaa.org
1270.	Shri Vijay, vijaykmr6262@gmail.com
1271.	vijayakanthj55@gmail.com
1272.	Ms. Vijayarani, vijayaranisanjay@gmail.com
1273.	Shri Vijay, vijaykmr6262@gmail.com
1274.	Shri Vijaykaant, vijaykmr6262@gmail.com
1275.	vijaysp3638@gmail.com
1276.	Shri Vimal Seeta, vimaljai03@gmail.com
1277.	Shri Vinay Keerthy, Mahadevapura, Bengaluru- 560016 vinaykeerthy97@gmail.com info@jhatkaa.org
1278.	vinobala85@gmail.com
1279.	Shri Vinoth Kumar T, vinothkumar9815@gmail.com
1280.	Shri Vinoth Kumar, vinoth18693kumar@gmail.com
1281.	Shri Vinothkumar Periyasamy, 2/366 paravalur South Street Vridhachalam Cuddalore- 606001 Vriddhachalam.TK,
1282.	Shri Vinothkumar S, vinothkumar.s1909@gmail.com
1283.	vinothkumar2921@gmail.com

Sl. No.	Name
1284.	Shri Viren Lobo, Institute for Ecology and Livelihood Action
1285.	Shri Vishal B Nair, Kottarathil House, Kanjikuzhy- 685606
1286.	Shri Vishal Sudhakar Rasal r.vishal1319@gmail.com
1287.	Shri Vishnu Kant, Joint Gen Sec; ABVKA; Delhi vanvishnu25@gmail.com
1288.	vishnugulu06@gmail.com
1289.	Shri Vishnupriya B M, Menjhaniyam , Kozhikode-673525
1290.	Shri Vishukumar Naguvanahalli, Bengaluru-560094 vishukumarnr@gmail.com info@jhatkaa.org
1291.	Shri Vishwad N Dinni, Responsible Citizen of India
	vishwasdinni@gmail.com
1292.	Shri Viswanathan K S, Jalakandapuram-636501 info@jhatkaa.org
1293.	Shri Vivek Shinde, Flat No 1102, Primal Homes Society, Backside of Moshi Dmart- 414006, Moshi, Pune
1294.	vmboopathy1810@gmail.com
1295.	Shri VS Kumar, Vyasar Nagar 6th Street , Vyasarpadi, Chennai-600039 sanathkumar.620@gmail.com info@jhatkaa.org
1296.	Shri W. Saravankumar, 0542004sk@gmail.com
1297.	wentotrade@gmail.com
1298.	WG CDR ID Soans, 29, Jal Vayu Vihar, Kammanahalli Main Road, Bengaluru-560043 idsoans@gmail.com, info@jhatkaa.org
1299.	wills87nellai@gmail.com
1300.	Worli, Mumbai-400018 info@jhatkaa.org
1301.	Shri Yadhavaraja. S, yadava.raja@gmail.com
1302.	yamunastudioblp@gmail.com
1303.	Shri Yannah Marchon (Indian Citizen) marchonyannah@gmail.com
1304.	Shri Yash Pal, 8/1 2nd cross, Wheeler Road, Fraser Town, Bengaluru-560005
1305.	yokenthirakumark1@gmail.com
1306.	Shri YPS Prabakar arulyps@gmail.com
1307.	Shri Yujin Leonidas, Sait Colony, Egmore-600008, Chennai yujindass02@gmail.com, info@jhatkaa.org
1308.	yuvaniya.2020@gmail.com
1309.	Shri Yuvaraj, yuvanhari1996@gmail.com

### <u>परिशिष्ट-IV</u>

## 2 से 7 जून, 2023 तक श्रीनगर, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में संयुक्त समिति के अध्ययन दौरे के दौरान वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा की गई चर्चाओं का विवरण।

बैठक सं.	बैठक की तारीख	बैठक की कार्ययूची
1	02.06.2023	वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में किए गए प्रावधानों पर विभिन्न रक्षा संगठनों और संस्थाओं जैसे बीआरओ, बीएसएफ, डीआरडीओ, सेना उत्तरी कमान (एक्सवी कोर) के साथ उनके विचारों के बारे में चर्चा।
2	03.06.2023	संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के मुख्य सचिव/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में किए गए प्रावधानों पर उनके विचारों के बारे में चर्चा करना।
3	05.06.2023	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और ओएनजीसी के प्रतिनिधियों तथा त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड राज्यों के मुख्य सचिवों/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में किए गए प्रावधानों पर उनके विचारों के बारे में चर्चा करना।
4	06.06.2023	असम, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में किए गए प्रावधानों पर उनके विचारों के बारे में चर्चा।
5	07.06.2023	भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के प्रतिनिधियों और ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में किए गए प्रावधानों पर उनके विचारों के बारे में चर्चा।

# <u>परिशिष्ट -V</u>

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों के विवरण।

Sitting No.	Date of Sitting	Agenda of the sitting
1	25.04.2023	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग। (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय)
2	16.05.2023	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के विचार प्राप्त करना: 1. गृह मंत्रालय 2. रक्षा मंत्रालय 3. जनजातीय कार्य मंत्रालय (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय)
3		वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विचार प्राप्त करना: 1. छत्तीसगढ़ सरकार 2. महाराष्ट्र सरकार 3. तेलंगाना सरकार (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय)
4	17.05.2023	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के विचार प्राप्त करना: 1. रेल मंत्रालय 2. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 3. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय)
5		वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के विचार प्राप्त करनाः 1. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 2. खान मंत्रालय 3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय)
6	30.05.2023	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर प्रेस विज्ञप्ति के जवाब में ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले हितधारकों/विशेषज्ञों/संगठनों के मौखिक साक्ष्य। (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय)
7		वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर हितधारकों/विशेषज्ञों/संगठनों के मौखिक साक्ष्य। (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय)
8	26.06.2023	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर खंडवार विचार (ये भी उपस्थित: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय – विधायी विभाग तथा विधि कार्य विभाग)
9	11.07.2023	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

# <u>परिशिष्ट-VI</u>

# समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले सरकारी/गैर-सरकारी साक्षियों की सूची

# क. सरकारी साक्षियों की सूची

क्र. सं.	मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम
1	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2	विधि और न्याय मंत्रालय - विधि कार्य विभाग
3	विधि और न्याय मंत्रालय - विधायी विभाग
4	गृह मंत्रालय
5	रक्षा मंत्रालय
6	जनजातीय कार्य मंत्रालय
7	छत्तीसगढ़ सरकार
8	महाराष्ट्र सरकार
9	तेलंगाना सरकार
10	रेल मंत्रालय
11	सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
12	ग्रामीण विकास मंत्रालय
13	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
14	खान मंत्रालय
15	उत्त्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर)

ख.	2 से 7 जून, 2023 तक श्रीनगर, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के अध्ययन दौरे के दौरान मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले सरकारी साक्षियों की सूची
क्र. सं.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संगठनों का नाम
1.	सीमा सड़क संगठन
2.	सीमा सुरक्षा बल
3.	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
4.	सेना उत्तरी कमान (XV कोर)
5.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र
6.	लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र
7.	हिमाचल प्रदेश सरकार
8.	पंजाब सरकार
9.	उत्तराखंड सरकार
10.	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय(डीजीएच)
11.	तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी(ओएनजीसी)
12.	त्रिपुरा सरकार
13.	सिक्किम सरकार
14.	नागालैंड सरकार
15.	असम सरकार
16.	मेघालय सरकार
17.	मिजोरम सरकार
18.	अरुणाचल प्रदेश सरकार
19.	भारतीय खान ब्यूरो
20.	ओडिशा सरकार
21.	आंध्र प्रदेश सरकार

# ग. <u>गैर-सरकारी साक्षियों की सूची</u>

क्र. सं.	विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों का नाम
1.	श्रीमती वृंदा करात, पूर्व सांसद (राज्य सभा) 2005-2011
2.	डॉ. प्रशांत कुमार झा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (सेवानिवृत्त), तेलंगाना वन विभाग
3.	श्री आर.डी. कंबोज, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (सेवानिवृत्त), गुजरात वन विभाग
4.	श्री सुरेश चोपाने, सदस्य - क्षेत्रीय शक्ति-प्राप्त समिति (आरईसी), नागपुर और रायपुर (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), अध्यक्ष - ग्रीन प्लैनेट सोसायटी
5.	श्री के. रविचंद्रन, निदेशक - भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम)
6.	डॉ. रविन्द्र कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ वन विभाग
7.	श्री शाहबाज अहमद, भारतीय वन सेवा (आईएफएस) (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव वार्डन, मध्य प्रदेश
8	देबी गोयनका, कार्यकारी ट्रस्टी, कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट
9	श्री अभिनव गौड़, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
10	श्री प्रवीण भार्गव, न्यासी वन्यजीव प्रथम पूर्व सदस्य - राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड
11	श्री मनोज पाटिल, संयोजक, वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल (वीआईईसी), मुंबई
12	श्री बिजय संयोजक, भारत जन आंदोलन (छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन)

### परिशिष्ट-सात

# बैठकों के कार्यवाही सारांश वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की पहली

## बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की पहली बैठक मंगलवार, 25 अप्रैल, 2023 को 1100 बजे से 1235 बजे तक समिति कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

### उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सभापति

#### लोक सभा

- 2. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 3. श्री सुरेश कश्यप
- 4. श्रीमती गोमती साय
- 5. श्री सुदर्शन भगत
- 6. श्री पल्लब लोचन दास
- 7. सुश्री दिया कुमारी
- 8. श्री टी.आर. बालू
- 9. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 10. श्री श्रीधर कोटागिरी
- 11. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 12. श्री गिरीश चन्द्र
- 13. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
- 14. श्रीमती गीता कोडा

#### राज्य सभा

- 15. श्री जवाहर सरकार
- 16. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
- 17. श्रीमती फूलो देवी नेताम

### सचिवालय

श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
 श्री सी. कल्याणसुंदरम - निदेशक
 सुश्री रचना सक्सेना - उप सचिव

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्रीमती लीना नंदन - सचिव
 श्री एस पी यादव - एडीजी

3. श्री रमेश कुमार पांडेय - वन महानिरीक्षक

4. डॉ. धीरज मित्तल - सहायक वन महानिरीक्षक

5. श्री चरण जीत सिंह - वैज्ञानिक 'डी'

## विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग)

6. श्री राजवीर सिंह वर्मा - अपर सचिव

7. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

- 2. सर्वप्रथम, सभापित ने संयुक्त समिति की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, उन्होंने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया, जिसे 29 मार्च 2023 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और राज्यसभा द्वारा सहमित दी गई। उन्होंने बैठक की कार्यसूची के बारे में सदस्यों को अवगत भी कराया।
- 3. तत्पश्चात, सभापित ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात, उन्होंने मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया।
- 4. तत्पश्चात, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया जिसमें विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों और उनके पीछे के तर्क को दर्शाया गया।
- 5. तत्पश्चात, सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जिसका नोडल मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तत्पश्चात, सभापित ने मंत्रालय को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।

### तत्पश्चात मंत्रालयों के प्रतिनिधि साक्ष्य देकर चले गए।

6. तत्पश्चात, समिति ने समिति द्वारा आगे की कार्रवाई पर संक्षेप में विचार-विमर्श किया और अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए 16 और 17 मई, 2023 को समिति की अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। समिति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आम जनता और विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/हितधारकों और संस्थाओं से विचार/सझाव वाले ज्ञापन आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी गई है।

### वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की दूसरी बैठक मंगलवार, 16 मई, 2023 को 1100 बजे से 1230 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

#### उपस्थित

#### श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सभापति

#### लोक सभा

- 2. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 3. श्री राजू बिष्ट
- 4. श्री तापिर गाव
- 5. श्री अजय टम्टा
- 6. श्रीमती गोमती साय
- 7. श्री पल्लब लोचन दास
- 8. श्री टी.आर. बालू
- 9. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 10. श्रीमती साजदा अहमद
- 11. श्री श्रीधर कोटागिरी
- 12. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 13. श्री गिरीश चन्द्र
- 14. श्रीमती गीता कोडा

#### राज्य सभा

- 15. श्री जवाहर सरकार
- 16. श्री आर. गिरिराजन
- 17. श्रीमती फूलो देवी नेताम

### सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 1. श्रीमती लीना नंदन सचिव
- श्री चन्द्र प्रकाश गोयल डीजीएफ एंड एसएस
- 3. श्री रमेश कुमार पांडेय वन महानिरीक्षक

### विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

### (विधायी विभाग)

4. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

### गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 5. श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार सचिव (बीएम), गृह मंत्रालय
- 6. श्री निशांत कुमार मिश्रा उप सचिव (एलडब्ल्युई), गृह मंत्रालय

#### रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

7. श्रीमती दीप्ति मोहिल चावला - अपर सचिव8. श्री मनीष त्रिपाठी - संयुक्त सचिव

9. ब्रिगेडियर प्रवीण बद्रीनाथ - ब्रिगेडियर एमओ (सी)10. श्री सी पी मीणा - वैज्ञानिक 'ई', डीआरडीओ

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

11. श्री अनिल कुमार झा - सचिव (टीए)
 12. श्री नवल जीत कपूर - संयुक्त सचिव
 13. श्रीमती समिधा सिंह - निदेशक
 14. श्री नदीम - अवर सचिव

- 2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति की दूसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।
- 3. तत्पश्चात, सभापित ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। तत्पश्चात् सभापित ने मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया।
- 4. गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार व्यक्त किए।
- 5. तत्पश्चात, सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों और गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के विचारों पर स्पष्टीकरण मांगा जिसका गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।
- 6. समिति ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों के मुख्य सचिवों/प्रतिनिधियों के साथ वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में किए गए उपबंधों पर उनके विचारों के संबंध में अनौपचारिक चर्चा करने के लिए 2 जून, 2023 से 7 जून, 2023 तक श्रीनगर, गुवाहाटी और भुवनेश्वर का अध्ययन दौरा करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात मंत्रालयों के प्रतिनिधि साक्ष्य देकर चले गए। समिति की बैठक स्थगित हुई।

शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी गई है।

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की तीसरी बैठक मंगलवार, 16 मई, 2023 को 1315 बजे से 1430 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

### उपस्थित

# श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

### लोक सभा

- 2. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 3. श्री राजू बिष्ट
- 4. श्री तापिर गाव
- 5. श्री अजय टम्टा
- 6. श्रीमती गोमती साय
- 7. श्री पल्लब लोचन दास
- 8. श्री टी.आर. बालू
- 9. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 10. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 11. श्री गिरीश चन्द्र
- 12. श्रीमती गीता कोडा

## राज्य सभा

- 13. श्री जवाहर सरकार
- 14. श्री आर. गिरिराजन
- 15. श्रीमती फूलो देवी नेताम

## सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. श्री सी. कल्याणसुंदरम निदेशक
- 3. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 1. श्रीमती लीना नंदन सचिव
- 2. श्री चन्द्र प्रकाश गोयल डीजीएफ एंड एसएस
- 3. श्री रमेश कुमार पांडेय वन महानिरीक्षक

# विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

# (विधायी विभाग)

4. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

### छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि

5. श्री अमिताभ जैन - मुख्य सचिव

श्री वी. श्रीनिवास राव - प्रधान मुख्य वन संरक्षक

7. श्री सुनील मिश्रा - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन) एवं नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

# महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि

8. श्री वेणु गोपाल रेड्डी - प्रधान सचिव (वन)

9. श्री वाई.एल.पी. राव - प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

## तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधि

10. श्री मोहन चंद्र परगईन, आईएफएस - मुख्य वन संरक्षक (एफसीए) और नोडल अधिकारी, तेलंगाना

- 2. सर्वप्रथम, सभापित ने संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।
- 3. तत्पश्चात, सभापित ने छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार और तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। तत्पश्चात सभापित ने प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया।
- 4. छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार और तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार व्यक्त किए।
- 5. तत्पश्चात्, सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों और छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार और तेलंगाना सरकार के विचारों पर स्पष्टीकरण मांगा जिसका छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार और तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तत्पश्चात सभापति ने नोडल मंत्रालय अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।

तत्पश्चात मंत्रालयों के प्रतिनिधि साक्ष्य देकर चले गए। तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई। शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी गई है।

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की चौथी बैठक बुधवार, 17 मई, 2023 को 1100 बजे से 1215 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

## उपस्थित

### श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सभापति

#### लोक सभा

- 2. श्री टी.आर. बालू
- 3. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 4. श्री राजू बिष्ट
- 5. श्री तापिर गाव
- 6. श्री सुदर्शन भगत
- 7. श्री पल्लब लोचन दास
- 8. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 9. श्रीमती साजदा अहमद
- 10. श्री श्रीधर कोटागिरी
- 11. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 12. श्री गिरीश चन्द्र

#### राज्य सभा

- 13. श्री जवाहर सरकार
- 14. श्री आर. गिरिराजन
- 15. श्रीमती फूलो देवी नेताम

## सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. श्री सी. कल्याणसुंदरम निदेशक
- 3. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री चन्द्र प्रकाश गोयल - डीजीएफ एंड एसएस

## विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

# (विधायी विभाग)

2. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

## रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधि

- 3. श्री रूप एन. सुनकर सदस्य (इंफ्रास्ट्रक्चर)
- 4. श्री अनिल कुमार खंडेलवाल प्रधान कार्यकारी निदेशक (गति शक्ति)
- 5. श्री धनंजय सिंह कार्यकारी निदेशक/गति शक्ति (सिविल)-II

## सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि

6. श्री अनुराग जैन - सचिव

7. श्री अमित कुमार घोष - अपर सचिव

3. श्री कमलेश चतुर्वेदी - संयुक्त सचिव

### ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

9. श्री शैलेश कुमार सिंह - सचिव

10. श्री प्रवीण महतो - मुख्य आर्थिक सलाहकार

11. श्री अमित कटारिया - संयुक्त सचिव (मनरेगा)

- 2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति की चौथी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।
- 3. तत्पश्चात, सभापित ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। तत्पश्चात, सभापित ने प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया।
- 4. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार व्यक्त किए।
- 5. तत्पश्चात, सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचारों पर स्पष्टीकरण मांगा जिसका रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तत्पश्चात, सभापित ने नोडल मंत्रालय सहित मंत्रालयों अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।

तत्पश्चात मंत्रालयों के प्रतिनिधि साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।
शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी गई है।

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक बुधवार, 17 मई, 2023 को 1215 बजे से 1315 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

## उपस्थित

# श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सभापति

#### लोक सभा

- 2. श्री टी.आर. बालू
- 3. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 4. श्री राजू बिष्ट
- 5. श्री तापिर गाव
- 6. श्री सुदर्शन भगत
- 7. श्री पल्लब लोचन दास
- 8. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 9. श्रीमती साजदा अहमद
- 10. श्री श्रीधर कोटागिरी
- 11. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 12. श्री गिरीश चन्द्र

#### राज्य सभा

- 13. श्री जवाहर सरकार
- 14. श्री आर. गरिराजन
- 15. श्रीमती फूलो देवी नेताम

# सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. श्री सी. कल्याणसुंदरम निदेशक
- 3. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 1. श्री चन्द्र प्रकाश गोयल डीजीएफ एंड एसएस
- 2. श्री एस पी यादव एडीजी
- 3. श्री रमेश कुमार पांडेय वन महानिरीक्षक

# विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

4. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

# जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के प्रतिनिधि

- 5. सुश्री विनी महाजन सचिव
- 6. श्री समीर कुमार आर्थिक सलाहकार

## खान मंत्रालय के प्रतिनिधि

7. श्री संजय लोहिया - अपर सचिव8. श्री मुस्ताक अहमद - निदेशक

9. श्री प्रदीप सिंह - निदेशक (तकनीकी)

# उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रतिनिधि

10. श्री लोक रंजन, आईएएस (टीआर: 1989) - सचिव

11. श्री अंशुमन डे, आईएफएस (टीआर: 1997) - संयुक्त सचिव

- 2. सर्वप्रथम, सभापित ने संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।
- 3. तत्पश्चात, सभापित ने जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग), खान मंत्रालय तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रतिनिधियों को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। तत्पश्चात, सभापित ने प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया।
- 4. जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग), खान मंत्रालय तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रतिनिधियों ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार व्यक्त किए।
- 5. तत्पश्चात, सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग), खान मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के विचारों पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसका जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग), खान मंत्रालय तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तत्पश्चात, सभापित ने मंत्रालय अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।

तत्पश्चात मंत्रालयों के प्रतिनिधि साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी गई है।

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की छठी बैठक मंगलवार, 30 मई, 2023 को 1030 बजे से 1230 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

## उपस्थित

## श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सभापति

#### लोक सभा

- 2. श्री टी.आर. बालू
- 3. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 4. श्री तापिर गाव
- 5. श्री अजय टम्टा
- 6. श्री सुदर्शन भगत
- 7. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 8. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
- 9. श्री गिरीश चन्द्र
- 10. श्री प्रद्युत बोरदोलोई

#### राज्य सभा

- 11. डा. अशोक बाजपेयी
- 12. डा. प्रशांत नन्दा
- 13. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
- 14. श्री आर. गिरिराजन
- 15. श्रीमती फूलो देवी नेतम

## सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 1. श्री चन्द्र प्रकाश गोयल डीजीएफ एंड एसएस
- 2. श्री एस पी यादव एडीजी

# विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

3. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

# हितधारक/विशेषज्ञ/संगठन

- 4. श्रीमती वृंदा कारत पूर्व संसद सदस्य, राज्यसभा
- 5. डॉ. प्रशांत कुमार झा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ)(सेवानिवृत्त), तेलंगाना वन विभाग
- 6. श्री आर.डी. कम्बोज अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (सेवानिवृत्त), गुजरात वन विभाग

7. श्री सुरेश चोपाने - सदस्य, क्षेत्रीय शक्ति प्राप्त समिति (आरईसी), नागपुर और रायपुर (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

अध्यक्ष - ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी

8. श्री के. रविचंद्रन - निदेशक - भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम)

9. डॉ. रविंद्र कुमार सिंह - प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़

- 2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति की छठी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची के बारे में सदस्यों को अवगत भी कराया।
- 3. तत्पश्चात, सभापित ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। तत्पश्चात, सभापित ने प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया।
- 4. तत्पश्चात, विशेषज्ञों ने एक-एक करके विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार स्पष्ट किए।
- 5. तत्पश्चात, सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों और विशेषज्ञों के विचारों पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसका विशेषज्ञों ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।
शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी गई है।

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की 7वीं बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की 7वीं बैठक मंगलवार, 30 मई, 2023 को 1230 बजे से 1400 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

#### उपस्थित

## श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सभापति

#### लोक सभा

- 2. श्री टी.आर. बालू
- 3. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 4. श्री तापिर गाव
- 5. श्री अजय टम्टा
- 6. श्री सुदर्शन भगत
- 7. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 8. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
- 9. श्री गिरीश चन्द्र
- 10. श्री प्रद्युत बोरदोलोई

#### राज्य सभा

- 11. डा. अशोक बाजपेयी
- 12. डा. प्रशांत नन्दा
- 13. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
- 14. श्री आर. गिरिराजन
- 15. श्रीमती फूलो देवी नेतम

### सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 1. श्री चन्द्र प्रकाश गोयल डीजीएफ एंड एसएस
- श्री एस पी यादव एडीजी

# विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

3. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

## हितधारक/विशेषज्ञ/संगठन

- 4. श्री शहबाज अहमद भारतीय वन सेवा (आईएफएस) (सेवानिवृत्त) पूर्व प्रधान मुख्य वन
  - संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश
- श्री देबी गोयनका कार्यकारी ट्रस्टी, कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट
- श्री अभिनव गौड़ अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

श्री प्रवीण भार्गव - ट्रस्टी वाइल्डलाइफ फर्स्ट,

पूर्व सदस्य – राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड लेखक – वाइल्डलाइफ लॉ फार रेंजर्स

8. श्री विक्रम हीरेसावी - राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

लेखक – वाइल्डलाइफ लॉ फार रेंजर्स

9. श्री मनोज पाटील - संयोजक, वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल (वीआईईसी),

मुंबई

10. श्री महेश भरत तापसे - अध्यक्ष, वीआईईसी

11. श्री बिजय के पांडा - संयोजक, भारत जन आंदोलन (छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन)

- 2. आरंभ में, सभापति ने संयुक्त समिति की सातवीं बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची के बारे में सदस्यों को अवगत भी कराया।
- 3. इसके बाद, सभापित ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। इसके बाद सभापित ने उपस्थित साक्षियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोकसभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकृष्ट किया।
- 4. तत्पश्चात, विशेषज्ञों ने एक-एक करके विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार स्पष्ट किए।
- 5. इसके बाद सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों और विशेषज्ञों के विचारों पर स्पष्टीकरण मांगा जिसका विशेषज्ञों ने संक्षेप में उत्तर दिया। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय को निदेश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के लिखित उत्तर देगा।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए। *बैठक स्थगित हुई।* 

शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

संयुक्त समिति की आठवीं बैठक मंगलवार, 26 जून, 2023 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कमरा संख्या '1', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

#### उपस्थित

## श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सभापति

#### लोक सभा

- 2. श्री टी.आर. बालू
- 3. डॉ. ढालसिंह बिसेन
- 4. श्री राजू बिष्ट
- 5. श्री तापिर गाव
- 6. श्री सुरेश कुमार कश्यप
- 7. श्रीमती गोमती साय
- 8. श्री सुदर्शन भगत
- 9. सुश्री दिया कुमारी
- 10. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 11. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
- 12. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 13. श्री प्रद्युत बोरदोलोई

### राज्य सभा

- 14. डा. अशोक बाजपेयी
- 15. श्री समीर उरांव
- 16. डा. प्रशांत नंदा
- 17. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
- 18. श्री आर. गिरिराजन

# सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. श्री सी. कल्याणसुन्दरम निदेशक
- 3. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 1. श्रीमती लीनानंदन सचिव
- 2. श्री चन्द्र प्रकाश गोयल डीजीएफ एंड एसएस

# विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

3. श्री उदय कुमार - संयुक्त सचिव & विधायी सलाहकार

# विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधि कार्य विभाग)

4. डा. पदमिनी सिंह - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

- 2. आरंभ में, सभापति ने संयुक्त समिति की सातवीं बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्य सूची के बारे में सदस्यों को अवगत भी कराया।
- 3. इसके बाद, अध्यक्ष ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया और वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित संशोधनों पर खंडवार विचार-विमर्श शुरू किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श के दौरान समिति की सहायता की।
- 4. सिमिति के सदस्यों ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार रखे और मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के बारे में स्पष्ट किया।
- 5. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में सभी प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की नौवीं बैठक मंगलवार, 11 जुलाई, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

### उपस्थित

श्री राजेंद्र अग्रवाल — सभापति

लोक सभा

- 2. श्री तापिर गाव
- 3. श्री सुदर्शन भगत
- 4. श्री पल्लब लोचन दास
- 5. कुमारी दिया कुमारी
- 6. श्रीमती अगाथा के. संगमा
- 7. डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 8. श्री गिरीश चन्द्र

राज्य सभा

- 9. श्री समीर उरांव
- 10. डॉ. सी. एम. रमेश
- 11. डॉ. प्रशांत नंदा
- 12. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
- 13. श्री आर. गिरिराजन
- 14. श्रीमती फुलो देवी नेताम

#### सचिवालय

- 1. श्री जे.एम. बैसाख संयुक्त सचिव
- 2. श्री सी. कल्याणसुंदरम निदेशक
- 3. सुश्री रचना सक्सेना उप सचिव
- 2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया। समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर पूर्ण रूप से विचार किया और उसे स्वीकार कर लिया। समिति ने माननीय सभापित को लोक सभा में प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने तथा इसे राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए भी प्राधिकृत किया।
- 3. सभापति ने यह भी घोषणा की कि यदि कोई सदस्य कोई विमत टिप्पण देना चाहता है, तो 13 जुलाई 2023 को सायं 4:00 बजे तक उसे सचिवालय में प्रस्तुत किया जाए।
- 4. तत्पश्चात, सभापित ने अपने समापन भाषण में संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिसने समिति को कम समय के भीतर एक महत्वपूर्ण कानून पर प्रतिवेदन की जांच करने और अंतिम रूप देने में सक्षम बनाया। सभापित ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समिति को प्रदान की गई निरंतर सहायता की सराहना भी की।

## तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

## विमत टिप्पण/कार्यवाही सारांश





# PRADYUT BORDOLOI

#### MEMBER OF PARLIAMENT (LOK SABHA)

# MEMBER, STANDING COMMITTEE OF PETROLEUM & NATURAL GAS

MEMBER, COMMITTEE OF RULES, LOK SABHA

MEMBER, CONSULTATIVE COMMITTEE OF MINISTRY OF POWER, NEW AND RENEWABLE ENERGY

D.O. No. MP: Nowgong: 03 Date: 26th June, 2023

Shri Rajendra Agarwal,
Chairperson,
Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

Dear Shri Agarwal ji,

# Subject: Comments of dissent on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 (TBD) for inclusion in the JPC Report.

At the outset, I would like to appreciate efforts being undertaken to conduct vital public consultation as a part of the Committee's examination of the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023. This is crucial for strengthening environmental protection mandate and building collective responsibility around forest conservation in India. I am thankful to you for allowing me to interact extensively during the hearings.

While the preamble of the proposed Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 invokes India's rich tradition of preserving forests and their importance in achieving net zero emission targets, there is reason to believe that the substance of the proposed changes will, however, emasculate the original Forest Conservation Act (FCA), thereby subverting the FCA's primary objective of providing for conservation of forests and checking further deforestation. The following are my detailed clause-wise comments, which are put forward for the Committee's consideration and if necessary, regarded as comments of dissent for the record:

# 1. Clause 3: Changing title of the Act from "Forest (Conservation) Act" to "Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam"

Given that the FCA is of great importance to people across the country, 60% of which are dependent on forests and other ecosystems directly for their sustenance and livelihood, it is vital that is inclusive in its terminologies, not leaving out population in non-Hindi speaking regions, including the South and the North-East regions.

#### 2. Clause 4: Insertion of Section 1A (subsection 1) regarding lands to be covered under the FCA

a.By proposing to include only those lands within the ambit of the FCA which are recorded as the forest on or after 25th October 1980, a significant section of forest land area will be exempted, especially because large tracts of forest land in India were recorded as 'forest' during transfer of lands to the forest department while abolishing the Zamindari system in respective states after independence (in 50s-70s). A large section of such transferred land could not be notified as forest under the Indian Forest Act, 1927, or state forest legislations because of improper demarcation, ownership disputes and administrative lethargy. However, such lands continue to be protected as forests under the FCA,

irrespective of their ownerships. Such forests can be easily found in ecologically rich landscapes like the Aravallis, central Indian plateaus, western ghats, etc and are important as wildlife habitats providing critical ecological services. These biodiversity hotspots will no longer be considered 'forest' and can potentially be sold, diverted, cleared, felled, utilized, exploited without any regulatory oversight, if the bill is passed in its current form.

b. Such an amendment would dilute the Hon'ble Supreme Court's 1996 landmark *Godavarman judgment* which widened the scope of the FCA to apply to any land recorded as forest by the government irrespective of its ownership. The proposed amendment would in effect limit the scope of the forest clearance mandate under the FCA at a time when India is rapidly losing essential forest cover.

#### Clause 4: Insertion of Section 1A (subsection 2) regarding lands to not be covered under the FCA:

The proposition to exempt certain categories of land from provisions of forest clearance bears the following grave implications:

- a. Threat to bio-sensitive areas: Significant forests in Himalayan. Trans-Himalayan and North Eastern regions, which are rich with endemic biodiversity will be exempted because of their proximity to international borders. Clearing of such forests without any assessment and mitigation plan will not only threaten the biodiversity but will also increase the vulnerability of the ecologically and geologically sensitive areas, which are already threatened by unsustainable infrastructure developments and extreme weather events. Blanket exemptions for border infrastructure projects are problematic as they have significant impact on sensitive landscape and biodiversity, and may adversely impact the infrastructures themselves, due to resultant environmental hazards in case of extreme weather events.
- b. Wide scope of terminology: The usage of forest land for 'security-related infrastructure' and 'public utility' is also very wide and can be used to establish a variety of infrastructure projects on forest lands without applying for forest clearance. For example, public utility services are commonly understood as services provided by the government essential to citizens' requirements. This includes transport, postal, telephone, power, water, etc. This virtually allows the construction of any project on forest land.
- c. Further, in Amendment of Section 2, further exemptions are provided using vague terminology like 'proposed', 'ecotourism facilities', and 'any other purposes' which can be exploited or misused for activities damaging forests and ecosystems in forest lands. Bringing all zoos, safaris and forest training infrastructures within the ambit of forestry activities, is inconsistent with the FCA and the FCA Guidelines, 2019 which clearly differentiate low footprint conservation establishments from exhibition-oriented outreach centers. Further, this may disproportionately commercialize forests and disturb forest ecosystems.
- **d.** The exemptions provided for are bound to **promote commercialisation of forests** (including notified forests) and **cause irreversible disturbance to wildlife**. It is a common misconception that wildlife only occurs inside Protected Areas (PA). On the contrary, areas outside PA are considered to support essential habitats and biodiversity.

The proposed Bill makes no provision for any impact assessment or any kind of regulatory oversight on the loss of habitats and species, nor would there be any remedies available for interventions to raise concerns. Roads, railway lines and such linear intrusions have a disproportionately vast impact on wild habitats and wildlife as it fragments, erodes natural forests. Removing safeguards in such a blanket manner will only further jeopardise, degrade and destroy forests.

#### 4. Clause (1) (a) (2) (c)

Blanket exemption of 100 km from international border is of particular concern in the North East region, due to proximity to international borders & small size of state—as a result, will subsume the entire state and open up pristine forest areas along with its biodiversity for non-forestry uses without FCA regulation. Further, the ecologically fragile landscape along the LAC has the majority of the Protected Areas with critically threatened endemic species of flora and fauna, whose conservation will be threatened.

#### 5. Clause 5: Insertion of sub-section 2 of Section 2:

This section which exempts survey activities, such as, reconnaissance, seismic survey and drillings by Oil Companies, prospecting, investigation or exploration from FCA clearance, would open vast tracts of biodiversity rich forest across the country for scoping, prospecting and surveys for coal, iron ore, diamond and other mining, as well as for oil with no environmental safeguards. Also at risk is our 7,517 kilometers long coastline and 1,382 islands from deep sea mining for deposits of minerals which will pave the way for commercial exploitation. Once scoping is done, analysis indicates that

clearances for projects is usually a fait accompli. The proposed exemptions for all surveys and investigations are arbitrary in nature, and such exemptions should instead depend on the underlying project and its implications on the forest and associated wildlife.

#### 6. Critically assessing emphasis on carbon neutrality through plantations:

The Bill's focus on raising tradeable vertical repositories of carbon, i.e achieving carbon neutrality through a push for plantations, can jeopardize the very purpose of the Act to protect and conserve India's forests. While India's commitments to meeting national Net Zero Emission targets are important, experts have long argued that **creating carbon sinks via plantations** and increasing tree cover is counter intuitive, and multiple studies, including in India show that these are poor in sequestering carbon, as well as in other ecosystem services such as containing soil erosion, biodiversity conservation, water retention etc. Research has shown that **natural forests are far more effective in this regard**, considering that the carbon sequestration potential of natural forests is 40 times greater as compared to plantations. Further, it is important to consider that the destruction and degradation of forests in itself **contributes to climate change through the release of carbon dioxide (CO2).** 

7. Need to foreground forest rights in forest conservation legislation: What remains an obvious gap, even in the statement and objects of the amendment, is the reconciliation of the forest conservation legislation with the forest rights question, which should have been important especially when almost all proposed amendments will necessarily come to bear on prevailing, pending or recognised forest rights. There is an absence of any perspective on how existing proprietary, customary, and livelihood use rights will be dealt with for net zero compliant lands or in the case of fresh forest land diversions.

While the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in its response (dated 19th June 2023) has attempted to clarify some of the above mentioned points, concerns persist as there is an overwhelming reliance **on implied meaning of provisions** rather than categorically laying out safeguards in the text of the amendment. Further, on the question of ensuring safeguards, one observes a tendency to leave terms & conditions to the discretion of the Executive at subsequent junctures, creating scope for misinterpretation and misuse.

India's ancient civilisation and culture is closely linked to nature. Millions of marginalized and indigenous people continue to depend on forests for their sustenance and livelihood and will be rendered even more vulnerable were the proposed amendments come to pass. I strongly believe that rather than weakening regulation, amendments to India's Forest Conservation Act must focus on ensuring more effective implementation of conservation practices, especially in view of the accelerating threat of climate change.

Regards,

(PRADYUT BORDOLOI)

Relevant Provisions of Principal Act	Provisions proposed in Amendment Bill	Comments of Shri Pradyut Bordoloi, MP Lok Sabha (Member JPC)	Suggestion for Redrafting
1(1) This Act may be called the Forest (Conservation) Act, 1980.	Amendment of section 1. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and brackets "Forest (Conservation) Act", the words and brackets "VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM" shall be substituted.	Should be amend to make it more acceptable to all across the country.  A separate Hindi translated version can be made available alongside the English version, for the purpose of improved accessibility.	English Translation of Bill: This Act may be called the Forest (Conservation) Act 1980 Appropriate Hindi name can be inserted
Not applicable (provisions do not exist in the Principal Act).	Insertion of new section 1A- Act to cover certain land.  After section 1 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—  "1A. (1) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—	1) Subsection 1A(1)(b) along with the proviso can be potentially misinterpreted to create an exception to the Supreme Court's judgment in T.N. Godavaraman case dated 12.12.1996 (which imposed applicability of Section 2 of the Act to any area recorded as forest in the Govt record irrespective of ownership and date)  This has negative implications on the applicability of Section 2 of the Act, which mandates permission of the Central Government for any non-forest activity on lands recorded as forest in 'government record', which also includes lands that are not notified under a statute.  2) The new changes also omit the category of lands which are neither notified nor recorded as forests in any government records but qualify the characteristics of a natural forest including those proposed to be notified as forest.  As per the latest FSI's "India State of Forests Report" (2021), Unclassed Forests account for approximately 15% of India's total forest cover, and in some States and Union Territories Unclassed Forests are a massive portion of their total forest cover. Some of these states constitute some of India's most unique and endangered biodiversity-rich regions (biodiversity hotspots).  For instance, in  Northeast India, 97.2% of Nagaland's, 88.2% of Meghalaya's, 75.6% of Manipur's, 53% of Arunachal Pradesh's and 33.4% of Assam's total	

		forest are categorized as unclassed forest. There is a concern that most of such lands may be exempted from the FCA as they are recorded as forests much before 1980.  3) The new changes also exclude those forest lands which are proposed to be declared forests but yet to be notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 or other state laws. (For e.g in Assam, nearly 730 sq.km. of lands are in the process of notification as RF from the existing category of Proposed RF under Assam Forest Regulation Act, 1891.)	
Not applicable (provisions do not exist in the Principal Act).	The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—  (a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.  (b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October 1980:		The following land shall be covered under this Act, namely: —  (b) the land that has been declared or notified or is under the process of being notified as a forest following the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.  (b) the land that is not covered under clause (a) but has been recorded in Government records as forest irrespective of their ownership.  (c) the land that is not covered under clauses (a) or (b) but is recognizable as forests by local communities or in terms of its ecological and cultural significance.  (d) the land that is not covered in clauses (a), (b), (c) but identified or used for compensatory afforest diverted under Section 2 of the Act.

#### Proviso There have been many instances where Recommend be to the States have unlawfully diverted deleted from lands recorded as forests for non-forest amendment Provided that the provisions of activities in the violation of the Act. The this clause shall not apply to proposed amendment attempts to such land, which has been legalize such diversions. changed from forest use to use for non-forest purpose on or before the 12th December, The Supreme Court has reiterated that 1996 in pursuance of an order, the primary purpose of the FCA is to issued by any authority prevent further deforestation, and any interpretations must sub-serve and help authorised by a State implement the intention of the Act. Government or an Union territory Administration in that behalf: Many of such forest lands were diverted on lease for activities such as plantations, mining etc., by the States before 12th December 1996 or even before the enactment of the FCA in 1980. For instance, Gavi, a RF in the core area of the Periyar Tiger Reserve, was leased to Kerala Forest Development Corporation for the cultivation of cardamom before 1980. The lease is set to expire in 2026, after which new permission will be required to be obtained under Section 2 of the Act. However, if the proposed amendment is accepted, many of such leased forest areas may get permanently diverted for such non-forest activity. This may also allow the lessee to change the nature of such plantation for other non-forest purposes like tourism, infrastructure etc. Not 1A. (2) (a) Exemptions for roadside amenities are Recommend to he applicable regressive and ultra vires the FCA. The deleted from visions do not exist new changes will fragment forest areas amendment The following categories of in the Principal and will be detrimental to wildlife land shall not be covered habitats and corridors, especially with Act). under the provisions of this lack of specifics with respect to the Act, namely:frequency of these facilities along such linear projects makes vast forest areas (a) such forest land situated susceptible. alongside a rail line or a public road maintained by the Already many railway lines such as Rail Government, which provides line thro the Deepor Beel (a Ramsar access to a habitation, or to a Site) on the outskirts of Guwahati City rail, and roadside amenity up and roads pass through sensitive to a maximum size of 0.10 biodiversity rich areas. More road and hectare in each case; railways infrastructure are proposed to be constructed in upcoming years, which are going to fragment forests and affect wildlife in other parts of the country.

	Granting any exemptions to areas alongside the roads will not only lead to massive deforestation but create multiple disturbance to forests and put immense pressure on wildlife. Linear infrastructure significantly affects and reverses the decades old conservation efforts to protect endemic flora and fauna, in many cases roads and railways are one of the major reasons of fatalities of protected species. According to reports, 45 elephants died between 2019-2021 and 26 tigers died between 2010-2021 due to railway accidents.  For development of access roads to adjoining villages or human habitations, diversion of forest lands must be allowed judiciously following due procedure of forest clearance under Section 2 of the Act and in such a manner that it causes minimum disturbance to the forest and wildlife, rather than through blanket exemption.	
(1) (a) (2)(b) such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1); and	Need for clarity on definition of 'reafforestation' and whether it is different from 'reforestation' - planting of trees on non-forest land or planting of trees on land which was previously forest. Act must define the term 'reafforestation' to prevent ambiguity or misuse	Definition of 'reafforestation' to be recommended for addition
(1)(a)(2)(c)  such forest land,—  (i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or  (ii) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related	According to the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, between 1996-2016, defence projects have taken up the second largest amount of forest land (1,549 sq.km.), second only to mining (4,947 sq.km.).  Strategically important linear infrastructures are already given permissions expeditiously by the Central Government under 'general approval' scheme. In such circumstance, blanket exemption is unreasonable and unwanted.  Infrastructure and linear development projects in Himalayan and North-Eastern India involve activities such as blasting and excavation, creating tunnels, damming of water streams etc.,	Recommend to be deleted from the amendment

infrastructure; or which has significant and irreversible damage to the ecologically sensitive landscape of these regions. Experts (iii) as is proposed to be used have pointed out the role of such for construction of defence infrastructure related project or a camp for development significant as paramilitary forces or public contributor in intensifying the impact of utility projects, as may be extreme weather events leading to specified by the Central landslides and severe floods. Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing As per (1)(a)(2)(c) (iii) the term 'public Extremism affected area as utility' remains ambiguous, open ended may be notified by the Central and open to interpretation - such blanket Government. exemptions are undesirable but are also inconsistent, and ultra vires to the purpose of FCA. Accordingly, any permission for such activities must be granted on a case-on-case basis following due procedure under Section 2 of the Act. (1)(a)(2)(c)Suggestion: prior to availing exemption for Blanket exemption of 100 km from security related international border is of particular infrastructure, in forest concern in the North East region, due to areas, it is proposed proximity to international borders & that listed agencies small size of state - as a result, will consult would subsume the entire state and open up stakeholders mainly pristine forest areas along with its local communities biodiversity for non-forestry uses residing nearby. As without FCA regulation. Further, the these forest areas form ecologically fragile landscape along the multiple use areas LAC has the majority of the Protected accessed by the local Areas with critically threatened communities endemic species of flora and fauna, blanket exemption, but whose conservation will be threatened. case-by-case forest clearance based on stakeholder consultation. (1)(a)(3)While plantations may provide some Recommend to be benefits, they do not provide the same deleted from level of ecological services as natural amendment The exemption provided under forests. Plantations, however, can sub-section (2) shall be subject exacerbate soil erosion and degrade soil to such terms and conditions, quality, as they often require intensive including the conditions of fertilization, pesticide use. and planting trees to compensate irrigation. Further, plantations do not felling of trees undertaken on provide habitat for the wildlife, as they the lands, as the Central do not contain the structural complexity Government may, and diversity of natural forests. guidelines, specify. Therefore, it is important to prioritize protection and restoration of natural forests and to manage them sustainably,

		rather than relying on plantations as a replacement. Any afforestation operation must be undertaken with the objective of ecological restoration and augmenting native biodiversity.	
Section 2(1) (iii)	Section 2(1) (iii)  (iii) that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organization subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify;	The purpose of such leasing of forest lands by the state must be ensured for conservation of forests and wildlife only.	(iii) that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency, or any other organization unless it is in the interest of in situ conservation of forest and wildlife, subject to such terms and conditions, as the Central Government may with reason prescribe;
Section 2 (1) (b)	Any purpose other than reafforestation, but does not include any work relating to or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife,	The purpose for all such establishments must be to protect and conserve the forests and wildlife, and not for any leisure or commercial purposes. Thus, it is essential that <b>sufficient reasoning</b> is provided for such developments as a necessity for forests and wildlife conservation.  Under the provision on exemption of works 'ancillary to conservation', the Act must also specify the Certified Authority which would decide whether the work falls under the category of ancillary or related work. It is suggested that the <b>Certified Authority</b> with respect to conservation of wildlife should be the Chief Wildlife Warden or Principal Chief Conservator of Forest ("PCCF") with respect to forest conservation.	Any purpose other than reafforestation, but does not include any work relating to or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife, which shall be certified by the concerned Chief Wildlife Warden or Principal Chief Conservator with reasons in writing.  • Need for Act to define 'reafforestation'.
Section 2(1) (b)	i. silvicultural operations including regeneration operations;	Silvicultural operations must be undertaken with the objective of ecological restoration and augmenting native biodiversity.	i. silvicultural operations including regeneration operations which are purported to restore the original flora of the area and do not include plantation of species exotic to the area in question or

		causing disturbance to the wildlife;
ii. establishment of check- posts and infrastructure for the front-line forest staff;	Specify to prevent misuse (such as illegal collection of money allowing extraction of forest materials)	Establishment of check-posts and infrastructure for the front-line forest staff, that do not affect or disturb the movement of wild animals
iii. establishment and maintenance of fire lines;		No change
iv. wireless communications;	Specify to prevent misuse	iv. wireless communications which are required for the front-line forest staff;
v. construction of fencing, boundary marks or pillars, bridges and culverts, check dams, waterholes, trenches and pipelines;	Specify to prevent misuse	v. construction of fencing, boundary marks or pillars, bridges and culverts, check dams, waterholes, trenches and pipelines, solely required for the purpose of forest and wildlife conservation and certified as such by the concerned Chief Wildlife Warden or Principal Chief Conservator of Forest.
vi. establishment of zoo and safaris referred to in the Wild Life (Protection) Act, 1972, owned by the Government or any authority, in forest areas other than protected areas;	Allowing zoos and safaris within the scope of non-forest activities in the FCA will disproportionately commercialise forests and wildlife.  Such establishments not only come at the cost of fragmentation and destruction of existing forest and wildlife habitats, but have a huge cumulative impact from associated infrastructure, access routes, public amenities and other disturbances which cannot be termed as beneficial to the forests and wildlife.	Recommend to be deleted from the amendment

vii. eco-tourism facilities	In recent years mushrooming of tourism	Recommend to be
included in the Forest Working Plan or Wildlife Management Plan or Tiger Conservation Plan or Working Scheme of that area; and	facilities has led to overuse, disturbance and serious management problems in several PAs. The National Wildlife Action Plan defines eco-tourism as eco-friendly and regulated wildlife-based tourism and also states that in case of any conflict between tourism and conservationinterests of a PA, the paradigm for the decision must be that tourism exists for the Protected Areas and not vice versa, and that demands of tourism must be subservient to and in consonance with the conservation interests of Protected Areas.	deleted from the amendment
	The exemption of establishment of ecotourism facilities be deleted, instead they may be regulated as per the existing procedure of forest clearance under Section 2 of the FCA and decided on a case-to-case basis keeping in view the local circumstances and species affected.	
viii. any other like purposes, which the Central Government may, by order, specify."]	Specify to prevent misuse	viii. any other like purposes necessary for conservation of forest and wildlife, which the Central Government shall by reason prescribe.
Section 2 (2) The Central Government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-forest purpose.	Exemption of permission for conducting such surveys will open the floodgates for conducting surveys for purely commercial activities like mining. Some of these surveys or investigations might require drilling/digging of surface, clearing of vegetation, levelling of ground, creating access roads and producing high decibel noise or use of light at night or any other activity which might be detrimental to the wildlife and the ecosystem. Recently, the Gauhati High Court stayed Environmental Clearance to Oil India Limited with respect to exploration and drilling through extended reach drilling for hydrocarbons at seven locations in Dibru Saikhowa National Park due to the absence of a Biodiversity Impact Assessment.  Therefore, a blanket exemption to such surveys is not recommended. It is	Recommend to be deleted from the amendment

	suggested that the exemption to survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation, or exploration be deleted, and the existing procedure for permission under Section 2 of the Act be continued for such activities.	

**Email Joint Committee on Forest Conservation** 

From: Pradyut Bordoloi pradyut.bordoloi@sansad.nic.in Fri, Jul 14, 2023 01:36 PM

Subject: Re: Sir/Madam, You have Received an Email from Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 (JCFCAB), Lok Sabha Secretariat

To: Joint Committee on Forest Conservation <jcfcab- Iss@sansad.nic.in>

Dear Chairman,

I as member of the JPC could not attend the last meeting held on the adoption of the report hereby confirm that I have read the report and already sent my letter of dissent to be recorded as per the Direction clause 87 by the Speaker.

Best regards,

Pradyut Bordoloi

MP Lok Sabha

-----Original Message------

From: jcfcab-lss@sansad.nic.in

To: pradyut bordoloi <pradyut.bordoloi@sansad.nic.in>

Sent: Fri, 14 Jul 2023 13:14:34 +0530 (IST)

Subject: Sir/Madam, You have Received an Email from Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 (JCFCAB), Lok Sabha Secretariat

Madam/Sir,

Kindly see the attached documents on the above mentioned subject.

Regards JCFCAB Cell

फूलोदेवी नेताम सांसद-राज्य सभा (छत्तीसगढ़) PHULODEVI NETAM Member of Parliament Rajya Sabha-Chhattisgarh Member-Standing Committee on Railways



# बंगला नं. 34, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली - 110001

34, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-110001 E-mail: phulodevi.netam@sansad.nic.in Mob.: +91-9425597472

> दिनांक: 10.07.2023 MPRS/CG/2023-10

आदरणीय श्री अग्रवाल जी,

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। गया था जिसकी मैं भी सदस्या हूँ। सिमिति ने सदस्यों की कई बैठकें की, कई राज्यों का दौरा किया, कई मंत्रालयों के साथ चर्चा की सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा की और उसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। मैंने भी अपने विचार सिमिति की बैठकों में रखे थे। वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने उचित है जिन्हें सभी बैठकों में प्रमुखता से उठाया गया है। जो निम्नलिखित है:

## 1. खंड 3: वन (संरक्षण) अधिनियम का शीर्षक बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम किया जाना ।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 में शीर्षक संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है कि इसका शीर्षक 'वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम रखा जाए। चूंकि वन संरक्षण से संबंधित अधिनियम हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां कि 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अपने भरण-पोषण और आजीविका के लिए जंगलों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों पर ही निर्भर है। अधिनियम की शब्दावली में सभी का समावेश होना आवश्यक है चाहे वो नॉर्थ-ईस्ट हो या दक्षिण भारत जहां गैर हिंदी भाषी आबादी रहती है इसलिए अधिनियम का शीर्षक नहीं बदला जाना चाहिए।

# 2. खंड 4: एफसीए के तहत कवर की जाने वाली भूमि के संबंध में धारा 1ए (उपधारा 1) को सम्मिलित किया जाना।

बिल प्रावधान करता है कि दो प्रकार की भूमि अधिनियम के तहत आएगी (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित / अधिसूचित भूमि या (ख) पहली श्रेणी में न आने वाली भूमि, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद वन के रूप में अधिसूचित। इसके अलावा अधिनियम 12 दिसम्बर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग में गैर-वानिकी उपयोग में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा, जिसका आदेश किसी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत अथॉरिटी ने दिया है।

यहां एफसीए के दायरे में केवल उसी भूमि को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है जो 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद वन के रूप में दर्ज है, ऐसे में वन भूमि क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को विशेष रूप से छूट दी जाएगी क्योंकि भारत में वन भूमि के बड़े हिस्से को हस्तांतरण के दौरान वन के रूप में दर्ज किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद संबंधित राज्यों में जमींदारी प्रथा को समाप्त करते हुए वन विभाग को भूमि का आवंटन हुआ। अनुचित सीमांकन, स्वामित्व, विवादों और प्रशासनिक सुस्ती के कारण ऐसी हस्तांतरित भूमि के एक बड़े हिस्से को भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य वन विधानों के तहत वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सका। हालांकि, ऐसी भूमि को एफसीए के तहत वनों के रूप में संरक्षित किया जाना जारी है, भले ही उनका स्वामित्व कुछ भी हो। ऐसे वन अरावली मध्य भारतीय पठार, पश्चिमी घाट आदि जैसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध परिदृश्यों में आसानी से पाए जा सकते हैं और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने वाले वन्यजीव आवास के रूप में महत्वपूर्ण हैं।

यदि विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है, तो इन जैव विविधता वाले हॉटस्पाट का अब वन नहीं माना जाएगा और इन्हें संभावित रूप से बिना किसी नियामक निरीक्षण के बेचा जा सकता है, काटा एवं हटाया जा सकता है।

# 3. खंड 4: एफसीए के तहत कवर नहीं की जाने वाली भूमि के संबंध में धारा 1ए (उपधारा 2) को जोड़ा जाना।

इसके तहत कुछ श्रेणियों को वन मंजूरी के प्रावधानों से छूट देने के प्रस्ताव के निम्नलिखित गंभीर परिणाम होंगे। जैसे :—

(a) जैव संवेदनशील क्षेत्रों पर खतरा हिमालय में महत्वपूर्ण वन एवं पर्वतमालाऐ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो स्थानिक जैव विविधता से समृद्ध है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता के कारण छूट दी जाएगी। बिना किसी assessment और mitigation plan के ऐसे जंगलों को साफ करने से न केवल जैव विविधता को खतरा होगा, बल्कि पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की संवेदनशीलता भी बढ़ेगी, जो पहले से ही अस्थिर बुनियादी ढांचे के विकास और चरम मौसम की घटनाओं से खतरे में हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूर्ण छूट समस्याग्रस्त है क्योंकि उनका संवेदनशील परिदृश्य और जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और चरम मौसम की घटनाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय खतरों के कारण बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

- (b) शब्दावली का व्यापक दायरा: सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता के लिए वन भूमि का उपयोग भी बहुत व्यापक है। वन भूमि पर सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं को बिना Forest clearance के स्थापित किया जा सकेगा। इसमें कई तरह की परियोजनाऐं आ जाती हैं जैसे परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि। यह वस्तुतः वन भूमि पर किसी भी परियोजना के निर्माण की अनुमित देता है।
- (c) इसके अलावा, धारा 2 के संशोधन में प्रस्तावित: इकोटूरिज्म सुविधाओं और किसी अन्य उद्देश्य जैसी अस्पष्ट शब्दावली का उपयोग करके छूट प्रदान की जा रही है। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे वन भूमि में वनों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। चिडियाघरों, सफारी और वन प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को वानिकी गतिविधियों के दायरे में लाना एफसीए और एफसीए दिशानिर्देश, 2019 के साथ असंगत है जो स्पष्ट रूप से कम पदचिहन संरक्षण प्रतिष्ठानों को प्रदर्शनी उन्मुख आउटरीच केंद्रों से अलग करता है। इसके अलावा, यह वनों का असंगत रूप से व्यावसायीकरण कर सकता है और वन पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ सकता है।
- (d) विधेयक में प्रदान की गई छूट व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगी और ये वन (अधिसूचित वनों सहित) तथा वन्यजीवों के लिए अपरिवर्तनीय अशांति का कारण होगी। एक आम धारणा है कि वन्यजीव केवल संरक्षित क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते है। जबिक इसके विपरीत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र भी वन्यजीवों के आवास और जैव विविधता वाले क्षेत्र होते है।

प्रस्तावित विधेयक किसी प्रभाव मूल्यांकन या किसी भी प्रकार का अन्य कोई प्रावधान नहीं करता है। इससे वन्यजीवों के आवासों और प्रजातियों के नुकसान पर कोई नियामक निगरानी नहीं होगी। सड़कें, रेलवे लाइन आदि का वन्य जीवों के आवासों और वन्य जीवन पर असमान रूप से व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये प्राकृतिक वनों का क्षरण करते हैं। इस तरह व्यापक तरीके से सुरक्षा उपायों को हटाना केवल और केवल जंगलों को और अधिक खतरे में डालना और नष्ट करना साबित होंगे।

- 4. खंड 6, धारा 3सी: निर्देश जारी करने की शक्ति विधेयक में सभी जगह यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार केन्द्र, राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण / संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी कर सकती है। चूंकि संविधान के तहत वनों की गणना राज्य सूची में की गई थी लेकिन 42वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे समवर्ती सूची के तहत लाया गया जो वनों पर कानून बनाने के लिए राज्य और केन्द्र की संयुक्त जिम्मेदारी बना देता है लेकिन विधेयक के माध्यम से राज्यों के पास कोई अधिकारी नहीं रह जाएंगे।
- 5. **खंड 4 (2) (c) (iii)**: इस उपधारा के लिए 'जन सुविधा परियोजनाऐं' में निम्नानुसार कार्य शामिल होने चाहिए, जिसकी छत्तीसगढ राज्य द्वारा लम्बे समय से मांग की जाती रही है। (1) मोबाईल टॉवर, (2) ओएफसी केबल (3) पैरामिलिटरी बलों और राज्य पुलिस के कैम्प के लिए पहुंच मार्ग और सुरक्षा बलों के लिए हेलीपेड (4) अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी हॉस्टल / आश्रम निर्माण (5) एकलव्य विद्यालयों की स्थापना (जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना) (6) 5 मेगावॉट तक के सौर्य ऊर्जा संयंत्र हेतु, जहां 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर से कम वाले वन भूमि वाले क्षेत्र या पहाड़ / चट्टान जैसे नैसगिक रूप से वृक्ष विहीन क्षेत्रों में।
- 6. खंड (1) (a) (2) (c): अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास और उत्तर-पूर्व के छोटे क्षेत्रफल वाले राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 100 कि.मी. तक की पूर्ण छूट विशेष चिंता का विषय है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य को इसमें शामिल कर लिया जाएगा और बिना एफसीए विनियमन के जैव विविधता के साथ प्राचीन वन क्षेत्रों को गैर वानिकी उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा एलएसी के साथ पारिस्थितिक रूप से नाजुक परिदृश्य में अधिकांश संरक्षित क्षेत्र है जहां गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवों की स्थानिक प्रजातिया है जिनके संरक्षण को खतरा होगा।
- 7. खंड 5: धारा 2 की उपधारा 2 जोडना: यह अनुभाग सर्वेक्षण गितविधियों, जैसे तेल कंपनियों द्वारा टोही, भूकंपीय सर्वेक्षण और ड्रिलिंग को एफसीए की मंजूरी, जांच या अन्वेषण से छूट देता है इससे कोयला, लौह के लिए स्कोपिंग, पूर्वेक्षण और सर्वेक्षण के लिए देश भर में जैव विविधता समृद्ध जंगल में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 1,382 द्वीप भी खतरे में आ जाएँगे जहां वाणिज्यिक लाभ के लिए बिना पर्यावरणीय सुरक्षा के तेल और अन्य खनिज भण्डारों का दोहन किया जाएगा। ऐसी छूट जंगल, तटरेखा द्वीप पर रहने वाले वन्यजीवों पर होने वाले विपरीत प्रभाव पर निर्भर होनी चाहिए।

इसके साथ ही एक अन्य प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। किसी भी वन क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को किसी व्यक्ति या अधिकारी, निगम एजेंसी या किसी अन्य संगठन को लीज पर दिया जा सकता है या अन्यथा, जो कि संबंधित राज्य सरकार से परामर्श के बाद केन्द्र सरकार अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 8. वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन तटस्थता पर जोर देगे का आलोचनात्मक मूल्याकन:वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन तटस्थता प्राप्त किए जाने का उल्लेख बिल में किया गया है। यह भारत के जंगलों की रक्षा और संरक्षण के अधिनियम के मूल उद्देश्य को खतरे में डाल सकता है।

हालांकि राष्ट्रीय शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताए महत्वपूर्ण हैं। हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ तर्क दे रहे हैं कि वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक बनाना और वृक्ष आवरण बढ़ाने की दिशा में कई हानियां होंगी जैसे मिट्टी का कटाव होगा, जैव विविधता का संरक्षण नहीं होगा, जल संसाधन समाप्त हो जाएंगे आदि अन्य पारिस्थितिकी तंत्र बिगड जाऐंगे।

एक शोध यह बताता है कि प्राकृतिक वन इस संबंध में कहीं अधिक प्रभावी है और प्राकृतिक वनों की कार्बन अवशोषण क्षमता वृक्षारोपण की तुलना में 40 गुना अधिक है। यह भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि वनों का विनाश और क्षरण स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगा जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।

9. वनों की रक्षा के लिए कर्तव्य का अभाव बिल में किए गए संशोधन में यह कहीं नहीं दिखता कि ये संशोधन वनों की रक्षा को प्रमुखता देने के लिए लाए गए हैं। संविधान ने सरकार को जंगलों का अभिभावक बनाया है और इस बिल के माध्यम से सरकार अपनी जिम्मेदारी का दुरूपयोग करने की कोशिश कर रही है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को अंधाधुंध वनों की कटाई को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो एक प्रमुख चिंता थी लेकिन बिल में दिए गए प्रावधानों से यह चिंता खत्म होती नहीं दिख रही।

आशा है उक्त आवश्यक संशोधनों को विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा। सादर,

भवदीया,

(फूलोदेवी नेताम)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल, सांसद अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023

# R.GIRIRAJAN MEMBER OF PARLIAMENT (RAJYA SABHA)

11th July, 2023

#### **Dissent Note**

To,

The Chairman,

Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

Sir,

I hereby give my dissent on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 due to the following:

1. The Title of the bill should be understood by all throughout the country as well as the all over the world. English language is known to all the stakeholders.

Therefore the word 'Forest Conservation Act' should be retained as it is understood well throughout the country... Sanskritic Terminology is untenable.

Let it be called the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023

- Forests and conservation of forest is under Concurrent List. State Governments have administrative control over forests. Therefore assigning all powers to Central Government infringes on Federal rights of the State Governments... Any decision should be arrive at only after proper discussion with the State Governments.
- 3. The Proposed amendments are inconsistent and *ultra vires* to the principal Act, severely compromises the constitutional mandate of the State (Article 48A) to safeguard forests, and jeopardizes the access to information, public participation and access to justice, which are essential component of Rio Declaration 1992 and fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution.

Hence I oppose and dissent the Bill.

R. GIRIRAJAN MEMBER OF PARLIAMENT (RAJYA SABHA) TAMIL NADU Point 1

The Title of the bill should be understood by all throughout the country as well as the all over the world.

English language is known to all the stakeholders.

Therefore the word 'Forest Conservation Act' should be retained as it is understood well throughout the

country... Sanskritic Terminology is untenable.

Let the it be called Forest (Conservation) Amendment Act, 2023

Point 2

Forests and conservation of forest is under Concurrent List. State Governments have administrative

control over forests. Therefore assigning all powers to Central Government infringes on Federal rights of

the State Governments... Any decision should be arrive at only after proper discussion with the State

Governments.

Point 3

The Proposed amendments are inconsistent and ultra vires to the principal Act, severely compromises

the constitutional mandate of the State (Article 48A) to safeguard forests, and jeopardizes the access to

information, public participation and access to justice, which are essential component of Rio Declaration

1992 and fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution.

Hence I oppose and dissent the Bill.

R. GIRIRAJAN

MEMBER OF PARLIAMENT

(RAJYA SABHA)

TAMIL NADU

Note of Dissent submitted by Shri Jawhar Sircar, MP (Rajya Sabha) and Smt. Sajda Ahmad, MP (Lok Sabha) to the Joint Committee on the Proposed Amendments to the Forest (Conservation) Act.

#### Suggestion 1.

Please retain original title of the Forest (Conservation) Act and DO NOT include the new words, namely "Evam Samvardhan)"

## Suggestion 2.

Under section 1A (1), please SUBSTITUTE amendment provision, namely,

"The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely: —

- (a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.
- (b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October 1980"

#### WITH THE WORDS:

- "The following land shall be covered under this Act, namely: —
- (a) the land that has been declared or notified or is under the process of being notified as a forest following the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.
- (b) the land that is not covered under clause (a) but has been recorded in Government records as forest irrespective of their ownership.
- (c) the land that is not covered under clauses (a) or (b) but is recognisable as forests by local communities or in terms of its ecological and cultural significance.
- (d) the land that is not covered in clauses (a), (b), (c) but identified or used for compensatory afforestation in lieu of forest diverted under Section 2 of the Act."

#### Suggestion 3.

Again, in 1A (1), please DELETE this part of proposed amendment, ie,

"Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for non- forest purpose on or before the 12th December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf".

#### Suggestion 4

In 1A. ((2) where roadside amenities are mentioned,

please SUBSTITUTE THE WORDS

"which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;"

#### WITH THE WORDS:

"which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 1000 square feet in each case;"

#### AND ADD PROVISO

"provided there are not more than three such amenities in each cluster and every cluster shall be not less than 50 kilometres apart"

in order to minimise the disturbance to forests.

### Suggestion 5.

Again, in 1A (2) b) AFTER the words

"such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1);"

**ADD PROVISO** 

"but shall not include compensatory afforestation"

### Suggestion 6.

Further, in 1A (2), AFTER THE WORDS

"such forest land,-

(i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international", insert "Himalayan" BEFORE CONTINUING as "borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or".

## Suggestion 7.

And, furthermore, in 1A (2), AFTER THE WORDS

"(3) The exemption provided under sub-section (2) shall be subject to such terms and conditions, including the conditions of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands, as the Central Government"

**INSERT** 

"in consultation with concerned State Government"

THEN CONTINUE

"may, by guidelines, specify."

## Suggestion 8.

Again, to continue with 1A (2)

the Act must limit the term "public utility projects" in the following phrase

"iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.",

BY CLEARLY STATING THAT such projects shall be directly under Government and it agencies and SHALL NOT BE

"privatised, leased or the operational control of which shall be handed over to any private company or entity".

## Suggestion 9.

In ALL PLACES ADD the words "in consultation with concerned State Governments" after the words "Central Government" wherever issuing of orders and guidelines appears.

# Suggestion 10.

After Section 2(1) (iii)

"that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organisation subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify;"

#### PLEASE INSERT PROVISO

"Provided there are wide public consultations before such assignment with environmentalists, wild life exports and the local community and it is in the interest of in situ conservation of forest and wildlife"

## Suggestion 1

In Section 2 (1) (b), after the words

"any purpose other than reafforestation, but does not include any work relating to or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife,"

#### **INSERT THIS PROVISO**

"Provided concerned Chief Wildlife Warden or Principal Chief Conservator of Forests shall certify the same with reasons in writing."

#### Suggestion 11.

In Section 2(1) (b) after the phrase

"i. silvicultural operations including regeneration operations;"

#### **INSERT THIS PROVISO**

"Provided that the species shall retain and restore the original ones and shall not be exotic or invasive or disturb the wildlife therein"

**Email** 

Joint Committee on Forest Conservation

From: Jawhar Sircar jawhar.sircar@sansad.nic.in

Thu, Jul 13, 2023 12:40 PM

1 attachment

Subject: Forest Conservation Act—Note of Dissent to Report of Joint Committee on Amendments to the Forest Conservation Act.

To: Joint Committee on Forest Conservation <jcfcab-lss@sansad.nic.in>

Cc: raypurnendu@yahoo.in

Sir/Madam,

I could not attend the last meeting held on 11 July, 2023 but I certify (as per Direction 87 of the 'Directions by the Speaker') that I have read the said report before I file this 'Note of Dissent'.

Jawhar Sircar, MP RS

Sent from my iPad Jawhar Sircar Sent from my iPad

Forest Conservation Act .docx 11 KB

#### **Email**

#### Joint Committee on Forest Conservation

## Certificate for JCFB Report

From: Sajda Ahmed sajda.ahmed@sansad.nic.in Fri, Jul 14, 2023 12:31 PM

Subject: Certificate for JCFB Report

To: Joint Committee on Forest Conservation <jcfcab -lss@sansad.nic.in>

Reply To: Sajda Ahmed <sajda.admed@nic.in>

To

The Chairperson

Joint Parliamentary Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill

Dear Sir,

I am writing to inform you that I was unable to attend the JCFB meeting that took place on July 11, 2023.

I would like to state that, in accordance with Clause 87 of the "Directions by the Speaker," I have read the report.

With regards

Sajda Ahmed MP / सजदा अहमद

Lok Sabha / संसद सदस्य (लोकसभा)

Uluberia PC, Howrah, West Bengal

Member Department Related Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change

Member Consultative Committee Ministry of External Affairs Govt of India

C-II/5 Tilak Lane NEW DELHI-110001 Tel-011-23782786, FAX-011-23782779 Mob-9836390227, 9871436166(PS)

अनुबंध-1

145

(ভা. ঘীতা বহিন্ত)
(Dr. REETA VASISHTA)
দ্বাবি এই ভবেংবাৰ
বিষি আই আমে মন্সাল্য
Ministry of Law & Justice
(বিঘানী বিশান/Legislative Deptt.)
লই বিল্লী/New Delhi

# 2023 का विधेयक संख्यांक 80

[दि फोरेस्ट (कंजरवेशन) अमेंडमेंट बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

# वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । उद्देशिका का अंत:स्थापन। 2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) दीर्घ शीर्ष के पश्चात् और अधिनियमिति सूत्र से पूर्व निम्नलिखित उद्देशिका अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1980 का 69

"और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए और पारिस्थितिकीय रूप से संतुलित भरणीय विकास के माध्यम से वन कार्बन स्टॉक का अनुरक्षण या वृद्धि करने के लिए वनों की महता को अनुभव किया जाना है;

और देश के राष्ट्रीय रूप से अवधारित योगदान लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन सीओ $^2$  के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने की परिकल्पना करते हैं:

और देश अपने भूमि क्षेत्र के एक-तिहाई तक वन और वृक्ष आच्छदन में वृद्धि करने की परिकल्पना करता है, जिसे बढ़ी हुई वृद्धि प्रक्षेप्कता के साथ बल प्रदान किया जाना है;

और भारत की वनों को और उनकी जैव-विविधता को संरक्षित करने की समृद्ध परंपरा रही है और इसलिए वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय फायदों में वृद्धि की जा रही है जिसके अंतर्गत वनों पर निर्भर समुदायों के जीवनयापन में सुधार की परिकल्पना भी सम्मिलित की गई है;

और इसलिए, वनों के संरक्षण प्रबंधन और पुन: बहाली से संबंधित उपबंधों का उपबंध करने, पारिस्थितिकीय सुरक्षा, भरणीय संस्कृति और वनों के पारंपरिक महता का अनुरक्षण करने तथा आर्थिक आवश्यकताओं और कार्बन तटस्थता को बनाए रखने की आवश्यकता है।"।

धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "वन (संरक्षण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

नई धारा 1क का अंत:स्थापन । 4. मूल अधिनियम की धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय भूमि को समाविष्ट करने के लिए अधिनियम। "1क. (1) निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात् :—

(क) वह भूमि, जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है:

1927 का 16

(ख) वह भूमि, जो खंड (क) के अधीन नहीं आती है, किंतु 25 अक्तूबर, 1980 को या उसके पश्चात् किसी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज की गई है:

परंतु इस खंड के उपबंध, ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस संबंध में राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर, 1996 को या उससे पहले वन से गैर-वन प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है; और स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी अभिलेख" पद से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग या वन विभाग अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी प्राधिकारी, स्थानीय निकाय, समुदाय या परिषद द्वारा धारित अभिलेख अभिप्रेत है।

- (2) निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट नहीं होगी, अर्थात :—
  - (क) रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क, जिसका अनुरक्षण सरकार द्वारा किया जा रहा है, के समीप अवस्थित ऐसी वन भूमि जो आवास या रेल या सड़क के किनारे सुख-सुविधाओं के लिए, प्रत्येक मामले में अधिकतम 0.10 हेक्टेयर माप तक पहुंच प्रदान करती है;
  - (ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष, वृक्षारोपण या वनरोपण जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं है; और

## (ग) ऐसी वन भूमि,—

- (i) जो राष्ट्रीय महता की सामरिक लिनियर परियोजना और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने के प्रयोजन हेतु यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित है; या
- (ii) जो सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक है; या
- (iii) जो रक्षा संबंधी परियोजना या अर्द्धसैनिक बलों के लिए कैंप या लोकोपयोगी परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित है जो वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पांच हेक्टेयर से अधिक नहीं है।
- (3) उपधारा (2) के अधीन उपबंधित छूट, ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत भूमि से पेड़ों की कटाई के प्रतिकर के लिए वृक्षारोपण की शर्त भी है, जैसा केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन रहते हुए होगी।"।
- 5. मूल अधिनियम की धारा 2 को उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और—

धारा 2 का संशोधन ।

- (क) इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) में,—
- (I) खंड (iii) में, "जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध या नियंत्रण के अधीन नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे;

(॥) स्पष्टीकरण में खंड (ख) के पश्चात आने वाली दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थातु :—

और प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य जैसे कि—

- (i) वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत पुनरूद्धार अभियान भी है;
- (ii) सीमावर्ती वन कर्मचारिवृंद के लिए चैक-पोस्ट और अवसंरचना की स्थापना:
  - (iii) अग्निरेखाओं की स्थापना और अन्रक्षण;
  - (iv) बेतार संचार;
- (v) बाड़, सीमा चिन्हों या स्तंभों, पुलों और पुलियाओं, चैक बांधों, जल-गट्टों, खाइयों और पाइपलाइनों का संनिर्माण;
- (vi) सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र से भिन्न वन क्षेत्रों में स्वामित्वधीन चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना :
- (vii) वन कार्यकरण योजना या वन्य जीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या उस क्षेत्र की कार्यकरण योजना में सम्मिलित पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाएं ;
- (viii) इस प्रकार का कोई अन्य प्रयोजन, जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

सम्मिलित नहीं है।";

- (ख) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
  - "(2) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या परीक्षण, जिसके अंतर्गत भुकंप सर्वेक्षण है, को गैर-वन प्रयोजन नहीं माना

जाएगा।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 3ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

3ग. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकारी को या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संगठन, इकाई या निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी. जो इस अधिनियम के कार्यान्यन के लिए आवश्यक समझे।

नई धारा 3ग का अंत:स्थापन।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने शक्ति।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह उपबंध करता है कि वन भूमि को अनारक्षित करने, गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग करने, प्राईवेट अस्तित्वों को पट्टे के माध्यम से वन भूमि देने और पुन: वन लगाने के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को काटने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित है।

- 2. इसके अधिनियमित होने के पश्चात्, पारिस्थितिकी, सामाजिक और पर्यावरणीय घटनाओं जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने और वन कार्बन स्टॉक को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने से संबंधित नई चुनौतियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई हैं। और, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3.0 बिलयन टन सीओ<sub>2</sub> के समतुल्य कार्बन सिंक के सृजन के लिए वन या वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करने के देश के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय फायदों में वृद्धि द्वारा, जिसके अंतर्गत वन पर निर्भर करने वाले समुदायों के जीवन-यापन में सुधार सिम्मिलत है, सहजीवी रूप से वन और उनकी जैव विविधता के परिरक्षण की समृद्ध परंपरा को अग्रसर करने के लिए इस अधिनियम के क्षितिज को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।
- 3. और, तारीख 12 दिसंबर, 1996 के माननीय उच्चतम न्यायालय के (टी॰एन॰ गोदावर्मन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में) निर्णय से पूर्व उक्त अधीनियम के उपबंधों को अधिसूचित वन भूमियों पर लागू किया गया था और न राजस्व वन क्षेत्रों पर लागू किया गया था तथा राजस्व वन क्षेत्रों में गैर वानिकी उपयोग को सरकार और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अनुदत्त अनुज्ञा के माध्यम से अनुज्ञात किया गया था। उक्त निर्णय के पश्चात्, अधिनियम के उपबंधों को अभिलिखित वन क्षेत्रों, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिलिखित वन सम्मिलित हैं, जिनको पहले से ही गैर वानिकी उपयोग के लिए रखा गया था, में लागू किया गया था, जिससे प्राधिकरणों को भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन करने तथा कोई विकास या उपयोगिता से संबंधित कार्य अनुज्ञात करने पर निबंधित किया गया। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में प्राईवेट और गैर सरकारी वन भूमियों में बागान लगाने के संबंध में चिंताए उठाई गई। इस स्थिति का परिणाम, अधिनियम के उपबंधों के विशेषकर अभिलिखित वन भूमियों, प्राईवेट वन-भूमियों, बागानों आदि में उनके लागू होने के संबंध में गलत निर्वचन के रूप में हुआ। इसलिए, विभिन्न किस्म की भूमियों में अधिनियम के लागू होने और लागू नहीं होने के परिणाम को विहित करना आवश्यक समझा गया है।
- 4. राष्ट्रीय महता की सामिरक और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के त्विरत निपटान की आवश्यकता भी है, तािक महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं के विकास को विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा-क्षेत्रों के साथ-साथ जैसे वास्तिवक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और लेफ्ट विंग चर्मपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार सार्वजिनक राजमार्गों और रेल के साथ के छोटे स्थापनों और बस्तियों को उन्हें मुख्य राजमार्गों और अन्य सार्वजिनक सुविधाओं तक पहुंच और संपर्क उपलब्ध कराके सुकर बनाने की भी आवश्यकता है।
- 5. चूंकि, अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् पिछले चार दशकों के दौरान वनों के पिरस्थण और विकास से संबंधित पारिस्थितकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं और नीतियों में

परिवर्तन हुआ है, जिससे इसके उपबंधों को देश की पारिस्थितिकीय, सामरिक और आर्थिक अभिलाशाओं में गितशील परिवर्तनों के अनुरूप रखने के लिए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को संसद् में पुर:स्थापित करना प्रस्तावित है। उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है—

- (i) देश की वनों, उनकी जैव-विविधता को परिरक्षित करने की समृद्धि परंपरा और अपने परिधि के भीतर जलवायु परिवर्तन चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिनियम में एक उद्देशिका अंत:स्थापित करना;
- (ii) अधिनियम के संक्षिप्त नाम को संशोधित करके वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 करना है, जिससे उसके उपबंधों की संभावना को उसके संक्षिप्त नाम में परिदर्शित किया जा सके:
- (iii) विभिन्न भूमियों पर अधिनियम के लागू होने के परिणाम को स्पष्ट करना तािक अस्पष्टता को दूर किया जाए और स्पष्टता लाई जा सके;
  - (iv) अधिनियम के कार्यक्षेत्र से भूमियों की कतिपय श्रेणियों को छूट प्रदान करना-
  - (क) राष्ट्रीय महता की सामरिक और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं का त्वरित निपटान;
    - (ख) सार्वजनिक मार्गों और रेल के किनारे छोटे स्थापनों को पहुंच प्रदान करना; और
    - (ग) गैर-वन भूमि पर पौधा रोपण को बढ़ावा देना;
- (v) अधिनियम के अधीन प्रस्तावित छूटों पर विचार करते हुए भूमि पर पेड़ काटने के कार्य को हाथ में लेने की प्रतिपूर्ति करने के लिए वृक्ष रोपण की शर्त सिहत निबंधनों और शर्तों का उपबंध करना;
- (vi) ऐसे अधिक कार्यकलापों, जिन्हें वन परिरक्षण और वन्य जीवन के लिए हाथ में लिया जाता है, को वानिकी गतिविधियों में सम्मिलित करना;
- (vii) सरकारी और प्राइवेट अस्तित्वों, दोनों की बाबत अधिनियम के उपबंधों के लागू होने में एकरूपता लाना;
- (viii) केन्द्रीय सरकार को आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करना, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या परीक्षण, जिसके अंतर्गत भूकंप सर्वेक्षण भी है, को गैर-वन प्रयोजन नहीं माना जाएगा;
  - (ix) केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने के लिए सशक्त करना।
- 6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली; भूपेन्द्र यादव

# उपाबंध

संक्षिप्त नाम, विस्तार और

अपारक्षण या

वन भूमि के बनेतर प्रयोजन

के लिए उपयोग पर निर्बन्धन।

के

विस्तार प्रारम्भ।

वनों

,	वन (संरक्षण) अधि	नियम, 1980 (1980	) का अधिनियम संख	झ्यांक 69) से	ने उद्धरण
*	*	*	*	*	*
1. (1)	इस अधिनियम का	संक्षिप्त नाम वन (स	गंरक्षण) अधिनियम,	1980 है।	
*	*	*	*	*	*
2. किर	प्ती राज्य में त्तसमय	प्रवित्त किसी अन्य	विधि में किसी बात	ा के होते हुए	ए भी, कोई राज्य
सरकार या अन	य प्राधिकारी यह निवे	श करने वाला कोई	आदेश, केन्द्रीय सरक	जर के पूर्व अ	नुमोदन के बिना,
नहीं देगा—					
*	*	*	*	*	*
	(iii) कि कोई वन	भूमि या उसका कोई	ई प्रभाग पट्टे पर या	अन्यथा किर	नी प्राइवेट व्यक्ति
या किर	ती प्राधिकरण, निगम	, अभिकरण या किसं	n गी अन्य संगठन को, व	जो सरकार के	स्वामित्व, प्रबंध
या नियं	त्रण के अधीन नहीं	है, समनुदेशित किया	जाए;		
*	*	*	*	*	*
	<b>स्पष्टीकरण</b> –इस धार	ा के प्रयोजन के लिए	र्''वनेतर प्रयोजन''	से,—	
	(क) चाय, काफी,	मसाले, रबड़, पान,	तेल वाले पौधे उद्या	न-कृषि फस	ालों या औषधीय
पौधे क्	ो खेती के लिए;				
	(ख) पुनर्वनरोपण सं	। भिन्न किसी प्रयोज	न के लिए,		
किसी वन भूगि	म या उसके प्रभाग व	नो तोड़ना या काट क	र साफ करना अभिप्रे	त है किंतु इ	सके अंतर्गत वनों
और वन्य-जीव	त्रों के संरक्षण, विक	जस और प्रबंध से र	पंबंधित या उनसे अ	ानुषंगिक को	ई कार्य, अर्थात्,
चौकियों, अग्	न लाइनों, बेतार संच	गरों की स्थापना औ	र बाड़, पुलों और पु	लियों, बाधों,	जलछिद्रों, खाई
चिन्हों, सीमा ि	चन्हों, पाइप लाइनों व	का निर्माण या अन्य र	वैसे ही प्रयोजन नहीं <sup>:</sup>	हैं।	
*	*	*	*	*	*

# <u>COMPOSITION OF THE JOINT COMMITTEE ON</u> THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023

## Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

### LOK SABHA

- 2. Dr. Dhal Singh Bisen
- 3. Shri Raju Bista
- 4. Shri Jamyang Tsering Namgyal
- 5. Shri Tapir Gao
- 6. Shri Ajay Tamta
- 7. Shri Suresh Kumar Kashyap
- 8. Smt. Gomati Sai
- 9. Shri Sudarshan Bhagat
- 10. Shri Pallab Lochan Das
- 11. Km. Diya Kumari
- 12. Shri T.R. Baalu
- 13. Smt. Agatha K. Sangma
- 14. Smt. Sajda Ahmed
- 15. Shri Kotagiri Sridhar
- 16. Shri Rajendra Dhedya Gavit
- 17. Dr. Alok Kumar Suman
- 18. Shri Mahesh Sahoo
- 19. Shri Girish Chandra
- 20. Shri Pradyut Bordoloi\*
- 21. Ms. Geeta Kora\*

## RAJYA SABHA

- 22. Dr. Ashok Bajpai
- 23. Shri Anil Baluni
- 24. Shri Samir Oraon
- 25. Dr. C. M. Ramesh
- 26. Shri Jawhar Sircar
- 27. Dr. Prashanta Nanda
- 28. Shri Hishey Lachungpa
- 29. Shri Birendra Prasad Baishya
- 30. Shri R. Girirajan +
- 31. Smt. Phulo Devi Netam +

### **SECRETARIAT**

Shri J.M. Baisakh
 Shri Kalyanasundaram
 Director

Ms. Maya Menon
 Shri Rajeev Kumar
 Smt. Sonia Gupta
 Under Secretary
 Executive Officer
 Executive Officer

<sup>\*</sup> Nominated by the Hon'ble Speaker, Lok Sabha w.e.f. 14.04.23.

<sup>+</sup> Nominated by the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha w.e.f. 19.04.23.

#### **INTRODUCTION**

- I, the Chairperson of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 to which 'The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023' was referred, having been authorized to submit the Report on their behalf, present this Report with the Bill, as reported by the Joint Committee annexed thereto.
- 2. The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 was introduced in Lok Sabha on 29<sup>th</sup> March, 2023. The Motion for reference of the Bill to a Joint Committee of both the Houses of Parliament was moved in Lok Sabha on 29<sup>th</sup> March, 2023 by Shri Bhupender Yadav, the Minister of Labour and Employment and Environment, Forest and Climate Change, (*vide* **Appendix-II**) and concurred by the Rajya Sabha on the same day (*vide* **Appendix-II**).
- 3. As per the motion moved in the House, the Joint Committee was to make a report to the House till last day of the first week of the Monsoon Session, 2023.
- 4. Keeping in view the importance of the Bill and its wide ranging implications, the Committee decided to call memoranda to obtain the views from public in general and experts/stakeholders/NGOs and other organisations in particular on the provisions of the aforesaid Bill. Accordingly, a press communiqué inviting memoranda from them was issued on 03<sup>rd</sup> May, 2023 in national and regional newspapers through the Central Bureau of Communication. The Committee has received 1309 memoranda (*vide* **Appendix III**). All the memoranda were circulated to the Members of the Committee. They were also sent to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and their comments were obtained on each of them. The Committee also heard the views/suggestions of twelve experts/stakeholder organisations who made personal appearance before the Committee. The points raised by the experts/stakeholders and public along with the comments of the nodal Ministry were suitably incorporated in the Report.
- 5. In addition, the Committee invited suggestions from concerned Ministries and heard the views/suggestions of Ministries/Departments *viz*. Ministries of Home Affairs, Defence, Tribal Affairs, Railways(Railway Board), Road Transport and Highways, Rural Development, Jal Shakti (Department of Drinking Water & Sanitation), Mines, Department of North Eastern Region (DoNER) including the nodal Ministry *i.e.* Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their sittings. The Committee also invited three State Governments from left wing extremism affected States *i.e.* Chhattisgarh, Maharashtra and Telangana to the sittings to take note of their comments on the Bill. The Committee also undertook a study tour of Srinagar, Guwahati and Bhubaneswar from 02.06.2023 to 07.06.2023 where they held discussions with fourteen other States/UTs including all North Eastern States and remaining left wing extremism affected States *i.e.* Odisha and Andhra Pradesh. During the said study-visit, the Committee also held discussions with various other stakeholder organizations and PSUs such as Army Northern Command (XV Corps), Border Road Organization (BRO), Border Security Force (BSF), Defence Research and Development Organization (DRDO), Directorate General of Hydrocarbons (DGH) and Oil and Natural Gas Company (ONGC) on various provisions of the Bill. (*vide* Appendix-IV).
- 6. The Joint Committee held eight sittings wherein, they heard the views of the representatives of various Ministries/Departments, State Governments/UTs and experts//stakeholder organisations. (*vide*Appendix-V). Sitting wise list of witnesses who appeared before the Joint Committee for oral evidence is enclosed (*vide* Appendix-VI).
- 7. Thereafter the Joint Committee completed Clause by Clause consideration of all Clauses of the Bill at their sitting held on 26<sup>th</sup> June, 2023. The Bill as reported by the Joint Committee is appended after the Report.
- 8. 04 Notes/minutes of dissent have been received from the 05 Members of the Joint Committee (vide **Appendix-VIII**).
- 9. The Joint Committee, in their 09<sup>th</sup> sitting held on 11<sup>th</sup> July, 2023 considered and adopted draft report and authorized the Chairperson to present the report on their behalf. The Committee also decided that one copy of the proceedings of the sittings of the Committee and two copies each of the memoranda received by the Committee on the Bill from various quarters may be placed in the Parliament Library after the Report has been presented to Parliament, for reference of the Members of Parliament.
- 10. The Joint Committee wish to express their thanks to the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) who appeared before the Joint Committee and placed their considered views to the points raised by the Joint Committee during the sittings held in connection with the examination of the Bill. The Joint Committee would also like to express their sincere thanks to the representatives of other Union Ministries, representatives of State Governments/UTs and other experts/stakeholder organizations who appeared before the Joint Committee and candidly presented and submitted their views about the impact of various provisions of Bill. The Joint Committee would also like to acknowledge the sincere and devoted efforts made by the Officers of

Lok Sabha Secretariat in facilitating conduct of all the sittings of the Joint Committee smoothly and for preparing the draft Report of the Joint Committee.

SHRI RAJENDRA AGRAWAL CHAIRPERSON,
JOINT COMMITTEE ON
THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023.

NEW DELHI; 11 July, 2023 20 Ashadha, 1945 (Saka)

#### **REPORT**

#### **CHAPTER-I**

#### Genesis and features of the Joint Committee on Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

1.1 Forests are the green lungs of the nation and provide various ecological services like clean air, water, maintenance of soil-moisture regime by checking soil erosion etc. Forests maintain environment stability and ecological balance. Natural forests with the vast variety of flora and fauna are hub of biodiversity. Forests directly sequester Carbon dioxide from atmosphere and play a critical role in checking global warming and climate change. Forests check extension of sand-dunes preventing desertification. Healthy forest eco-systems are necessary for reversal of land degradation in the country.

#### **Definition of Forest**

- 1.2 As per decision 19 of Conference of Parties 9-Kyoto Protocol, the forest can be defined by any country depending upon the capacities and capabilities of the country as follows:—
  - cover percentage: Tree crown cover- 10 to 30%;
  - Minimum area of stand: area between 0.05 and 1 hectare; and
  - Minimum height of trees: Potential to reach a minimum height at maturity in situ of 2 to 5 m.
- 1.3 India's definition of forest has been taken on the basis of above three criteria only and very well accepted by United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Food and Agriculture Organization (FAO) for their reporting/communications. The forest cover is defined as 'all land, more than one hectare in area, with a tree canopy density of more than 10 percent irrespective of ownership and legal status. Such land may not necessarily be a recorded forest area. It also includes orchards, bamboo and palm'. The definition of forest cover has clearly been defined in all the India State of Forest Report (ISFR) and in all the International communications of India.
- 1.4 In ISFR 2021 recently published by the Ministry on 13<sup>th</sup> January, 2022, the forest cover figures are divided as 'Inside Recorded Forest Area' and 'Outside Recorded Forest Area'. Those 'Inside Recorded Forest Area' are basically natural forests and plantations of Forest Department. The Forest cover 'Outside Recorded Forest Area' are mango orchards, coconut plantations, block plantations of agroforestry. Thus data of mango plantations etc. is automatically getting separated out as Forest Survey of India is reporting the figures of 'Outside Recorded Forest Area' separately.

#### **Indian Forest Act, 1927**

1.5 The **Indian Forest Act, 1927** consolidates the law relating to forests, the transit of forest-produce and the duty leviable on timber and other forest-produce. During pre-independence era, besides the local Acts, majority of forests were being managed and protected under the provisions of the Indian Forest Act, 1927.

#### The Forest (Conservation) Act, 1980

- 1.6 According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, before the enactment of the Forest (Conservation) Act, 1980 and during the period of 1951 to 1975-76 of post independence era, approximately 4.135 million hectares of forest land was diverted for various non-forest purposes without any regard to environmental considerations. Taking cognizance of fast depleting forest resources of the country, the forests were added to the Concurrent List by the Constitution (Forty- second Amendment) Act, 1976. It was felt necessary that to put a check on uncontrolled and unregulated use of forest land for various non-forestry uses, a regulatory mechanism should be in place. Accordingly, regulation on de-reservations and non-forestry use of forest land was introduced by enacting the Forest (Conservation) Act, 1980 by the Parliament on 25.10.1980.
- 1.7 The Forest (Conservation) Act, 1980, is an important Central statute for the conservation of forests in the country. It provides that the de-reservation of reserved forests, use of forest land for non-forest purpose, assigning forest land by way of lease or otherwise to private entity and clearing of naturally grown trees for the purpose of reafforestation requires prior permission of the Central Government. During last four decades, after the enactment of Act average annual rate of diversion of forest land has been reduced to approximately 22,000 ha. During last 43 years, approximately 9.83 lakh ha of forest land was diverted for non-forest purposes with adequate mitigating measures.
- 1.8 As per the written submission made by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, till 12.12.1996, the general practice was that State Governments, Union territory Administrations and Central Government used to apply the Act only to the forests notified under the Indian Forest Act, 1927 or under any other local law, and to forests which were under the management control of the Forest Department. The Act was only sporadically applied to lands that were under the control of Revenue or other Departments.

#### **Hon'ble Supreme Court's judgment**

- 1.9 Hon'ble Supreme Court in its Judgment dated 12.12.1996, passed in the Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India and Others, clarified the scope of applicability of provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980. From the judgement it became clear that the provisions of the Act are applicable to the following types of forests/ forest lands:—
  - (a) all areas which are recorded as 'forest' in any government records irrespective of ownership, recognition and classification. This included areas notified as forest under any law;
  - (b) all areas, other than those covered under sub-para (a) above and conform to the 'dictionary meaning of forest; and
  - (c) all areas which are identified as 'forest' by the expert committee constituted in pursuance of the 12.12.1996 order of the Supreme Court and affidavit has been filed in the Supreme Court in 1997 accordingly.

#### **Necessity to bring in amendments**

- 1.10 In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have stated that pursuant to Judgment dated 12.12.1996, the State Governments also started applying the Act to any other area identified by the Expert Committee in each State as 'forest' and to lands that were covered under the dictionary meaning of forest. Therefore, the applicability of the Act in various types of lands has been dynamic *i.e.* initially provisions of the Act were being applied to the notified forest land only and subsequently, the Act was made applicable to revenue forest land or in lands which were recorded as forest in government records. Many of such lands were already put to non-forestry use such as habitations, institutions, roads, etc. with the required approval of the competent authority. This situation resulted in misinterpretation of the provisions of the Act with respect to their applicability specially in recorded forest lands, private forest lands, plantations, etc. Therefore the Government of India felt it is necessary to remove ambiguities and bring clarity about the applicability of the Act in various lands.
- 1.11 According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, a declining tendency of undertaking plantations in non-forest lands has been observed owing to the apprehension among individuals, organisations and authorities regarding such plantations being considered forests due to the various interpretations regarding applicability of the Act, and this misapprehension is becoming a hindrance in enhancing green cover to fulfil the Nationally Determined Contribution targets of creating additional carbon sink of 2.5 to 3.0 billion tons of CO<sub>2</sub> equivalent. Besides this, the strategic and security related projects of national importance need to be fast-tracked to ensure development of vital security infrastructures, especially along the international border areas such as Line of Actual Control (LAC), Line of Control (LoC), as also in the notified LWE areas. Similarly, small establishments, habitations on the side of roads/railways also need to be facilitated by providing them access and connectivity to main arterial roads and other public utilities.
- 1.12 Further the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have stated that in 1988, the clause (iii) of section 2 was inserted to regulate the assignment of forest land on lease to private entities for raising commercial plantations. However, in recent times, the provisions of this section are being invoked by the States and user agencies for assignment of forest land on lease for mining and other purposes. In their existing expression, the provisions of sub-section cannot be applied to entities, owned and managed by Government including for mining resulting in lack of uniformity, and therefore to bring uniformity in the provisions, amendment has been proposed in the subsection. Moreover, such leases may be assigned as per the terms and conditions laid down by the Central Government.
- 1.13 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change have also submitted that to carry out various forestry management activities and respond to quick natural hazards in the forests, basic infrastructural facilities are required to be maintained in the forest land. For want of enabling provisions in the Act, it is difficult to create such basic infrastructure in the forest area thereby impacting the forestry operations, regeneration activities, monitoring and supervision, prevention of forest fires, etc. Moreover, the proper protection and conservation of forests by local communities requires availability of livelihood opportunities which can be effectively enabled through promotion of eco-tourism, zoos and safaris. Therefore, activities ancillary to forestry management have been explained under this sub-section. The term 'Explanation' has been made elaborate to include activities which are taken up for the cause of conservation of forest and wild life. Therefore, the 'Explanation' to the proposed sub-section (1) has been amended to include activities which are taken up for the cause of conservation of forest and wild life.
- 1.14 Temporary survey activities in forest area such as investigation, reconnaissance etc. causes no permanent change in the forest land use i.e. there is no perceptible change in the forest vegetation or in breaking of land. These investigations, reconnaissance of exploratory surveys, etc. are an effective tool to determine the availability of minerals without impacting the forest land. It is therefore, proposed not to treat surveys, etc. as a non-forest activity subject to certain terms and conditions which the Central Government will specify.
- 1.15 There has been change in the ecological, social and environmental regimes and policies relating to conservation and development of forests during the last more than four decades since the enactment of the Act. To keep the provisions of the

Act in tandem with the dynamic changes in the ecological, strategic and economic aspirations of country, an enabling provision for issuance of directions as a new section 3C has been inserted in the Bill.

1.16 The Act was promulgated mainly to regulate the use of forest lands for various non-forest purposes. During the intervening period, after the promulgation of the Act, new challenges relating to ecological, social and environmental developments have emerged at national as well as international levels. For example mitigating the impact of climate change, achieving the national targets of Net Zero Emission by 2070, maintaining or enhancing the forest carbon stock, etc. Therefore, to carry forward the country's rich tradition of preserving forests and their bio-diversity and to tackle the climate change challenges, it is necessary to encompass such issues in the ambit of the Act.

#### **The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023**

- 1.17 In view of the foregoing, the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 has been proposed. The salient features of the Bill include:—
  - (i) Insert a preamble to the Act to encompass country's rich tradition of preserving forests, their biodiversity and tackling climate change challenges
  - (ii) Amend the short title of the Act to be called Van (SanrakshanEvamSamvardhan) Adhiniyam, 1980 so as to ensure that potential of its provisions is reflected in its short title
  - (iii) Clarifying the scope of applicability of the Act upon various lands so as to remove ambiguities and bring clarity
  - (iv) Exempt certain categories of lands from the purview of the Act—
    - (a) to fast track the strategic and security related projects of national importance,
    - (b) to provide access to small establishments, habitations on the side of public roads and railways; and
    - (c) to encourage plantation of the non-forest land;
  - (v) Provide for terms and conditions including the conditions of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands while considering the proposed relaxation under the Act;
  - (vi) Include more activities, which are taken up for the cause of conservation of forests and wildlife in the array of forestry activities;
  - (vii) Bring uniformity in the applicability of the provisions of the Act in respect of both Government and private entities;
  - (viii) Empower the Central Government to specify, by order, the terms and conditions subject to which any survey, such as reconnaissance, prospecting, investigation or exploration, including seismic surveys, shall not be treated as nonforest purpose;
  - (ix) Empower the Central Government to issue directions.

#### Joint Committee on Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 has been referred by the Parliament to this Joint Committeeon Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 for examination and report. A motion to refer the Bill to amend further the Forest (Conservation) Act, 1980 to the Joint Committee on Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 was adopted by Lok Sabha on March 29,2023 and the same day Rajya Sabha concurred with the recommendation of the Lok Sabha regarding constitution of the Joint Committee on the Bill. According to the motion, the Committee shall present their report by the last day of the first week of the next session. Joint Committee is comprised of 31 Members with 21 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha. Shri Rajendra Agrawal, MP (Lok Sabha) is the Chairperson of the Committee. At the first sitting, the Committee were briefed by the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change which is the nodal Ministry responsible for the Bill. In the second to fifth sittings, the Committee heard the views of the representatives of ten Central Ministries viz. Ministries of Home Affairs, Defence, Tribal Affairs, Railways (Railway Board), Road Transport and Highways, Rural Development, Jal Shakti (Department of Drinking Water & Sanitation), Mines, DoNER who are mainly concerned with the Bill including the nodal Ministry i.e. Ministry of Environment, Forest and Climate Change and also the views of the representatives of three State Governments viz Chhattisgarh, Maharashtra and Telangana. At the sixth and seventh sitting, the Committee heard the views of some of the experts on the subject matter and also some individuals who had submitted their suggestions to the Committee. The Committee also decided to issue a Press Communique inviting suggestions from the public on the provisions contained in the Bill. Subequently, a press communiqué was issued in print and electronic media inviting suggestions from the public. In response, a total of 1309 memoranda/suggestions were received by the Committee. The Committee also undertook a study tour to Srinagar, Guwahati and Bhubaneshwar from 2 June to 7 June, 2023 to hear the views of representatives of fifteen other States/UTs including all North Eastern States and remaining left wing extremism affected States i.e. Odisha and Andhra Pradesh. The Committee also held discussions with various other stakeholder organizations and PSUs such as Army Northern Command (XV Corps), BRO, BSF, DRDO, DGH and ONGC on various provisions of the Bill during the Study-visit. At the eighth sitting, the Committee took up the clause by clause consideration of the Bill. The Committee considered and adopted the draft report in their ninth sitting held on  $11^{th}$  July, 2023.

1.19 The following chapter deals with the clause by clause examination of the Bill by the Committee.

#### **CHAPTER-II**

#### Clause by Clause examination of the

#### Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

#### Clause 1

- 2.1.1 (1) This Act may be called the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023.
  - (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

### Clause 2

#### **Relevant provisions of Principal Act**

#### Preamble:

2.2.1 Provisions do not exist in the Principal Act.

#### **Provisions proposed in Amendment Bill**

2.2.2 It is proposed to insert preamble to the Act after the long title and before the enacting formula as under:

"WHEREAS, the importance of forests is to be realised to enable achievement of national targets of Net Zero Emission by 2070 and maintain or enhance the forest carbon stocks through ecologically balanced sustainable development;

AND WHEREAS, Nationally Determined Contribution targets of the country envisage creating carbon sink of additional 2.5 to 3.0 billion tons of CO<sub>2</sub> equivalent by 2030;

AND WHEREAS, the country envisages an increase in the forest and tree cover to one third of the land area of the country which has to be given impetus with an enhanced growth trajectory;

AND WHEREAS, India has a rich tradition of preserving forests and their bio-diversity, and therefore enhancing forest based economic, social and environmental benefits, including improvement of livelihoods for forest dependent communities is envisaged;

AND WHEREAS it is necessary to provide for provisions relating to conservation management and restoration of forests, maintaining ecological security, sustaining cultural and traditional values of forests and facilitating economic needs, carbon neutrality."

#### Reasons/Justification given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

2.2.3 To keep the provisions of the Act in tandem with the dynamic changes in the ecological, strategic and economic aspirations of country and to have the scope of this act relevant with the emerging ecological challenges for forest conservation, restoration, compensatory mechanism, mitigation measures, etc, it has been proposed to change the name of the Act and to insert the preamble in the Act.

### **Examination by the Committee**

2.2.4 During briefing on the Bill, it was observed that targets fixed in the Preamble if not fulfilled by the year mentioned, the Act has to be amended again. Even if the target is achieved before the target year, the Act would have to be amended again. So, the target year need not be fixed in the preamble. In regard to the above observation, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written clarification stated as under:—

"The preamble mentions the national targets of Net Zero Emission by 2070, creation to carbon sink, increasing the green cover, preserving the bio-diversity and improving the livelihood of forest dependent communities, besides the Nationally Determined Contributions. Operations of all proposed provisions will act as a driving force for the forest management augmentation. The included preamble, reflects the intents of the Central Government to broaden the scope of Act to combat global issues."

2.2.5 During clause by clause examination of the Bill on 26 June, 2023, when the matter was again raised, the Director General of Forest and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified that the targets mentioned in the proposed preamble are in accordance with the international commitments made by the Government of India. While elaborating the same, he made the following submission during clause by clause examination of the Bill:—

"Sir, the Preamble can be read in four parts. The first part is basically the international commitments that we have agreed upon in different international Conferences regarding the net-zero and also additional carbon sink. So, that is basically to provide the guidelines to the policy-makers and not only the policy-makers, but also to the State Governments and also

the officers who are in the field to devise their policies and action plans in accordance with the international commitments. Ultimately, because these commitments had to be met by the country as a whole--all the officers, all these policy-makers and all the Governments should combine their hands together for this commitment. Part number two is regarding the forest policy that is presently in vogue where we have to bring 1/3rd of the entire country's geographical area under forest. So, that is also a reminder to all the policy-makers and various stakeholders that this is the commitment of the Government made in the policy that we should bring 1/3rd of the forest area under green cover. If you go with the third part, it echoes the sentiments of most of the hon. Members also. It talks about the rich tradition of the forest and also the dependent communities. As hon. Members have raised concerns about what will happen to the dependent communities, we have already mentioned about it in the Preamble that we are going to take all the measures that enables the Government to protect the interests of the dependent communities wherever the dependent communities are there. I have already mentioned in various meetings that FRA will be applicable. As such we are not going to dilute any of the Acts after this Amendment. All the Acts as are applicable on date will be applicable after this Amendment also. Then in the last part we talk about diversity of the forest. So, this is not only for the Government or the Forest Department, but this is also for the user agencies that are coming up for different purposes like for taking clearance under the Forest Act. They have also been reminded about all these things that there are dependent communities & whenever they are planning any activities, they have to consider that there are forest dependent communities. The forests are diverse. So, they should plan their activities in such a way that all these things are not disturbed. This is basically the idea of having the Preamble and highlighting all these issues in the Preamble."

2.2.6 It was also observed during briefing that the Preamble talks about economic needs but it is not clarified as to whose economic needs are proposed. With regard to enabling achievements of national targets as stated in preamble and carbon stock neutrality, it was highlighted that the carbon sequestration potential of natural forests is 40 times green as compared to plantation. In this regard, the Ministry of Environnment, Forest and Climate Change has clarified in writing as under:—

"the economic aspirations included in the Bill symbolizes the economic aspirations of the local communities which eventually lead to the aspiration of the nation."

#### Important suggestions by other Ministries/State Governments/organizations

#### **Ministry of Tribal Affairs**

- 2.2.7 The Ministry of Tribal Affairs have made the following submission to the Committee:—
  - "(i) The term 'forest dependent communities' is wide and not specific. It is suggested that we may qualify this term by adding Forest Dwelling Scheduled Tribe (FDST)/Other Traditional Forest Dwellers (OTFD).
  - (ii) In order to specifically protect the FDST/OTFD, after 'values of forest' the following can be inserted: 'including the forest and customary rights as well as protection of community forest resources in respect of the FDSTs/OTFDs."

## 2.2.8 **State Governments**

#### Observations/suggestions of the State Reply/comment of the nodal Ministry Government **Government of Sikkim** There is no preamble in the existing Principal Act and accordingly, a Preamble has been inserted to the The Preamble needs rationalization. Changes in the 'Preamble' Principal Act. and the addition of noble aims/vision of the Government in an explicit form is welcome but how aims would be achieved with The proposed preamble does not supress the long the provisions needs clarity. title of the Principal Act. The preamble of the Bill is in addition to the existing long title of the Act which provides for conservation of forest and activities ancillary or incidental thereto. Preamble has been inserted to the Act to strengthen Government of Mizoram:— The contents of the preamble shall be in consonance with the the forest management by improving its health, contents of the Act. As the amendment of the Act implies productivity and flow of services besides promoting exclusion of a substantial extent of forest area out of the purview community participation. Moreover, enabling of the Forest (Conservation) Act, the preamble may be required provisions provided under section 6 of the Bill will to be suitably worded to avoid implied contradiction between the be invoked, whenever needed, to clarify the preamble and the provisions of the Act. applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place.

Provisions of the Bill supports the aims and objectives given in the Preamble.

The provisions of clause (b) of subsection (2) of section 4 of the proposed Bill encourages to raise afforestation in private lands, thereby facilitating the peoples participation in increasing the green cover of the country and to combat the global issues such as carbon neutrality, enhancing the carbon sink, better forest management, etc.

Promotion of afforestation in the non-forest land will create additional carbon sink besides reducing pressure on forests.

Management of forest for improved productivity and flow of ecosystem goods and services will also add to mitigate the impact of climate change and conservation of forests.

Explanation provided under section 5 of the Bill provides enabling provisions for quick response to natural hazards in the forests, and to facilitate the effective forest management by way of enabling provisions for basic infrastructure for forest front line staff.

Provisions also promotes people participation in the process of forest conservation besides providing them livelihood opportunities by way of ecotourism and setting of zoos and safaris.

#### Important suggestions by various experts/ public

- 2.2.9 In written memoranda submitted to the Committee, stakeholders suggesting for deletion of Preamble stated as under:—
  - "A preamble is a clause at the beginning explanatory of the reasons for enactment. The present Act does not have preamble as the title is succinct and self explanatory.
  - Proposed preamble should be entirely deleted. Proposed amendment subverts the FC Act's primary objectives
    "to provide for conservation of forests" and to "check further deforestation". Amendments undo the provisions
    of existing Act, gains of conservation through W.P. No. 202 of 1995, reduce the ambit of FC Act and privatize
    the large portion of forests in the name of creating plantations.
  - Current Act is a strong piece of legislation and requires no amendment but better and effective implementation."
- 2.2.10 In response to the above observation brought to the notice of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, they furnished clarification which is given below:—

"The proposed Bill primarily intends to clarify the applicability of the Act in various lands. Horizons of the Act have been proposed to be broaden to encompass and combating of global issues pertaining to forest conservation and management. With a view to encourage plantation on the non-forest lands, a clarity has been provided in the Bill to keep such lands outside the purview of the Act. Current provisions of the Bill do not allow the private sector to take control of forests but provide for augmentation to increase the productivity and strengthening of forestry practices."

- 2.2.11 Other experts and individuals in their written memorandum expressed concerns regarding difference between the objectives envisaged in the Preamble and the content of the Act. In this regard, the following observations have been made by stakeholders:
  - o "means to support and achieve the aims as net zero emission, increasing forest tree cover, carbon neutrality etc. mentioned in the Preamble have not been provided in the Bill.

- Preamble mention to reach the aim of having one-third area of the country under the forest cover. However, there is no such provisions in the amendment Bill. Therefore, adequate power may be provided to the State to notify the lands which are adjacent to the forests. Amendment do not provide any mechanism to achieve the targets mentioned in the preamble."
- 2.2.12 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written response to the above observation have stated as follows:—

"The provisions of clause (b) of subsection (2) of section 4 of the proposed Bill encourages to raise afforestation in private lands, thereby facilitating the peoples participation in increasing the green cover of the country and to combat the global issues such as carbon neutrality, enhancing the carbon sink, better forest management, etc.

Explanation provided under section 5 of the Bill provides enabling provisions for quick response to natural hazards in the forests, and to facilitate the effective forest management by way of enabling provisions for basic infrastructure for forest front line staff.

Provisions also promotes people participation in the process of forest conservation besides providing them livelihood opportunities by way of eco-tourism and setting of zoos and safaris.

Exempting non-forest land from the purview of the Act will encourage plantation in the non forest land which will eventually enhance the productivity of natural forests due to reduced pressure on natural forests."

- 2.2.13 On similar grounds the other written memoranda observed about preamble as follows:—
  - "The current preamble totally fails to regulate and control the diversion of forest land as it lays emphasis on 'increasing forest and tree cover by creation of carbon sinks'; 'improvement of lives and livelihoods of forest communities' and 'conservation and management and restoration of forests'. These are already covered under other acts like the Indian Forest Act, 1927, The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights), Act, The Wildlife Protection) Act and the Biological Diversity Act, 2002.
  - It has been suggested by one NGO that the Preamble fails to mention this primary objective of the Statute which is to regulate and control diversion of forests.
  - In the Preamble, it is stated that this Bill is introduced to make the carbon emission to zero and carbon reduction, which should be avoided. And it cannot be accepted to make forests into gardens/estates for the above mentioned two reasons. The abovementioned targets can be achieved only through forestry plantation activities and increasing the area of under green cover.
  - The preamble speaks about the noble aim of achieving environmental sustainability in terms of net zero emission, creation of carbon sink, increasing the forest and tree cover, maintaining ecological security, carbon neutrality etc. The bill facilitates more towards the diversion of forest lands for non-forestry purposes rather than ensuring the environmental sustainability.
  - o A separate Act is required for commitments because in future we are going to have more international commitments. The Act is inconsistent with preamble."
- 2.2.14 In a written reply to the above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change stated as follows:—

"The intent of the existing provisions of the Principal Act *i.e.* long title of the Act has not been amended and is retained in its existing form. Therefore, regulatory provisions of the Act have been kept intact. Preamble proposed in the Bill is in addition to the existing provision of the Act. Preamble has been inserted to the Act to strengthen the forest management by improving its health, productivity and flow of services besides promoting community participation. Moreover, enabling provisions provided under section 6 of the Bill will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place.

Provisions of the Bill supports the aims and objectives given in the Preamble. The provisions of clause (b) of subsection (2) of section 4 of the proposed Bill encourages to raise afforestation in private lands, thereby facilitating the peoples participation in increasing the green cover of the country and to combat the global issues such as carbon neutrality, enhancing the carbon sink, better forest management, etc. Promotion of afforestation in the non-forest land will create additional carbon sink besides reducing pressure on forests. Management of forest for improved productivity and flow of ecosystem goods and services will also add to mitigate the impact of climate change and conservation of forests. Explanation provided under section 5 of the Bill provides enabling provisions for quick response to natural hazards in the forests, and to facilitate the effective forest management by way of enabling provisions for basic infrastructure for forest front line staff. Provisions also promotes people participation in the process of forest conservation besides providing them livelihood opportunities by way of eco-tourism and setting of zoos and safaris."

- 2.2.15 Further the following observations have been made in the written memoranda:—
  - (i) It has been observed that in para 2 of preamble delete the words 'tree cover' as tree cover can imply promoting monoculture plantations. Instead, it should just say one-third land area under forest cover.
  - (ii) The emphasis in the preamble on achievement of Net Zero emission by 2070 through increase in tree cover goes against the purpose of Original Act.
  - (iii) To achieve the Net Zero Emission by 2070 is appreciable, however, use of words like tree, forests and carbon stack threatens the ecological integrity of the country. The carbon stock of various ecosystem such as Alpine meadows, grass lands, flood affected forest areas, despite having lesser tree density maintain the high carbon stock and such important ecosystems have been isolated by the proposed provisions of the Bill.
- 2.2.16 In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written reply stated as follows:—
  - (i) "Clarification in this regard, if any needed in future, will be issued by the Central Government by invoking the provisions provided under section 6 of the Bill.
  - (ii) Achievement of Net Zero Emission by 2070 is in consonance with the provisions of the Principal Act. Increase in tree cover, envisaged in the Bill, by promoting afforestation on non-forest land and improving the health and productivity of the forest will help to achieve the said target besides reducing biotic pressure on the forests and thereby achieving the purpose of forest conservation, as envisaged in the Principal Act.
  - (iii) Achievement of Net Zero Emission by 2070 envisages forest ecosystem as well as other ecosystems, such grass lands, desserts, alpine meadows, etc. Net Zero emission by 2070 envisages cumulative enhancement of carbon stock by the various ecosystem of our country to achieve the carbon neutrality. Increase in tree cover, envisaged in the Bill, by promoting afforestation on non-forest land and improving the health and productivity of the forest will help to achieve the said target besides reducing biotic pressure on the forests and thereby achieving the purpose of forest conservation, as envisaged in the Principal Act."

#### Observation/Recommendation of the Committee

2.2.17 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause to add a preamble to the Principal Act including the suggestions made by stakeholders and the rationale/replies/clarifications given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

#### Clause 3

#### **Relevant provisions of Principal Act**

2.3.1 Name of the Act: The Forest (Conservation) Act, 1980

#### Provisions proposed in Amendment Bill

2.3.2 Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

## Reasons/Justification given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

2.3.3 To keep the provisions of the Act in tandem with the dynamic changes in the ecological, strategic and economic aspirations of country and to have the scope of this act relevant with the emerging ecological challenges for forest conservation, restoration, compensatory mechanism, mitigation measures, etc, it has been proposed to change the name of the Act and to insert the preamble in the Act.

## **Examination by the Committee**

2.3.4 During the briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, it was pointed out that the amendment proposed for change in the name does neither add any value to the statute nor serve any purpose to the scope and objectives of the present Act. It would be more appropriate to call it as the Forest (Conservation) Amendment Act. Further it was also pointed out during the course of briefing that the title of the Bill or Act is non-inclusive because it leaves out vast tracks of population both in South India and also in the North-East.. So, it needs to be inclusive. The title should be changed so that it is properly understood and really reflects the ethos of forest protection or forest conservation. In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change stated in their written reply stated as under:—

"Dynamic changes in the policies and programme call for more efficient management of our forest resources to increase their productivity. Besides this, to cater the global challenges viz. carbon neutrality, Nationally Determined Contributions (NDC), it is necessary to increase the green cover, striking a balance between ecological stability and economic aspirations, etc. Therefore, considering the aforementioned facts, it has been proposed to assign a self-contained name to the Act".

2.3.5 During Clause by Clause examination of the Bill, when it was enquired about the salient features that are going to derive out of changing the name from Forest (Conservation) Act to Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, the Director General of Forest and the Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has replied as under:—

"As of now, the name is Forest Conservation Act. I am sorry to say that in general parlance, it is known as Forest Clearance Act. Whatever user agencies coming to the Government of India, even the senior officers, do not know that it is a diversion. They simply think that this is sort of an NOC or clearance. That is a misnomer that we want to remove. By using the word 'augmentation' along with conservation, we want to stress on all the user agencies and the State Governments that this Act is not basically meant only for giving the permissions for developmental works. Along with the developmental works, this also gives the impetus on the fact that while the developmental activities are necessary, the conservation and augmentation of the forest are also necessary. Otherwise, whatever the effects of the climate change that we are seeing today will become more severe and we are already seeing the cyclones etc., their intensity will increase. Whatever we are going to do for the development, that is necessary."

### Important suggestions by various experts/ stake holders

2.3.6 While appearing before the Committee, an expert made the following submission regarding change in name of the Act—

"The next point is about name in Hindi. I think, we need a bilingual approach with the name of the Act in Hindi and English. This, actually, provides a legal clarity and uniformity. So, inserting 'samvardhan' and there is nothing contained in the Bill which, actually, is for development, it is clearly focussed on conservation and we should not dilute it to create any ambiguity. Therefore, I think, it can be deleted. It was also pointed out that a common person will not find it easy to speak the words Sanrakshan and Samvardhan. There is also language diversity. To have one language in the title of the Bill itself it is doubtful whether that is suitable at this stage."

- 2.3.7 An expert appearing before the Committee stated that there are no corresponding provisions which would suggest that the Legislature wants to have any expansion of the forest land by this amendment. There is no doubt about the reasons of the projects which may be for genuine purpose, but the ultimate reality would be that the forest land cover would be decreased.
- 2.3.8 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change have stated that 'Samvardhan' implies augmentation of health, productivity and services besides increasing area under tree cover by adopting better management practices, strengthening capabilities of front line staff, encouraging people participation by providing them forest based livelihood opportunities.
- 2.3.9 At the sitting held on 16 May, 2023, on the question of change of the name of the Act to Hindi Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified as follows:—

"Sir, if you will kindly look at Section 4, it has clarified forest and it has actually encouraged afforestation. It is encouraging tree outside forest, agroforestry and through these means having greater tree cover in the country, which will add to more carbon sequestration. This is also one of the things that is required for the country to be able to meet its carbonneutrality goal."

2.3.10 At the sitting held on 16 May, 2023, on the question of addition of word 'samvardhan' in the name of the Bill, the Director General of Forest and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified as follows:—

"It is a misconception that if trees are planted on the banks of roads or canals, then later the Forest Department will consider it as a deemed forest and whenever a proposal for land transfer or diversion comes, the provisions of the FC Act will apply. The blank areas which were lying, like NTPC, Universities, PSUs etc used to do plantation. But after the order of 1996, everyone stopped the plantation because they felt that if they do future expansion of the plant, permission will have to be taken under this act. While this was not the case in the rule. To remove this misconception, we have brought the section, as stated by Chhattisgarh Section 1 (a) such trees, plantations and reforestation raised on lands that are not specified in Clause (a) and (b) of Section 1. Apart from this, the FC Act will not apply to whatever plantations are done, whether in the institutional area or on the roads. This will send the right message to the general public, so we have added the word promotion in it."

2.3.11 At the sitting held on 17 May, 2023, on the question of addition of word 'samvardhan' in the name of the Bill, the Director General of Forest and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change further clarified as follows:—

"Earlier there was monoculture, but now it is mixed culture. Talked to you yesterday. We are also planting kardai etc., closing the areas, planting potatoes, so we are also supporting natural regeneration. You have said why we have done augmentation. Clarification has come in the definition, now people will move towards agroforestry. As far as carbon

credit is concerned, different agencies have already started working for it. We are already working on how carbon credits are being produced in the three divisions of western Uttar Pradesh, how to incentivize them, how to monetize them. Apart from this, we have started a scheme called Green Credit. Along with carbon credit, if someone is controlling pollution, then how much will be in green credit, we are now deciding this. The scheme of green credit will also start very soon, how will we incentivize it, how will farmers get benefits, we will definitely do it in the coming years."

- 2.3.12 The following are some of the observations received from the public:—
  - Changing the name of the Act in Hindi only, without providing an English translation, could be argued to be against the constitutional intent of inclusiveness and the promotion of linguistic diversity.
  - A bilingual approach, with the name of the Act provided in Hindi and English in their respective versions, promotes legal clarity and uniformity. The Hindi version is always published in the Gazette.
  - Inserting 'Samvardhan' (Enrichment) in the name of the act appears to be inconsistent with the provisions of the principal act and the proposed amendment.
  - There is no provision in the proposed Bill to implement the objective of enrichment of forest.
  - Existing name of the Act should continue. As change in the name would weaken the social fabics of the country.
  - Change in the name of the Act ignores that there are vast stretches of the community that speak different language especially the South and North East India. Hence this must be done away with and the original title retained.
  - This is against the linguistic federalistic principle of the Constitution.

#### 2.3.13 Important suggestions by States/UTs

Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
The State Government of Sikkim stated that Samvardhan has not been explicitly defined. A clear definition should be included as it would help in achieving the goals enshrined in the Amendment	In response, the Ministry stated that there is no definition clause in the Bill and clarification if any needed in future would be issued by the Central Government under Section 6 of the Bill.
Meghalaya suggested that the short title/name of the Act should be both in English and Hindi.  Mizoram stated that FCA must be retained as it is well understood throughout the country and all the stakeholders are conversant with the term.	Dynamic changes in the policies and programmes call for more efficient management of our forest resources to increase their productivity. Besides this, to cater the global challenges viz. carbon neutrality, Nationally Determined Contributions (NDC), it is necessary to increase the green cover, striking a balance between ecological stability and economic aspirations, etc. Therefore, considering the aforementioned facts, it has been proposed to assign a self-contained name to the Act.

## Observation/Recommendation of the Committee

2.3.14 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause to change the name of the Act including the suggestions made by stakeholders and the rationale/replies/clarifications given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change thereto and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

#### Clause 4

#### Relevant provisions of Principal Act

2.4.1 Not applicable (provisions do not exist in the Act).

#### **Provisions proposed in Amendment Bill**

2.4.2 In the Forest (Conservation) Act, 1980 (hereinafter referred to as the principal Act), after section 1, the following section shall be inserted, namely:—

## 1A: Act to cover certain land

(1) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—

- (a) that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act 1927 or under state or local law:
- (b) that is not covered under clause (a), but has been recorded as forest in any Government record, as **on or after 25.10.1980**, except such land whose land-use was changed from forest to non-forest purpose on or before 12.12.1996 in compliance with an order in that behalf issued by such authority authorised by a State Government or Union territory Administration in this behalf;

Explanation.—(i) For the purposes of this sub-section, the expression 'Government record' means record held by Revenue Department or Forest Department of the State Government or Union territory Administration or any authority, local body, community or council recognised by the State Government or Union territory Administration.

- (2) The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely:—
  - (a) to such forest land situated alongside a rail line or a road, which is proposed to provide access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity upto a maximum size of 0.10 hectare in each case;
  - (b) Such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1); and
- (c) such forest land,
  - (i) as is situated within a distance of **hundred** kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of a strategic linear projects of national importance and concerning national security; or
  - (ii) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure; or
  - (iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed *five hectare* acres in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.
  - (3) The exemption provided under sub-section (2) shall be subject to such term and conditions, including the conditions of planting trees to compensate for felling of trees undertaken on the lands, as the Central Government may, by general or specific guidelines, specify.

#### 2.4.3 Reasons/Justification given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

- Absence of clarity on scope of the Act necessitated introducing the "Applicability" section. This is also in line with clarification given by Hon'ble Supreme Court in 1996.
- Government record for the purpose of Act needed clarity and accordingly defined as an explanation.
- Exemption has been proposed to provide the connectivity to the roadside amenities, habitation and access to rail.
- Clarity is being provided to promote plantation on non-forest land as envisaged in the National Forest Policy.
- Strategic and security related projects of national importance need to be fast-tracked to ensure development of vital
  security infrastructure, especially along the international border areas such as Line of Actual Control (LAC), Line
  of Control (LoC), as also in the notified LWE areas.

## **Examination by the Committee**

2.4.4 During briefing on the Bill, there was an observation that 100 kilometers from border may not be possible as in eastern Himalayas and in North Eastern States it may cover large chunks of land and the State Governments may not agree to the proposal. In regard to the above, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change stated in its written reply as follows:—

"The proposed provisions providing exemption along the international borders are not generic exemptions i.e. proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. Moreover, said dispensation will be subject to such terms and conditions, including payment of compensatory levies and compensation of trees, which will be a binding on the States to ensure their compliance while considering such projects within 100 km. Analysis of approvals accorded in the past for defence projects revealed that out of total area of 80,408 ha diverted in the last 8 years, only 2480 ha of forest land has been diverted to defence projects including roads which account for 3% of the total area diverted. It is also important to note that during last 8 years out of the total forest area of 19305 ha diverted for road in the bordering States of the country, only 3.5% is diverted for defence road projects."

2.4.5 Further during the course of briefing, another observation was made that the people living in forest areas face difficulties as there are no schools and water facilities. There is also communication gap as they lack telecommunication facilities. In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change stated in a written submission as under:—

"To promote development of LWE affected areas, forest land up to 5 ha has been exempted from the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980 for construction of public utility projects as may be specified by the Central Government."

2.4.6 At the sitting held on 17 May, 2023, when it was further enquired whether the proposed exemption of 0.10 hectare alongside a rail line or road will be permitted left side or right side, the Director General of Forest and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified as follows:—

"Sir, after that you said, there is a concept of 0.1 hectares, it is a little vague. So the concept of 0.1 hectare, we have called it maximum that we will not apply the provisions of the FCA Act in such cases up to 0.1 hectare. As far as left side and right side is concerned, whether it is in left or right, if the connectivity in the road is from right side then exemption will be given in right side, if connectivity is in left side then exemption will be from left side. There is no cumulative of both. Both are different. In particular, in one instance, if that episode is upto 10.1 hectares, then it will be free from the provisions of our FAC Act after this amendment."

2.4.7 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written reply have explained the said amendment as under:

"Exemption (of 0.10 ha of forest land), proposed in the Bill, has been decided by the Central Government, as appropriate, after carrying out the consultation process with the Ministries, States and public.

Exemption of 0.10 ha of forest land, considered under section 1A(2)(a), will provide connectivity to road side habitations and establishment to ensure their connectivity with the mainstream of development.

The terms and conditions, including defining amenities, strategic roads, public utilities, etc. will be undertaken subsequently, by the Central Government in accordance with the provisions of section 1A(3) of the Bill.

Clarification in this regard, if any needed in future, will be issued by the Central Government by invoking the provisions provided under section 6 of the Bill."

- 2.4.8 The reference to Godavarman case was drawn by hon'ble members during the sitting of the Committee held on 17.05.2023, where it was observed that the Hon'ble Supreme Court has said in the T.N. Godavarman case that any land recorded in the name of forest in government documents would require forest clearance. But in the proposed amendment bill, only that land has been considered as forest, which was recorded on or after October 25, 1980. There should also be a provision in this bill.
- 2.4.9 In regard to the above observation, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have submitted in their written reply to the Committee:

"The phrase of the Bill '....recorded as forest as on 25.10.1980....' implies that all lands which have been recorded as forest even before 25.10.1980 will also be covered under the provisions of the Act.

Section1A clarifies that the provisions of the Act will be applicable on the notified lands under the Indian Forest Act, local Acts or laws and lands recorded as forest in the revenue records. Moreover, the government records have also been defined to capture all types of forest lands available in a particular area.

Government records, defined under section 1A of the Bill, implies that the scope of the applicability of the Act is in line with the Supreme Court order dated 12.12.1996.

There is no dilution of Hon'ble Supreme Court order. Explanation provided under proposed section 1A(1) of the Bill clarifies that all forests, including unclassed forests, recorded in the record of Government, Forest Department local bodies, or authority will also attract the provisions of the Act. Moreover, enabling provisions provided under section 6 will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place."

2.4.10 Further, the representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change made the following submission to the Committee in this regard:

"The Deemed Forest case of TN Goda Varman in the year 1996 will be violated somewhere. So, there is no mention of violation in the TN Goda Varman case. The misconceptions that have arisen at present from that case that they had said that all the states should sit and make a definition and declare their respective deemed forest areas. But some people did it and some people did not, so the misconception remained that if there is a green patch somewhere and if a private person plants a forest, then the FC Act will be applicable. Due to this reason many people have given up agro forestry. Now since these misconceptions will be cleared, the concept of Agro Forestry will be more stable and people will be attracted towards it and our area which is Tree Outside Forest, will grow."

- 2.4.11 It was also observed during the sitting held on 16 May, 2023 that as several unclassified land get classified as deemed forest especially in the state of Arunachal Pradesh stalling development projects under Forest Rights Act.
- 2.4.12 In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written reply submitted as under:
  - "Applicability of the Act as proposed in the bill is in line with the Hon'ble Supreme Court order dated 12.12.1996. Government records, defined under section 1A of the Bill, implies that the scope of the applicability of the Act is in line with the Supreme Court order dated 12.12.1996. Further, deemed forest lands, identified by the Expert Committee of the State, have been taken on record and hence the provision of the Act will be applicable in such lands also."
- 2.4.13 During the course of examination by the Committee, observations were made that the administration of forest is a federal subject. It is not a central subject. Therefore wherever, it is said in the bill as such that, the Central Government may specify or my decide, may be modified.
- 2.4.14 It was further observed in this regard that all the sections in the Bill falls under the jurisdiction of Central Government. In view of security requirements of state police forces, making provisions for availability of land should fall within the purview of state government as they are engaged with local and tribal people in land negotiations and arrangement of alternate lands when original plans does not materialize.
- 2.4.15 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written reply have submitted as under:

"Enabling provisions have been provided under section 1A (3) of the Bill to prescribe terms and condition while considering exemption. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards should always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government. Views of the States/UTs are generally obtained by the Ministry before issuing any guidelines. In the extant case also terms and conditions will be finalized in consultation with the States/UTs."

2.4.16 Further, during clause by clause examination of the Bill, the Director General of Forest in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change while summarizing the questions raised by members regarding Hon'ble Supreme Court judgement and the provisions made in the Bill stated as follows:—

"Sir, basically, this clause deals with the scope of the forest wherever the Act is applicable, and that emanates from the judgement of the hon. Supreme Court of 12.12.1996. I would like to read the content of the judgement. The judgement says 'the Forest Conservation Act, 1980 was enacted with a view to check further deforestation which ultimately results in ecological imbalance and therefore provisions made therein for the conservation of forest and for matters connected therewith apply to all the forest irrespective of the nature of ownership or classification thereof. The word 'forest' must be understood according to its dictionary meaning.' This was the judgement. It further says 'that each State Government should constitute within one an expert committee to (i) identify areas which are "forests", irrespective of whether they are so notified, recognized or classified under any law, and irrespective of the ownership of the land of such forest; (ii) identify areas which were earlier forests but stand degraded, denuded or cleared; (iii) identify areas covered by plantation trees belonging to the Government and those belonging to private persons.' So, this was the judgement. Prior to that, the Act does not speak about the scope of the forest. There may be a confusion as to where this Act should be applicable after this 12.12.1996 judgement. So, there was a general statement not only by the general public but also by the forest officers that it is applicable on the areas which look forest, which is not there in the judgement of the hon. Supreme Court. So, to clarify this and to make it clearer as to where this Act will be applicable and going by the spirit of the judgment, we have mentioned that this will be applicable on the land that has been declared or notified as forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act or any other law for the time being in force. For example, Punjab Land Preservation Act (PLPA) which is relevant for the Punjab and Haryana, the land is not covered under Clause A but has been recorded in Government record as forest as on or after 25th October, 1980. For the Government, we have said that for the purpose of this sub-section, the expression 'Government record' means the records held by the Revenue Department or Forest Department. In many States, the forest record is not included in the revenue record. That is why, we have said here that the records either held by the Forest Department or Revenue Department of the State Government, Union Territory Administration or any authority, local body, community or council recognized by the State Government. As madam Sangma has expressed her concern about the forest of Meghalaya, I would like to say that 90 per cent of the forest in Meghalaya is owned by the community and all these records are there. It will be the Act as such after amendment will be applicable on those lands also. It will be applicable in the entire North-Eastern region. To clarify this part where the hon High Court has said 'deemed forest', there is still a misnomer that this is a dynamic thing. This is not a dynamic thing. The hon. Supreme Court has only given the timeline for one month only. I agree that this was not covered within one month and it took almost a year and almost all the States have filed their affidavits with regard to which are the areas that have been identified as forest, 'look like forest area' and degraded

forest, which were once a forest and now they are degraded etc. All these things have been taken care of by the Expert Committee that was constituted after this judgement. These are also on record. They have been filed before the hon. Supreme Court also. These things will also be taken care of. To further clarify, we have the provisions for the first time. We are coming up with the provisions of the guidelines. By going with the sentiments of the hon. Committee, to err is human. We must have made some error. I do not think that everything has been sacrosanct. In case we are missing something, then I assure you that we will take care in the guidelines."

2.4.17 The following statement shows the written observations/suggestions made by Members and the reply given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:—

Suggestions/Comments of the Member	Reply of the MoEF&CC
The major concern of this Bill is that the 2023 amendment will likely dilute the Supreme Court's 1996 landmark Godavarman judgment which had widened the scope of the FCA to apply to any land recorded as forest by the Government irrespective of its ownership; though the ministry have issued a clarification, saying that the proposed changes will not negate the SC Order.	There is no dilution of Hon'ble Supreme Court order. Explanation provided under proposed section 1A(1) of the Bill clarifies that all forests, including unclassed forests, recorded in the record of Government, Forest Department local bodies, or authority will also attract the provisions of the Act. Moreover, enabling provisions provided under section 6 will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place.
Bulk of the Aravallis, tiger habitats of the Terai and Central India, the Western Ghats and the biodiversity hot spots of the north-east, may no longer be considered 'forest' and can potentially be sold diverted cleared, felled, utilized, exploited without any regulatory oversight, if the Bill is passed.	Explanation provided under the section 1A(1) of the Bill defines and broadens the scope of Government records not only restricted to the records of revenue Department and Forest Department but also to any other authority or even local body recognized by the State Government. Moreover, the forest like areas identified by the Expert Committee and informed to Hon'ble Supreme Court in pursuance to order dated 12.12.1996, has also been taken on record.
The new Bill will create ambiguity for the land which was earlier handed over to the Forest Department by the Revenue Department but is yet to be cleared in the records since both Revenue Department and Forest Department may have the forest land in the records. The proposed Bill fails to clarify how the ambiguity will be dealt with in such cases and therefore, it is recommended that clarity is brought to fix the management and control rights over the lands which had been declared forest without any formal paperwork before the year 1996.	Explanation provided under Section 1A(1) provides that land recorded as forests in the records held by the Revenue Department or Forest Department will attract the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.
Revenue department should update the status of forest lands in their records clearly identifying them as forest lands. This will prevent the issuance of pattas or any other rights within these areas and the inclusion of forest land in the Prohibitory Order Book of the Revenue Department will further reinforce their protected status.	Enabling provisions provided under section 6 of the Bill empowering the Central Government to issue directions, will be invoked whenever needed to issue such clarifications in future.
Bill should also provide that the pending notification of forest blocks should be prioritized and resolved promptly within a given period of time since many forest lands remain under the ambiguous categories of lands, leading to chances for encroachment.	Provisions of section 1A(1)(a) provides that land notified under Indian Forest Act or local Act will fall within the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980. Therefore, land which have been intended to be notified such as section 4 lands under the IFA or similar land under any local Act will also attract the provisions of the Act.
It is also suggested that the Bill also provides for demarcating the land assigned under RoFR (Recognition of Forest Rights) Act,	Enabling provisions provided under section 6 of the Bill empowering the Central Government to issue directions

2008 to prevent encroachment by tribals, who frequently move will be invoked whenever needed to issue such from their original patta site to other areas by felling trees, clarifications in future. resulting in forest destruction and further encroachment. Bill should also introduce a robust mechanism for the mandatory Guidelines/instructions in this regard are already in demarcation of the forest land. Constructing boundary pillars or place. Enabling provisions provided under section 6 of digging trenches can provide clear physical demarcations, the Bill empowering the Central Government to issue reducing confusion and encroachment attempts by local villagers. directions, will be invoked whenever needed to issue To enhance the protection of forest lands, the jurisdictional area such clarifications in future. assigned to a single forest guard may also be provisioned to be reduced. 'Government land record' may be inserted in place of Government record has been defined in line with 'Government record' in 4IA(1)(b). various orders of Hon'ble Supreme Courts. Government record defined in the Act pertains to the Government as well as non-government lands for the purpose of clarifying the applicability of the Act. An additional provision in Section 1A, after sub-clauses (1)(a) and Such areas are generally notified under the Indian Forest Act, 1927 or local forest Act after following the (b), to exclude areas with habitations which officially existed in due statutory process including settlement of rights by Government records prior to notification of the Reserved Forest(s) and Protected Areas, irrespective of the date of notification of the Settlement Officer. such Reserved Forest(s) and Protected Areas". Proviso added to clause (b) of section 1A provides for exemption to such revenue forestlands, which have been put to non-forestry use by an order of the competent authority of the State following due process before 12.12.1996 including cases of pre 25.10.1980 period. It is not applicable in respect of lands notified under the IFA or local Acts/laws. Provisions of the Bill primarily clarifies the applicability of the Act in various lands and it does not provide for changing the legal status or de-reserving any forest land notified under the IFA of local Act. Moreover, Hon'ble Supreme Court in its order dated 13.11.2000 has restrained de-reservation of forests and national Parks/Wildlife Sanctuaries. "1 hectare" may be inserted in place of "0.1 hectare" [Para Exemption of 0.10 ha will provide connectivity to 4IA(2)(a)]. road/rail side habitations and establishment to ensure their connectivity with the mainstream of development. Proposed dispensation, as decided, after thorough consultation, has been considered as optimum. Provisions of section 4(2)(b) of the proposed Bill Exemption of the category of private forests from the purview of the FCA may benefit landowners and farmers and incentivize encourages to raise afforestation in private lands, them to plant more trees, however will it prevent their lands from thereby facilitating the peoples participation in being taken over for development processes or will actually be increasing the green cover of the country and to combat facilitative of that. The letter would have a huge negative impact the global issues such as carbon neutrality, enhancing for the climate change mitigation related national commitments the carbon sink, better forest management, etc. and obligations. Promotion of afforestation in the non-forest land will create additional carbon sink besides reducing pressure on forests. "One Hundred fifty kilometres" may be inserted in place of "One The exemption of linear projects located within 100 km hundred kilometres" [Para 4IA(2)(c)(i)]. of distance from the international borders, including LAC and LoC is not a blanket exemption. It has been proposed in consultation with the M/o Defence with a view to fast track the development of security related infrastructure in the border areas.

Heavy construction in geographically sensitive areas can endanger our wildlife. Forests within 100 KM of international borders or Line of Control will no longer require any forest clearance to construct highways, hydel power projects etc. This is deeply problematic.

The proposed exemption along the international borders is not generic exemptions i.e. proposed exemption are only for specific **linear** projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. Said exemptions will not be available for private entities. The 100 km distance is maximum allowable distance. The use of exemption will be need based i.e. may be used within 5 km or 10 km.

India's 15,100 KM international terrestrial border, comprises rich ecosystems - grasslands, deserts, wetlands, lowland forests, evergreen rainforests – that are mostly untouched due to their remoteness. This is a natural defence cover to our country. Needs to be protected any cost. Animals and birds do not have international borders. Its free movement across the borders should not be restricted. Impacts on wildlife could be catastrophic. It is a misconception that wildlife is confined to protected areas (PAs). Over a third of India's tigers, 70 % of elephants and a good part of wolf, bustard, leopard populations reside in landscapes outside of PAs. Unchecked construction on such seismically and geologically sensitive landscapes not just threatens rare wildlife and the country's water security but also renders these regions vulnerable to earthquakes and landslides.

Power conferred under section 1A(3) of the Bill is to prescribe terms and condition while considering exemptions. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards should always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government. Moreover, said dispensation will be subject to such terms and conditions, including payment of compensatory levies and compensation of trees, preparation of Wildlife management Plans, Soil and Moisture Conservation Plan, as per requirement, which will be a binding on the States to ensure their compliance while considering such projects under exemption. Provisions of the Bill will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

Areas declared as already protected under the Wildlife (Protection) Act, 1972 including Tiger Reserves, National Parks, Wildlife Sanctuaries, Community Reserves and Conservation Reserves as well as other areas such as Wildlife Corridors and those self declared a Community Conserved Areas by local people are strictly protected from any diversion for large scale development projects, without impacting the rights of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers. There is a genuine fear of these areas being indiscriminately used and deforested for any developmental activity without any safeguard for the local people or for the environment. Linear projects have already proven to be most detrimental for biodiversity and wildlife movements.

Provisions of the Bill do not infringe or abrogate the provisions of the Forest Rights Act, 2006, PESA or LARR Act, 2006. The processes envisaged in these laws, including the consent of the ST and OTFD under the Forest Rights Act, 2006is not impeded in any way by the proposed amendment.

Moreover, provisions given under rule 9(6) (b) (ii) mandates that compliance of FRA, 2006 is completed by the State before handing over the land to the user agency.

Such exemptions could lead to unchecked exploitation of forest resources and ecological damage. Considering this, I would like to propose that a clause be inserted into the proposed Bill to check the ecological damage caused by such projects.

The proposed exemption along the international borders is not generic exemptions i.e. proposed exemption are only for specific **linear** projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. Said exemptions will not be available for private entities. The 100 km distance is maximum allowable distance. The use of exemption will be need based i.e. may be used within 5 km or 10 km.

This clause could require that any linear infrastructure project that seeks exemption from prior approval must undergo an environmental impact assessment (EIA) to assess the potential ecological impact of the project. This EIA should consider factors such as the extent of forest land that would be affected, the impact

Power conferred under section 1A(3) of the Bill is to prescribe terms and condition while considering exemptions. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards.

on wildlife habitats, and the potential for soil erosion and water pollution.

Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards should always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government. Moreover, said dispensation will be subject to such terms and conditions, including payment of compensatory levies and compensation of trees, preparation of Wildlife management Plans, Soil and Moisture Conservation Plan, as per requirement, which will be a binding on the States to ensure their compliance while considering such projects under exemption. Provisions of the Bill will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

The proposed Bill could lead to the eviction of forest-dwelling communities and threaten their traditional livelihoods, particularly with the fast tracking of strategic and security-related projects of national importance located in forest areas. A provision be included in the proposed Bill to protect the rights of forest dwelling communities and their traditional livelihoods.

Rehabilitation and resettlement or eviction of people, if any involved, will be undertaken as per the provisions of the relevant R&R policy of the State and abiding by the provisions as given under the Forest Rights Act, 2006, PESA Act, 1996 and LARR Act, 2013 or any other relevant Act or rules.

No provisions of the Bill impedes with any provisions of the FRA, PESA or LARR Acts.

Moreover, provisions given under rule 9(6) (b) (ii) mandates that compliance of FRA, 2006 is completed by the State before handing over the land to the user agency.

This provision could require that any strategic or security-related project of national importance located in a forest area undergo a comprehensive social impact assessment (SIA) that considers the potential impact of the project on forest-dwelling communities Furthermore, the provision could require that any project that is found to have a significant impact on forest-dwelling communities and their traditional livelihoods should be subject to a resettlement and rehabilitation plan that ensures that the affected communities are adequately compensated for any loss of livelihoods, and provided with alternative means of livelihoods. The resettlement and rehabilitation plan should be developed in consultation with the affected communities and be implemented before any project activities commence.

Provisions of obtaining environmental clearance, wherever applicable, will be abided by the agency. The power conferred under section 1A(3) of the Bill is to prescribe terms and condition while considering exemptions. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards should always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government.

### Important suggestions by various stakeholders

### **Ministry of Tribal Affairs**

2.4.18 The Ministry of Tribal Affairs in their submission to the Committee in regard to this proposed amendment stated as under:—

"Section 2 (d) of FRA defines 'forest land' as " land of any description falling within any forest area and includes unclassified forests, undemarcated forests, existing or deemed forests, protected forests, reserved forests, Sanctuaries and National Parks. To ensure that rights guaranteed to Forest Dwelling Scheduled Tribes (FDSTs) and Other

Traditional Forest Dwellers (OTFDs) under FRA are protected, MoEFCC may please consider inserting a saving clause mentioning that "the said definition of 'forest land' will not be in derogation of FRA, 2006"."

- 2.4.19 The Ministry of Tribal Affairs have also further suggested that MoEFCC may insert a saving clause that "the land on which the forest rights have been recognised or are in the process of recognition under FRA, will continue to be treated as forest land.
- 2.4.20 During the sitting held on 17 May, 2023, the Director General of Forest and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified as follows:—

"Sir, you were talking about FRA Now we are taking FRA in all areas. In 100 KM (exemption along international border) we will keep FRA. We are not exempting that in this Act. FRA Act will be applicable in that. FRA is applicable in any projects other-wise as well. It is also applicable in out development projects also."

## Ministry of Rural Development

- 2.4.21 The Ministry of Rural Development have suggested that the proposed Sub-section (2) of Section 1 (A) may be modified appropriately to include the following:
  - "a. New connectivity to habitations/ upgradation of rural infrastructure (roads and bridges) under PMGS.
  - b. Construction/upgradation of rural roads and bridges for movement of security forces and providing connectivity in LWE affected or other areas considered important from security or strategic point of view."
- 2.4.22 In regard to the above suggestion, Director General of Forests and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change made the following clarification before the Committee in the sitting of the Committee held on 17 May, 2023:—
  - "As far as connectivity is concerned, those roads of PMGSY, our amendment of 0.1 hectare of land that we have made provisions for road side amenities and public utilities. Many roads of PMGSY are laid in interior areas and our prohibited areas are near those roads. So their connectivity is stopped. Now the relaxation of 0.1 hectare which is given by us now will solve 70-80 percentage of those cases. The matter will be resolved, because wherever there is a facility, we will give it through the guidelines. We have also given relaxation for LWE areas. If there is any necessity, we will look into it separately."

## Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation

2.4.23 The Ministry of Jal Shakti, has suggested that the proposed Para 4 Section (2) sub-section (c) (i) may be modified appropriately to include the following:

"In pursuance of the relaxation for strategic projects being proposed up to 100 km from LoC, LAC- works relating to water supply provisions to such projects (in view of the Vibrant Villages Programme) should also be allowed without forest clearance."

2.4.24 In regard to the above suggestion, Director General of Forests and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change made the following clarification before the Committee in the sitting of the Committee held on 17 May, 2023:—

"Regarding the issue of the drinking water pipelines, it has been asked as to what will happen to drinking water if there is a strategic road. On all the ROWs which will be coming up with the highways, the drinking water pipelines can be laid. There is no restriction even in the existing guidelines also. If there is a road already passing through the forest, if the Ministry wants to use the ROW for laying a pipeline, initially it was one metre by one metre and now we have raised it to two metres by two metres because the size of the pipe increases with the amount of water that has to be taken through it."

## 2.4.25 Ministry of Petroleum and Natural Gas

- i) <u>In 1A (2)</u>: Addition of Sub clause (d) may please be considered as under: (d) to undertake further drilling activities from an already diverted forest land for which Forest Clearance has been obtained earlier for drilling activity.
- ii) Need for inclusion of Clause in FC Bill, 2023 regarding Nonapplicability of FC Act on Extended Reach Drilling (ERD) Technology in oil and gas sector projects outside the forest area.

#### **State Governments**

### Government of Chhatisgarh

2.4.26 Government of Chattisgarh has observed in its submission made to the Committee that the type of security related infrastructure and the use agencies shall be mentioned explicitly. In this regard, it has suggested that the works shall be carried by the Central Government agencies only to prevent the escape routes for the use of forest land by the private individuals and other entitities. Therefore the following amendment is proposed:—

#### 1A(2)(c)(iii)

"(iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces/state police or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed *six hectares* in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government."

Explanation:— For the purpose of this Sub-Section, "public utility projects" shall include the following but not limited to the following:—

- (a) Mobile tower
- (b) OFC Cable
- (c) Road connecting to camps of paramilitary forces & state police and helipads for forces
- (d) Tribal hostels and Ashrams in scheduled area
- (e) Establishment of Ekalavya Vidyalaya(Scheme of Ministry of Tribal Affairs)
- (f) Upto 5 Km solar plants in an area where forest land has less than 50 trees per Acre or which are natural blanks in the form of Hills and Rocks.

#### Government of Maharashtra

2.4.27 Government of Maharashtra has suggested to insert the following proviso:—

"Provided that the land classified in this clause will not attract provision of Forest (Conservation) Act 1980 in the cases where (a) Lands have been put to nonforestry use prior to 25th October, 1980 irrespective of issuance of de-reservation notification under section 27 of Indian Forest Act 1927 or otherwise. (b) The privately owned lands which are deemed to be reserved forest under section 3 (3) of Maharashtra Private Forest (acquisition) act 1975 and have been restored back to land owners for livelihood purposes under section 22-A of the same act as amended in 1978."

2.4.28 In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written reply submitted as under:

"Applicability of the Act as proposed in the bill is in line with the Hon'ble Supreme Court order dated 12.12.1996. Government records, defined under section 1A clarifies that the provisions of the Act will be applicable on the notified lands under the Indian Forest Act, local Acts or laws and lands recorded as forest in the revenue records. Moreover, the government records has also been defined to capture all types of forest lands available in a particular area.

Further, deemed forest lands, identified by the Expert Committee of the State, have been taken on record and hence the provision of the Act will be applicable in such lands also."

## 2.4.29 Government of Assam

Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
1. Such exemption not to be extended though out the length of forest through which the linear infrastructure passes. Such diversions of 0.1 Ha maximum should be restricted to areas close to townships, tourist hubs but should not stretch all along the forest. Rest of the forest should not be disturbed. The amenities should include public utilities like public health centre etc.	Exemption of 0.10 ha of forest land, considered under section 1A(2)(a), will provide connectivity to road/rail side habitations and establishment to ensure their connectivity with the mainstream of development.  The exemption allowed is upto 0.1 ha i.e. based on the actual requirement the access may be considered for construction of 2, 3, 4, or 5 meters wide road involving area not exceeding 0.1 ha.
2. The exemption be considered only for strategic linear project of national importance concerning national security i.e. Defense purposes only. The word 'and' between 'importance' & 'concerning' should be deleted. The modified line to read "proposed to be used for construction of strategic linear project	The proposed exemption along the international borders is not a generic exemptions i.e. proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central

of national importance concerning national security; or	Government. The 100 km distance is maximum allowable distance. The use of exemption will be need based i.e. may be used within 5 km or 10 km.
	need based i.e. may be used within 5 km of 10 km.

# 2.4.30 Government of Jammu & Kashmir

	Observations/suggestions of the UT Government	Reply/comment of the nodal Ministry
(i)	In the provisions given under section 1A(1)(1), reference to "as on or after the 25th October, 1980" may be dropped as appears superfluous.	The phrase "as on or after the 25 <sup>th</sup> October, 1980" to eliminate the scope of ambiguity on the applicability of the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 in the lands which have been recorded forest before or after the 25.10.1980.
(ii)	The Phrase appearing as "proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security." in sub clause (i) of clause (c) of sub-section (2) of Section 1A may be substituted with the phrase "proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance or concerning national security, as may be notified by the Central Government"	The exemption has been considered for the projects of national importance and concerning national security i.e. both preconditions national importance and national security needs to be satisfied to avail the exemption. Exemptions will be applicable to the such qualifying linear projects, as may be identified by the M/o Defence and MHA.
		Further, provisions given under section 1A(3) will be used to prescribe the terms and conditions for such exemptions.
(iii)	The phrase "as may be notified by the Central Government" may be suffixed to sub clause (ii) of clause (c) of sub-section (2) of section 1A.	Exemptions will be applicable to such qualifying infrastructure, as may be identified by the M/o Defence and MHA.
		Further, provisions given under section 1A(3) will be used to prescribe the terms and conditions for such exemptions.

## 2.4.31 Government of Nagaland

Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
1. Most forest areas in the State are not recorded as forests and as no land records are maintained. There is no mention of how specifically the privately and community owned areas in the State will be treated. It is submitted that a specific insertion may be made keeping the private (naturally grown) forest areas out of the purview of the act to remove any ambiguity.	Explanation provided under proposed section 1A(1) of the Bill clarifies that all forests, including unclassed forests, recorded in the record of Government, Forest Department local bodies, or authority will also attract the provisions of the Act. Moreover, enabling provisions provided under section 6 will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place.
2. With regards to exemption of 100 km, it is to submit that entire Nagaland State will be excluded. Given the peculiar shape of NE except Assam the nearly all States becomes excluded. The uniformity of 100 Km needs to be removed, more so as the Indo Mayanmar border is not as sensitive as Indo China or Indo Pakistan Border. Further, the entire 100 km belt falls into the Indo-Burma Biodiversity Hotspots-one of the riches area in terms of gene pool diversity in the entire world.	The proposed exemption along the international borders is not a generic exemptions <i>i.e.</i> proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. The 100 km distance is maximum allowable distance. The use of exemption will be need based <i>i.e.</i> may be used within 5 km or 10 km.
3. A new section may be inserted which while keeping the naturally grown private areas out of the purview of the Act but also keeps them at par with forest areas as far as loss of ecosystem services and biodiversity is concerned. It is once again emphasized that	Section 1A(3) of the Bill provides for terms and condition while considering exemption. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account

private forest areas in the NE are extremely rich and the loss needs to be compensated either through restoration or long-term protection provided to equivalent areas through realization of NPV, in agreement with the community.

all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards will always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government.

Moreover, these provisions will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

## 2.4.32 Government of Himachal Pradesh

	Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
		1 7
(i)	The authority competent to certify/specify such projects as of National importance and National Security needs to be defined in the Act;	Exemptions will be applicable to the such qualifying linear projects, as may be identified by the M/o Defence and MHA of the Central Government.
(ii)	It is understood that the distance of 100 km is aerial distance.	Distance of 100 km is aerial distance.
1.	Under Section 1A(2)(c)(ii), it has been proposed that the land upto 10 hectare, proposed to be used for construction of 'Security related infrastructure' shall not be covered under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980. In this context, it is suggested that the 'Security related infrastructure' needs to be elaborated by defining various categories of such infrastructure and also the authority competent to certify as to which type of infrastructure shall be declared as related to Security.	Terms and conditions, including defining amenities, strategic roads, public utilities, etc. will be undertaken subsequently, by the Central Government in accordance with the provisions of section 1A(3) of the Bill. Moreover, public utilities have already been specified by the Ministry in the guidelines.
2.	Authorization of State Government to grant approval (Forest Clearance) for project of National importance, National security and Defence related infrastructure and charge amounts of NPV & CA.	Exemption considered under the Bill are not blanket exemptions. Such projects will be exempted from the prior approval of the Central Government under the Act while the processes are to be carried out at the State level including the payment of CA and NPV and other mitigating measures as may be specified by the Central Government while deciding the terms and conditions in accordance with the provisions of section 1A(3) of the Bill.
3.	The distance of 100 Km along the international border, mostly covers the tribal areas of the State, which will affect the rights of the tribal people. Therefore, to protect the rights of tribal communities, provision may be made as per Section 4(3) of the amendment, to use the forest land after obtaining the recommendations of the concerned Gram Sabha under the provisions of Forest Rights Act, 2006.	The provisions proposed in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 do not bar or infringe with the operation of other parallel laws, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, PESA Act, 1996 and Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013, which mandates to obtain the consent of Gram Sabha.

# 2.4.33 Government of Sikkim

Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
1. 1A (Act to cover certain land)  (i) The proviso shifts the cutoff date from 25.10.1980 to 12.12.1996 will regularize recorded forest land converted for nonforest purposes where corrections in records have been made without due diligence, as well as the consent of the Forest Department;	Provisions of the Bill exempting the lands whose land use has been changed to non-forest use on or before 12.12.1996 will be applicable to those recorded (revenue) forest lands which have been put to non-forestry use by an order of the competent authority of the State following due process.
(ii) This will also encourage large-scale encroachment in the forest land, as precedence of shifting of the cutoff date has been created;	Cutoff date has been selected keeping in view the direction of Hon'ble Supreme Court. Moreover, enabling provisions provided under section 6 will be invoked, whenever needed, to ensure that no misuse of forest land takes place.
(iii) It will exclude forests that are being proposed to be declared forestland under section 4 of the Indian Forest Act, 1927, or the Sikkim Forests, Water Courses and Road Reserve (Preservation and Protection) Act, 1988;	Area notified under the Indian Forest Act, 1927, including the areas notified under section 4 (proposed to be notified), will be covered under the provision of the Bill.
(iv) Interpretation of the sub-section does not align with the order issued by the Hon'ble Supreme Court in TN Godhavarman case, in the WP (C) 202 of 1995 dated 12th December 1996.	Provisions of the Act are in line with the orders of Hon'ble Supreme Court. The 'Explanation' provided under proposed section 1A(1) of the Bill clarifies that all forests, including unclassed forests, recorded in the record of Government, Forest Department local bodies, or authority will also attract the provisions of the Act.  Moreover, enabling provisions provided under section
	6 will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place.
2. Sikkim being a mountainous State has roads constructed along the steep hill slopes which are prone to erosion and slides. The exception provided for large openings of 0.1 ha would be detrimental to the slope stability. The 0.1 hectares or 1000 sqm of openings for National Highways with 12 m RoW would create an opening having a length of 83 m which for a hilly State is large access and unreasonable. The extent of exemption may be limited to a width of two-lane access or around 10 mts.	The exemption allowed is upto 0.1 ha <i>i.e.</i> based on the actual requirement the access may be considered for construction of 2, 3, 4, or 5 meters wide road involving area not exceeding 0.1 ha.
3. Sikkim with a total area of 7096 sqkms is bound by International Borders on three sides having an extent of 114 km from North to South and 64 km from East to West. Thus, the exemption of 100 kms distance from LAC from regulations of FCA, 1980 will subsume the entire state and open up pristine forest areas along with its biodiversity for non-forestry uses without FCA regulation. In Sikkim's geographical context, the proposed exemption may be reduced to 2 kms from 100 kms from the International Borders;	Exemption have been considered purely in the public and national security interests of the country. The proposed exemption along the international borders and in LWE District are not generic exemptions <i>i.e.</i> proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. Said exemptions will not be available for private entities. Moreover, even after the diversion of forest land, the legal status of forestland remains unchanged, therefore, there will be no reduction in the forest area.
4. Up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure is large in extent. Maximum up	Moreover, said dispensation will be subject to such terms and conditions, including payment of

	to 5 hectares of land for security related well-defined and listed Infrastructure may be allowed.	compensatory levies and compensation of trees, which will be a binding on the States to ensure their
5.	As per the FCA related data specific to Sikkim; out of the total forest land diversion of 3015 ha for non-forest purposes to date the diversion for defence purposes is 1529 ha which is nearly half of the total diversion;	compliance while considering such projects under exemption.

# Government of Tripura

2.4.34 The exemption of upto 100 km along the international border may not be applicable to small state like Tripura and it may be reduced to 10 KM. In regard to the above suggestion, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has furnished the following clarification:—

"The proposed exemption along the international borders is not a genericexemptions i.e. proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. The 100 km distance is maximum allowable distance. The use of exemption will be need based *i.e.* may be used within 5 km or 10 km."

### 2.4.35 Government of Arunachal Pradesh

Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
1. Exemption of 0.1 ha may be enhanced to 1 ha	Exemption, proposed in the Bill, has been decided by the Central Government after carrying out the consultation process with the Ministries, States and public. Exemption of 0.10 ha of forest land, considered under section 1A(2)(a), is considered appropriate to provide connectivity to road side habitations and establishment to ensure their connectivity with the mainstream of development.
2. 100 KM distance may be enhanced to 150 km.	The exemption of linear projects located within 100 km of distance from the international borders, including LAC and LoC is not a blanket exemption. It has been proposed in consultation with the M/o Defence with a view to fast track the development of security related infrastructure in the border areas.
Regeneration and cultivation of medicinal plants may also be included as forestry activity.	Provisions of regeneration activities have already been included at clause (i) of the Explanation given under section 2 of the Act.
	As per the provisions contained in the Principal Act the activities like cultivation of tea, coffee, spices, rubber, palms, oil-bearing plants, horticultural crops or medicinal plants have been categorised as non-forestry activities. These activities are commercial and non site-specific. To ensure better protection and management of forests for enhanced flow of ecosystem goods and services such activities are not permitted in the forest lands. Moreover, such activities are not in consonance with the provisions of the National Forest Policy, 1988 which discourages use of forest land for cultivation.

## 2.4.36 Government of Mizoram

1 More clarity on the type of Government record acceptable for this Explanation provided under proposed section	
purpose is required. Since taking out of forest land other than of the Bill clarifies that all forests,	Explanation provided under proposed section 1A(1) of the Bill clarifies that all forests, including unclassed forests, recorded in the record of

effect in contradiction to the preamble and those forests area may disappear/ cleared taking advantage of this.

- 2. In respect of 2(a), the contents are not clear at all, what it means. Further, it is not clear that if such areas are notified forests or recorded forests, then what is required to be done, as this provision will be in contradiction to section 1A.
- 3. (2)(b): This provision will again have disastrous effect as many plantations are being raised by the forest department on the lands, which are neither notified forests nor recorded forests. Thus, anyone will be free to clear those plantations and use such areas for any other purpose.
- (2)(c)(i)(ii)(iii) & (3): This provision gives free hand to any agency to take up any work in any reserve forest, Wildlife sanctuary or National Park situated within 100 kms of international borders. Any activity coming under the definition of linear project by any agency can be taken up mentioning it a project of national importance or of national security as all works in one way or another are of national importance and any work in states having international borders can be termed by the working agencies as of national security. This will also give free hand to all agencies involved in defence projects to take up any work in any area in any reserve forest, Wildlife sanctuary or National Park situated within 100 kms of international borders, which will completely destroy all these areas, which will be a disastrous act for the survival of human beings, as entire ecological balance will be destroyed. As almost entire Mizoram State falls within 100 kms of aerial distance of international border (Myanmar & Bangladesh Border) and therefore, all its forest and wildlife areas will get destroyed with such provision. This provision is strongly objected to and is not acceptable and shall be dropped.

Government, Forest Department local bodies, or authority will also attract the provisions of the Act. Moreover, enabling provisions provided under section 6 will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place

With a view to encourage plantation on the nonforest lands, a clarity has been provided in the Bill to keep such lands outside the purview of the Act.

Moreover, provisions of the Bill supports the objectives of the National Forest Policy, 1988. It promotes afforestation on non-forest land by bringing clarity on the non-applicability of the Act on such lands.

The proposed exemption along the international borders and in LWE District are not generic exemptions i.e. proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. Said exemptions will not be available for private entities. Moreover, said dispensation will be subject to such terms and conditions, including payment of compensatory levies and compensation of trees, which will be a binding on the States to ensure their compliance while considering such projects under exemption.

These provisions will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

#### 2.4.37 Government of Punjab

Observations/suggestions of the State Government

1. Power for sanctioning of approval under the FCA may be delegated to the state government in the cases where the User Agency is the land owning agency like the PWD, Railways, Irrigation department etc. and the area involved is upto 5 ha.

Reply/comment of the nodal Ministry

As the provisions of the General Approval are not supported by the provisions of the Principal Act, the same were not considered by the Ministry.

Process of approval has been streamlined by notifying the Forest (Conservation) Rule, 2022 wherein clear delegation has been given to IRO to process and approve the proposals involving areas up to 40 ha. Process for processing of the proposal at State Government has also been streamlined by introducing the Project Screening Committee to facilitate participatory and parallel examination of the proposal replacing the existing linear way of examination of the proposal. In addition to this Ministry have taken several other initiatives viz. conduction of Fortnightly Regional Coordination Meetings at each IRO, conduction of REC meetings twice a months, etc. to facilitate the processing such proposals in a time bound manner.

#### Other organizations

#### **Border Road Organization**

- 2.4.38 BRO has suggested that the exemption range of 100 km from Line of Actual Control/Line of Control/International Border to be increased to 150 km as numerous works of tunneling, bridging and road infrastructure are proposed to be constructed which will provide strategic depth to border areas.
- 2.4.39 In order to reduce the "infrastructure differential" with China in terms of roads, bridges, tunnels, habitats, permanent defences, air fields, etc., it is strongly recommended to notify the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 so that expeditious construction of defence infrastructure projects upto 100 km from LAC/LC/IB can take place. In regard to the above suggestion of Border Roads Organization, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified in writing as follows:—

"The exemption of linear projects located within 100 km of distance from the international borders, including LAC and LoC is not a blanket exemption. It has been proposed in consultation with the M/o Defence for security related infrastructure in the border areas."

#### Important suggestions by experts/stake holders

- 2.4.40 Stakeholders in their written submissions to the Committee made the following observations:—
  - (i) the amendment Bill seeks to limit the definition of forest land as directed by Hon'ble Supreme Court in its order dated 12.12.1996 by exempting the lands which are forests in their dictionary meaning.
  - (ii) Introduction of the clause (b) of sub-section (1) of section 1 A will overturn the Supreme Court Judgement dated 12.12.1996.
  - (iii) Provision given in the section 1(A)(1)(b) should also include dictionary meaning of forests as per Supreme Court orders.
- 2.4.41 In regard to the above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have clarified in their written reply as below:—
  - "The provisions proposed in the Bill are in line with the order dated 12.12.1996 of Hon'ble Supreme Court. All lands which were forests in their dictionary meaning, have been identified by the Expert Committee in each State and taken on record. The proposed provisions of the Bill further clarifies the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 in various lands."
- 2.4.42 Stakeholders have also observed as follows in their written memoranda submitted to the Committee:
  - "Proviso given in the section 1(A)(1)(b) dilutes the provisions of Hon'ble Supreme Court order dated 12.12.1996 as it will legalize the diversion of forest lands from 1980 to 1996."
- 2.4.43 In regard to the above, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified in their written reply as follows:—
  - "It applies only on those forest lands recorded in Government records where land use has been changed before 12.12.1996 with the approval of competent authority of the State following due processes i.e. provisions of the proviso is applicable to revenue forests lands only and not to the forest land notified under the IFA or local Acts. Proviso provides for exemption to such revenue forest lands, which have been put to non-forestry use by the State before 12.12.1996 including cases of pre 25.10.1980 period. Therefore, provisions of the proviso do not dilute the Supreme Court order."
- 2.4.44 Further a stakeholder observed that the Supreme Court order, in 1996 had offered legal protection to many forests which are not notified. The new amendments will not only dilute that protection but also help it destroy fast. There are multiple grey areas like "public utility specified by central government" in the Bill, which are unclear and leave us abundant space to misuse this for the destruction of forests. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change in this regard clarified as under:—
  - "The provisions of the Bill do not dilute the legal protection considered by the Hon'ble Supreme Court. With a view to ensure applicability of the Act to non notified forest land, an exhaustive explanation extending the scope of government record up to local bodies level. Public utilities will be clarified by the Central Government under the enabling provisions of section 1A(3) of the Bill."
- 2.4.45 Further, stakeholders in the written memoranda submitted to the Committee stated that Section 1A (1) restricted the scope of the FCA and it overturns the order of Hon'ble Supreme Court dated 12.12.1996. There are lands where only intent of notification is issued, large tract of orange lands, unclassed forests in North Eastern States. It is unclear whether the provisions of the Act will ceases to be applicable to such lands. In this regard, the Ministry of Environment, Forest, Climate Change has clarified that Provisions of the Bill do not overturn the Hon'ble Supreme Court's order dated 12.12.1996 and the explanation provided under proposed section 1A(1) of the Bill clarifies that all recorded forests, including unclassed forests recorded in the

record of Government, Forest Department local bodies, or authority will also attract the provisions of the Act. Moreover, enabling provisions provided under section 6 will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place.

2.4.46 In another written memorandum it was observed that the proposed Bill also states that this Act shall be inapplicable to forest land changed for non-forest purposes on or before 12<sup>th</sup> December 1996. We believe hat this clause has direct implications for forest conservation. In the past, forest land has been converted for several non-forest uses like plantation of cash crops, infrastructure development, mining leases, etc. The FCA (1980) mandates that any such diversion of forest lands or the extension of leases over such areas requires proper prior approval. Exempting the spectrum of these activities from obtaining forest clearances will not be in compliance with the conservation objectives of the FCA (1980). In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified as under:—

"Provisions of the Bill exempting the lands whose land use has been changed to non-forest useon or before 12.12.1996 will be applicable to recorded/revenue forest land only i.e. proviso added to clause (b) of section 1A provides for exemption to such revenue forestlands, which have been put to non-forestry use by an order of the competent authority of the State following due process before 12.12.1996 including cases of pre 25.10.1980 period."

## 2.4.47 Further, following written observations have also been received from the public:—

- 1. Forests which were recorded as forests in any government record prior to 25 October 1980 will not be regulated or protected under the principal Act.
- 2. Critical ecosystems such as Western Ghats, Wildlife Corridors have been compromised as they are not covered under the Act. The cut off date of 25.10.1980 opens up a large extent of forest land that are with other departments on lease with just usage rights.
- 3. many areas of land are proposed for notification under Indian Forest Act, 1927 before this date, and have not been finalized yet. The legality in such cases need to be looked into and clarified.
- 4. The new section 1A sub-section 1 threatens the bulk of the biodiversity-rich forests in Aravallis, Terai, Central India, Western Ghats and the North-East, which may no longer be considered 'forest' for the purpose of the Principal Act.
- 5. Approximately, 27.62% percent of our forests (recorded forest), out of the total forest area will fall beyond the scope of the Act.
- 6. The proposed amendments are in gross violation of Articles 14, 19 and 21 of our Constitution.
- 7. Compensation for felling of trees, would not be a replacement. In no way a natural habitat can be rehabilitated.
- 8. The proposed Section 1A attempts to delineate 'land' which shall be covered by the FCA on the one hand, and 'land' which shall not be covered by the FCA. There is no rationale for such classification, nor any correlationship between such classification and the objective and purpose of the FCA, which is forest conservation. On the face of it, the classification of forest lands in this proposed provision is irrational and unconstitutional.
- 2.4.48 In regard to the above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified in their written comments furnished to the Committee repectively as under:—
  - 1. The phrase of the Bill '....recorded as forest as on 25.10.1980....' implies that all lands which have been recorded as forest even before 25.10.1980 will also be covered under the provisions of the Act.
  - Section 1A clarifies that the provisions of the Act will be applicable on the notified lands under the Indian Forest Act, local Acts or laws and lands recorded as forest in the revenue records. Moreover, the government records has also been defined to capture all types of forest lands
  - 3. Area notified under the Indian Forest Act, 1927, including the areas notified under section 4 (proposed to be notified), will be covered under the provision of the Bill."
  - 4. There is no dilution of Hon'ble Supreme Court order. Explanation provided under proposed section 1A(1) of the Bill clarifies that all forests, including unclassed forests, recorded in the record of Government, Forest Department local bodies, or authority will also attract the provisions of the Act. Moreover, enabling provisions provided under section 6 will be invoked, whenever needed, to clarify the applicability of the Act and to ensure that no misuse of forest land take place.
  - 5. The India's State of the Forest Report of the Forest Survey of India mention that about 5,16,630 sq km of the forests of India are within Recorded Forest Areas (notified forest areas) while 1,97,159 sq km of forests lie outside Recorded Forest Areas which includes revenue forests, private forests, agroforestry plantations, etc. Provisions of the Act are applicable on the revenue forest land, private forest land and other land recorded as forest in the records. Therefore, observations that 27.62% of the forest will fall beyond the scope of the Act is not tenable.
  - 6. By the 42nd Amendment Act 1976 of the Constitution "Forests" was added as Entry 17A in the Concurrent List. Therefore, proposed a mendment is within the ambit of the powers conferred to the Central Government. Moreover, the propose d amendment of the Bill do es not infringe or violate the other Constitutional provisions of Article 14, 19 and 21 of our Constitution

- 7. Agreed, natural forests, lost from the diversion, cannot be replaced with the plantation. However, to compensate the loss and to recouped the services lost over a period of time, provisions of afforestation/plantation, and other similar conditions, as the Central Government may specify, have been proposed in the Bill.
- Enabling provisions have been provided under section 1A(3) of the Bill to prescribe terms and condition while considering exemption. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards will always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government.
- 2.4.49 Following observations were also made in the written memoranda submitted to the Committee:—
  - Proviso exempting forest land already put to non-forestry use before 12.12.1996 is ominous as gamut of activities such as mining allowed in the forest area will be exempted.
  - It will legalise all the forest land put to non-forestry use before the 12.12.1996 without the prior approval of the Central Government.
  - The land use can be changed without payment of NPV and following the process of forest clearance.
  - Exemption of land which changed from forest use to non-forest use before December 12, 1996 may contradict a Supreme Court judgment.
- 2.4.50 In reply to the above observations, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has submitted its following written comments:—

"Provisions are applicable for recorded (revenue) forest land only i.e. proviso added to clause (b) of section 1A provides for exemption to such revenue forestlands, which have been put to non-forestry use by an order of the competent authority of the State following due process before 12.12.1996 including cases of pre 25.10.1980 period.

All other cases belonging to post 12.12.1996 period will be regulated as per the existing process, including payment of NPV and CA.

As the provisions will be applicable to the cases belonging to pre 12.12.1996 period, therefore, order of Hon'ble Supreme Court will not be violated."

2.4.51 An expert in his written memorandum submitted to the Committee has stated that the exemption of 0.10 hectare may be misused for the destruction of forests Clause "Permission from the State Government/officer authorized without the stipulation of CA and NPV" should be inserted. In regard to the above observation, the Ministry of Environment, Forest, Climate Change has clarified in its written submission to the Committee as under:—

"Sub-section (3) of the Section 1A provides that such dispensation will be subject to such terms and conditions, including the compensating the loss of trees, as the Central Government may be specify. Central Government will prescribe the terms and conditions, including measures for conservation and protection of biodiversity, which will be binding for the authorities in the State as well as on the user agency."

- 2.4.52 It was also observed in written memoranda received from public that the proposed amendment undermines the provisions of the FRA, 2006, LARR Act, 2013, PESA Act, and National Forest Policy, 1988. Exemptions considered under the Act are in violation of the provisions of the FRA, 2006. In this regard, the Ministry of Environment, Forest, Climate Change have clarified that no non-obstante clause or section has been provided in the Bill. Further the provisions proposed in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 do not bar or infringe with the operation of other parallel laws, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, PESA Act, 1996 and Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (LARR) Act, 2013, which mandates to obtain the consent of Gram Sabha.
- 2.4.53 During presentation before the Committee on the provisions contained in the Bill, a stakeholder made the following submission on 17 May, 2023:—

"Please look at the North-East, for example, and the huge forested areas in the North-East of India. If you are going to exempt 100 kilometres from each border, what is going to be left of the North-East? It is a very sensitive area. As it is, we are seeing the problems which are being created because certain communities who have had traditional rights and customary rights to forests under Schedule VI of the Constitution which itself, I believe, is inadequate. If you are going to give exemptions even for that in the name of security, I believe that it is going to be very problematic. This is a clause which the Committee has to very seriously look at. The other exemptions also, which are being given, are going to free up large portions of India's forests for projects in various categories which are being given. So, basically as I started off by saying, this regime which is sought to be introduced of exemptions, without any kind of barrier, is an automatic exemption regime which is very dangerous and risky. I am sure, the rulers are very responsible and I am sure that they are all very concerned about conservation. But once you bring this on to the Statute Book, you are opening up a

Pandora's box which is going to be very difficult for you to reverse. These are the points which I would like to make as far as exemptions are there."

Another expert/stakeholder made the following observation pertaining to exemptions and jurisdiction of state government in the matter of exemptions:

"Exemptions considered under the Bill should not be blanket exemptions and should be considered with the approval of officers to be authorized by the State in this regard."

2.4.54 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written reply have submitted as under:

"Extent of 100 km has been decided in consultation with the Ministry of Defence and is considered optimum to meet the requirement of various defence organization to meet their strategic requirements.

Exemption have been considered purely in the public and national security interests of the country. The proposed exemption along the international borders and in LWE District are not generic exemptions i.e. proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. Said exemptions will not be available for private entities. Moreover, even after the diversion of forest land, the legal status of forestland remains unchanged, therefore, there will be no reduction in the forest area.

Moreover, said dispensation will be subject to such terms and conditions, including payment of compensatory levies and compensation of trees, which will be a binding on the States to ensure their compliance while considering such projects under exemption.

Defence projects which are to be completed in a time bound manner, often gets delayed due to length procedures and documentations involved in the process of approval."

2.4.55 Further, two stakeholders who appeared before the Committee on 30 May, 2023 made the following submissions to the Committee:—

- (i) This limits the applicability of the Act on a vast tract of forest land in a country that got protection since the Godavarman order. Such exclusions of forest land can, therefore, potentially be sold, diverted, cleared, felled, utilized, or exploited without any forest clearance. All those forest lands which do not fall in the reserved area but are available in government records before 1980 will not come under the purview of the Act. This diverts away from the Supreme Court's 1996 verdict which had ensured every forest mentioned in government records gets legal protection against deforestation.
- (ii) In clause 1A, after B, we need to add one Sub-clause that 'the lands defined in the Godavarman Judgement of 12.12.1996' needs to be included. In the first proviso to the same clause, there are two aspects which are very important. We need to make a distinction between de-notification and diversion. Therefore, we need to make a difference and those lands which have been diverted should not be left out of the purview of the Act. This will be a major loophole, which will be exploited. Only those that have been de-notified may be considered for keeping them outside the purview of the law.
- 2.4.56 In regard to the above submissions, the Director General of Forests and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change replied during the sitting of the Committee held on 30 May, 2023 as under:—

"Among the new issues that were highlighted, one was related to applicability of the date i.e. 12th December 1996, and whether all legal works done prior to that date will be treated as legalized or not. I will bring to the attention of the hon. Committee the language that we have used: "Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land which has been changed from forest use to the use for non-forest purpose on or before the 12th December 1996 in pursuance of an order issued by any authority authorized by the State Government or the Union Territory administration in that behalf." If anything has not been authorized by the State Government or the Union Territory administration, that will remain illegal and will still be considered illegal under this provision. This provision was inserted only to facilitate those activities which have taken place prior to 12th of December 1996. For example, if some school has been constructed and now, they want to add a toilet or room, that will not come under the purview of the Forest Conservation Act."

2.4.57 An invitee made the following submission before the Committee on 30 May, 2023:—

"The other aspect which I wanted to say very loudly is that we have got the law of the Forest Rights after a lot of conflicts. I was also on that committee. I remember a lot of congratulations. My point is how long we have all fought together for it. After such a fight, we have got a certain regime which at least gives three things. The first is protection for tribal communities and traditional forest dwellers. The second thing is a kind of democratic governance for our areas which come under the forest. Now, if we are going to jettison all that, All these forests may be used for our industrialization, because there is no mention. There is also no mention in the rules of Forest Rights Act and PESA that it is also a right. There is no mention of the role of tribals in conservation. If you bring the amendments and will not

even mention these communities, then I understand that this is very wrong. If you sidestep the rights of tribal communities in this way, it will be very wrong. I will say in the end that without reference and linking with the Forest Rights Act, with PESA and with other constitutional guarantees for the tribal communities and the forest dwellers, these amendments are going to be a grave injustice. So, I would request the Committee to ensure that the rights of tribal communities are embedded in our conservation Acts, including in these amendments."

2.4.58 In regard to the above submission, a representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change made to the following submission to the Committee:—

"Regarding the FRA, I have already explained that the Act does not violate FRA. For the knowledge of the hon. Member, I will read it again: "The State Government or the Union Territory Administration, as the case may be after obtaining the final approval of the Central Government under Section 2 of the Act, shall ensure the recognition of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest dwellers (Recognition of Forest rights) Act, which is the FR Act, and to determine and inspect the prosecution lease after fulfilling and complying with the provisions of all other Acts and Rules made thereunder, as applicable, shall issue an order." So, the State Government will issue the final permission only when the Gram Sabha of the concerned area has given the permission in writing."

- 2.4.59 Further, in written memoranda submitted to the Committee, the following observations have been made:—
  - (i) Bill takes a narrow view of forest conservation by completely ignoring the forest-dwelling local communities, and in fact sidelines their existing rights to "conserve, manage and protect forests" enshrined under the Forest Rights Act, 2006. Consent provisions of local communities before forest diversion be adequately reflected in clause 2 of the Principal Act and Clause 4 of the proposed Bill.
  - (ii) Exemption of Forest Land where Individual Forest Rights (IFRs) have been Recognized from the applicability of the Forest (Conservation) Act, 1980.
  - (iii) The Forest (Conservation) A mendment Bill, 2023 as the proposed act will weaken both the Forest Rights Act-2006 and PESA Act-1996 formulated for welfare of Tribes and im plemented in the areas notified in 5th Schedule of Indian Constitution specially and gra dually diminish the welfare measures taken under above two acts. So we suggest nece ssary steps should be taken to withdraw the proposed bill. The rights of forest dwelling communities under the Forest Rights Act, 2006 have been undermined. Failure to specifically include any provisions to incorporate the powers granted to the Gram Sabha under the FRA. Violation of PESA Act 1996.
  - (iv) The new Bill must address the fundamental problem of failure to recognize that the local communities are the actual custodians and defenders of the forests. Though the Forest Rights Act has attempted to correct the historic injustice, the FCA needs to be amended to grant the rights to protect and defend the forests to the local communities by ensuring that no forest is diverted or used for non-forest purposes without Gram Sabha approvals.
  - (v) The Bill makes no reference to any other laws relevant to forest: The Forest Rights Act, 2006; the Biological Diversity Act, 2002 finds no reference either in the text of the Bill or the statement of Objects and Reasons. The fact that forest are not empty spaces but areas where there are rights conferred under the law finds no reference in the Bill. In the last few years, nearly 2, 95,000 Biodiversity Management Committees have been set up and are functional. Individual and Community Forest Rights (CFR) have been conferred on forest dwelling communities and Gram Sabhas are mandated to protect and conserve these Community Forest Resources. Yet, the Bill gives a carte blanche to divert forest on various grounds. There is no recognition of the efforts that might have been put in by communities in protecting and regenerating these forest areas.
  - (vi) The 2023 Bill, however, displays a worrying lack of knowledge about the provisions in the Constitution of India, laws and judicial precedents which give a special constitutional status to Scheduled Areas and Scheduled Tribes in India. Article 244 read with the Fifth and Sixth Schedules of the Constitution, which relate to special governance of these Areas, have been completely ignored. The 2023 Bill also ignores the *Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996*, enacted under the mandate of Article 243M of the Constitution of India, under which Gram Sabhas in Fifth Schedule Areas are vested with authority over their natural resources in general, and over a wide array of mineral, forest, and water resources in particular. Diversion of these resources for developmental projects without due consultation with the Gram Sabhas has been prescribed by this law.
- 2.4.60 In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have clarified in writing as follows:—

"Provisions of the Bill do not infringe or abrogate the provisions of the Forest Rights Act, 2006, PESA or LARR Act, 2006. The processes envisaged in these laws, including the consent of the ST and OTFD under the Forest Rights Act, 2006 is not impeded in any way by the proposed amendment.

The provisions proposed in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 do not bar or infringe with the operation of other parallel laws, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, PESA Act, 1996 and Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (LARR) Act, 2013, which mandates to obtain the consent of Gram Sabha.

No non obstante clause has been provided in the Bill. Therefore, provisions of the Bill do not impede with the provisions of the Forest Rights Act, 2006 and Biological Diversity Act, 2002. The rights conferred to the Gram Sabha/Committee under the said Acts will continue to be enjoyed by the Gram Sabha/Committees or other statutory body.

By the 42<sup>nd</sup> Amendment Act 1976 of the Constitution "Forests" was added as Entry 17A in the Concurrent List. Therefore, proposed amendment is within the ambit of the powers conferred to the Central Government. Moreover, the proposed amendment of the Bill does not infringe or violate the Constitutional provisions."

## 2.4.61 Further observations received from the public state as under:—

- (i) the exemptions proposed in the Amendment will weaken the Act's role in checking deforestation and safeguarding forests. Excluding land "situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control" from the Act's purview severely compromises the conservation of large tracts of open natural ecosystems like deserts, semi-arid savanna grasslands, rocky outcrops, and wetlands.
- (ii) Exemptions would result in the destruction of forest cover and would have a negative impact on the environment. These regions, namely the Line of Control or Line of Actual Control, and areas affected by "Left-wing extremism" are highly eco-sensitive areas in extremely fragile ecosystems. Such destruction of forest cover would lead to an adverse impact on tribal habitats and wildlife. Such proposed exemptions cannot be offset with tree plantation and afforestation.
- (iii) Instead of giving arbitrary extent of 100 km an alternate arrangement such 'Security Sensitive Zone' may be adopted which may be notified from time to time.
- (iv) Distance of 100 km for the construction of security related projects should be reduced to 50 km as 100 km would destroy much of the higher and Central Himalayas.
- 2.4.62 In regard to above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have clarified as under:—

"The proposed provisions providing exemption along the international borders and in LWE District are not generic exemptions i.e. proposed exemption are only for specific projects of strategic importance concerning to national security to be identified by the Central Government. Said exemptions will not be available for other projects of the region including private entities. Moreover, said dispensation will be subject to such terms and conditions, including payment of compensatory levies and compensation of trees, which will be a binding on the States to ensure their compliance while considering such projects under exemption.

Extent of 100 km has been decided in consultation with the Ministry of Defence. Certain category of lands have been exempted from the purview of Act purely in the public and national security interests of the country.

Enabling provisions therefore, have been provided in sub-section (3) of the Section 1A of the proposed Bill which provides that such dispensation will be subject to such terms and conditions, including the compensating the loss of trees, as the Central Government may be specify. Said provisions will also be invoked to prevent misuse of exemptions."

2.4.63 In another written memorandum from the public it has been observed that critical ecosystems such as Shola Grasslands, Myristica swamps, grassland on laterite hills, private owned mangrove forest, will be excluded from the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980. In its reply, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified in this regard as below:—

"The proposed Bill primarily intends to eliminate the ambiguities in the applicability of the Act in various lands. Applicability of the Act is decided by the status of a land recoded in the records which has been explained under section 1A(1) of the Bill. Land is a State subject and in case the State Government desires, the land records may be updated to include ecologically important areas/ecosystems in the category of forests."

2.4.64 In another memorandum submitted to the Committee, a stakeholder has suggested that as regards to exemption considered under IA(2)(a), the provisions for construction of eco-bridges may be provided to ensure safe passages for wildlife. In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has stated in its written reply as below:—

"Sub-section (3) of the Section 1A provides that such dispensation will be subject to such terms and conditions, including the compensating the loss of trees, as the Central Government may be specify. Central Government will prescribe the terms and conditions, including measures for conservation and protection of biodiversity, which will be binding for the authorities in the State as well as on the user agency."

2.4.65 Regarding proposed amendment in 1A 2 (a) of the Bill, the following observations/suggestions were made by stakeholders:—

- Exemption of 0.1 should be increased to 1.0 ha for the States like Arunachal Pradesh;
- Exemption of 0.1 ha is unjustified and would create long term challenges in habitat connectivity and wild animal dispersal/migration, and, therefore, should be deleted from said Bill.
- The terms habitations, road and railways and exemptions of 0.10 is vague for want of definition.

- Exemption of 0.10 needs more clarity to exclude the forest areas which are not strip plantation.
- The Bill doesn't explain the exemption for habitation access from road/rail amenities.

2.4.66 In regard to the above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified in their written comments furnished to the Committee repectively as under:—

- "Exemption, proposed in the Bill, has been decided by the Central Government, as appropriate, after carrying out the consultation process with the Ministries, States and public.
- Exemption of 0.10 ha of forest land, considered under section 1A(2)(a), will provide connectivity to road side habitations and establishment to ensure their connectivity with the mainstream of development.
- The terms and conditions, including defining amenities, strategic roads, public utilities, etc. will be undertaken subsequently, by the Central Government in accordance with the provisions of section 1A(3) of the Bill.
- Clarification in this regard, if any needed in future, will be issued by the Central Government by invoking the provisions provided under section 6 of the Bill.
- The provisions of the relevant section i.e. 1A(2)(a) clearly explain the purpose of exemption of 0.1 ha stating that 'such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by government, which provides access to a habitation, or to such rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case'.

Moreover, the said provisions has also been explained in the Statement of the objects stating that Bill envisages to exempt certain categories of land to provide access to small establishment, habitations on the sides of the roads and railways."

- 2.4.67 In regard to the proposed amendment in 1A(2)(c)(i) the following observations were made in their written memoranda received from the public:—
  - (i) "With regards to exemptions considered for security related projects, there is no data to substantiate the fact that forest clearance has stalled national-importance projects within the forest area. In such a scenario the proposed amendment is irrational and arbitrary.
  - (ii) Exemption relating to defence projects in border areas and security related infrastructure should be deleted. Exemptions considered under the Act will destroy various wildlife areas, forests, mountains and other ecosystems creating loss of habitats and species alongside rails and roads.
  - (iii) With regards to exemptions of security related projects what should be the procedure and standin case of a previously notified Protected Area (eg. Kaziranga National Park, Valmiki Tiger Reserve, Valley of Flowers National Park, etc). Will there be no need for any permissions or procedure requiringsay/opinion of the forest department? What shall be the checks and balances in such cases? Will it be a free pass? There is no cap or limit on the area of such usage of forest land in a given area."
- 2.4.68 In regard to above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change clarified, respectively, in its written comments as under:—
  - (i) "Defence projects which are to be completed in a time bound manner, often gets delayed due to length procedures and documentat ions involved in the process of approval. Analysis of approvals accorded in the past for defence projects revealed that out of total area of 80,408 ha diverted in the last 8 years, only 2480 ha of forest land has been diverted to defence projects including roads which account for 3% of the total area diverted. It is also important to note that during last 8 years out of the total forest area of 19305 ha diverted for road in the bordering States of the country, only 3.5% is diverted for defence road projects. Moreover, these exemptions are subject to terms and conditions as will be specified by the Central government which will include the compensatory conservations compliances as mentioned in the Bill.
  - (ii) Enabling provisions have been provided under section 1A(3) of the Bill to prescribe terms and condition while considering exemption. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards should always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government.
  - (iii) Proposed exemptions will not be applicable in respect of Protected Arears notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972. To mitigate the impact of construction activities for roads/railways, besides greening the area, it is necessary to undertake other measures as well such for the conservation, protections and stabilization of local topographical regimes besides the flora and fauna. Existing mitigation measures will be continued to be complied during the construction activities. Enabling provisions therefore, have been provided in sub-section (3) of the Section 1A of the proposed Bill which provides that such dispensation will be subject to such terms and conditions,

including the compensating the loss of trees, as the Central Government may be specify. Said provisions will be also be invoked to prevent misuse of exemptions."

- 2.4.69 Further, the following observations made in the written memoranda received from the public:—
  - (i) Public utility of very wide term which will virtually allow construction of any project on the forest land.
  - (ii) The Bill doesn't define terms such as rail/roadside amenity, public utility, strategic projects, security-related and defence related projects.
  - (iii) In general understanding, 'roadside amenities' involve numerous infrastructures like petrol pumps, restrooms etc. The National Highway Authority of India's 'Policy Guidelines for the Development of Wayside Amenities along National Highways and Expressways' provide an insight into the mandatory and permissible facilities. The guideline includes food court/restaurants, dedicated area for promoting local artisansup to an area of 1000 sq. ft, landscaping and others as mandatory facility category. Similarly, the Uttar Pradesh Public Works Department clarification with respect to roadside amenities along the State Highways and Major District Road describes 'roadside amenities' to include dhabas, separate parking for cars, buses and trucks, open-air rest area with benches and tables, dormitories for drivers/truckers andothers, etc. These facilities virtually provide townships along highways and the lack of specifics with respect to the frequency of these facilities along such linear projects makes vast forest areas susceptible. Therefore, section 1A(2)(a) should be deleted from the Bill.
- 2.4.70 In regard to the above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change provided the following clarifications, respectively:—
  - (i) Public utilities have already been specified by the Ministry in the guidelines. Only specified category of projects to be implemented by the Government Department will be allowed under the proposed exemptions. Moreover, these exemption are for the diversion of forest land upto 10 or 5 hectare and not each proposal of 10 or 5 hectares as are being understood. Further the provision should be read with sub-section (3) which states that such exemptions will be subject to terms and conditions as specified by the Central government.
  - (ii) Terms and conditions, including defining amenities, strategic roads, public utilities, etc. will be undertaken subsequently, by the Central Government in accordance with the provisions of section 1A(3) of the Bill. Moreover, public utilities have already been specified by the Ministry in the guidelines.
  - (iii) Exemption of 0.10 ha of forest land, considered under section 1A(2)(a), will provide connectivity to road/rail side habitations and establishment to ensure their connectivity with the mainstream of development local officers, the dispensation will be provided.

The proposed dispensation will be used to provide connectivity to the habitation with the road and other facilities situated along the road and railways. The dispensation will be used as per actual requirement i.e. wherever such connectivity is required as per the assessment of the local officers, the dispensation will be provided.

- 2.4.71 Regarding amendment proposed in 1A(2)(b), the following observations were received from the public:—
  - Exclusion of tree plantations is unreasonable.
  - Exempting plantation on non-forest land will open up the excluded forest lands as compensatory afforestation.
  - Amendment proposed is against the National Forest Policy, 1988
  - In India, besides the forest areas under the control of the Government, therefore the forest areas which are under the ownership of private people and in the areas no, non-forest activities/projects can be implemented. This bill now, is trying to give exemption to raise plantation and carryout construction work. In these forest areas under the provisions of Forest (Conservation) Act. In the protected forest areas and Tiger and Elephant sanctuaries in Tamil Nadu, there are several hectares of forest land are available belonging to the private people. If those areas are exempted from the controls of the forest (protection) Act, it will lead to cultivation of cash crops in those areas and trees would be felled. When such activities are carried out in the private owned forest near or at the center of the preserved forest area, it may lead to soil erosion, and during the rainy season due to the soil erosion the forest ecosystem will be affected.
- 2.4.72 In reply to above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change provided the following clarifications respectively:—
  - Provisions have been proposed to eliminate the ambiguities in the applicability of the Act in non-forest lands and to
    promote people's participation in increasing the forest cover of the country and in the process of forest conservation
    and management.
  - Lands used for compensatory afforestation are invariably notified as forests under the Indian Forest Act or local Act. Therefore, provisions of the Act will be applicable on such lands.

- Provisions of the Bill supports the objectives of the National Forest Policy, 1988. It promotes afforestation on nonforest land by bringing clarity on the non-applicability of the Act on such lands.
- The provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of proposed Bill encourages to raise afforestation in private lands, thereby facilitating the peoples participation in increasing the green cover of the country and to combat the global issues such as carbon neutrality, enhancing the carbon sink, better forest management, etc. Promotion of afforestation in the non-forest land will create additional carbon sink besides reducing pressure on forests. The Forest (Conservation) Act, 1980 as well as the Amendment Bill do not contravene any of the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

## Observation/Recommendation of the Committee

2.4.73 The Committee deliberated upon the proposals made in the Clause including the suggestions made by stakeholders and the rationale/replies/clarifications given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change thereto and decided to accept the amendments proposed under the Clause.

#### Clause 5

# Relevant provisions of Principal Act

2.5.1 Existing provision of Section 2 are as under:

Restriction on the de-reservation of forests or use of forest land for non-forest purpose

- 2.5.2 Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in a State, no State Government or other authority shall make, except with the prior approval of the Central Government, any order directing
  - i. that any reserved forest (within the meaning of the expression "reserved forest" in any law for the time being in force in that State) or any portion thereof, shall cease to be reserved;
  - ii. that any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose;
  - iii. that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organisation not owned, managed or controlled by Government;
  - iv. that any forest land or any portion thereof may be cleared of trees which have grown naturally in that land or portion, for the purpose of using it for reafforestation.

Explanation —For the purpose of this section, "non-forest purpose" means the breaking up or clearing of any forest land or portion thereof for—

- a. the cultivation of tea, coffee, spices, rubber, palms, oil-bearing plants, horticultural crops or medicinal plants;
- b. any purpose other than reafforestation;

but does not include any work relating or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife, namely, the establishment of check-posts, fire lines, wireless communications and construction of fencing, bridges and culverts, dams, waterholes, trench marks, boundary marks, pipelines or other like purposes.

## Provisions proposed in Amendment Bill

2.5.3 Amendment of Section 2 of the Act

In the principal Act, in section 2,—

- (a) the said section shall be renumbered as sub-section (1) thereof and in sub-section (1) as so renumbered.
- (I) in clause (iii), for the words "not owned, managed or controlled by Government", the words "subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify" shall be substituted;
- (II) in the Explanation, for the long line occurring after clause (b), the following shall be substituted:—

"but does not include any work relating to or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife, such as—

- (i) silvicultural operations including regeneration operations;
- (ii) establishment of check-posts and infrastructure for the front line forest staff;
- (iii) establishment and maintenance of fire lines;
- (iv) wireless communications;

- (v) construction of fencing, boundary marks or pillars, bridges and culverts, check dams, waterholes, trenches and pipelines;
- (vi) establishment of Zoo and Safaris referred to in the Wild Life (Protection) Act, 1972, owned by the Government or any Authority, in forest areas other than Protected Areas;
- (vii) eco-tourism facilities included in the Forest Working Planor Wildlife Management Plan or Tiger Conservation Plan or Working Scheme of that area; and
- (viii) any other like purposes, which the Central Government may, by order, specify."

# 2.5.4 Reasons/Justification given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

- 1. Existing provisions of section 2(iii) of the Act, which dealt with assignment of forest land on lease, are not applicable to Government entities. Therefore, to bring uniformity, the section 2 (iii) has been proposed for amendment.
- 2. The term 'non-forestry purpose' needs more clarity. The explanation has been made elaborate to include activities which are taken up for the cause of conservation of forest and wild life.

# Examination by the Committee

2.5.5 The representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change were asked to specify properly the provision made in Clause (iii) of the Section 2 of the principal Act during their briefing on the Bill. In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change submitted in a written note as below:—

"In 1988, the clause (iii) of proposed sub-section (1) of section 2 was inserted to regulate the assignment of forest land on lease to private entities for raising commercial plantations. Provisions of the said sub-section are not being applied to Government entities resulting in lack of uniformity. Therefore, to bring uniformity in the provisions, amendment has been proposed in clause (iii) of the proposed sub-section (1) of section 2 of the Act."

- 2.5.6 During briefing on the Bill, it was further pointed out that the Proposed Bill mentions establishment of Zoo and Safari on forest land will increase commercial activities and the forest eco system, food chain and food cycle system will be disturbed leading to forest deterioration. In this regard, it is suggested that Zoo and Safari should be set up on non-forest land, so that tribals are not disturbed.
- 2.5.7 Further, in written memoranda received from public, the following observations have been made:—
  - (a) dispensation to Zoos and Safari may lead to concrete structures and road network in the forest areas.
  - (b) Zoos and Safari now being treated as forestry activity is based on absurd premises that it is ancillary to conservation of forest and wildlife.
  - (c) Allowing Zoos and Safaris within the scope of non-forest activities may disproportionately commercialize forests and wildlife without considering the rights of forest-dependent people, wildlife habitats, and ecosystem services.
  - (d) Provisions to include forestry activities such silvicultural activities, zoo, ecotourism and like purposes is vague and is ultravires.
  - (e) In a time where the privatization of Zoo, Eco- Tourism, and Safari are in rampant increase, this amendment will be served only in the interest of private corporations.
  - (f) Establishments in the name of ecotourism facilities, zoos and safaris and infrastructure comes at a cost of native vegetation and wildlife habitat.
  - (g) Inclusion of zoo and safari as forestry activities is a back door entry for amending the Wild Life (Protection) Act, 1980.
  - (h) Bill must remove from its fold increasing swathes of forest under the exclusionary protected area regimes the national parks, wildlife sanctuaries and tiger reserves and must resist drooling over the mounting disposable income of small global leisured class through ecotourism, even if it be by importing wildlife from the African wild for their viewing pleasure.
  - (i) Proposed provisions of the Bill will likely create a new system of commercial ecology that caters to corporate enterprise rather than investing in conservation and a sustainable future.
  - (j) In India from 2019 some private entities have started establishing zoos and subsequently in 2020 Union Environment and forest department entered into agreement with private people to manage several zoos. Thus, there is a danger that through this amendment to the act, the zoos and wild life/Eco- tourism will be handed over to the private entities through agreement which will spoil the nature of the forest.

2.5.8 In their written clarification to the above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change stated as follows:—

"Zoo and Safari is an activity which is ancillary to the forest conservation and management. Zoo and Safaris will be setup as per the Plan approved by the National Zoo Authority. Therefore, it does not promote commercialization of the forests. Similarly, ecotourism, as per approved Working Plan or Wildlife Management Plan or Tiger Conservation Plan will be taken up in the forest areas. Such facilities in the forest area, besides catering to recreational and aesthetic aspirations of local population, also sensitize and generate awareness among them about the importance of protection and conservation of forest land and wildlife. Such facilities are generally created in the proximity of habitation to ensure minimum disturbances to the forest ecosystem. Setting up Zoos and safari in the forests, besides sensitizing people, will also add to the livelihood sources of local communities and thereby providing them opportunities to connect with the mainstream of development. Enabling provisions provided under section 6 of the Bill, will be used by the Central Government to ensure the legitimate use of the dispensations proposed in the Bill and to issue directions to prevent misuse, if any reported, from these activities. To ensure quick response to natural hazards in the forests, and to facilitate the effective forest management, provisions for basic infrastructure for forest front line staff has been provided in the Bill. The Forest (Conservation) Act, 1980 as well as the Amendment Bill do not contravene any of the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972. Moreover, establishment of Zoo and safari will be undertaken with the prior approval of the Central Zoo Authority of India. No provisions of the Bill promote corporate enterprises in the forests. All exemptions are considered for the Government entities. Moreover, the new forestry activities included in the Bill were already in place by way of guidelines and such activities viz. eco-tourism, zoo and safaris will be implemented through Government Department."

2.5.9 Further during briefing meeting, it was suggested that exemptions should be given to monuments of historical importance in States like Rajasthan which have been put it in the revenue records that are also in forest land. In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in its written comments stated as under:—

"As per provisions proposed in the Bill, the 'Eco-tourism' has been proposed to be included in the array of forestry activities. Therefore, monuments located in the forest lands, intrinsic part of nature's tourism, may also be covered under the ecotourism activities."

2.5.10 During the briefing on the Bill, it was also pointed out that under Clause 5, Section 2 of the Act, inclusion of zoos, safaris, and ecotourism facilities can be potentially destructive and come at a cost of native vegetation and wildlife habitat because there is endemic species, which are very important and these have to be protected. In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in its written comments stated as below:—

"The provisions proposed in the Bill neither infringe to any other law nor impede with conservation of forests including wildlife."

- 2.5.11 It was also observed during briefing that there are many primitive tribes and tribal people, they depend on forests There should also be some provision in this act so that the living conditions of those who are dependent on forests be improved.
- 2.5.12 During briefing on the Bill, it was further observed that the proposed terms such as eco-tourism facility land and activities can harm the ecosystem and may be misused. Forest is the means of livelihood for the tribals. There is a problem in making culverts and roads in the present situation of the Act, it should be simplified so that the people living in the village can be facilitated.
- 2.5.13 In reply to the above observations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in their written comments stated as below:—

"Further, activities like ecotourism, establishment of Zoo and Safaris, etc. have been included in the Bill as forestry activities. Such facilities, besides sensitizing and generating awareness about the importance of protection and conservation of forest land and wildlife, will also add to the livelihood sources of local communities and thereby providing them opportunities to connect with the mainstream of development. The provisions proposed in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 do not bar or infringe with the operation of other parallel laws, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006."

2.5.14 The following statement shows the observations/suggestions received from Members in writing and the reply given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:—

Observation made by Members	Reply given by the Nodal Ministry
	Provisions of regeneration activities have already been included at clause (i) of the Explanation given under section 2 of the Act.

All the terms used in the proposed Bill including 'forest', 'public utility', 'eco tourism facilities' and 'any other purposes' need to be defined to avoid misinterpretation.

The move to allow forests to be used for "any other like purposes specified by the Central Government". This vaguely defined term can potentially open the proverbial floodgates, easing the way for forests to be diverted from a mine to a mall and any purpose in between.

The proposal to keep pristine areas intact and not to subject to diversion for a specific period is also much needed. Identification and demarcation of such areas should however not impact the rights of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers and be done in accordance with the provisions of PESA, FRA, and the Biological Diversity Act. 2002. Demarcation of such areas should not mean that the areas which have not been set aside will then be diverted with greater ease. Country's ecological security will be highly compromised if the process of diversion of forests is made lenient and the rigorous process of forest clearance, including the consent clauses, is not applied to all existing forest areas.

The exemption of exploratory drilling and survey activities on forest land is dangerous precedent. It has several proven effects on air, water and land quality and also causes severe disturbance to wildlife. As per the provisions contained in the Principal Act the activities like cultivation of tea, coffee, spices, rubber, palms, oil-bearing plants, horticultural crops or medicinal plants have been categorised as non-forestry activities. These activities are commercial and non site-specific. To ensure better protection and management of forests for enhanced flow of ecosystem goods and services such activities are not permitted in the forest lands. Moreover, such activities are not in consonance with the provisions of the National Forest Policy, 1988 which discourages use of forest land for cultivation.

The term forest for the purpose of the Forest (Conservation) Act, 1980 has been clarified in Section 1A of the Bill. Further, the terms viz. 'public utility', 'eco tourism facilities' and 'any other purposes' in the section will be clarified/defined by the Central Government, if so needed, in future invoking the provisions of the section 1A(3) and Section 6 of the Bill.

The Phrase '..other like purposes' already exists in the Principal Act.

Provisions of the Bill do not infringe or abrogate the provisions of the Forest Rights Act, 2006, PESA or LARR Act, 2006. The processes envisaged in these laws, including the consent of the ST and OTFD under the Forest Rights Act, 2006is not impeded in any way by the proposed amendment.

Moreover, provisions given under rule 9(6) (b) (ii) mandates that compliance of FRA, 2006 is completed by the State before handing over the land to the user agency.

Survey activities such as investigation, reconnaissance, etc., in forest area are temporary in nature and result in no perceptible change in the forest vegetation or in breaking of land. Exemption considered under the Bill is limited to survey and investigation only, it will not result into diversion of forest land for which prior approval of the Central Government is mandatory. Moreover, the exploratory drilling for hydrocarbons which involves permanent change in the land use of the forest land is not covered under the exemption proposed in the Bill.

The Central Government will prescribe certain terms and conditions to be abided by the States and the concerned user agencies that are undertaking surveys in the forest lands. The provisions of the Bill will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

# Important suggestions by various stakeholders

## Ministry of Tribal Affairs

2.5.15 The Ministry of Tribal Affairs has suggested that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may consider inserting a saving clause that "The rights guaranteed to FDSTs and OTFDs under FRA shall remain protected."

# Government of Chattisgarh

2.5.16 Government of Chattisgarh has suggested the following in respect of Section 2 (iii) of the Principal Act:—

"that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organisation "subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify after consultation with the concerned State Government for the specific lease"

## 2.5.17 Government of Sikkim

## Observations/suggestions of the State Government Reply/comment of the nodal Ministry Sub-section (vi) related to the establishment of zoos and safaris Activities like establishment of Zoo and Safaris, etc. owned by 'any authority' in forest areas is not clear and, in all will be owned by Government and will be set up as per the Plan approved by the Central Zoo Authority. likelihood, bound to be misused. Therefore, it does not promote commercialization of In reference to the establishment of Zoos and Safaris 'owned by any the forests. other authority' needs clarity. A clear process or mechanism for the Similarly, ecotourism, as per approved Working Plan establishment of Zoos and Safaris owned by 'any other authority' may or Wildlife Management Plan or Tiger Conservation be provided in the amendment. Plan will be taken up in the forest areas. These facilities are generally created in the proximity of habitation to ensure minimum disturbances to the forest ecosystem Such facilities, besides sensitizing and generating awareness about the importance of protection and conservation of forest land and wildlife, will also add to the livelihood sources of local communities and thereby providing them opportunities to connect with the mainstream of development. Guidelines, in this regard, are already in place. Enabling provisions provided under section 6 of the Bill, will be used by the Central Government to ensure the legitimate use of the dispensations proposed in the Bill. The Forest (Conservation) Act, 1980 as well as the Amendment Bill do not contravene any of the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972. Detailed nature and type of eco-tourism activities that are to be Guidelines in this regards already in place. allowed and the maximum extent of area for development of Zoos However, clarification, if any, needed in future will be provide by the Central Government by invoking and Safaris need detailing. the provisions of section 6 of Bill.

# 2.5.18 Government of Mizoram

Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
5. (a)(I): Giving all powers to Central Govt. is not agreeable as forest is a subject in concurrent list.	Power conferred under section 1A(3) of the Bill is to prescribe terms and condition while considering exemptions. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards will always be included in the terms and

conditions to be prescribed by the Central Government.

Provisions proposed under section 2 (iii) are not general powers but specific powers to prescribe terms and conditions that too for the limited purpose of assignment of forest land on lease only and not for diversion of forest land. These provisions will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

Provisions given under clause (viii) of the Explanation "....any other like purpose..." already exists in the Principal Act.

Provisions provided under section 5(2) of the Bill are specific to survey and exploration in the forest areas and enables the Central Government to prescribe certain terms and conditions to be abided by the States and the concerned user agencies that are undertaking surveys in the forest lands.

Provisions provided under section 6 of the Bill will be used by the Central Government to ensure the legitimate use of the dispensations proposed in the Bill.

6. 5.(a)(II): There seems to be no need to specify the activities. It should simply state that "any activity ancillary to forest conservation, development and management of forests and wildlife". Also, all power related to any matter shall not be vested with the Central Govt. as forest is a subject in the concurrent list and all forests in the States are under the control of the State Govts. only.

To carry out various forestry management activities and respond to quick natural hazards in the forests, basic infrastructural facilities are required to be maintained in the forest land. For want of enabling provisions in the Act, it is difficult to create such basic infrastructure in the forest area thereby impacting the forestry operations, regeneration activities, monitoring and supervision, prevention of forest fires, etc. Moreover, the proper protection and conservation of forests by local communities requires availability of livelihood opportunities which can be effectively enabled through promotion of eco-tourism, zoos and safaris. Therefore, activities ancillary to forestry management have been explained under this sub-section. The term 'Explanation' has been made elaborate to include activities which are taken up for the cause of conservation of forest and wild life.

# 2.5.19 Government of Meghalaya

Observations/suggestions of the State Government

 With regards to the clause (viii) given under explanation of Section 5 of the Bill i.e. "any other like purposes, which the Central Government may, by order, specify."; the State Government should also be consulted on matters which hinge directly or indirectly on State subjects. Reply/comment of the nodal Ministry

Provisions "any other like purposes, which the Central Government may, by order, specify" proposed in section 5 of the Bill already exist in the Principal Act and the same have been further strengthened keeping in view the dynamic changes in the policies relating to conservation and management of forests.

Whenever, provisions of the clause (viii) of the Explanation or other similar provisions of the Bill will be invoked by the Central Government in

future, prior consultation with the States/UTs will
be made as per need.
be made as per need.

## 2.5.20 Government of Himachal Pradesh

Suggestion of the State Government	Reply given by nodal Ministry
In the Bill, it has been proposed that eco-tourism facilities included in the Forest Working Plan or Wildlife Management Plan or Tiger Conservation Plan or Working Scheme of that area shall not be construed as non-forestry purpose. It is suggested that the "Eco-tourism" may be defined in the Act for better clarity and transparency.	Guidelines in this regard are already in place. However, in case the need arises in future, further clarification will be issued by the Central Government as per the provisions provided under section 6 of the Bill.

# Important suggestions by experts/public

2.5.21 In a memorandum submitted to the Committee, an eminent person made the following suggestion:—

"Clause 5(II)(vi) of the Bill be substituted by the following— "establishment of zoo and safaris referred to in the Wildlife (Protection) Act, 1972, owned by the Government or any public authority, in forest areas other than protected areas."

"The following Explanation be added after clause 5(II)(vii) of the Bill—"Explanation: 'ecotourism facilities' in a forest area includes basic infrastructure for the purpose of regulated ecotourism such as non-tarred and non-concrete pathways, temporary halting and nature observation huts for the convenience of visitors and ecotourism managerial staff, but does not include residential accommodation for tourists, hotel complexes, airstrips and concrete structures which alter the basic forest/natural ambience of the site."

2.5.22 During his appearance before the Committee, an expert stated, "I think, zoos and safaris should not be allowed on forest lands. There should be absolutely no construction activity in the name of eco-tourism in the forests". In this regard, a representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has replied before the Committee as below:—

"The other issue was raised about zoos and safaris and eco-tourism facilities. I will bring to the attention of the hon. Committee that if we are coming to the FC Act, they were getting the sanction of the Government twice. For establishment of any zoo or safari, prior permission of the Government of India is required because they are governed by the Central Zoo Authority. Then they are coming for the permission under FC Act. For ease of doing business, if they are getting the permission of CZA, we are not requiring them to come up again. They are also to be used only for the activity that are done by the Government or any authority. Then regarding the eco-tourism activities, if we read the language, eco-tourism facilities are included in the forest working plan or wildlife management plan or tiger conservation plan. I would like to apprise the Committee that the hon. Supreme Court vide an order has said that the areas will be managed by a working plan or wildlife management plan only after they are approved by the Government of India. So, our IROs who are stationed in 11 localities, approve the working plan and the management plan of that particular area. If eco-tourism facility is part of that working plan, then only they will be allowed and separate requirement of permission under FC Act will not be there. So, it is not correct that the Government of India is shying away from the responsibility. Government of India is very much concerned about the protection of environment and we will do all that we can."

- 2.5.23 Regarding Eco-tourism, the following observations have been made:—
  - (i) Ecotourism may result destruction of the forest areas and wildlife.
  - (ii) Clause 5(a)(II)(vii) also provides for consideration of eco-tourism as forestry activity. The word facilities need to elaborated to prevent cropping up of commercial establishment like hotel, roads, airstrips, and other commercial constructions".
  - (iii) the construction activities should not be permitted in forest land for creation of eco-tourism facilities.
- 2.5.24 The Ministry of Environement, Forest and Climate Change in a written note clarified in this regard as under:—

"Enabling provisions provided under section 6 of the Bill, will be used by the Central Government to ensure the legitimate use of the dispensations proposed in the Bill. To word 'facilities' will be will be clarified through the enabling clause."

2.5.25 Two stake holders in a written memoranda suggested, "In clause (b) of Clause 5 relating to survey and investigation, the phrase "... which does not involve clearing of forest or cutting of trees or construction of roads or paths including blasting and drilling..." should be added. In regard to the above suggestion, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change furnished the following written reply:—

"Provisions of levying terms and conditions mentioned in the section will be invoked by the Central Government and additional precautionary conditions, including mitigating measures, as may be needed will be stipulated."

2.5.26 It was also observed by a stakeholder that activities mentioned under the explanation to section 5 of the Bill would have adverse effects on the wildlife health, also this would influence more human intervention and infrastructure and human activities would disturb animal habitat. In a written reply to the above observation, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has stated as below:—

"To carry out various forestry management activities and respond to quick natural hazards in the forests, basic infrastructural facilities are required to be maintained in the forest land. For want of enabling provisions in the Act, it is difficult to create such basic infrastructure in the forest area thereby impacting the forestry operations, regeneration activities, monitoring and supervision, prevention of forest fires, etc. Moreover, the proper protection and conservation of forests by local communities requires availability of livelihood opportunities which can be effectively enabled through promotion of eco-tourism, zoos and safaris in the forest areas."

- 2.5.27 Further, stakeholders have stated in written memoranda as under:
  - (i) Exempting any survey, reconnaissance, prospecting, investigation, exploration and seismic survey has impact on forests and wildlife habitats. In all these processes, the trees are felled and temporary roads are constructed for transporting equipments.
  - (ii) Exemption considered for survey and exploration proposed in the Bill is going to open up all our forests to mining and similar commercial activities.
  - (iii) Exemptions for survey and explorations are arbitrary, and should depend on the underlying project and its implications on the forest and as sociated wildlife. Recently, the Gauhati High Court stayed Environmental Clearance to Oil India Limited with respect to exploration and drilling through extended reach drilling for hydrocarbons at seven locations in Dibru Saikhowa National Park due to the absence of Biodiversity Impact Assessment.
- 2.5.28 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change have clarified in writing as follows:—

"Survey activities such as investigation, reconnaissance, etc., in forest area are temporary in nature and result in no perceptible change in the forest vegetation or in breaking of land. Moreover, the Central Government will prescribe certain terms and conditions to be abided by the States and the concerned user agencies that are undertaking surveys in the forest land. Moreover, these exemptions will not be applicable in respect of Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972."

2.5.29 In a written memorandum from the public it was observed that silvicultural activities are proposed to be considered as forest related activities, however the same involves felling of trees for commercial purpose. In regard to this observation, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified in a written reply that silvicultural operations are carried out to maintain the health, productivity and flow of ecosystem goods and services from forests.

# Relevant provisions of Principal Act

2.5.30 Not applicable (provisions do not exist in the Act).

# Provisions proposed in Amendment Bill

- 2.5.31 (b) after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-sections shall be inserted, namely:—
  - "(2) The Central Government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-forest purpose.",

# Reasons/Justification given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

2.5.32 This is an activity in which no perceptible change in the forest vegetation is resulted.

# Important suggestions by various stakeholders

# Government of Chhattisgarh

2.5.33 Government of Chhattisgarh has suggested the following in respect of the proposed amendment above:—

"The Central Government may, by order, specify the terms and conditions after consultation with the concerned state Government subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-forest purpose."

# Important suggestions by experts/public

2.5.34 A stakeholder, in a written memorandum submitted to the Committee, observed that the Bill also intends to limit the definition of non-forest activities like surveys, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, which currently requires forest clearance. In a written clarification to the above observation, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has stated as follows:—

"Survey activities such as investigation, reconnaissance, etc., in forest area are temporary in nature and result in no perceptible change in the forest vegetation or in breaking of land. The Central Government will prescribe certain terms and conditions to be abided by the States and the concerned user agencies that are undertaking surveys in the forest lands"

- 2.5.35 Further it was observed by stakeholders in written memoranda as under:—
  - (i) Amendment of section 2(iii) gives the wide powers to the Central Government to specify terms and conditions."
  - (ii) Giving the Central Government authority to "specify the terms and conditions subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as nonforest purpose" without mentioning any safeguards.
  - (iii) Sub-clause (1) (iii) the substitution of the words 'not owned, managed or controlled by Government' by 'subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify' vastly enhances the powers of the Central Government to decide which lands can be diverted or given on lease. Thus, the conservation concerns of state governments or forest officials or local communities who manage such lands will be rendered irrelevant in making such a decision.
  - (iv) The Bill keeps a window open for future dilution by saying that the Central Government can bring in terms and conditions subject to which surveys and investigation will not be considered non-forest purpose.
  - (v) Forests should not be leased to any private person or any other agency (government, non-government or private) to maintain the sanctity of forests.
  - (vi) Provisions of FRA, 2006 should not be compromised
  - 2.5.36 In this regard, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified as below:—
  - (i) Power proposed to be conferred to the Central Government under the said section are not general powers are but specific powers to prescribe terms and conditions that too for the limited purpose of assignment of forest land on lease and not in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.
  - (ii) Moreover, provisions propose to bring uniformity by including the government entities within the ambit of the Act for the purpose of assignment of forest land on lease to them which hithertofore could have been done without the prior approval of the Central.
  - (iii) Provisions provided under section 5(b) of the Bill are specific to survey and exploration in the forest areas and enables the Central Government to prescribe certain terms and conditions to be abided by the States and the concerned user agencies that are undertaking surveys in the forest lands.
  - (iv) Provisions were introduced in 1988 and the same are now being extended to the Government companies as well to bring them under regulation.
  - (v) As the provisions of the section does not entail diversion of forest land, the provisions of Forest Rights Act, 2006 will not be contradicted. However, the authorities in the State/UT concerned will ensure compliance of FRA, 2006 before the assignment of forest land on lease.

# Observation/Recommendation of the Committee

2.5.37 The Committee deliberated upon the proposals made in the Clause including the suggestions made by stakeholders and the rationale/replies/clarifications given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change thereto and decided to accept the amendments proposed under the Clause.

## Clause 6

# Relevant provisions of Principal Act

2.6.1 Not applicable (provisions do not exist in the Act).

# Provisions proposed in Amendment Bill

2.6.2 In the principal Act, after section 3B, the following section shall be inserted, namely:—

"3C. The Central Government may, from time to time, issue such directions, to any authority under the Central Government, State Government or Union territory or any organization, entity or body recognized by the Central Government, State Government or Union territory Administration, as may be necessary for the implementation of this Act".

# Reasons/Justification given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

2.6.3 So far, power to issue directions were drawn from the various orders of Hon'ble Supreme Court or policy decision taken by the Central Government on case to case basis. Therefore, it has been proposed to provide the enabling provisions to issue directions keep pace with the dynamic ecological changes.

## **Examination by the Committee**

2.6.4 In regard to the above provision, during the briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, it was pointed out that the forest management is done on a federal basis now. It is the States which maintain most of the forests except certain national reserved forests This appears to be a bit one-sided. This can be done in a different manner. In response to the above observation, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in its written reply stated as under:—

"Currently, no enabling provisions have been provided in the Act and rules made there under enabling the Central Government to issue clarifications or directions on the provisions of the Act. Bill also proposes to broaden the horizons of the Act to combat the global issues such as climate change and carbon neutrality which will require road map for augmenting the forest management practices. Therefore, it has been proposed to provide the enabling provisions in the Act empowering the Central Government to issue directions, as may be required for the implementation of the provisions of the Act."

2.6.5 The following statement shows the written observations/suggestions made by Members and the reply given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:—

## Observation made by Members

Reply given by the Nodal Ministry

The entire jurisdiction under the proposed Bill has been given to the Central Government. It is suggested that equal agency is set within the purview of Union and State Governments so that a system of checks and balance is present.

Stringent protection of ecologically sensitive areas is ensured through the amendment. Forest lands situated along international borders, particularly in the Himalayan region and the northeast belt, should receive special care and extreme protection to maintain ecological security, preserve biodiversity, and mitigate climate change threats.

Power conferred under the various section of the Bill are not generic powers rather they are specific to that section only enabling the Central Government to implement the provisions of said section for the better conservation, management and development of the forests.

Power conferred under section 1A(3) of the Bill is to prescribe terms and condition while considering exemptions. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards should always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government. Provisions proposed under section 2 (iii) are not general powers but specific powers to prescribe terms and conditions that too for the limited purpose of assignment of forest land on lease only and not for diversion of forest land. These provisions will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972. Provisions given under clause (viii) of the Explanation "....any other like purpose..." already exists in the Principal Act. Provisions provided under section 5(2) of the Bill are specific to survey and exploration in the forest areas and enables the Central Government to prescribe certain terms and conditions to be abided by the States and the concerned user agencies that are undertaking surveys in the forest lands. Provisions

It is recommended that the Government holds a pre-legislative consultation meeting with the forest dependent communities before making any amendments to the Act which impacts them the most. The Government must attempt a pre-legislative consultation meeting with the forest dwelling communities before making any amendments to the Act.

There is requirement of wide scale consultations with the forest dwelling communities on the provisions of the Bill keeping in view the likely impact of its implementation on their livelihood and socio cultural aspects. The provisions of the Bill be translated in languages which they can understand and make such translations available to them while providing sufficient time period for such consultations to take place.

provided under section 6 of the Bill will be used by the Central Government to ensure the legitimate use of the dispensations proposed in the Bill.

A Press Communique has been published inviting comments from the public in Hindi and English as per standard practice followed by the Lok Sabha Secretariat. Comments have been received from the public, including from organization working for the welfare of tribals, and replies thereon provided by the MoEF&CC. Moreover, as per the provisions of the Pre-Legislative Consultation Policy of the Government of India, the public consultation was also made by the Ministry and a concept paper indicating the amendments proposed in the Act was circulated in the vernacular languages and based on the comments received from the Public, including in vernacular languages, the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 has been finalized by the MoEF&CC.

A Press Comments have been received from the public, including from organization working for the welfare of tribals, and replies thereon provided by the MoEF&CC. Moreover, as per the provisions of the Pre-Legislative Consultation Policy of the Government of India, the public consultation was also made by the Ministry and a concept paper indicating the amendments proposed in the Act was circulated in the vernacular languages and based on the comments received from A Press Communique has been published inviting comments from the public in Hindi and English as per standard practice followed by the Lok Sabha Secretariat. the Public, including in vernacular languages, the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 has been finalized by the MoEF&CC.

# Important suggestions by various stakeholders

# **Ministry of Tribal Affairs**

2.6.6 In order to ensure that Rules made under this Act or instructions issued give due regard to the protection of forest rights, a clause may be added to say that the provisions of this Act will not be in derogation of any existing act.

## Government of Sikkim

2.6.7 All power related to any matter shall not be vested with the Central Govt. as forest is a subject in the concurrent list and all forests in the States are under the control of the State Governments only and therefore, all decisions are proposed to be taken in consultation with the State Govts.

# Government of Meghalaya

#### Observations/suggestions of the State Government Reply/comment of the nodal Ministry The following also to be considered: Provisions of the section are not abrogating the powers of the State Government. Provisions have The primacy of the State Government in matters falling been proposed to issue guidelines and clarification under its jurisdiction may perhaps not be abrogated. from time to time which may be needed by the (ii) No such authority could perhaps be conceded in favour of various functionaries in view of the dynamic the Central Government considering that forest is a changes in the policies not only at national but at concurrent subject and land is further a State subject international level also. (Entry - 45) as per List II of VII Schedule of the Currently, no enabling provisions have been Constitution. provided in the Act and rules made thereunder (iii) Similarly, authorities, organizations, entities or bodies enabling the Central Government to issue functioning under the State Government are amenable clarifications or directions on the provisions of the

only to the authority of the State Government who are bound solely by the directions of the State Government.

(iv) VII Schedule of the Constitution prescribes the subjects which are dealt under State List, Central List & Concurrent List respectively. The autonomy conceded to the State Govt. in matters falling under List II and III may perhaps be preserved. Act. As the Bill proposes to broaden the horizons of the Act to combat the global issues such as climate change and carbon neutrality which will require road map for augmenting the forest management practices. Therefore, it has been proposed to provide the enabling provisions in the Act empowering the Central Government to issue directions, as may be required for the implementation of the provisions of the Act.

## 2.6.8 Government of Odisha

Observations/suggestions of the State Government	Reply/comment of the nodal Ministry
The proposed new Section-3C may be deleted as the Government of India has been issuing guidelines, advisories through executive orders, the same be continued.	Currently, no enabling provisions have been provided in the Act and rules made thereunder enabling the Central Government to issue clarifications or directions on the provisions of the Act. As the Bill proposes to broaden the horizons of the Act to combat the global issues such as climate change and carbon neutrality which will require road map for augmenting the forest management practices. Therefore, it has been proposed to provide the enabling provisions in the Act empowering the Central Government to issue directions, as may be required for the implementation of the provisions of the Act.

# Important suggestions by experts/stakeholders

2.6.9 In a written memorandum, it is observed, "Provisions of section 3C gives unfettered power to interfere with any state government or authority's decision under the FCA." In its written reply, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified as follows:—

"Provisions of the said section will be invoked, whenever needed, to clarify the various issues related to the implementation of the provisions of the Act and to ensure that no misuse of forest land takes place."

- 2.6.10 In written memoranda further observations made in this regard as under:
  - i. Implementation of any Act is facilitated by framing of appropriate Rules. Insertion of this Clause-6 allows uncontrolled powers to the Central Government to enforce its 'directions' howsoever justified (unjus tified) they may seem to be. This is avoidable.
  - ii. Section 3 C may abrogate the primacy of the State Government. No such authority should be given to the Central Government.
- 2.6.11 In its written reply, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified, respectively, as under:
  - i. Currently, no enabling provisions have been provided in the Act and rules made thereunder enabling the Central Government to issue clarifications or directions on the provisions of the Act. Bill also proposes to broaden the horizons of the Act to combat the global issues such as climate change and carbon neutrality which will require road map for augmenting the forest management practices. Therefore, it has been proposed to provide the enabling provisions in the Act empowering the Central Government to issue directions, as may be required for the implementation of the provisions of the Act."
  - ii. Provisions of the section are not abrogating the powers of the State Government. Provisions have been proposed to issue guidelines and clarification from time to time which may be needed by the various functionaries in view of the dynamic changes in the policies not only at national but at international level also.
- 2.6.12 Further stakeholders made the following observation in the written memoranda as follows:—
- "the Amendment Bill reserves plenary powers in the Central Government to add and modify the number of permissible works that can be undertaken in forests under Section 5 and Section 6 of the Amendment Bill. Therefore the Central

Government will be able to justify almost any project or activity in forest land by invoking its new plenary powers sought to be introduced under Explanation clause (viii) to Section 2 (1), Section 2 (2) Section 3(C). Such vesting of excessive and unguided powers in the Central Government will defeat the purpose of the Forest Conservation Act and should not be allowed."

The provision made in Section 4(2) where unbridled discretion has been given to the Central government and little consolation provided in Section 4(3) is ambiguous and left to the mercy and will the Central Government which may frame guidelines violating provisions in PESA-1996, FRA-2006, RFCTLARR Act-2013 vis-a- vis calling upon of Article-13 of the Constitution.

2.6.13 In regard to the above, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have furnished the following clarification:—

"Power conferred under the various section of the Bill are not generic powers rather they are specific to that section only enabling the Central Government to implement the provisions of said section for the better conservation, management and development of the forests. Power conferred under section 1A(3) of the Bill is to prescribe terms and condition while considering exemptions. The Central Government shall ensure that relaxation considered under the Act is implemented by taking into account all environmental safeguards. Various aspects like impact assessments, mitigation measures, safe passages for wildlife, implementation of site-specific plans, wherever required, monitoring mechanism are implemented by the concerned agencies in consultation with the State Government. While considering such exemptions, such safeguards should always be included in the terms and conditions to be prescribed by the Central Government.

Provisions proposed under section 2 (iii) are not general powers but specific powers to prescribe terms and conditions that too for the limited purpose of assignment of forest land on lease only and not for diversion of forest land. These provisions will not be applicable in the Protected Areas of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

Provisions given under clause (viii) of the Explanation "....any other like purpose... already exists in the Principal Act.

Provisions provided under section 5(2) of the Bill are specific to survey and exploration in the forest areas and enables the Central Government to prescribe certain terms and conditions to be abided by the States and the concerned user agencies that are undertaking surveys in the forest lands.

Provisions provided under section 6 of the Bill will be used by the Central Government to ensure the legitimate use of the dispensations proposed in the Bill."

# Observation/Recommendation of the Committee

2.6.14 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by stakeholders and the rationale/replies/clarifications given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change thereto and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

SHRI RAJENDRA AGRAWAL
CHAIRPERSON,
JOINT COMMITTEE ON
THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023.

NEW DELHI; 11 July, 2023 20 Ashadha, 1945 (SAKA)

## **APPENDIX-I**

## MOTION IN LOK SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT COMMITTEE

Wednesday, March 29, 2023/Chaitra 8, 1945 (Saka)

Shri Bhupender Yadav moved the following motion:—

"That the Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980 be referred to a Joint Committee of the consisting of the following 19 Members from the House:—

- 1. Shri Rajendra Agrawal
- 2. Dr. Dhal Singh Bisen
- 3. Shri Raju Bista
- 4. Shri Jamyang Tsering Namgyal
- Shri Tapir Gao
- 6. Shri Ajay Tamta
- 7. Shri Suresh Kumar Kashyap
- 8. Smt. Gomati Sai
- 9. Shri Sudarshan Bhagat
- 10. Shri Pallab Lochan Das
- 11. Km. Diya Kumari
- 12. Shri T.R. Baalu
- 13. Smt. Agatha K. Sangma
- 14. Smt. Sajda Ahmed
- 15. Shri Kotagiri Sridhar
- 16. Shri Rajendra Dhedya Gavit
- 17. Dr. Alok Kumar Suman
- 18. Shri Mahesh Sahoo
- 19. Shri Girish Chandra

and two Members to be nominated by Hon'ble Speaker,

and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee;

The motion regarding reference was adopted.

# **APPENDIX-II**

## MOTION IN RAJYA SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT COMMITTEE

Wednesday, March 29, 2023/Chaitra 8, 1945 (Saka)

Message from Rajya Sabha:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 and resolves that the following Members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint committee:—

- 1. Dr. Ashok Bajpai
- 2. Shri Anil Baluni
- 3. Shri Samir Oraon
- 4. Dr. C. M. Ramesh
- 6. Shri Jawhar Sircar
- 6. Dr. Prashanta Nanda
- 7. Shri Hishey Lachungpa
- 8. Shri Birendra Prasad Baishya

and two Members to be nominated by Hon'ble Chairman, Rajya Sabha.

The above motion was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, 29th March, 2023."

# **APPENDICES-III**

# LIST OF EXPERTS/STAKEHOLDERS/ NGOs/ORGANIZATIONS AND PUBLIC IN GENERAL WHO SUBMITTED MEMORANDA

Sl. No.	Name
1.	1. Shri Achyut Das, Social worker, Agragamee, Kashipur Odisha,
	2. Dr.Aurobindo Behera, IAS, Ex- Principal Secretary, Department of Forest and Environment Government of Odissha
	3. Dr. Sanjaya Kumar Panda, IAS, Ex-Chief Secretary, Government of Tripura
	4. Shri G.V. Venugopala Sarma, IAS, Ex-Member, Board of Revenue, Govt. of Odisha
	5. Shri Anil Pradhan, Sikshasandhan, Bhubaneswar
	6. Shri Gouranga Mohapatra, BGVS Odisha
	7. Shri Sandeep Patnaik, Social Worker, AtPo - Dimirisena, Via - Brahamagiri, Dt - Puri, Odisha, Pin -752011
	sandeepkumar.pattnaik@gmail.com
2.	23venkatesan@gmail.com
3.	Shri A Cardoso, Vasco Mormugao Goa-403712, Vasco, info@jhatkaa.org
4.	Shri A K Varma, avanivarma413@gmail.com
5.	Shri A. Chanru, cspallavicspallavi@gmail.com
6.	Shri A. K. Johari, IFS (Retd.), Ex Principal Chief Conservator of Forests-Assam, johari60@yahoo.com
7.	Shri A. Karthikeyan, karthikthamizhan@gmail.com
8.	Shri A. Mohamed Elahi, Tamilnadu, mohdi552@gmail.com
9.	Shri A. Murugan, muruganpitchu@gmail.com
10.	Shri A. Punitharaj, punitharaj11873@gmail.com
11.	Shri A. Ram Rexahan, ramrexahan7@gmail.com
12.	Shri A. Sahul Hameed, sahul75hameed@gmail.com
13.	Shri A. Thamilselvan, tamilmeena644@gmail.com
14.	Shri A.Akbar Basha, Cheyyaru, akbarnizam.ab@gmail.com
15.	Shri A.C. Raj, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, jasu1440@gmail.com
16.	Shri A.C. Zonunmawia, Chairman, Centre for Environment Protection (CEP), Aizawl, Mizoram., cep_earth@yahoo.com
17.	Shri A.Pandurangan, hepsiba.0506@gmail.com
18.	Shri A.R. Meghna Bhandari Saklecha
	meghnarbhandari@gmail.com
19.	aakashchandru2003@gmail.com
20.	Shri Aan Priya C Philip, Parappallill Pathirappally Junction, Alappuzha-688081
21.	Shri Aasic Raja aasicparveen69@gmail.com
22.	Shri Abani Kumar Kanhor, Secretary, Kui Samaj Seba Samiti, Phulbani, kuisamajss.plb@gmail.com
23.	Shri Abdul Hameed Mohamed Anvar, New St. Vellayapuram -623315 mdanvar2013@gmail.com, info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
24.	Shri Abdul Hameed, hameedabdul21934@gmail.com
25.	Shri Abdul Kalam BS, acekalam@gmail.com
26.	Shri Abdul Majeed, 3, Chennai- 600013 info@jhatkaa.org
27.	Shri Abdul Nayeem, 11-38, Godavari Road, Lakshettipet-504215 mohammad03081991@gmail.com, info@jhatkaa.org
28.	abdulraja6843@gmail.com
29.	Shri Abdur Rahman MA veeraezhil1432@gmail.com
30.	Shri Abhi Sabar, padmalaya103@gmail.com
31.	Shri Abhijit Prabhudesai, General Secretary, Federation of Rainbow Warriors, rainbowwarriors2014@gmail.com
32.	Shri Abhijit Thengodkar, <u>Thengodkar, abhijit.thengodkar@googlemail.com</u>
33.	Shri Abhimanyu Sabar, padmalaya103@gmail.com
34.	Shri Abhinand, abhinandmspld@gmail.com
35.	Shri Abhinav Gaur, Advocate, Allahabad High Court, abhinav.cgaur@gmail.com
36.	Shri Abhinav Prasad, RR nagar, Bangalore, Bangalore-560098 abhinavpblr@gmail.com info@jhatkaa.org
37.	Shri Abul Fazal, Yari Road, Mumbai- 400095 abulf3@gmail.com, info@jhatkaa.org
38.	adhiasaithambi@gmail.com
39.	Shri Adhithyan. V, adhithyanvenkatesan@gmail.com
40.	Shri Aditi Kale, Pune, India blueski122@gmail.com
41.	Shri Aditya L, No D 81, Dhanishka Allegria Gardens, Plot No.23, Vengadamangalam Main Road, Kandigai, Kanchipuram-600127
42.	Shri Aditya Prasad, 35 Mutthiganj-700053, Allahabad aditya.prasad332@gmail.com info@jhatkaa.org
43.	Adv. Nithianandan Balagopalan Flat 8/1201, Nerio Building, Kesar Exotica CHS Ltd., Plot No. 264, 265, 266, Sector-11, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra- 410210
44.	Shri Agadesh Waran, G, 641603 Tiruppur info@jhatkaa.org
45.	Shri Aganathavenkatesh. M, aganvenkateshbe@gmail.com
46.	Shri Ahamed Ali, 9C, Pathu Nonbu Chavadi Str, 1st Lane, Goripalayam, Madurai-625002
47.	Shri Ahmad Bin muhammmad, Darul khairath, Kuttur-670306 670306 ahmadktr3@gmail.com, info@jhatkaa.org
48.	Shri AIKMKS Sabha Kisan Mazdoor Khet India LLA, Bengal West Purrup, Village Post-731236
49.	Shri Aishwarya Kammili, Noida-201305, kammiliaish88@gmail.com, info@jhatkaa.org
50.	Shri Aishwarya, 92aishwarya.s.iyer@gmail.com
51.	Shri Ajay C, No:27E, Poonthotta Street, Krishna Puram, Kadayanallur, Tenkasi-627759
52.	Shri Ajay Dsouza, Benson Town, Bangalore-560046 ajayd81@yahoo.com info@jhatkaa.org
53.	Shri Ajay Phatak, phatak.ajay@gmail.com
54.	Shri Ajay Shah <u>ajayh.shah@yahoo.in</u>
55.	Shri Ajay Shah F-403, Parmeshwar 7, near Godrej Garden city, Jagatpur, Ahmedabad
56.	Shri Ajin Mon, aajinmon1994@gmail.com
57.	Shri Ajith, ajith13040@gmail.com

Sl. No.	Name
58.	Shri Ajith Kumar ajithkumardae2225@gmail.com
59.	Shri Ajith Kumar S, Dharmapuri, aeroajith143@gmail.com
60.	Shri Ajith Kumar. A, ajithkumardae2225@gmail.com
61.	Shri Ajith R, 2/32, Kongavembu, Dharmapuri-636902
62.	Shri Akash. K, olukumaresan@gmail.com
63.	akashjos88@gmail.com
64.	akdinesh85@gmail.com
65.	Shri Akhilesh Chipli, General Secretary, SWAN & Man (Save-Wild-Atmosphere-Nature & Man), Chipli Lingadahalli, Post:Varadamoola, Sagar Taluk-577417, Shivamogga-Karnataka
66.	Shri Akilan Balaguru, Vriddhachalam-606001, Tamilnadu info@jhatkaa.org
67.	Shri Akruara Luha, AT Budhibahal, P.O., Turekela, Dist. Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
68.	Shri Akshaya Raj, Ashoknagar, Chennai-600083 info@jhatkaa.org
69.	Shri Alisha Pereira, bournetapereira03@gmail.com
70.	Shri N. Alaguponnirul, alaguthamilan74@gmail.com
71.	Shri Along Longkumer, Convenor, The Naga Rising & Khriezodilhou Yhome, Secretary, The Nagar Rising nagarising office@gmail.com
72.	Shri Aman Bharti, Begusarai Bihar-851101, Begusarai amanbharti995@gmail.com, info@jhatkaa.org
73.	Shri Amar Ghosalkar, Bhandup, Mumbai-421306 amarghosalkar@gmail.com, info@jhatkaa.org
74.	Shri Ameen, ameenmeister@gmail.com
75.	Shri Ameet Singh, economist & farmer, ameetgsingh@gmail.com
76.	Shri Amer Jaleel, (Indian Citizen), amerswork@yahoo.com
77.	Shri Amit Lahiri, AE 520, Bidhannagar, Kolkata-700064
	lahiriamit07@gmail.com info@jhatkaa.org
78.	Shri Amit Nagwanshi, Guna-473001, Toriua, M.P. amit.nagputraaimbscs@gmail.com, info@jhatkaa.org
79.	ammaanpillai@gmail.com
80.	Ms. Ammu, TamilNadu ammukutty318@gmail.com info@jhatkaa.org
81.	Shri Ammulu D, 77 indra Nagar, Thiruninravur -602024
82.	Shri Ana Gracias, Near SFX Cross, Chinchwadda chimbel graciasana123@gmail.com
83.	Shri Anand Paramasivam haiaanand@gmail.com
84.	anandhraj6362@gmail.com
85.	anandhsugumaran@gmail.com
86.	anandjob1706@gmail.com
87.	Shri Anantharaman, anandharaman.s@gmail.com
88.	Shri Ananthi Ponnusamy, IIT Madras- 600036 Chennai ponnusamyananthi@gmail.com info@jhatkaa.org
89.	Shri Anbarasan Kannan, Naam Tamilar Katchi District Organizer, Cuddalore Wes anbarasankannan1993@gmail.com
90.	Shri Anbazhagan Palanichamy, Aratt Premier Apartment, Bangalore-560048 panbu2000@gmail.con info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
91.	anbumuni25@gmail.com
92.	anbushangami@gmail.com
93.	Shri Anden Mesmar, andenmesmar123@gmail.com
94.	Shri Aniket J, P 7/1 , NAD Colony, Navi Mumbai-410206
95.	Shri Anil kumar H A, 97 7 th cross lpo, Bangalore 560003
96.	Shri Anil Xalxo AT/PO-Ratakhandi , Dist-Sundergarh Odisha, Pin code-770039 aniroxalxo25@gmail.com
97.	anithaanitha27078@gmail.com
98.	Ms. Anju, avtarharsana0056@gmail.com
99.	Shri Antaraa Vasudev, Founder, Civis, antaraa@civis.vote
100.	Shri Antonio Vital Luis, Carmona ,south Goa,
	antoniovitalluis@yahoo.co.in.
101.	Shri Antony, jantonysmp@gmail.com
102.	anudharma1623@gmail.com
103.	Shri Anuj Mishra, Gwalior-474011, M.P.,
	anujmishra1955@gmail.com, info@jhatkaa.org
104.	Shri Anujan Prabhakaran, anuxtz@gmail.com
105.	anuragureti.asu@gmail.com
106.	Ms. Anusha B, Nayandahalli, 560039 Bengaluru,
	anu151829@gmail.com, info@jhatkaa.org
107.	Ms. Anuviya Anbuselvam, Chetpet, Chennai-600031
	anuviyanbuselvam@gmail.com, info@jhatkaa.org
108.	aramthirumalainnpl@gmail.com
109.	Shri Arasakumar, arasakumarntk@gmail.com
110.	Shri Aravind beckham2391@gmail.com
111.	Shri Aravind Kathiravan, Tamilnadu Social Media Division In-charge, Naam Tamilar Katchi.Tamilnadu, aravindkathiravan26@gmail.com
112.	archananarasimman29@gmail.com
113.	Shri Arikrishnan, ppmuthu02@gmail.com
114.	Shri Aril Krishnappa Sugandhini, S/O. Sri Krishnappa Poojary, Kalnayabagh, Andinje Post & Village, Belthangady Taluk, 574242, D.K. District, Karnataka.
115.	Shri Arka Roychoudhury, P86 Green View Baoshmabghata-700084, Kolkata
116.	Shri Arnab Dutta, Dr BC Roy Road Shyamnagar, North 24 Parganas-743127 arnabduttamusic@gmail.com, info@jhatkaa.org
117.	Ms. Aruthi, tamildivakar007@gmail.com
118.	Shri Artheeswaran S, 2/25, perumal koil Street, Then puthur village , Viluppuram-604306
119.	Shri Arul Prasath M, Aranganal street, Chennai-600113 arulmech404@gmail.com info@jhatkaa.org
120.	arulmani.ski@gmail.com
121.	Shri Arulprasath M, arulprasathm76@gmail.com

Sl. No.	Name
122.	Shri Arumugam K, No 44, Kannagi ST, Rajeshwari Nagar, Chennai-603202
123.	Shri Arun Anthony Raj S., arunanthony2803@gmail.com
124.	Shri Arun Chakaravarthy, No.3 middle street, Vadakurumboor-607201
125.	Shri Arun Kumar, im.arunofficial@gmail.com
126.	Shri Arun N, aarounn@gmail.com
127.	Shri Arunabh Dev Sharma, For Hope & Care Foundation, kokrajharhopecarefoundation@gmail.com
128.	arunjunai.selvan@gmail.com
129.	Shri Ash M, Jayamahal Extension Benson Town, Bangalore-560092 the9colors@gmail.com info@jhatkaa.org
130.	Shri Ashay Chaware, Flat no. 007, Sai Sadan Apt, Sugwekar Ali , Neral-410101
131.	Shri Ashish Kotamkar ashkot@yahoo.com
132.	Shri Ashok Kumar asokkumar83@gmail.com
133.	ashok20292@gmail.com
134.	ashrafdigital2006psm@gmail.com
135.	Shri Ashwinkumar Rangasamy, Padhirikuppam, Cuddalore-607401 ashwinranga95@gmail.com, info@jhatkaa.org
136.	Shri Ayush Sahoo, Shreekhetra Vihar, Bhubaneswar-751003 ayush.ronu@gmail.com
137.	azeesfarmer@gmail.com
138.	Shri Azharudeen, deensocial.2020@gmail.com
139.	Shri B K Singh, Retired PCCF (Head of Forest Force), Karnataka, bksinghretiredpccf@gmail.com
140.	Shri B. Babusandar, babusandar706@gmail.com
141.	Shri B. Girija, Director, info@cpf.in
142.	Shri B. Prabhakaran Hospitality Supplies & Services, prabha010356@yahoo.in
143.	Shri Babu, penpencil662@gmail.com
144.	Shri Babu S, prancisbabu@gmail.com
145.	babukannan1994@gmail.com
146.	Shri M. Siva, shivaram2007@gmail.com
147.	Badapalli Gramsabha At-Badapalli, Po-Badapalli, <i>Via</i> -Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
148.	Shri Badnaran Majhi, Trustee, (Simlipal Trust for Ecology & Economic Development), durgaprosadmajhi@gmail.com
149.	Shri Baibaraj Majhi, on behalf of Bagbel Gram Sabha, AT- Bagbel , P.O. / Via-Turekela District Balangir, Odisha , Pin 767060 zindabadsangathanbgr@gmail.com
150.	Baidipada Nuasahi Gramsabha At- Baidipada Nuasahi, Po-Jagilipadar, <i>Via</i> -Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032 padmalaya103@gmail.com
151.	Shri Baidyanath Sing, General Secretary (Org.) of Bahujan Mukti Party (BMP), District Unit Mayurbhanj, Odisha
152.	Shri Baishanb Hans, At- Malibahali, Po Mahakhand, Via- Bangomunda, dist. Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
153.	Shri Bakiyaraj rarayaraudo@gmail.com

Sl. No.	Name
154.	Shri Bala Murugan, Pachapalayam, Coimbatore-641010 mail2thaai@gmail.com, info@jhatkaa.org
155.	Shri Balachandran Chinnaiyan, 1109, V. O. C. Nagar , Pudukkottai-622004
156.	Shri Balaji Chitravel, kuttyb40@gmail.com
157.	Shri Balajee T E krishbala.raghul@gmail.com
158.	Shri Balaji balajie3@gmail.com
159.	Shri Bala Mukundhan Vysar Moorthy, 5/817 c Sriram Nagar Kunnur Road Krishnan Kovil- 626138
160.	Shri Balamurugan T NTK Environmental Wing balamnc23@gmail.com
161.	Shri Balamurugan. Mu, balamurugankani02@gmail.com
162.	Shri Banadhikar O Prakriti Banchao Adivasi Mahasabha, Garbeta, Paschim Medinipur, West Bengal-721127 banadhikar.adivasimahasabha@gmail.com
163.	Banadhikar O Prakriti Banchao Adivasi Mahasabha, Paschim Medinipur, Garbeta, Tigar House, West Bengal
164.	barkavi131@gmail.com
165.	barockiasamy64@gmail.com
166.	Shri Baskar Pandiyan, No.4, 3rd Street, Kamarajar Nagar, Avadi-600071
167.	Shri Baspet Bag, On behalf of Bagdor Gram sabha , zindabadsangathanbgr@gmail.com
168.	Bayasahi Gramsabha At-Bayasahi, Po-Mundula, Via-Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032 padmalaya103@gmail.com
169.	Beherakhai, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
170.	bestonecommunication2022@gmail.com
171.	Shri Bhagaban Putel, AT/P.O., Turekela, Dist. Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
172.	Shri Bhagvan Shiv, sivajudo1990@gmail.com
173.	Shri Bhagyashree Pancholy, Add Pancholy House, PP Singhal Marg, Udaipur - 313004, Rajasthan
174.	Shri Bhaja Majhi, AT-Tikrapada P.O Salemudhanga, <i>Via</i> - Bangomunda Dist. Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
175.	Shri Bharath Kumar R, 50, Vettavalam Road, Tiruvannamalai-606602
176.	Shri Bharathi Raja Pandi, Sivaganga-630561 info@jhatkaa.org
177.	bhubalan@gmail.com
178.	Shri Bijay Kumar Hembram, Rastriya Adivasi Ekta Parishad (RAEP), hembram.bijaykumar@gmail.com
179.	Shri Bijaya Jani (Village President), padmalaya103@gmail.com
180.	Shri Biju Sabar, padmalaya103@gmail.com
181.	Shri Biram Soren, Mayurbhanj Hanat Paranik, biramsoren83@gmail.com
182.	Shri Bisambar Mura, General Secretary, All India Jan Adhikar Suraksha Committee, jascommittee@gmail.com
183.	blueski122@gmail.com
184.	Shri Boobathi Raja.V, S/O.K.Veerappan, Samiyarpudur, Oddanchatram, Dindigul boobathi2599@gmail.com
185.	Shri Boopathi, Naam Thamizhar Party, Tamil Nadu, imjust4u4ever@gmail.com
186.	bose.chandraleka@icloud.com
187.	Shri Brian Lobo lobobrian41@gmail.com

Sl. No.	Name
188.	Shri Brijesh CS, brijesh4architect@gmail.com
189.	Ms Brinda Karat, Member, Polit Bureau, CPI(M), Former Member, Rajya Sabha, cc@cpim.org
190.	Shri B.vijayaprabakaran vijayaprabakaran.b@gmail.com
191.	Shri C. Kugan shyamkugan@gmail.com
192.	Shri C.M. Kartik Kumar, cmvsk82@gmail.com
193.	Shri C.R Bijoy, cr.bijoy@gmail.com
194.	Shri C. Suresh, NTK Environmental Wing
195.	Shri C.V. Anandan, cvanandan16@gmail.com
196.	career.dhasthaa@gmail.com
197.	cd.murugan79@gmail.com
198.	Shri Cedric Savio Dsouza
199.	Shri CH Varte, Joint Secretary, Hmar Inpui (Hmar Supreme House), Assam Hills Region, Assam, India
200.	Shri Chambra Munda, AT –Kusumdihi, PO-Kalta, Dist-Sundargarh, Odisha, 770052
201.	Shri Chanchara Sahi Gramsabha At-Chanchara Sahi, Po-Mundula, <i>Via</i> -Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032
202.	Shri Chandru Chawla, cchawla123@gmail.com
203.	chandruksubash@gmail.com
204.	Shri Charles Ebinezer, ebijebi@gmail.com
205.	Shri Charles Teunissen, Botterland, Zevenaar
	teunissencharles@gmail.com, info@jhatkaa.org
206.	Shri Chetan Agarwal, chetan_agarwal1@hotmail.com
207.	Chhattisgarh Bachao Andolan, Conveners – Shri Sudesh Tikam, Shri Manish Kunjam, Shri Bijay Bhai, Ms. Shalini Gera, Shri Ramakant Banjare, Shri Nandkumar Kashyap, Shri Alok Shukla, cbaraipur@gmail.com
208.	Shri Chiranjit Roy, Durgapur-713212, West Bengal royfire007@gmail.com, info@jhatkaa.org
209.	Shri Chitra Iyer Sah, Headingly Cottage, Nainital-263002 chitraiyer@gmail.com, info@jhatkaa.org
210.	Shri Chitrakar Majhi, on Behalf of Mahulmunda Gram sabha zindabadsangathanbgr@gmail.com
211.	Shri Clara Vaz Goa 67writers@gmail.com
212.	Shri Cleo Wendy, DENISEJACKIE@hotmail.com
213.	Col CP Muthanna [Retd], Hon Secretary, Environment and Health Foundation [India], colmuthanna@gmail.com
214.	Concerned Punekars, C/o Sarang Yadwadkar, A-10 Pradnyangad, Sr. No. 119/3, Sinhgad Raod, Pune- 30
215.	Shri Cuz Judas S. Barreto, judas.barreto1967@gmail.com
216.	Shri D. Ajith Kumar, aaji37503@gmail.com
217.	Shri D. E. Asokan, asokan.de@gmail.com
218.	Shri D. Manokaran, manokaranduraisamy2@gmail.com
219.	Shri D. Raja, rajad617746@gmail.com
220.	Shri Dadio Podar, Gram Sabha, GP-Haldi, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com

Sl. No.	Name
221.	Dahu Gramsabha, Dahu, Hatmunda, PS- Brahmanigon, Dist-Kandhamal, 762021, Odisha, nuangabalanhadra@gmail.com
222.	Shri Dakshina Ranjan Kisku, West Bengal-713209, Bardhaman, drkisku@gmail.com, info@jhatkaa.org
223.	Shri Daman Kumar, Pahari Gate Hariana -144208 V.P.O Hariana
224.	Shri Dandasi Sabar ( Village President), padmalaya103@gmail.com
225.	Shri Danny R., Anand Park, Pune-411007 dee.rau@gmail.com, info@jhatkaa.org
226.	Shri David Rodrigues, H.No.191, Murmo Vaddo, Tamsheriem, Borim. Ponda, Goa - 403401
227.	Shri Dayasagar Patil, Savali, Plot No 476/A 2nd Cross Bhagyanagar, Belgaum-590006
228.	Shri Debadityo Sinha, Lead, Climate & Ecosystems, Vidhi Centre for Legal Policy, A-232, Defence Colony, New Delhi - 110024
229.	Shri Debaraj Budek, on Behalf of Masina Gram Sabha zindabadsangathanbgr@gmail.com
230.	Shri Debi Goenka, Executive Trustee, Conservation Action Trust, 5 SahakarBhavan, 1st Floor, LBS Marg, Narayan Nagar, Ghatkopar (West),Mumbai 400086
231.	Shri Deekshith N, 428 5th Main Road Domlur Village Domlur, Bengaluru-560071 deekshith.n@honeysys.com, info@jhatkaa.org
232.	Shri Deepak, allisdeepak@gmail.com
233.	Shri Deepak Gogate, thandademag@gmail.com
234.	Shri Deepak Holkar, Bhigwan-413105 holkardd24@gmail.com, info@jhatkaa.org
235.	Shri Deepak kumar, 4th block,Koramangala , Bangalore-560034
236.	deepakevr@gmail.com
237.	deepakperiyasamy23@gmail.com
238.	Shri Deivasigamani R., Bryant nagar, Thoothukudi-628008
239.	Shri Denis Fernandes, House No. 405, Agas, Loliem, Canacona, Goa.
240.	Shri Devaki Kunte devaki.kunte@gmail.com
241.	Shri Dhanasekar. K, dhana81@gmail.com
242.	Shri Dhanraj Karthikeyan, Thiruvarur, Tamilnadu -613701, gkkdraj@gmail.com
243.	Shri Dhanush Chandra, Water Tank Road, Bengaluru-560085 dhanushfenix@gmail.com, info@jhatkaa.org
244.	Shri Dharmaraj C S, Our Own Nature, Reg.No.68/10,
	P.O.Krishnagiri, Meenangadi, Wayanad Dist, Kerala-673591
245.	Dharma Babu, No. 2/5, First floor, Sardar colony first street, Ek 600032 Chennai babudharma1007@gmail.com , info@jhatkaa.org
246.	dhaya44m@gmail.com
247.	Shri Dheeran Mukesh, mukesh2k1@rediffmail.com
248.	Shri Dhinakaran V dinakarandina12233@gmail.com
249.	dhineshporchilai@gmail.com
250.	Shri Dhiraj U Mirajkar, B.Sc., LL.M., Legal Advisor to Sanjay Gandhi National Park (2000 - 2023), Legal Advisor to Mangrove and Marine Biodiversity Foundation of Maharashtra (2020 - 2023), 405-406 Kanchan Holy Cross Road, Borivali West, Mumbai 400103
251.	Dhobapadar Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com

Sl. No.	Name
252.	Shri Dhruvang Sunil Hingmire, 4, Vrindavan society, Near Mhatre bridge, Pune - 411030
253.	Shri Dhuruvan Selvamani, Spoke Person, Naam Tamilar Katchi parisalkaran@gmail.com
254.	Shri Diamond D Fernandes (Indian Citizen) diamond1827f@gmail.com
255.	Shri Dickson Agnelo Pereira (Indian Citizen) dicksonsail79@rediffmail.com
256.	Shri Dileep Kumar Yadav (I.F.S.), Divisional Forest Officer, Garhwa North Forest Division, Van Bhawan, Kutchery Road, Garhwa, Jharkhand-822114
257.	Shri Dilip Chakma, Executive Director, Indigenous Rights Advocacy Centre (IRAC), indigenousrightsadvocacy@gmail.com
258.	Shri Dilip Gode, Executive Director, <i>VNCS</i> , Vidarbha Nature Conservation Society,B-401, Gondawana-Dhruv Apartments, KT Nagar, Katol Road, Nagpur-440013
259.	Shri Dilli Rajan, dillirajan95972@gmail.com
260.	Ms. Dimple Asha, 4-280/2A, Balaji Nagar-517002 Chittoor
261.	Shri Dinesh Kumar Agrawal, S/o Late Moti Lal Agrawal, 1/24, First Floor, Charmwood Village, Eros Garden, Suraj Kund, Faridabad-121009.
262.	Shri Dinesh Kumar G, gdineshkumar065@gmail.com
263.	Ms. Dipti Arora, diptiarora60@gmail.com
264.	District Forest Right Group Member, 15 Ward Member, Vettaikaranpudhur, Dapslip, Coimbatore, Tamil Nadu
265.	divanaslan1432@gmail.com
266.	Ms. Divya Sree, Jettypalem, Venkatagiri-524132 divyasree92159@gmail.com, info@jhatkaa.org
267.	Ms. Dolly Pandya, Mangal Bagh Street No. 1, Gurudwara Road, Jamnagar-361001
268.	domnicraja1996@gmail.com
269.	Domturunji Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com
270.	Dr. Arvind Kumar Jha, PCCF & DG (SFD), Maharashtra, Member (Bar Council of High Court of Bombay and Goa)
271.	Dr. Ashok Kaushal akaushal 1960@yahoo.co.in
272.	Dr. Bhushi Venkata Rao. Convenor, Visakha Dalit Unity Forum, Bhushi Bhavan, Ashok Nagar, Desapalrunipalem, Nea Check Post, Parawada(M), Visakhapatnan-531021
273.	Dr. D K Sriwastwa IFS Rtd, Secretary, SILVAN, silvansociety@gmail.com
274.	Dr. H.S Gupta, Ranchi -834002., Jharkhand (India)
275.	Dr. Thimmappaiah G, Vijayanagar, Bangalore-560040 info@jhatkaa.org
276.	Dr. A. Simon Justin, simjus6@gmail.com
277.	Dr. Balathandayuthabani P, PhD (Sweden) Environmental Science balapselvam@gmail.com
278.	Dr. Fr. Bolmax Fidelis Pereira, Convenor, Diocesan Commission For Ecology Goa (DCE), goaecology@gmail.com
279.	Dr. Kalpana S Gupte gupte.sankalp@gmail.com
280.	Dr. Kishor Moghe 19, Vishalnagar, Moha, Dhamangaon Road, Yavatmal- 445001
281.	Dr. M. Saren, Paranik/President (B.J.M, P.M.),Barsarsa, P.O. Itachuna,Block- Pandua, District- Hooghly, W.B.
282.	Dr. M.P. Singh, IFS, Director, Institute of Wood Science and Technology, 18Cross, Malleshwaram, Bengaluru- 560 003

Sl. No.	Name
283.	Dr. Mailaraaj, tamilantamayilraai@gmail.com, 13.05.2023 08.37
284.	Dr. Mairee Chet, selvamselvammv@gmail.com 13.05.2023 08.27
285.	Dr. N M Saran MD Physician (Russia & Armenia),
	nmsaran2040@gmail.com
286.	Dr. Sejal Worah, Programme Director, WWF India, vuppal@wwfindia.net
287.	Dr. T. Santhosh Raj, t.santhose@gmail.com
288.	Shri Durai, themotherkpn6@gmail.com
289.	Shri Durairaj durairaj242@gmail.com
290.	Shri Durga M, Adyar, Chennai-600020
291.	Shri Durgacharan Hembram, (vice president,Mayurbhanj Surakhya Manch) BadNaran Majhi, (Advisor, Mayurbhanj Surakhya Manch) durgaprosadmajhi@gmail.com
292.	Shri Durgacharan Singh, Working President of Bahujan Mukti Party (BMP), District Unit Mayurbhanj, Odisha At:— Kanchanpal, PO:— Orachandabilla, PS:— Betnoti, Dist:— Mayurbhanj, State:— Odisha, Pin: 757103
293.	Shri E Sathish Kumar, sathishbharathy88@gmail.com
294.	Shri E Tamilselvan, ts0582020@gmail.com
295.	Shri E. Batsha, Naam Tamilr Katchi, yuvanbatsha@gmail.com
296.	Shri A. Manikanandan, manimalai00315@gmail.com
297.	Shri E. Rasaiya, rasaiyae@gmail.com
298.	Shri E. Tamilselvan, ts0582020@gmail.com
299.	Shri E.A.S.Sarma, 14-40-4/1 Gokhale Road, Maharanipeta, Visakhapatnam- 530002
300.	Ms. R Kanagapriyaa, kanagapriyamsc@gmail.com
301.	elaiyarasan1989@gmail.com
302.	elangovanselva@gmail.com
303.	Shri Eliel D'Souza, Panaji 403002, North Goa, Panaji mrlel96@gmail.com info@jhatkaa.org
304.	elilkrasa90@gmail.com
305.	Ms. Elisabeth Bechmann, Neugebäudeplatz 4 / 67, St. Pölten, elisabeth.bechmann@kstp.at, info@jhatkaa.org
306.	Er. Royson E. Da Costa Consultant Civil Engineer, royson24@gmail.com
307.	erodevpg@gmail.com
308.	Shri Eswar M, 250, Santhiyakinatru Street, Srivilliputhur-626125
309.	Shri Eswara, eswara7@gmail.com
310.	ethirmuttu@gmail.com
311.	Shri Fahad CV, #202 Sri Ram NIlaya Apartments, 145, AECS B Block, Wellington Paradise, Begur, Bengaluru, Karnataka-560068, Bangalore
312.	Ms. Fatima M Noronha fmn2011@gmail.com
313.	Shri Felix Furtado, H. No. 330, Cavorim, Chandor, Salcete, Goa-403714
314.	Shri Felix Pereira, H. No. 642, Moll ward, Sao Jose de Areal, Salcete Goa 403709
315.	Forest Rights Committee, Distt Bayurbhanj, Odisha

Sl. No.	Name
316.	Shri Francis, francismmvdj@gmail.com
317.	Shri Francis Selvaraj, francismmvdj@gmail.com
318.	Shri Fred Hamilton Hamilton, Hiranandani Gardens Powai, Mumbai-400076 hamilton.fred@gmail.com info@jhatkaa.org
319.	Shri G Dhayalan, dhaya4144@gmail.com
320.	Shri G Maharajan, maharajangurunath@gmail.com
321.	Shri G. Munisamy, munisamy0401@gmail.com
322.	Shri G. Prasanna, prasanna.g89@gmail.com
323.	Shri G. Prasannavenkatesh, prasan4p@gmail.com
324.	Shri G. Rajasekar., rajasekardhileepan@gmail.com
325.	gaganshetty047@gmail.com
326.	Shri Ganesan Pazhani, 25/162 Kali Amman koil Street Virugambakkam-600092 Chennai
327.	Shri Ganesh G, Chennai-600019 ganeshg@duck.com, info@jhatkaa.org
328.	Shri Ganesh Sabar, padmalaya103@gmail.com
329.	Shri Ganesh Veluswami, Thilagar Street, Chennai-600091 gunnniboy@yahoo.com, info@jhatkaa.org
330.	ganeshtamil9789@gmail.com
331.	Shri Ganga Majhi, on Behalf of Rautmunda Gram sabha, District- Balangir, Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
332.	Shri Gangadhar Majhi, At- Ganjaudar Po /via Turekela, Dist- Balangir (Odisha) Pin 767060, zindabadsangathanbgr@gmail.com
333.	Shri Gaurish Angawalkar, 25/C/104,Green Hill Goregaon East Near NNP 1&2, Mumbai-400065
334.	Shri Gehla Charan Munda, AT-Birtola, P.ODarjing, Via-lahunipara, PS-Chandiposh, Pin-770040, Stateodisha gelhamunda@gmail.com
335.	Shri Gerald C, 44 Bajanai Madam Street, Pondicherry- 605003 info@jhatkaa.org
336.	Shri Ghana Majhi, on Behalf of Barakani gram sabha
	zindabadsangathanbgr@gmail.com
337.	ghostofjustice2@gmail.com
338.	Gilinda Gramsabha At-Gilinda, Po-Angaragaon, Via-Sumandal, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761035 padmalaya103@gmail.com
339.	gmsaibalaji@gmail.com
340.	gnanamtech85@gmail.com
341.	Shri Gnanamuthu, gnanamuthutvl@gmail.com
342.	Shri Gnanamuthu. T, gnanamuthu.t@sfl.co.in
343.	gnanaseelan98@gmail.com
344.	Shri Gnanasekar, gnanasekarsudararaj@gmail.com
345.	Shri Gobinda Majhi, on Behalf of Jharani gram sabha
	zindabadsangathanbgr@gmail.com
346.	Shri Gogulan. S, gogulan4648@gmail.com
347.	Shri Gokul KR, 16 Brindavan Road Salem-636016

Sl. No.	Name
348.	Shri Gopal, gopal.cse2007@gmail.com
349.	Shri Gopalakrishnan Srinivasan, 1-1/438, Rasi Nagar, Mohan Nagar P.O., Salem – 636030
350.	Shri Gopi Vijayakumar, gopivijayakumar24@gmail.com
351.	Shri Gopikrishnan N, krish.kannan89@gmail.com
352.	Shri Gopinath K, 36/47, Nachiappa Street, Chennai-600004
353.	Shri Goutam Rana, AT Pandaren P.O Kuibahal, Via- Turekela, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
354.	Shri Govindarasu, govindarasu292@gmail.com
355.	Shri Gowri Shankar Manimuthu, Senganoor, boominaikenpatty, 636304 Salem mgssalem@gmail.com, info@jhatkaa.org
356.	Shri Gowtham M, Environmentalist, gowthamvedha26@gmail.com
357.	Shri Gowthamraj Kandasamy, Tamil Nadu, gowthamrajkandasamy65@gmail.com
358.	gowthamvedha26@gmail.com
359.	Gramasabha Samuha, Dadapalla Block, Nayagarh Odisha, Odisha. muduli.trilochan143@gmail.com
360.	Gudikia Gramasabha, P.O. Gudikia, PS-Brahmanigam, District Kandhamal, Odisha sauravbaliarsingh2@gmail.com
361.	Gumandi Gramasabha, nuangabalanhadra@gmail.com
362.	Shri Gura Singh, Member of Rashtriya Adivasi Ekta Parishad, District Unit, ayurbhanj, Odisha At:— Kandaliasole, PO:— Sankerko, PS:— Badasahi, Dist:— Mayurbhanj State:— Odisha, Pin:— 757024
363.	Shri Gurudas Nulkar gurudasn@gmail.com
364.	Shri Hamza Tariq, Kanuni Lok Sahayta Kendra-Mandvi hamza.csj@gmail.com
365.	Shri Hannan Mollah, bhumiadhikarandolan@yahoo.com
366.	Haraguda Gramasabha, saratmalick306@gmail.com
367.	Shri Harald Nixon C C, haraldnixon0225@gmail.com
368.	Shri Haraprasad Raut, on behalf of Dumermunda Gramsabha zindabadsangathanbgr@gmail.com
369.	Shri Hari Krish, 620 Bharathi Road, Chennai-600050
370.	Shri Hariharan. K, k.hariharan25@gmail.com
371.	harinimlr64@gmail.com
372.	Shri Hariprasad G, harikalam@gmail.com
373.	Shri Haripriya Haridasan, Eliyan House , illipuram, PO: Irinave, District Kannur-670301
374.	Shri Harish N, Mahadeshwarnagar, Bangalore-560091 info@jhatkaa.org
375.	harishgmogaveera810@gmail.com
376.	Shri Haritha M, Meledath House, Thaliparamba-670581
377.	harithesmart6@gmail.com
378.	harshith2701@gmail.com
379.	harshshah9990@yahoo.com
380.	Ms. Hema Chari, kandalahema@gmail.com
381.	Hema Chari, hema_05@rediffmail.com
382.	Ms. Hema Ramani, Campaigns Director info@beag.in

Sl. No.	Name
383.	Shri Hemant Kumar Lodhi, Middle High Teacher, Gram+Post- Kundli, Tehsil- Hilwani, District- Raisen (MP)
384.	Shri Hemanth, hemanthinmail@gmail.com
385.	Shri Hemasagar Dharua, At Khutulumunda, Po Kantabanji, Dist Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
386.	Shri Himanshu Singh, Bijliasi, 226003 Lucknow
387.	Shri Hussain Ahamed. madhusathya0806@gmail.com, Software Engineer. hussainahamed107@gmail.com
388.	Shri I. Jayaraman, jeyechange304@gmail.com
389.	imsadiq12@gmail.com
390.	Shri Inamdar Tabussum S., Advocate, Mumbai High Court
391.	Shri Inder Jit Singh, D 383, Defence Colony-110024, New Delhi
392.	Indigenous Lawyers Association of India C3/441, Top Floor, Janakpuri, New Delhi -110058
393.	indrakumar7063@gmail.com
394.	Shri Infant Prakash, infantprakashl@gmail.com
395.	info.kuums@gmail.com, Kachchh Camel Breeder's Association
396.	Initiative for Social Inclusion & Change, Silchar, Cachar, Assamm, mail.ourmedia@gmail.com
397.	Shri Iniyan PK, Ayothidhasar Nagar, Madurai-625514 iniyaa10@gmail.com, info@jhatkaa.org
398.	iniyangeorge0767@gmail.com
399.	Shri Iona Yvette Fernande, Goa ionayvette@gmail.com
400.	Shri J Chandralega, Advocate, Thiruppullani, Ramanathapuram 623532 advchandralega2016@gmail.com
401.	Shri J Johnwesly, kingsj604@gmail.com
402.	Shri J. Loganathan, 4u.logu@gmail.com
403.	Shri J. Richard Amalraj traditionalcnr@gmail.com
404.	Shri J.F. Jino (President), Mountainside Farmers Association, Kamarajapuram, Thadikkarankonam (Post) Kanniyakumari Dist629851
405.	jabezduke95@gmail.com
406.	Shri Jacob Raja, kittanmani@gmail.com
407.	Shri Jadelin Athena, 3 51 24 Arokia Nagar Muthalakurchy Thuckalay Post Kanyakumari Dist. Kanyakumari-629175, Tamil Nadu
408.	Shri Jaffer Li, jaffersara786@gmail.com
409.	Shri Jaffer Ali, jaffersara786@gmail.com
410.	Shri Jagadeesh S, 24/31, Perumal 1st Street, Purasaiwalkam Chennai-600007
411.	Shri Jagadish G Shet, Nagara-577425, Hosanagara Tq, Shivamogga Dist jagga.nagar@gmail.com
412.	Shri Jagan Shekhar, jekansekhar@icloud.com
413.	jaganratnam@gmail.com
414.	Shri Jainam Sheth, Mulund west-400080, Mumbai jsrock2004@gmail.com, info@jhatkaa.org
415.	Shri James Zacharias, Former Forest Officer, Kerala james.zacharias@gmail.com
416.	Ms Janaki Gandhi, #6 Shivalik Apartment, 88 Anand Park , Pune-411007
417.	Ms Janani, Parisar Pune janani@parisar.org

Sl. No.	Name
418.	Shri Janardan Nayak, Milita Adibasi Kalyan Monch, Keonjhar, Odisha-758001
419.	Shri Janarthanan Mani vellorejana@gmail.com
420.	Shri Janarthanan Mohan, 269 new Street Kedambur, Ambur-635808
421.	Janibili Gramsabha At-Janibili, Po-Mardamekha, Via-Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032 padmalaya103@gmail.com
422.	Jarapalli Gramsabha At-Jarapalli, Po-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
423.	Ms. Jaya Sabar (Village President) At- Telimal, Po- Jagilipadar, Via- Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032
424.	jayakarthickofficial@gmail.com
425.	Shri Jayakumar, jayaguru84@gmail.com
426.	Ms. Jayanti K. Ramani (Lakdawala) jklakdawala@gmail.com
427.	Shri Jayapal Balaji, balaji211190@gmail.com
428.	jayaprakash2071975@gmail.com
429.	jayaprakashkarthick28@gmail.com
430.	jayasamy57@gmail.com
431.	jeba.embassy600100@gmail.com
432.	jebajulians@gmail.com
433.	Shri Jeferry Rebello, President, United Planters Association of Southen India (UPASI), Coonoor, Nilgiris, Tamil Nadu
434.	Shri Jegan Raj, jegannivash0007@gmail.com
435.	Shri Jeganathan S., jeganathan 1170@gmail.com
436.	Jesufair Environmental Activist, jesufair@gmail.com
437.	Shri Jeya S, jeyasribalan@gmail.com
438.	jeyagopal784@gmail.com
439.	Shri Jeyaraj, jeyamjeyaraj1999@gmail.com
440.	Shri Jodi Rodar, 223 North Valley Road, Pelham
441.	Shri John Mark Pena, President, Hmar Students' Association, HSA Campus, Muolhoi, Haflong, Dima Hasao, Pin-788819
442.	Shri John paul, johnpaulmaria0@gmail.com
443.	Shri John Peppin, johnpeppin1974@gmail.com
444.	Shri Jon Botham, bothamj50@gmail.com
445.	Shri Jose Carlos Da Veiga Gracias, 54 Borda Fatorda Goa 403602 zecarlos@rediffmail.com
446.	Shri Joseph D'costa (Indian Citizen) joseph.dcosta@3i-infotech.com
447.	Shri Joseph Hoover, Former member, State Board for Wildlife, Karnataka, Independent Senior Journalist joehoover60@gmail.com
448.	joshuajackrio@gmail.com
449.	Ms. Jothimageswari R, prasan4p@gmail.com
450.	jsugumaran7@gmail.com

Sl. No.	Name
451.	Shri Jubaraj Dharua, AT Barakani, P.O. Jamkhunta, <i>Via-</i> Sindhekela, Dist-Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
452.	Shri Juheb Jhony, Barak, Assam juheb5@gmail.com
453.	juliyamass@gmail.com
454.	Ms. Jyoti Pande Lavakare pande.jyoti@gmail.com
455.	Jyoti Pande Lavakare, pchopra@dpncglobal.com
456.	Shri Jyotiraditya Chillal, Gandhinagar-411041, Narayanpet jyotiradityachillal2020@gmail.com, info@jhatkaa.org
457.	Shri K .Jagadeesan Dhana jagadeesan.jd0804@gmail.com
458.	Shri K Suresh Nayak, Member, NECF, Mangaluru, Karnataka ksureshnayak@rediffmail.com
459.	Shri K. Elumalai, elumalai.logu@gmail.com
460.	Shri K. Johnson, kjohnson1101990@gmail.com
461.	Shri K. Murugesan, mchellathambi@gmail.com
462.	Ms. K. Rajalakshmi, mahamahalakshmi953@gmail.com
463.	Shri K. Silamabarasan, gurutraders75@gmail.com
464.	Shri K. Silamabarasan, simbustr9629@gmail.com
465.	Shri K. Silambarasan, saisimbu4450@gmail.com
466.	Shri K. Venkatesh, k1995@gmail.com
467.	Shri K. Venkatraman, General Secretary – Thamizh Thesiya Periyakkam, (Thamizh National Movement), SP – 10 / 34, First Sector, Third Street, First Floor, Kalaignar Karunanithi Nagar, Chennai – 600 078.
468.	Shri K. Vijayakumar, vijaysha79@gmail.com
469.	Shri K. Yuvaraj, yuvrajuv591@gmail.com
470.	Shri K.A.S.S.Rahman shafiq7441@gmail.com
471.	Shri K.M. Kajendiran, NTK MEMBER, kajendiran2114@gmail.com
472.	Shri K.Nuagan Gramsabha, PS-Brahmanigam, District Kandhamal, Odisha sauravbaliarsingh2@gmail.com
473.	k.u.guru8897@gmail.com
474.	Shri Kaartikeyan, Vellore, novanavkarthik@gmail.com
475.	Shri Kailash. S, kailash.gold@gmail.com
476.	Shri Kalaigukan Mathivanan, kalaigukan33@gmail.com
477.	Shri Kalaimani, kalai19641992@gmail.com
478.	Shri Kalaimaran A, 302 A Harihar Residency, Tiruchi-620020
479.	Shri Kalaivendan J, kalaivendan2323@gmail.com
480.	Shri Kalidadan, kalidasanthamizhan@gmail.com
481.	Shri Kalimuthu S esskayashok147@gmail.com
482.	kaliyappanmsk@gmail.com
483.	Shri Kalpavriksh kalpavriksh.info@gmail.com
484.	Shri Kamal Rathi, Naturalist and Conservationist, kamalrathi20@yahoo.co.in
485.	Ms. Kamali Sudhakar, mounisudha980@gmail.com

Sl. No.	Name
486.	kamankathir944@gmail.com
487.	kamarajmugesh@gmail.com
488.	Shri Kameswar Majhi, At- Kadalipali, PO Mahakhand, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
489.	kanagagomathi9@gmail.com
490.	Shri Kankani Pdar, Gram Sabha, GP-Malisira, District Balangir, Odisha
491.	kapadavel@gmail.com
492.	Shri Karan Bhure, Tatya Tope Nagar Nagpur -440015 Karanbhure599@gmail.com, info@jhatkaa.org
493.	Shri Karn Debara, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharua@gmail.com
494.	Kartas Gramasabha, Post-Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057
495.	Shri Karthi, <u>karthipoonga2001@gmail.com</u>
496.	Shri Karthick, j.karthick9500787385@gmail.com
497.	Shri Karthick Manickam, No. 46/52 Valluvan Street, Chennai -600012
498.	Shri Karthick R, karthick2988@gmail.com
499.	Shri Karthik, youngpolitician7@gmail.com
500.	Shri Karthik M, mpkarthikeee@gmail.com
501.	Shri Karthikeyan S, Kanchipuram, karthikiyammal@gmail.com
502.	karthikeyan.r2k18@gmail.com
503.	karthikpheonixxx@gmail.com
504.	karthiktamilanda95@gmail.com
505.	Shri Kartik Lunge, Raheja vistas, near Royal Heritage mall, Pune-411060
506.	karunatattooartist@gmail.com
507.	kasavankasavan20@gmail.com
508.	kash4277@gmail.com
509.	kathirstudio1990.kk@gmail.com
510.	Shri Kaushalendra Kumar Jha IFS (Retd) Former PCCF, Uttar Pradesh
511.	Shri Kavidasan P, 1, Govindraj Street demallows Road Choolai-600112, Chennai
512.	Shri Kavin, <u>kavinmuthusamy2003@gmail.com</u>
513.	kavinkumark242003@gmail.com
514.	kavisathya.65@gmail.com
515.	Ms. Kavita Mehta, Executive Director, Sahjeevan, 175-Jalaram Society, B/h. Vishwamangal Apartment, Vijaynagar, Bhuj 370 001 Kachchh, Gujarat, INDIA
516.	Ms. Kavitha Devi Anbazhagan, Radhanagar Main Road, Chennai-600044 drkavitha20188@gmail.com, info@jhatkaa.org
517.	Shri Kaviyarasan N., kaviyarasann6150eee@gmail.com
518.	kayalyaal@gmail.com
519.	Shri Kaza Ramana Prasad, Yapral, Hyderabad-500087 info@jhatkaa.org
520.	Shri Keerthivasan T, New Colony Street Keezh Edaiyalam, Tindivanam -604302 keerthivasan1209@gmail.com, info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
521.	Shri Kesar Singh, Social worker and resident Village Kot, Dist. Faridabad, Haryana
522.	Shri Keshav Jangid, Near Neelkanth public school, khari kothi mohalla, Dausa-303303
523.	Ms. Ketaki Patil, kvp.ketaki@gmail.com
524.	kezhi.kavai@gmail.com
525.	Khadakpada Adivasi Gaothan Main Pump House, Aarey Milk Colony, Goregaon East, Mumbai- 400065, Maharashtra.khadakpada65@gmail.com
526.	Khajuri Sahi Gramasabha At-Khajuri Sahi, Po-Badapalli, <i>Via</i> -Khallikote, Dist-Ganjam, Odisha, Pin-761029 padmalaya103@gmail.com
527.	Khandyanal Gramsabha At-Khandyanal, Po-Badapalli, <i>Via</i> -Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
528.	kidjeeva@gmail.com
529.	kishoremidas43@gmail.com
530.	koretikoya750@gmail.com
531.	Kovilpatti Forest Rights Committee, Nilgiris Dist. Masinagudi Post-643223, Tamil Nadu
532.	kpramod249@gmail.com
533.	Shri Krishna Chandra Chattar, Rastriya Adivasi Ekta Parishad, District President/Co-ordinator, District-Keonjhar, Odisha
534.	Shri Krishna Kumar D, Periyar Nagar- 626203, Sattur krish97.jsaa@gmail.com, info@jhatkaa.org
535.	Shri Krishna Prasath G, Naam Thamizhar Katchi – Chennai, krisnaa.san@gmail.com
536.	Shri Krishna Raj, Jeeva Nagar, 605602 Villupuram, krishna.ishna81@gmail.com, info@jhatkaa.org
537.	Ms. Krishna Valli M, rkff542@gmail.com
538.	krishnagunal51@gmail.com
539.	Shri Krishnan Nimmathi, 889, Malligai St, Anbarasu Nagar, Poonamallee-600123
540.	Ms. Kriti Mehra, Malad W, Mumbai-400064 info@jhatkaa.org
541.	Shri Krunal Bhagat, Achole Road, Nalasopara East, Maharashtra -401209 Vasai
542.	Shri Kshetramohan Majhi, AT Pingalmunda, P.O. Ghunasar, Via- Khaprakhol Dist Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
543.	Shri Kuldip Singh, Member of Rashtriya Adivasi Ekta Parishad (RAEP), District Unit Mayurbhanj, Odisha At:— Kukudakhumpi, PO:— Kuchei, PS:— Kuliana, Dist:— Mayurbhanj, State:— Odisha, Pin: 757105
544.	kumar7477@gmail.com
545.	kumarmanikandan270@gmail.com
546.	kumarsuresh85952@gmail.com
547.	Kutani Jhoran Gramsabha, GP-Gudighot, District Balangir, Odisha keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
548.	Shri Kuttalam, kuttalam07@gmail.com
549.	Shri L J Raj, blesstou2014@gmail.com
550.	Shri L Kumar, Vyasar Nagar 6th Street, Vyasarpadi, Chennai -600039 sannathkumar49471@gmail.com info@jhatkaa.org
551.	Shri L. Senthilkumar, senthilkumar15433@gmail.com
552.	Shri Lakapati Bag, AT-Gudramunda, P.O. Kuibahal, Via- Turekela, Dist Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com

Sl. No.	Name
553.	Shri Lakhia Sabar, padmalaya103@gmail.com
554.	Shri Lakshmanakumaran Kumaran, 175/176, Radhakrishnan Nagar, Avaniapuram Byepass Road, Madurai-625012
555.	Shri Lakshmanan R, vnslaxman@gmail.com
556.	lakshmipathi111995@gmail.com
557.	lal392283@gmail.com
558.	Ms. Lalita Premsila Lakra, Block-lathikata, Vill-Birkera, District -Sundagarh (Odidhsa) lalitalakra236@gmail.com
559.	Shri Lalringhnem Pulamte, Secretary, Hmar Women's Association, Assam Hills Region, Hqr Muolhoi, Haflong, Assam
560.	Shri Lalrothang Thiek, General Secretary, Hmar Youth Association N. Chills Joint Headquarters Muolhoi, Haflong, hyanchjthqrs@gmail.com
561.	Shri Latasahada, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha keshabdharua@gmail.com
562.	Shri Laxmidhara sahoo, ddtcoordinator@gmail.com
563.	leelaa1234@gmail.com
564.	Ms. Leona Delphi, leonadelphi@gmail.com
565.	lokendrasoren4699@gmail.com
566.	Shri Lochan Bariha, on Behalf og Barla Gram Sabha, AT - Barla , P.O. Ghunesh PS-Turekela , Dist. Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
567.	loguraja302@gmail.com
568.	lokakavi@gmail.com
569.	lokendrasoren4699@gmail.com
570.	Shri Lokesh P., No. 6/2, Ashok Nagar, 600083 Chennai
571.	Ms. Lona Yvette Fernande, Goa
572.	Shri S. Shiva, sivajudo1990@gmail.com
573.	lurthulaisington@gmail.com
574.	Shri M Karthik, karthikmsk76@gmail.com
575.	Shri M Kavin, naamtamilaryoungsters@gmail.com
576.	Shri M Nishar Ahamed, thennurnishar@gmail.com
577.	Shri M. Palaniswami, nandhinistudioslm@gmail.com
578.	Shri M. Antony Stephen antonystephen9610@gmail.com
579.	Shri M. Anand, joypremanand@gmail.com
580.	Shri M. Baskaran, bossmani750@gmail.com
581.	Shri M. Gopalsami, Muthumari Amman, Kovil Keela, Velipalaoam, Nagapatinam
582.	Shri M. Isai Desan isaithesam@gmail.com
583.	Shri M. Jeeva, selvamselvammv@gmail.com
584.	Shri M. Kaja kajavrs1@gmail.com

Sl. No.	Name
585.	Shri M. Kathiresan, msamykathir@gmail.com
586.	Shri M. Kesavan newqueensmobiles@gmail.com
587.	Shri M. Lakshamanan, lakshmananl685@gmail.com
588.	Shri M. Mohamed Kani, kanisfi1012@gmail.com
589.	Shri M. Muthukrishnan, muthukrishnanmmuthu@gmail.com
590.	Shri M. Muthukrishnan, muthukrishnan501@gmail.com
591.	Shri M. Pandian, Presidient, Theni District Farmers Union, Periyakulam, Tamil Nadu mvetrivelformer1984@gmail.com
592.	Shri M. Prabaharan, prabakarandhilipan@gmail.com
593.	Shri M. Prabhakaran, mprabhasurya333@gmail.com
594.	Shri M. Sathish, sathish4181@gmail.com
595.	Shri M. Sathishkumar, sathishkumar_tms@yahoo.in
596.	Shri M. Subramanian, Secretary, Maramalai Planters Association, Vivekanandan Street, K.P. Road, Nagarcoil-629001
597.	Shri M. Venkatesan, venkatesanmurugaiah73@gmail.com
598.	Shri M. Antony Stephen antonystephen9610@gmail.com
599.	Shri M. Asisa mafil8745@gmail.com
600.	Shri M. Kesavan
601.	Shri M. Deepan, deepan90ns@gmail.com
602.	Shri Madan Sharma, madanlal.sharma92@gmail.com
603.	Shri Mahesh Kumar BN mahesh.kumarbn61@gmail.com
604.	Shri Maheswar Dharua, on behalf of Sanbanki Gram sabha, District- Balangir, Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
605.	Shri Malarvizhi Ekambaram, 10/17A, 8th Street, B.V. Nagar, Pazhavanthangal Chennai -600114, Tamil Nadu
606.	Shri Maneck Kapadia, Havelock Rd., Camp, Belgaum-590001
607.	Shri Mangilal Gujjar, Jangal Jamin Jan Andolan, mlgurjar@gmail.com
608.	Shri Mani, tamilgooogle@gmail.com
609.	Shri Manian NTK, k.maniyan64@gmail.com
610.	manickakandasamy@gmail.com
611.	manieie.maran@gmail.com
612.	Shri Manika Sabar ( Village President), padmalaya103@gmail.com
613.	Shri Manikandan K K, maniajith8582@gmail.com
614.	Shri Manikandan Kuppusamy, kpm.manikandan@gmail.com
615.	Shri Manikandan S, r15.manikandan05@gmail.com
616.	Shri Manikandan M, manimahi006@gmail.com
617.	manimalai00315@gmail.com
618.	Shri Maninder Singh seekerstrail@gmail.com
619.	Shri Manish Ghurde, Amravati-444607 ghurdemanish50@gmail.com, info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
620.	manisuku07@gmail.com
621.	Ms. Manjushri mranjushrisavadi@gmail.com
622.	Shri Manohar chauhanmanohar@gmail.com
623.	Shri Manoj Negi, Brothers Apartment, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092 negi2u@gmail.com, info@jhatkaa.org
624.	Shri ManojKumar, manojindian912@gmail.com
625.	Shri Mansoor Ali, ma8648950@gmail.com
626.	manuelkr66@gmail.com
627.	Marad Gramasabha, Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com
628.	Shri Marcos Agostinho dos Santos marcosdossantos@yahoo.com
629.	Shri Margaret Viegas, (Indian Citizen) margaretviegas10@gmail.com
630.	Shri Maria do Carmo Fernandes mariadocarm@hotmail.com
631.	Shri Maria Jacinta de Silva (Indian Citizen) jacintasmseducator@gmail.com
632.	Shri Maria Jegan, Estimation Supervisor, ZIMIPCO Dammam, K.S.A., jegan.susai@icloud.com
633.	Shri Mariappa T, mariappanadar1@gmail.com
634.	Shri Mariappan, bestjoy321@gmail.com
635.	Shri Mariya Bakiya Raj, rarayaraudo@gmail.com
636.	Shri Mariya Mary Joseph, Mundoor h, Panathady. P.O., Cherupanathady, Kasaragod-671532
	mariyamaryjoseph888@gmail.com info@jhatkaa.org
637.	Shri Mariyamuthu M, mmathan8@gmail.com
638.	massmano604@gmail.com
639.	Shri Mathan Kumar, Jailaniyastreet 6th Cross, Subramaniapuram -620020, Trichy
640.	Shri Mathan Muthuswamy, 22-12, Ananthapadmanabhapuram-629901, Nagercoil
641.	Shri Mathavan M, mathavanngo@gmail.com
642.	Shri Mathumitha Sathiyamoorthy, MCA, madhusathya0806@gmail.com
643.	Shri Mayank Mikhail Mukherjee, Advocate, Chambers of Mayank Mikhail Mukherjee, B6/58, Terrace, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110 029
644.	Mayurbhanj Jungle Manch, AT-Jyotipur, P.O. Goudadiha, Baripada, Mayabhan-757003, Odisha onlinecentre7@gmail.com
645.	Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Village - Devdungri, Post - Barar, District - Rajsamand, Rajasthan, India - 313341, mkssrajasthan@gmail.com
646.	Ms. Meenakshi Kapoor and Ms. Krithika A Dinesh, Independent Environmental Researcher meenakshi.em@gmail.com
647.	Ms. Meenal Tatpati, Salisbury Park, Pune-411037 meenaltatpati@gmail.com info@jhatkaa.org
648.	Ms. Meera meera.rajesh@gmail.com
649.	Shri Melvi Fernandes, (Indian citizen) melvifernandes@gmail.com
650.	Shri Mervin, mervinjsm@gmail.com
651.	Shri Mervyn Vales, merwynvales@gmail.com

Sl. No.	Name
652.	Minapur Gramsabha At-Minapur, Po-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
653.	Minjapanka Gramasabha, saratmalick306@gmail.com
654.	Shri Mirona Afonso (Indian Citizen) maura711afonso@gmail.com
655.	Shri Misbah Qureshi, 403/A Wing Kshitij Building, Mumbai-400016
656.	Shri Mo Haroon, 4, Kasturi Bai Street, Chennai-600094
657.	Shri Mohamed Shareef, mohamedshareef0128@gmail.com
658.	Mohamed Shareef, mohamedshareef1995@gmail.com
659.	Shri Mohamed Siddiq, tamilann1976@gmail.com
660.	Shri Mohamed Thajudeen, taj987@gmail.com
661.	Shri Mohan M, mohan.m909@gmail.com
662.	Shri Mohanam, mohanamhema@gmail.com
663.	mohenkumar1961@gmail.com
664.	Ms. Monisha V, kanchiseemanadhithyan@gmail.com
665.	Shri C. Lalaji, lalaji84@gmail.com
666.	Shri Durai themotherkpn6@gmail.com
667.	Shri Edwin Jayakumar, edvinj92@gmail.com
668.	Shri Joseph Sequeira Calangute joseph.sequeira@casaseverina.com
669.	Shri D.A. Narayanan ( Serve a Tribe ) ADVOCATE, Coimbatore 312, Lawyers Chambers District Court complex, Gopalapuram, Coimbatore – 641018, Tamilnadu State
670.	Ms. Fatima Fernandes, Siolim-Bardez, Goa fatimasiolim@gmail.com
671.	Ms. Peruma, Naam Tamilar Party, Tamilnadu, perumasekar24@gmail.com
672.	1. Ms. Prerna Singh Bindra, Former member, Standing Committee, National Board for Wildlife, Former member, State Board for Wildlife, Uttarakhand, PhD Scholar, University of Cambridge.
	2. Ms. Prakriti Srivastava, IFS, Principal Chief Conservator of Forests, Kerala bindra.prerna@gmail.com, prakritii_2000@yahoo.com
673.	Ms. Bhagyashree Panchaly, Pancholy House, PP Singhal Marg, Udaipur, Rajasthan
674.	Ms. Qaneez Sukhrani, Convenor - Association of Nagar Road Citizens Forum, A/3 Hermes Drome CHS Ltd., S.no.211/3/1B Viman Nagar, Pune 411 014
675.	Ms. Shubhda Deshmukh, Dr Satish Gogulwar, Convener, Amhi Amchya Arogyasathi arogyasathi@gmail.com
676.	msrinidpintk@gmail.com
677.	mukesh2k1@rediffmail.com
678.	Shri Mukilan Manikandan, Thelepan Street, P. Vadugapalayam, Palladam-641664 mukilanjm@gmail.com, info@jhatkaa.org
679.	Shri Mukund V Mavalankar, mukund.mavalankar@gmail.com
680.	Shri Munindra, IFS (retd) munindra47@gmail.com
681.	Shri Murali Kumar K, T.N, Ranipet, kmurali.ind@gmail.com
682.	muralidharanemail@gmail.com
683.	muruganmuruga5659@gmail.com

Sl. No.	Name
684.	murugesansantha3@gmail.com
685.	mushroommahe@gmail.com
686.	musicaddict286@gmail.com
687.	musicianjabezrio2001@gmail.com
688.	Ms. Muskan Agarwal, Malviya Nagar Delhi, Delhi-302017 muskanagarwal2615@gmail.com, info@jhatkaa.org
689.	Shri Muthu, muthusamy1593@gmail.com
690.	Shri Muthu Kumaran, muthu.mk4@gmail.com
691.	Shri Muthu Veerasamee, itsmeveera8@gmail.com
692.	Shri Muthukrishnan Uthaman, Thirunagar-625006, Madurai
693.	Shri Muthukumar Gurusamy Kadavur, Mayilampatti-621301 info@jhatkaa.org
694.	Shri Muthukumar S, sivasamymdr@gmail.com
695.	Shri Muthukumar V, muthukumar.v96@gmail.com
696.	Shri N Alagu Ponnirul, alaguthamilan74@gmail.com
697.	Shri N K, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 knatesa@gmail.com info@jhatkaa.org
698.	Shri N.K., 560082 Bengaluru raghavnk@gmail.com, info@jhatkaa.org
699.	Shri N. Udaya, Member of NECF, Mangalore udeeachar@gmail.com
700.	naamtamilar.sam@gmail.com
701.	Shri Nagaraj H Shettar, 1st cross, park extension, Durgigudi, Shivamogga, Karnataka -577201
702.	Shri Nagaraja Koove, Ganapathikatte, Koove Post MudigereTaluk, Chickamgalur District
703.	Shri Nagesh S.V., 'Navyasgree', 100ft Road, Vinayaka Nagara, Shivamogga-577201
704.	Shri Nakul Bariha, AT -Khuripani, P.O Rengali, Via- Khaprakhol, District Balangir zindabadsangathanbgr@gmail.com
705.	Ms. Namrata Das, J-78/2, Pandav Nagar, Opposite Mother Dairy, New Delhi-400061
706.	Shri Nandha Kumar, Asf3 Barathi Avenue 1st cross street New Perungalathur Tamilnadu, Chennai-600063
707.	Shri Narasimma, officialnarasimma@gmail.com
708.	Shri Narendra Armor, President, Forest Right Committee, Village- Morga, Post- Morga, Tahsil- Podi, District- Korba, Chhattisgarh
709.	Shri Naresh B, Thiruvanmaiyur- 600018 Chennai naresh.endless@gmail.com, info@jhatkaa.org
710.	Shri Naresh Jamatia, President, Radhacharan Debbarma, General Secretary, GMP, Tripura. nareshjamatia@gmail.com
711.	Ms. Natarajanjothi, M.Com, nata6ajan777@gmail.com
712.	Shri Nathiya Raman, 16/27 Meenakshipuram-629301, Aralvoimozhi
713.	National Alliance on CFR and MFP, C/o Dr. Kishor Moghe, 19 Vishal Nagar, Moha, Dhamangaon Road, Yavatmal, Maharashtra- 445001
714.	Shri Navaneethakrishnan S, navakrish@outlook.com
715.	Shri Naveen Kumar H C, Hadinaru Village and Post Chatra Hobli Nanjangud, Thaluk Mysore, district, Mysore-571302 naveenkumarhc333@gmail.com info@jhatkaa.org
716.	naveenkumarnk1712@gmail.com

Sl. No.	Name
717.	naveensivakumars6120@gmail.com
718.	Shri Navin, navin774433@gmail.com
719.	Shri K. Navinrajan, k.navinrajan23@gmail.com
720.	Shri Nawinrajtamiz, nawinrajtamizha@gmail.com
721.	Ms. Neela Dhavale neela.dhavale@gmail.com
722.	Ms. Neelam Ahluwalia Nakra, Co-Founder and Trustee, Aravalli Bachao Citizens Movement aravallibachao.team@gmail.com
723.	Shri Neenu Somaraj, Sreevalsam, Parippu, P.O. Kottayam, Kerala
724.	Ms. Nelisha Trindade, Goa ,Candolim, Mapusa-403515
725.	nilavucomputers@gmail.com
726.	Shri Niruban Chakaravarthy, No.8/30A Mettu Street Agraharam Korattur Chennai - 600076
727.	Shri Nishikant Jadhav, Nishikant Bhaskar Jadhav At post shirgaon tehsil Deogad District Sindhudurg-416610, Maharashtra spredlove.999@gmail.com info@jhatkaa.org
728.	Shri Nithin K M, Prestige Willow Tree, Vidyaranyapura, Bangalore-560097 nitkm88ster@gmail.com info@jhatkaa.org
729.	Shri Nitin Shinde, neetinlic@gmail.com
730.	Shri Nityan and Shri Jayaraman, S45, 35th Cross, Besant Nagar, Chennai-600090
731.	Shri Nivaas Sudhan, C403, Coimbatore-641041 shrinivaasanln@gmail.com info@jhatkaa.org
732.	nramarvijay@gmail.com
733.	Shri NTK Ranipet, naamtamilarkatchiranipettai@gmail.com
734.	ntkssptupnorth@gmail.com
735.	Shri Nu Nizaam Ahmad, nijamfirtho999@gmail.com
736.	Nuapalli Gramsabha At-Nuapalli, PO-Badapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029 padmalaya103@gmail.com
737.	Shri Om Rane, 12, Raigad Society, Mumbai-400078
738.	on behalf of Area Sabha Association of Pune (ASAP) asapcitizens@gmail.com
	1. Ms. Swapna Narayan, Co-ordinator,
	2. Shri Ravindra Sinha, Member,
	3. Ms. Vaishali Patkar, Member,
	4. Shri Makarand Shende, Member,
	5. Ms. Hema Chari, Member,
	6. Shri Akhilesh Bhandari, Member
	7. Shri Satya Natarajan, Member
739.	oneshotphotographysvks1@gmail.com
740.	Our Race, visinaa048@gmail.com
741.	Shri Oviyan K, 1 ayothidhasar nagar, Madurai-614154
	oviyankanna@gmail.com info@jhatkaa.org
742.	Shri P Mallikharjuna Rao,Hyderabad pmkrao72@gmail.com
743.	Shri P. Pasupathy, agpasupathy@gmail.com

Sl. No.	Name
744.	Shri P. Prakash, prakasharasu123@gmail.com
745.	Shri P. Raghuveer, it4dss@gmail.com info@jhatkaa.org
746.	Shri P. Raghuveer, Flat No. 205, Sri Tirumala Prestige Apartments, Hill Top Colony, Erramanzil, Hyderabad - 500 082
747.	Shri P. Tamilselvam., Rtd. PSU officer, Vellore,
	selvamtamil.bsnl@gmail.com
748.	Shri P. Thiruvalluvan, p.thiruvalluvan1@gmail.com
749.	Shri P. Thiruvalluvan, pthiruvalluvan9@gmail.com
750.	Shri P. Vasanth Raj, Salem, Tamilnadu, vrgarlands@gmail.com
751.	Shri Pa. Bharatirajaa, bharathirock37@gmail.com
752.	Shri P.A. Kalidhasan palaiyankalidhasan@gmail.com.
	kalidhasanpalaiyan@gmail.com
753.	Shri Padmanagarajan, cobraking1993@gmail.com
754.	Shri Pagala Prudhvi, Ganganagunta- 517507, Tirupati
	prudhvipower.pp@gmail.com info@jhatkaa.org
755.	palanisamy.mayavan1953@gmail.com
756.	pandieswaran186@gmail.com
757.	Shri Pandiyan, pandiyanindiacyr@gmail.com
758.	Shri Pankaj Singh, A Narayanapura, Bengaluru-560016
	pankajking04@gmail.com info@jhatkaa.org
759.	Shri Partha Sarathy, Mylapore- 600004, Chennai
	ramcinema9@gmail.com, info@jhatkaa.org
760.	Shri Pasupathy, tpasupathy1@gmail.com
761.	Patiasil Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput, Odisha, Pin-764057 deepakgonda68@gmail.com
762.	Shri Pavan Kumar, #21,1st Cross Kenchenahalli, Rajarajeshwari Nagar-560098
763.	Shri Pavan Kumar, Electronic City-560100, Bangalore,
	pavangrandhi123@gmail.com
764.	periyasamypsy@gmail.com
765.	Shri Peruamal, Gram Sabha, GP-Haldi, District Balangir, Odisha, keshabdharuakeshabdharua@gmail.com
766.	perumallakshmana67@gmail.com
767.	perumasekar24@gmail.com
768.	Phasikhol Gramsabha AT-Phasikhol, P.OBadapalli, Via-Khallikote, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761029, padmalaya103@gmail.com
769.	Shri Phuduku Sabar, on behalf of Mudakani Gram Sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
770.	pkpratna@gmail.com
771.	Shri Ponnuppandian, ponnaiyathevan457@gmail.com
772.	Shri Ponnusamy S, 32, Kannimar Kovil Pudur-638661 Tiruppur

Sl. No.	Name
773.	ponraja3007@gmail.com
774.	Shri Poonam Saini, Landscape Architect and Research Scholar, poonam.phd261la20@spa.ac.in
775.	Shri Pounvel, velpounvel@gmail.com
776.	powerparasu2@gmail.com
777.	Shri Prabakaran Veera Arasu, Poovulagin Nanbarkal (Friends of Earth), 12th Street, Vaigai Colony, Ashok Pillar, Chennai-600083
778.	prabakarandhilipan@gmail.com
779.	prabakarankannan881@gmail.com
780.	Shri Prabhakar Thayumanavan, pat.rawlinsons@gmail.com
781.	Shri Prabhakaran Veeraarasu, Ramakrishna Nagar-600048, Chengelpet, prabhakaranenvi@gmail.com info@jhatkaa.org
782.	Shri Prabuddha Gaikwad, Solapur-413004,
	prabuddhagaikwad01@gmail.com info@jhatkaa.org
783.	Shri Pradeep Arjunan, Denalai, Coonoor-643102,
	pradeeparjunan.nk@gmail.com info@jhatkaa.org
784.	Shri Pradeep Ghumare p_ghumare@yahoo.co.in
785.	Shri Pradeep Kumar G, urspradeep86@gmail.com
786.	Shri Pradeep Mokardkar, President, Poinguinkarancho Ekvott judas.barreto1967@gmail.com
787.	Shri Pradeep S, pradee.sp.94@gmail.com
788.	Shri Pradeep Singh, Advocate, District Bar Association, Chamoli (Gopeshwar), Gram- Sagar, Post- Gwad Devaldhar, District – Chamoli, Pin- 206401.
789.	Shri Pradip Chatterjee, National Convener, NPSSFW
	npssfw@smallscalefishworkers.org
790.	Shri Pradip Kumar Mahapatra, General Secretary, Paschimbanga Vigyan Mancha, 162-B, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata – 700 014
791.	Shri Pradyumna Behera, on behalf of Community Network Against Protected Areas (CNAPA)
792.	Shri Prakaran Veeraarasu, on behalf of Poovulagin Nanbargal
793.	Shri Prakash Manivel, Thular east street, Sendurai-621719, Ariyalur
794.	Shri Prakash Shrivastava, D-270, Old Minal Residency, Bhopal-462023 prakritii_2000@yahoo.com
795.	prakashking561@gmail.com
796.	Prakriti Banchao Adivasi Banchao Mancha, Ajodhya Hill, District - Purulia West Bengal, prakritibanchaoadivasibanchaom@gmail.com
797.	Ms. Prakriti Srivastava, I.F.S, PCCF, Kerala Forest Department
798.	Shri Pranab Doley, Assam, JA Shivu, Karnataka, Pradyumna Behera, Odisha, Sharanya Nayak, Odisha, OSR Rajaraman, Tamil Nadu
799.	Shri Pranav Kalra, 4, Bamroli Road, Godhra-411045, pranavkalra66@gmail.com info@jhatkaa.org
800.	Shri Pranav Takkar, Pandit Parth Extension, Delhi-110051, pranavtakkar510@gmail.com info@jhatkaa.org
801.	Ms. Praneti Lawange, pranetilawange@gmail.com
802.	Shri Prasadkumar GM, Byndoor Udupi District

Sl. No.	Name
803.	Shri Prasanna Hial, on Behalf of Gadagada bahal Gram sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
804.	Shri Prasanth D, prasanthdeep8@gmail.com
805.	Shri Prasanth Muthuraman, 1/680, Sivasakthi Nagar, Pamban-623521
806.	prasanth1601n@gmail.com
807.	Shri Prasath Renganathan, Manjanviduthy, Pudukkottai-622303
808.	Ms. Pratibha R, pratibha.rk@gmail.com
809.	Shri Praveen, romalan.june@gmail.com
810.	Shri Praveen Bhargav, Trustee - Wildlife First, Former Member - National Board for Wildlife, Author-Wildlife Law for Rangers wildlifefirst@gmail.com
811.	Shri Praveenkumar R, praveen.r608612@gmail.com
812.	Shri Pravin Mathew, Plot No. 326/327,G2, Baba Nagar 2nd Main Road, Villivakkam- 600049, Chennai
813.	Shri Pravin Mote pravin.mote.cpc@gmail.com
814.	Shri Pravinsingh Shedgaonkar, pravinsingh03@gmail.com
815.	Shri Premkumar D, Oomerabad, Ambur-635808,
	premkumar19be@gmail.com
816.	Shri Premkumar R premkumarnellai@gmail.com
817.	President, Jangle Adhikar Committee, Bandhabhuin, Jhillimili,
	mundakande40@gmail.com
818.	President/Secretary, National Environment Care Federation (NEFC), Mangalore, Karnataka
819.	Shri Prince Nadar, chelliahv7@gmail.com
820.	prithiselva@gmail.com
821.	Ms. Priya Kumari, Dharamapuri-636906, Tamil Nadu,
	ranipriya9745@gmail.com, info@jhatkaa.org
822.	priyaalemane@gmail.com
823.	Ms. Priyadarshini J, 560085 Bangalore, info@jhatkaa.org
824.	Ms. Priyanka Gunjikar, 4, Vrindavan society, Near Mhatre Bridge, Pune -411030
825.	Ms. Priyanka Verma, Delhi-110001, info@jhatkaa.org
826.	Prof. Richard Hay, Ex MP, Asset Rangoli, 12 B, Maradu, Kochi-682304.
827.	Prof. (Dr.) Tejbir Singh Rana, Department of Geography, Shivaji College, University of Delhi, Delhi-110027
828.	Shri Pugal Suriya, suryapugal619@gmail.com
829.	Shri Pugal, suryapugal619@gmail.com
830.	Shri Pugazhanthi. M, ponp51593@gmail.com
831.	Pullikata Gramsabha, Odisha, phinyalata143@gmail.com
832.	Shri Purushothaman. N, Kumbakonam, Tamil Nadu, kelvin.purushoth@gmail.com
833.	Shri Pushkar Kulkarni ramanm764@gmail.com
834.	Shri Pushkar.V.Kulkarni D-901, Kapil Aasamant, Near Shivshakti chowk Pashan Sus road, Pashan, Pune – 411 021

Sl. No.	Name
835.	Shri Pushpa Lingam Padmaraj, padmarajpushpalingam@gmail.com
836.	pushparajdme6@gmail.com,
837.	pushparajr715@gmail.com
838.	R J Travels, No.1 MGR Street, 2nd Cross, Padhuvanchery, Chennai – 126, rraja.sekaran@rediffmail.com
839.	Shri R Prabakaran, prabakaranbsms@gmail.com
840.	Ms. R Swarnalatha r.swarnalatha@gmail.com
841.	Shri R. Anbarasan, aanbarasan552@gmail.com
842.	Shri R. Anbarasan, Naam Tamilar Party, Thanjavur District Secretary, anbuyalinianbu@gmail.com
843.	Shri R. Bhuvanendran Tirunelveli, nellainanban@gmail.com
844.	Shri R. Elango, r.elango125@gmail.com
845.	Shri R. Gopinathan, srvgopi@gmail.com
846.	Shri R. Gowtham, gowtham.pr002@gmail.com
847.	Shri R. Hariprasath, hariprasath985@gmail.com
848.	Shri R. Kannan, abrezbuilding@gmail.com
849.	Shri R. Sanjiv, Deputy State Secretary, Anti Bribe Wing, Naam Tamilar Party, kaiyootuolippu13@gmail.com
850.	Shri R. Siva, rsiva4407@gmail.com
851.	Shri R. Srinivasan, Sales Officer North Arcot Zone, SKM Siddha and Ayurvedics Pvt. Ltd., Vellore, s.srini1992@gmail.com
852.	Shri R.Mohan, Tamil Nadu, rm.mohan2010@gmail.com
853.	Shri R.Murugananatham, shavanshavan349@gmail.com
854.	Shri R.Sivaramakrishnan, sivanithe@gmail.com
855.	Shri R. A. Murugananda, shavanshavan349@gmail.com
856.	Shri Rabi Sabar, padmalaya103@gmail.com
857.	radhakrishnan662003@gmail.com
858.	raghu011989@gmail.com
859.	Shri Raj Kumar, 8/1, 13 solaiamman Kovil Street, Purasawalkam-600007
860.	Shri Raja C., poovairaja2012@gmail.com
861.	Shri Raja. M, North kattur, Trichy 19, rajaharini5050@gmail.com
862.	rajangreenaqua@gmail.com
863.	Shri Rajaram, rajacomputer2018@gmail.com
864.	Shri Rajaselvam M, South Boag Road, Chennai-600017
865.	Shri Rajavel. R, rajavel328@gmail.com
866.	Shri Rajeev Savant rajeev_savant@yahoo.com
867.	rajejayamani@gmail.com
868.	Shri Rajen Tudu, President, Bharat Jakat Majhi Pargana Mahal Juwan Mahal Purulia District rajentudu1973@gmail.com
869.	Shri Rajendra Thilahar, Chengalpet-603101, info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
870.	rajendranlic1964@gmail.com
871.	Shri Rajesh Gosalia, C- 314 Antophill Warehouse, Wadala East-400037 Mumbai
872.	Shri Rajib Baskey, Raghunathpur, Dahijuri, Binpur, Jhargram-721504, rajibbaskey 62@gmail.com
873.	Shri RajiniKanth B, rajini.rkn@gmail.com
874.	Shri Rajiv Gandhi, rajivgrk@gmail.com
875.	Shri Rajkumar Vellore, rajbhava10@gmail.com
876.	Shri Rajmohan Jegatheesan, 199, Lakeview Road West mambalam-600033, Chennai
877.	Rajpur Gramasabha, nuangabalanhadra@gmail.com
878.	Shri Raju K, 255, 5th cross st, Yeshwanth nagar, Madambakkkam, Tambaram- 600126
879.	Shri Ram Kumar. M, ram447495@gmail.com
880.	ramalingamsk86@gmail.com
881.	Shri Ramamoorthy, ramamoorthyabi3042@gmail.com
882.	Shri Raman, ramanm764@gmail.com
883.	Shri Raman
884.	Shri Ramanan Ganapathy, rini_4444@yahoo.com
885.	Rambuli Gramasabha, saratmalick306@gmail.com
886.	Shri Ramesh Sabar, padmalaya103@gmail.com
887.	rameshlp001@gmail.com
888.	Shri Ramkumar, sbramkumar1@gmail.com
889.	Shri Ramkumar B, s.b.ramcivil2828@gmail.com
890.	Shri Ranen Bhadra , 4/C Dhrubesh Chatterjee Lane, PO: Uzarpara, Pin: 712258 Dist: Hooghly
891.	Shri Ranjan Sabar (Village President), padmalaya103@gmail.com
892.	Ranpudi Gramsabha AT-Rampudi, Po-Pandiripada, Via-Polasara, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761105, padmalaya103@gmail.com
893.	Shri Rans, ranscatb@gmail.com
894.	rarayaraudo@gmail.com
895.	Rasaiya Rasa, rasaiyae@gmail.com
896.	Rastrya Advasi Ekta Parisad, Rourkela
897.	Shri Ravi Palanisamy, Mondipalayam, Bhavani-63831, mailravipkumar@gmail.com info@jhatkaa.org
898.	ravi.sankartheni@gmail.com
899.	Shri Ravichandran k, kraviad05@gmail.com
900.	Shri Ravina Raj Kohli ravinakohli13@gmail.com
901.	Shri Ravindra Nath Saxena IFS (Retd.), Former Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh Bhopal – 462026 (M.P.)
902.	Shri Ravindra Sinha, Flat no C-703, Camellia Apartments, Baner Pashan Link RoadPashan, Pune – 411 021
903.	Shri Ravindra Velip, H.No. 39/04, Velipwada Caurem Quepem, Goa
904.	Shri Ravivarma Kumarasamy, Kuruvikkarambai, Post Petavurani Taluk-614802, ravivarma.lk@gmail.com info@jhatkaa.org
905.	Shri Raymond, raymond.aj@icloud.com

Sl. No.	Name
906.	rganesh6196@gmail.com
907.	Shri Richardson Colaço, H. No 1545, Udden Shiroda, Ponda Goa
908.	Shri Rishabh Karade, Bibwewadi, Pune-411037,
	karadekailasmamta@gmail.com info@jhatkaa.org
909.	Shri Rishabh Pardeshi, House no 1165, Olkaiwadi, Lonavala-41040,
	ritzmillan@gmail.com, info@jhatkaa.org
910.	Shri Rishi Kant Chaudhary, Durg -491001, Chhattisgarh
911.	Shri Rishi Senthil, Karamadai, Chikkarampalayam-641104,
	senvai96@gmail.com info@jhatkaa.org
912.	Shri Rishi senvai96@gmail.com
913.	Ms. Ritanya, ddharan410@gmail.com
914.	Shri Ritwick, N-73 Lower Ground Floor, Greater Kailash 1,New Delhi
915.	rockfortnarayanan@gmail.com
916.	rocksampath84412@gmail.com
917.	Shri Rohit M, Tirupur-641652, info@jhatkaa.org
918.	Shri Rohit Menon, Mulund-West-400080, Mumbai,
	funkyduderohit@gmail.com info@jhatkaa.org
919.	Shri Rohit Pandit, Secretary General, Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), PHD House (3 <sup>rd</sup> Floor), 4/2 Siri Institutional Area (Opposite AsianGames Village), New Delhi – 110 016 (India).
920.	Shri Rohith, Udupi, Karnataka rohithworkstuff@gmail.com
921.	rohithdevaraj1@gmail.com
922.	ronikasm1102@gmail.com
923.	Shri Rooban, Coimbatore district Secretary, Naam Tamil Party, Environmental Wing, roobancbe@gmail.com
924.	Ms. Rosaria Pimenta, Convent of Jesus and Mary, Palanpur-385001, cjmv2009@gmail.com info@jhatkaa.org
925.	Roseipadar Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057, deepakgonda68@gmail.com
926.	Shri RP Ganesan BE, 268/2B2, Thennamplayam, Arasur PO, Sulur TK, Coimbatore DT, Tamil Nadu - 641407
927.	Ms. Rupa Majhi, on Behalf of Lahumunda Gram Sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
928.	Shri Rupadhar Bag, AT/PO Kuibahal, <i>Via</i> - Turekela, Dist. Balangir , Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
929.	Shri S Jothimani, Member of Parliament, Karur, Tamil Nadu jothimanimpoffice@gmail.com
930.	Shri S Karthick, karthick740@gmail.com
931.	Shri S Lohith, Vyasar Nagar 6th Street , Vyasarpadi , Chennai -600039, lohithkumar.s.1008@gmail.com info@jhatkaa.org
932.	Shri S Nagaraj, nr761982@gmail.com

Sl. No.	Name
933.	Shri S Srikanth, sricbi12@gmail.com
934.	Shri S. Arun, Subsistence Farming, arunkumar22077@gmail.com
935.	Shri S. Edward Xavier, sedxavi93@gmail.com
936.	Shri S. Jaya Prakash, sjayaprakash219@gmail.com
937.	Shri S. Kanojkumar, dawankanoj92@gmail.com
938.	Shri S. Kumar, natlinthara@gmail.com
939.	Shri S. Kumaresa Moorthy, s.kumaresan85@gmail.com
940.	Shri S. Kurlanda Gram Sabha, Post- Tarangada, District- Gajapati, Odisha
941.	Shri S. Mohith, home2office2016@gmail.com
942.	Shri S. Murugapandi, murugapandi877@gmail.com
943.	Shri S. Nandakumaar, nanthuanil9596@gmail.com
944.	Shri S. Prabakar, arulyps@gmail.com
945.	Shri S. Radhakrishnan, ntk148nakkambadi@gmail.com
946.	Shri S. Rajan, vnselvar17@gmail.com
947.	Shri S. S. Karthik, sskarthikmech@gmail.com
948.	Shri S. Sarathraj, rrksarathraj@gmail.com
949.	Shri S. Sharmi, sathishkumar_tms@live.in
950.	Shri S. Siva, sivajudo1990@gmail.com
951.	Shri S. Varun, State Joint Secretary of Environmental Wing in NTK, sssvarun22@gmail.com
952.	Shri S. Vetriselvi, Assistant Commissioner of GST Retired, Thanjavur, pranilathayus@gmail.com
953.	Shri S.Gnana Prathaban, killer.prathap@gmail.com
954.	Shri S.Gunasekaran, right2work6@gmail.com
955.	Shri S.Kumaran, Naan Tamilar Katchi (NTK), (Environmental Wing), Chennai, aquagreen2011@gmail.com
956.	Shri S.M. Selvakumar, selvakumarsm92@gmail.com
957.	s.u.madan1974@gmail.com
958.	Shri SA Arulraj Selvamarry, Sriperumbudur -602105, Vallam, arulfuel81@gmail.com info@jhatkaa.org
959.	Ms. Saanvi Roshan kurunji, Mangalore-574142, saanvikurunji5@gmail.com info@jhatkaa.org
960.	sabari.in.heaven@gmail.com
961.	sabarishbala420@gmail.com
962.	Ms. Sabita D'costa, (Indian Citizen), sabitadcosta24@gmail.com
963.	Sachin Dave, Shardanahar Society, Paldi-400058, Ahmedabad sachin.dave9@gmail.com info@jhatkaa.org
964.	Sachin Yadav, C-101, Tivoli ,Godrej City, Ahmedabad-380054 sachinbyadav@gmail.com info@jhatkaa.org
965.	Sadat Khan, Subedarpalya Yeshwantpur, Bangalore-560022 sadatkhan411@gmail.com info@jhatkaa.org
966.	Shri Sadhu Charan Jarika, dharambirhembram76@gmail.com
967.	Vetri, jaya98411@gmail.com
968.	Shri Sagnik Sengupta, Director, Stripes And Green Earth Foundation sagnik@sagefoundation.in
969.	Shri Sahadev S H, Paschima Ghatta Jaagruti Vedike, Shivapura, Koppa Taluk, Chickamgalur District

Sl. No.	Name
970.	Shri Sahadev Shivapura, Shivapura, Suryadevasthana Post , Chickmagalur District-Koppa-560062
971.	sahitya9750mathurkar@gmail.com
972.	saikailasam@gmail.com
973.	Shri Sajjan Bhajanka, President, Federation of Indian Plywood & Panel Industry, 404, Vikrant Tower 4, Rajendra Place, New Delhi – 110008
974.	Shri Sakani Podar, Gram Sabha, GP-Gudighat, District Balangir, Odisha, keshabdharua@gmail.com
975.	Shri Sakshi Khare, Banjara hills, Navi Mumbai-410206, itsmesakshi.khare@gmail.com info@jhatkaa.org
976.	Shri Sakthivel, shakthivelsjs@gmail.com
977.	Shri Sakthivel Duraisamy, Kamaraj Nagar-638301 Bhavani, dsvelavan@gmail.com info@jhatkaa.org
978.	Shri Samara Tudu, Manjhi Pargana Mahal, Keonjhar, Odisha-758001
979.	Shri Sambhav Jain, Nirman Vihar-110092, East Delhi, jainsambhav227@gmail.com info@jhatkaa.org
980.	Shri Samuel L Khobung, President, The Hmar Student Association, New Delhi.
981.	Shri Samy, adaikkalasamy@gmail.com
982.	Ms. Sandhiya Murugan, murugansandhiya087@gmail.com
983.	Ms. Sandra Fernandes, Sarpanch, Village Panchayat, Carmona, Goa
984.	Shri Sanjay Bramhane sanjaybramhane1968@gmail.com
985.	Shri Sanjay Kumar Srivastava, IFS (Retd) &, Praveen Chandra Tyagi, IFS (Retd), Formerly PCCFs (HoFF), Tamil Nadu
986.	Shri Sanjay. G, 21cs144@kpriet.ac.in
987.	Shri Sanjay. G, sanjay.gopalsamy2003@gmail.com
988.	Shri Sanjeev Gaur, IFS, CGM (Planning), Forest Development Corporation of Maharashtra Limited, Nagpur, Maharashtra
989.	Shri Sanjeev Gawade, Pune Maharashtra India, sanjeevgawade1@gmail.com
990.	Shri Sanjeev Gawade, Shantisheela Soc Plot No 18, Law College Road Pune -411016, Maharashtra State
991.	Shri Sanjeev Jagtap, Pune, jagtapsanjeev@gmail.com
992.	sanjeevbl9@gmail.com
993.	Shri Sankar Sabar, padmalaya103@gmail.com
994.	Shri Sankaran C, sankarcsurvey@gmail.com
995.	Shri Sankaran Lakshmanan, slakshman28@gmail.com
996.	sankarmari00@gmail.com
997.	santhosh190183@gmail.com
998.	santkola438@gmail.com
999.	Shri Santosh Shintre, samadhan,prabhat road 9th lane,Pune-411004
1000.	Shri Saran, dssaran14122002@gmail.com
1001.	Shri Saran Subramaniam, 17, Gandhinagar-641024, Coimbatore, saran.s87@gmail.com, info@jhatkaa.org
1002.	Shri Saranya Inbaa, 2/182, Mel Theru, Neikkarapatty, Salem-636010
1003.	Shri Saranya kumaresan, KGM Hospital, Coimbatore- 641062, drsaranyadeepak@gmail.com, info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name
1004.	Shri Saranya Raghavan, sahaatravels2014@gmail.com
1005.	Shri Saravana Kumar, 1/110/51-A ,Sri Senthil Nagar ,Iduvai P.O. Tirupur -641687
1006.	Shri Saravana Kumar, 3/90-A, Avalchiinampalayam- 642123
1007.	Shri Saravanan, sstamizh19@gmail.com
1008.	Shri Saravanan, abcsaravanan@gmail.com
1009.	Shri Saravanan Moorthi, Ramadoss Street, Cuddalore-607001, saravanansame84@gmail.com, info@jhatkaa.org
1010.	saravannak@gmail.com
1011.	Shri Sasikumar G, sasikumar.g90@gmail.com
1012.	Shri Sastha, sasathasastha1996@gmail.com
1013.	Shri Satheesh S, 1/280 Gadambur,oomerabad Post, Ambur Taluk, Ambur-635808
1014.	Shri Satheeshkumar S, kings1318sks@gmail.com
1015.	Shri Sathishkumar, thamizhsathish2106@gmail.com
1016.	sathishkumartamil13@gmail.com
1017.	sathiyavenkatesan2425@gmail.com
1018.	Shri Sathya. V, tamilanaraciyal@gmail.com
1019.	sathya83.r@gmail.com
1020.	savariraj2003@gmail.com
1021.	Shri Saviola Fernandes iteng.sferns@yahoo.co.in
1022.	Ms.Savitha Nagabhushan, Nagabhushansavitha, Mysuru-570009, info@jhatkaa.org
1023.	Shri Seeman Thambi, udayatamizhan@gmail.com
1024.	Shri Seenivasan M, seenimsenthil@gmail.com
1025.	Shri Seenuvasan V, vaseenuvasan@gmail.com
1026.	Shri SeKi, sskrishnan9582@yahoo.com
1027.	Shri Selin Paulraj, Tamilnadu, selinpaulraj.civil@gmail.com
1028.	Shri Selva Kumaran, Palaya Thottam- 638505 Gobichettipalayam, dravidkumaran.19@gmail.com info@jhatkaa.org
1029.	selvainge@gmail.com
1030.	Shri Selvakumar, selvam17781@gmail.com
1031.	Shri Selvakumar. P, selvadmech@gmail.com
1032.	selvakumarsm92@gmail.com
1033.	selvam17781@gmail.com
1034.	selvam2035@gmail.com
1035.	Shri Selvendran A, khallaas123@gmail.com
1036.	sengelsoren@gmail.com
1037.	Shri Senthamil selvan MP, 16 akr 3rd Street, Valasaravakkam-600083
1038.	Ms. Serena Chopra, New Delhi serenachopra31@gmail.com
1039.	Shri Seshadri Vasu, Sobhitha seshadri, Sai Sunayana, Sai Chanasya, Lakshmidevamma seshadri.vasu@gmail.com

Sl. No.	Name
1040.	Shri Sethupathy. M, sethupathyse10@gmail.com
1041.	Shri Shahbaz Ahmad IFS Retd., Ex-Principal Chief Conservator of Forests & Chief Wildlife Warden, MP, 81/3, North Malaka, Prayagraj, UP- 211001
1042.	Ms. Shailaja Deshpande, on behalf of Jeevitnadi Living River Foundation, jeevitnadi@gmail.com
1043.	Ms. Shailaja Deshpande shailajadesh@gmail.com
1044.	Shri Shailender Singh, Vpo Kolar, Teh. Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.), 173001
1045.	Shri Shailesh Dathe, Shailesh Sathe, Datta Nagar , Panchavati Nashik-422003 , shailesh.7021@gmail.com info@jhatkaa.org
1046.	shajakhan.executive@gmail.com
1047.	Ms. Shalini, shalininetpark@gmail.com
1048.	Shri Shamsher Singh on behalf of the Residents of Villages
	residentsofvillages@gmail.com
1049.	Shri Shankar Prakash, aspmajaa@gmail.com
1050.	shankarr.1986@gmail.com
1051.	shanmugatamizhar9@gmail.com
1052.	Shri Shanu Charan Murmu, Rastriya Adivasi Ekta Parishad, District President/Co-ordinator, District-Mayurbhanj, Odisha, karanhansdah21@gmail.com
1053.	Shri Sharad Paliwal, President, Paryavaran Prerna Maharashtra, paliwalsharad10@gmail.com
1054.	Ms. Sharmila Deo, Pune. sharmiladeo@gmail.com
1055.	sheikabdulla7383@gmail.com
1056.	Shri Shekhar Phatak (Indian Citizen), shekhar.phatak@gmail.com
1057.	Shri Sheriff Mohamed Nagoore Mohideem, West Street, Achanputhur -627803
1058.	Ms. Sherlin Pinto, Amtady, Bantwal T.Q., Karnataka-574211, Bantwal, sherlinneil@gmail.com info@jhatkaa.org
1059.	Shri Shirish Kanitkar, Ecologist, Consultant, shirishkanitkar@yahoo.com
1060.	Shri Shiv Ka Bhandar, sivapaed@gmail.com
1061.	Shri Shiva Kumar, sivakumarlee20@gmail.com
1062.	Shri Shivam Kushawah, Etawah, Uttar Pradesh-206120 Bakewar , Etawah, shivamindald@gmail.com info@jhatkaa.org
1063.	Shri Shogun Fernandes , President , Chicalim Youth Farmers Club, cyfarmersclub@gmail.com
1064.	Ms. Shomona Khanna, Advocate, Supreme Court of India shomona@gmail.com
1065.	Shri Shree Arun Kumar, arunkagitham05@gmail.com
1066.	Shri Baijnath Pandey, S/o Late Shri Baikunth Nath Panday, 127/317 W Block, Kesav Nagar, Kanpur-208014
1067.	Shri D.A. Narayanan, Advocate, 312, Lawyers Chambers, District court complex, Gopalapuram, Coimbatore-641018, Tamil Nadu
1068.	Shri Dinesh Kumar Agrawal, S/o Late Moti Lal Agrawal, 1/24, First Floor, Charmwood Village Eros Garden, Suraj Kund, Faridabad-121009
1069.	Shri Jitendra Chaudhary, Formar MP, National Convener, Aadivasi Adhikar Rashtriya Manch
1070.	Shri K.K. Singh Lohali Jalal, Nainital, Uttrakhand

Sl. No.	Name
1071.	Shri Lalaji P., Secretary, Blackrock Hill Planters Association, Nagercoil,
1072.	Shri M.S. Selvaraj, Campaign for Survival and Dignity-Tamil Nadu, Vyavasaayikal Thozhilalarkal Munnetra Sangam, Tamilnadu Pazhangudi Makkal Sangam
1073.	Shri Rajan Singh, R/o Lane No. 5, Lower Tathar, Pooja Colony, Bantallab, Jammu-J&K UT
1074.	Shri. L Kuki President, Shri S. Jeme, Working President, Shri L. Hlima Keivom, General Secretary, Indigenous People Forum's, HQ- Haflong, N.C. Hills, Assam, Pin-788819.
1075.	Shri. Sanjay Deshpande, Shrushti Parayavaran Mandal, Nagpur
1076.	Ms. Shristy Mukherjee, Shristy, Bangalore-560032, shristymukherjee9@gmail.com info@jhatkaa.org
1077.	Ms. Shriya M, Laburnum, Gurgaon-400069, shriyam@gmail.com info@jhatkaa.org
1078.	Ms. Shruti Mahajan, 699, Saraswati Vihar, MG Road, Gurgaon -122002
1079.	Ms. Shweta Vernekar, shweta@parisar.org
1080.	Shri Shyam K, shyam.kamaraj@gmail.com
1081.	Ms. Shyamala Das, Bengaluru-560066, shdas.athashri@gmail.com info@jhatkaa.org
1082.	sinivasaperumal@gmail.com
1083.	Siunapadar Gramasabha Post- Haridaguda, Block-Borigumma Ps-B.Singhpur, Dist-Koraput Odisha, Pin-764057, deepakgonda68@gmail.com
1084.	Shri Siva, sivaoct2k@yahoo.com
1085.	Shri Siva R, Ozone Greens, Chennai-600100, sivarajantrgml@gmail.com info@jhatkaa.org
1086.	siva999494@gmail.com
1087.	Shri Sivabalan Chidhambaram, Journalist, Dream T amilnadu-(Junior Vikatan).
1088.	Shri Sivabalan Chidhambaram, No.14/A, Sakthi Nagar, Nerkundram, Chennai-600107
1089.	Shri Sivasakthivel, sivasakthi0981@gmail.com
1090.	Shri Skanda, skandaprasad93@gmail.com
1091.	Shri SL Kumar, Vyasar Nagar 6th Street, Chennai-600039, lohithkumar.1008@gmail.com info@jhatkaa.org
1092.	Ms. Smitha Naik, smithasanjeevnaik@gmail.com
1093.	snaveen.nn@gmail.com
1094.	Ms. Sneha C, Kannur-670142, Kerala
1095.	Shri Snehasis Sarkar, Silchar-781011 Guwahati, snehasis056@gmail.com info@jhatkaa.org
1096.	Ms. Sobha Royyuru IFS Retd, Advisor to Govt.of Telangana , Forestry Affairs, Hyderabad, Telangana , India.
1097.	Shri Soma Shekhar Venugopal, 475, 9th Cross BSK 3rd Stage, Bengaluru-560085
1098.	Ms. Soniya DE, magadi road, Bengaluru-560091
1099.	Ms. Soniya Tadvi, Jalgaon, Jalgaon - 425002, info@jhatkaa.org
1100.	soulnathan37@gmail.com
1101.	Shri Soundarraj M, soundarrajmurugan44@gmail.com
1102.	Shri Sourav Mukherjee, Howrah, West Bengal, prakritibadi@gmail.com
1103.	Shri Sourav Paul, Electronic City, Bengaluru-560100, souravpnccs@gmail.com info@jhatkaa.org
1104.	sowkathali23@gmail.com
1105.	Shri Sreekanth sreekanthsv8@gmail.com

Sl. No.	Name
1106.	Shri Sri Blr, Bengaluru-560027, sri4blr@gmail.com info@jhatkaa.org
1107.	Shri Sri Gopinath Majhi, Convenor, Campaign for Survival and Dignity, Odisha csdorissa@gmail.com
1108.	Shri Srichandra Mallik, on behalf of Khujen Gram Sabha, AT Khujen P.O. Ghunesh, Via H.S.Road, District Balangir, Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1109.	Shri Srikant Verma srikantjaraikela@outlook.com
1110.	Shri Srikant Verma, Divisional Forest Officer, Ranchi Forest Division, Ranchi, Block- F, Van Bhawan, Doranda
1111.	Shri Srikanthan V, 32, 14th Cross New Colony, Chromepet-600044
1112.	Srikrushnasara Gramsabha At-Srikrushnasara, Po-Sankuda, Via-Sumandal, Dist- Ganjam, Odisha, Pin-761035, padmalaya103@gmail.com
1113.	Shri Srikumaran, For Karnada Estate- Melta Div., Gunumalai House, Virudhunagar-6260001
1114.	Shri Srimuralidharan, srimuralidharan03@gmail.com
1115.	Shri Srinivasan.M, msrinidpintk@gmail.com
1116.	srivi.lingam@gmail.com
1117.	sspandiyan9124@gmail.com
1118.	Shri Stalin, stalinsg100.sm@gmail.com
1119.	Shri Stanley Balasingh.S D, stanleybalasingh@gmail.com
1120.	stylethiru4@gmail.com
1121.	Shri Su. Ranjith Kumar, ranjithraj1991143@gmail.com
1122.	subashl35072129@gmail.com
1123.	Shri Subir Mario Chowfin, Gadoli House,Gadoli Fee Simple Estate,Pauri,District Pauri Garhwal,Uttarakhand - 246001.
1124.	Shri Subodh Bansal, 3, North Idgah Colony, Agra 282010, UP, subodh5050@gmail.com
1125.	Shri Subramani Kandasamy, 8 and 9, Tulips Sherwood, Thuthipattu-632011, Vellore
1126.	Shri Sudam Bhoi, H.S. Road, District- Balangir, Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1127.	Shri Sudarshan Ramakrishnan, 3/1/148, T.Kallupatti-625702
1128.	Shri Sudhansu Sekhar Mishra, Retd Forest Officer, Govt of Odisha, Flat no c 203, PDN Exotica Apartment, Panchasakhanagar, Dumduma, Bhubaneswar, Odisha, Pin 751019
1129.	Shri Sudharsanam Subramani, 268, AV salai, Veerapuram, Ch - 55, Avadi-600055
1130.	Shri Sudip Birade, Nashik-422001, sudipbirade7@gmail.com info@jhatkaa.org
1131.	suhailrasith1996@gmail.com
1132.	Sujanith Shetty, Vijayanagar , Bangalore-560072, info@jhatkaa.org
1133.	Shri Sujit Vetal, Manjinagar , Narhe-411041, Pune
1134.	sujitlomga7@gmail.com
1135.	Shri Sukumar, Chennai, Thamilnadu, plsugu116@gmail.com
1136.	Shri Suman Sabar, padmalaya103@gmail.com
1137.	Shri Sumathikabilan, sumathikabilan81@gmail.com
1138.	Ms. Sumi Munda, At-Birtola, Po-Darjing, Ps-Lahunipara, Dist-Sundargarh, Pin-770040, State-Odisha, punampurty0502@gmail.com

Sl. No.	Name
1139.	Ms. Sumitha, bayamariyaan.nt@gmail.com
1140.	sunai1990126@gmail.com
1141.	Shri Sundar Mohan Soren, Mayurbhanj Hanat Pargana, Shri Biram Soren, Mayurbhanj, Shri Hanat Paranik, Bharat Jakat Majhi Pargana Mahal, Majhi Pargana Mahal Bakhul, Pawra, Ghatsila, District- East Singbhum, Jharkhand biramsoren83@gmail.com
1142.	Shri Sundararajan P., Thambu Chetty Street, Chennai-600001, 600001 lawyersundar@gmail.com info@jhatkaa.org
1143.	Shri Sundermohan Soren and Biram Soren, Bharat Jakat Majhi Pargana Mahal, biramsoren83@gmail.com
1144.	Shri Sunil Chhabra, Aamgam Road, Sanjan-396150, chhabra.sunil.58@gmail.com info@jhatkaa.org
1145.	Shri Sunil Harsana, Independent researcher and conservationist, Resident of Mangar Village, Faridabad, Haryana -121004
1146.	Ms. Sunita Dhairyam (Jayapathy) (Indian Citizen), sdhairyam@gmail.com
1147.	Ms. Suparna Sankaran, Flat GB, Sivedha Apartments, New no 27, 3rd Avenue, Chennai-600090
1148.	Shri Suresh, sanjur707@gmail.com
1149.	Shri Suresh Kumar Vadivel, sureshsince82@gmail.com
1150.	sureshaachimuthu@gmail.com
1151.	Shri Sureshbabu R, Karavalimathappur, Coimbatore-641668, 641668 rsureshbabu101@gmail.com info@jhatkaa.org
1152.	sureshdivya43@gmail.com
1153.	sureshtanishq29@gmail.com
1154.	Shri Suru Sing Majhi, on behalf of Gunchijor Gram sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1155.	Shri Susan Sharma, C-2490, Sushantlok-122009, Gurgaon
1156.	Ms. Suwathy Venugopal, S.V.Puram, Venkatesa Mills, Udumalpet-642128, suwathyvenugopal@gmail.com info@jhatkaa.org
1157.	Swacch Association, swacchnagpur@gmail.com
1158.	Shri Swaminathan E, Nathapattu Housing Board, Cuddalore-607001, swaminathansnp@gmail.com info@jhatkaa.org
1159.	Shri Swaminathan G L, 37/63, Kala Complex, 4th Avenue, Ashok Nagar, Chennai- 600083
1160.	Shri Swapnil Gupta, 302 Tower 3 ILD Greens Sector 37C, Gurgaon-122001
1161.	Ms. Swathilakshmi S, swathisekar0308@gmail.com
1162.	Ms. Swati M, Indiranagar, Bangalore-560008, am.i.swati@gmail.com info@jhatkaa.org
1163.	Shri Swayambar Majhi , on behalf Phulakimunda Gram sabha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1164.	Shri Syed Naqvi, Jaipur-302004, smoiz123@gmail.com info@jhatkaa.org
1165.	Shri T .Franklin, 17 A, Henry Road, Nagercoil, Tamilnadu.
1166.	Shri T Deiva Arul, deiva.t@hap.in
1167.	Shri T Deivaarul , deivaarul98@gmail.com
1168.	Shri T Deivaarul , ntdarul333@gmail.com
1169.	Shri T Pandiyan cheyyar pandiyanindiacyr@gmail.com
1170.	Shri T. Mayilraj, tamilantamayilraai@gmail.com
1171.	Shri T. Mohanta, General Secretary, Society of Geoscientists & Allied Technologists, Plot No. ND-12 (Part), V.I.P. Area, P.O.: IRC Village, Bhubaneswar - 751 015, Odisha, India

	Name
1172.	Shri T. Vinmeen Pandian, kperipandian@gmail.com
1173.	Tabhabania Gramsabha At-Tabhabania, Po-Mardamekha, <i>Via</i> -Kodala, Dist- Ganjam, Odisha, Pin- 761032, padmalaya103@gmail.com
1174.	Tamil Ulagan Sanjay, sanjaisagu321@gmail.com
1175.	Tamil, ghostofjustice2@gmail.com
1176.	tamilan.photography@gmail.com
1177.	Tamilnadu Tribal peoples Assn, 103 / 4, Kannappan Kinatru Veethi, Anthiyur - 638501, erodevpg@gmail.com
1178.	tamizharasanr600@gmail.com
1179.	Shri Tamizharvan Thandayuthapany, Tamil Nadu, tamizharvan1991@gmail.com
1180.	Ms. Tannistha Lahiri, 396/9 Becharam Chatterjee Road, Kolkata-700034
1181.	Ms. Tanuja Aundhe, Raheja Gardens, Thane-400604
1182.	Ms. Tara Misra, Binny Crescent Rd, Benson Town, Bangalore-560046
1183.	Ms. Tatum Ghosh, Amrapali Silicon City, Noida-201304, tatumghosh@gmail.com info@jhatkaa.org
1184.	Shri Tej Vohra, Bangalore, Karnataka telltej@gmail.com
1185.	tejasvita.malhotra@gmail.com
1186.	Shri Tejaswi Kumar Pradhan, Advocate, S/o Late Muralidhar Pradhan, Chamber No. 5 (R.K. Garg Block), Supreme Court of India New Delhi, tejaswipradhan@gmail.com
1187.	Shri Teju Rana, At Semla, Po Kuibahal , <i>Via-</i> Turekela, Dist. Balangir Odisha, zindabadsangathanbgr@gmail.com
1188.	Shri Thamilum Aramum, kollywooddaily2022@gmail.com
1189.	thanigaikarthika96@gmail.com
1190.	thanrajj848@gmail.com
1191.	Shri Thasarathan V, svtdass@gmail.com
1192.	Shri Theeran Thirumurugan,S/o Ganesan,Morepannai Fishing Village,Uppoor post, Thiruvadanai Taluk,Ramanathapuram District.
1193.	thillai97nathan@gmail.com
1194.	Shri Thiru, thirukumar732@gmail.com
1195.	Shri Thiru ragava Krishna, Thiruporur, Chennai-600001
1196.	Shri T Thirumalaikumar Thangaiah, Gandhi street, 2/107, Vedanthankal Nagar, Arasan kazani, Chennai 600126 Chennai, karthikumarmsd007@gmail.com info@jhatkaa.org
1197.	Shri Thiruvalluvan, p.thiruvalluvan1@gmail.com
1198.	Shri Tiak Bariha, AT/PO - Ghunesh, Via Harishankar Road, Dist. Balngir , Odisha zindabadsangathanbgr@gmail.com
1199.	Shri Tommy Lobo, 53, Coconut Grove, Behind Deva Matha School, Horamavu, 560043 Bangalore
1200.	Shri Tony AR, E-503 Santha Towers Paruthipattu, Avadi Chennai-600071
1201.	Shri Toshesh Daulta, AFNOE, Sec-7, Plot-11, Dwarka-400095, New Delhi
1202.	Shri Trilochan Punji, Zindabad Sangathan, Balangir, Odisha
1203.	ts0582020@gmail.com

Sl. No.	Name
1204.	Shri Uday Kumar, Thanjavur-614205, Papanasam uday_tj@rediffmail.com info@jhatkaa.org
1205.	udayakmr5@gmail.com
1206.	Shri Udhayakumar TS, No 1c, 3rd Street, Jothy Nagar, West Tambaram, Chennai-600045.
1207.	Uhavan Art Gallery, tamilanvicky007@gmail.com
1208.	Shri Uma Shanker Singh IFS (Retd.), Director Vanashakti, 3/184, VibhavKhand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
1209.	Shri Umesh Athavia, Pune uathavia@gmail.com
1210.	United Conservation Movement priyaalemane@gmail.com
1211.	United Conservation Movement, rajukidoor@gmail.com
1212.	United Conservation Movement, sahajaputtur@gmail.com
1213.	United Conservation Movement, dheerajsalian333@gmail.com
1214.	United Conservation Movement, united conservation movement @gmail.com
1215.	United Conservation Movement, danielsukumar@gmail.com
1216.	Shri Ushnish Chattopadhyay, Dy. General Manager (Raw Materials), JK Paper Ltd, 2 <sup>nd</sup> Floor, Nehru House,4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
1217.	Shri V. Thirumurugan, rvtmurugan1980@gmail.com
1218.	Shri V G Srikara BE Convener, Shimoga District Westernghat Conservation, Committee R/o Channappa layout, Ist Cross, Shimoga, Karnataka
1219.	Shri V. Muruga Anand murugananand7305@gmail.com
1220.	Shri V. Sathish Kumar, venkatsathish12@gmail.com
1221.	Shri V. Selva Kumar selvam17781@gmail.com
1222.	Shri V. Subash, subashmenaka1980@gmail.com
1223.	Shri V. Thampi vijigish@gmail.com
1224.	Shri V. Vignesh M.Sc Biotechnology, vigneshk984@gmail.com
1225.	Shri V. Vimalraj, vimalraj.dgl@gmail.com
1226.	Shri Vaarthai, mervinjsm@gmail.com
1227.	Shri Vaibhav Shettar, 1st cross, Park Extension, Durgigudi, Shivamogga, Karnataka -577201
1228.	Ms. Vaira Meenakshi, vyshi5979@gmail.com
1229.	zohanandco@gmail.com
1230.	Ms. Vaishali Nikam, B/403, Mumbai-400092
1231.	Ms. Vaishali Rawat, Writer and wildlife conservationist, M.Sc. Biodiversity, Conservation and Management, University of Oxford vaishali.rawat@gmail.com
1232.	Ms. Vaisshali J Patkar, President, Aundh Mohalla Committee, Director, CCP, Environmental Foundation, Trustee, Bhujal Abhiyan, Convener, Pune Texas-Austin Sister city International, Area Sabha Association of Pune, Ramnadi Restoration Mission vpshali25@gmail.com
1233.	Ms. Vaitheeswaran, mpvaitheeswaran@gmail.com
1234.	vallarasugk001@gmail.com
1235.	Shri Valluvan Valai, priyakumaran182@gmail.com
1236.	Ms. Vanisri K, Chennai-600015 vanisrikalpana@gmail.com info@jhatkaa.org

Sl. No.	Name	
1237.	Ms. Vanya Jain, 31 Tramoo Street, Lalor-110076	
1238.	varith034@gmail.com	
1239.	Shri Varun savarun@gmail.com	
1240.	Shri Vasuki Tamilselvam, B.A history, Vellore, selvamtamil.bsnl@gmail.com	
1241.	Ms. Vasumati Kale, Pune, India vasumatikale@gmail.com	
1242.	Vayagam Amar Rahen, manofattitude408@gmail.com	
1243.	Veeramani, veera1607.mani@gmail.com	
1244.	Shri Veeramuthu A, vamprats@gmail.com	
1245.	velganesh326@gmail.com	
1246.	Velkum55555@gmail.com	
1247.	Shri Velkumar Satchidanandam, Kandaswami koil street, Kosapet-600012 velkumar_61@yahoo.in, info@jhatkaa.org	
1248.	Shri Vellian Giri, Kudlu, Bangalore-560068 vellian3156@gmail.com, info@jhatkaa.org	
1249.	Shri Velmurugan, vr8019783@gmail.com	
1250.	Shri Velmurugan R, velmuruganraja.t@gmail.com	
1251.	Shri Vembuselvam M, vembuselvamm@gmail.com	
1252.	venkataraj01@gmail.com	
1253.	Shri Venkatesan. D, kanchiadhithyan@gmail.com	
1254.	venkatesanmurugaiah73@gmail.com	
1255.	Shri Venkatesh Nagarajan, 4/233, Mullukurichi, Namakkal-636142	
1256.	Shri Venkatesh Pandi B, #697, Thanthai Periyar Nagar 4th street, Burma Colony Karaikudi-630002	
1257.	venkisumathi@gmail.com	
1258.	Ms. Vennila Thayumanavan, vennithayumanavan@gmail.com	
1259.	verbindenkarthick@gmail.com	
1260.	vetri6006@gmail.com	
1261.	Shri Vetriselvi Thayumanavan, Assistant Commissioner of GST Retired, pranilathayus@gmail.com	
1262.	vetrivelmayavel@gmail.com	
1263.	Ms. Viana Fernandes, H.No.268/A, Arossim Bandar , Cansaulim Mormugao, Goa	
1264.	Vibrant India Economic Council,Shri Manoj Patil, Shri MaheshTapase, Shri Pawan Kolte info@viecglobal.com	
1265.	Shri Shri Vignesh B., vignesh.subramaniam1511@gmail.com	
1266.	Shri Vignesh Kumar G, 8/16,palathumarriamman street, Musiri-621215	
1267.	Shri Vignesh Rajendran, Norton Road, Mylapore-600028	
1268.	Shri Vigneshwaran RK, 4/82, Annai Nagar, Visuwasapuram -641035 Coimbatore	
1269.	Shri Vihaan Vee, Kasavanahali - 560035, Bangalore vihaan0vee@gmail.com info@jhatkaa.org	
1270.	Shri Vijay, vijaykmr6262@gmail.com	
1271.	vijayakanthj55@gmail.com	
1272.	Ms. Vijayarani, vijayaranisanjay@gmail.com	

Sl. No.	Name	
1273.	Shri Vijay, vijaykmr6262@gmail.com	
1274.	Shri Vijaykaant, vijaykmr6262@gmail.com	
1275.	vijaysp3638@gmail.com	
1276.	Shri Vimal Seeta, vimaljai03@gmail.com	
1277.	Shri Vinay Keerthy, Mahadevapura, Bengaluru- 560016 vinaykeerthy97@gmail.com info@jhatkaa.org	
1278.	vinobala85@gmail.com	
1279.	Shri Vinoth Kumar T, vinothkumar9815@gmail.com	
1280.	Shri Vinoth Kumar, vinoth18693kumar@gmail.com	
1281.	Shri Vinothkumar Periyasamy, 2/366 paravalur South Street Vridhachalam Cuddalore- 606001 Vriddhachalam.TK,	
1282.	Shri Vinothkumar S, vinothkumar.s1909@gmail.com	
1283.	vinothkumar2921@gmail.com	
1284.	Shri Viren Lobo, Institute for Ecology and Livelihood Action	
1285.	Shri Vishal B Nair, Kottarathil House, Kanjikuzhy- 685606	
1286.	Shri Vishal Sudhakar Rasal r.vishal1319@gmail.com	
1287.	Shri Vishnu Kant, Joint Gen Sec; ABVKA; Delhi vanvishnu25@gmail.com	
1288.	vishnugulu06@gmail.com	
1289.	Shri Vishnupriya B M, Menjhaniyam , Kozhikode-673525	
1290.	Shri Vishukumar Naguvanahalli, Bengaluru-560094 vishukumarnr@gmail.com info@jhatkaa.org	
1291.	Shri Vishwad N Dinni, Responsible Citizen of India	
	vishwasdinni@gmail.com	
1292.	Shri Viswanathan K S, Jalakandapuram-636501 info@jhatkaa.org	
1293.	Shri Vivek Shinde, Flat No 1102, Primal Homes Society, Backside of Moshi Dmart- 414006, Moshi, Pune	
1294.	vmboopathy1810@gmail.com	
1295.	Shri VS Kumar, Vyasar Nagar 6th Street , Vyasarpadi, Chennai-600039 sanathkumar.620@gmail.com info@jhatkaa.org	
1296.	Shri W. Saravankumar, 0542004sk@gmail.com	
1297.	wentotrade@gmail.com	
1298.	WG CDR ID Soans, 29, Jal Vayu Vihar, Kammanahalli Main Road, Bengaluru-560043 idsoans@gmail.com, info@jhatkaa.org	
1299.	wills87nellai@gmail.com	
1300.	Worli, Mumbai-400018 info@jhatkaa.org	
1301.	Shri Yadhavaraja. S, yadava.raja@gmail.com	
1302.	yamunastudioblp@gmail.com	
1303.	Shri Yannah Marchon (Indian Citizen) marchonyannah@gmail.com	
1304.	Shri Yash Pal, 8/1 2nd cross, Wheeler Road, Fraser Town, Bengaluru-560005	
1305.	yokenthirakumark1@gmail.com	
1306.	Shri YPS Prabakar arulyps@gmail.com	

Sl. No.	Name
1307.	Shri Yujin Leonidas, Sait Colony, Egmore-600008, Chennai yujindass02@gmail.com, info@jhatkaa.org
1308.	yuvaniya.2020@gmail.com
1309.	Shri Yuvaraj, yuvanhari1996@gmail.com

# **PPENDIX-IV**

# DETAILS OF THE DISCUSSIONS HELD BY THE JOINT COMMITTEE ON THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023 DURING THE STUDY VISIT OF THE JOINT COMMITTEE TO SRINAGAR, GUWAHATI AND BHUBANESWAR FROM 2 TO 7 JUNE, 2023.

Sitting No.	Date of Sitting	Agenda of the sitting
1	02.06.2023	Discussion with various defence organizations and institutions viz. BRO, BSF, DRDO, Army Northern Command (Chinar Corps) regarding their views on provisions made in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.
2	03.06.2023	Discussion with Chief Secretary/State Government Representatives of Union Territories of Jammu & Kashmir and Laddakh, States of Himachal Pradesh, Punjab and Uttarakhand regarding their views on provisions made in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.
3	05.06.2023	Discussion with Directorate General of Hydrocarbons (DGH) and ONGC representatives and with Chief Secretaries/State Govt. Representatives of State of Tripura, Sikkim and Nagaland regarding their views on provisions made in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.
4	06.06.2023	Discussion with Chief Secretary/State Govt. Representatives of State of Assam, Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh regarding their views on provisions made in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.
5	07.06.2023	Discussion with representatives of Indian Bureau of Mines (IBM) and with Chief Secretary/State Government Representatives of State of Odisha and Andhra Pradesh regarding their views on provisions made in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

# **APPENDIX-V**

# <u>DETAILS OF THE SITTINGS OF THE JOINT COMMITTEE ON THE FOREST (CONSERVATION)</u> <u>AMENDMENT BILL, 2023</u>

Sitting No.	Date of Sitting	Agenda of the sitting
1	25.04.2023	Briefing by the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.
		(Also Present: Ministry of Law & Justice - Legislative Department & Department of Legal Affairs)
2	- 16.05.2023	To elicit views of representatives of the following Ministries on the Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023:
		1. Ministry of Home Affairs
		2. Ministry of Defence
		3. Ministry of Tribal Affairs
		(Also Present: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
3		To elicit views of Left Wing Extremism Affected States on the Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023:
		1. Government of Chhattisgarh
		2. Government of Maharashtra
		3. Government of Telangana
		(Also Present: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
4	- 17.05.2023	To elicit views of representatives of the following Ministries on the Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023:
5		1. Ministry of Railways
		2. Ministry of Road, Transport and Highways
		3. Ministry of Rural Development
		(Also Present: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
		To elicit views of representatives of following Ministries on the Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023:
		1. Ministry of Drinking Water and Sanitation
		2. Ministry of Mines
		3. Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER)
		(Also Present: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
6	30.05.2023	Oral evidence of Experts/Stakeholder/Organizations who submitted memoranda in response to Press Communique on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.
		(Also Present: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
7		Oral evidence of Experts/Stakeholders/Organizations on the Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023.
		(Also Present: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)

8	26.06.2023	Clause by Clause consideration of the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023
		(Also Present: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice- Legislative Department & Department of Legal Affairs)
9	11.07.2023	Consideration and adoption of the draft report on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

# **APPENDIX-VI**

# $\frac{\text{LIST OF OFFICIAL/NON-OFFICIAL WITNESSES WHO TENDERED ORAL EVIDENCE BEFORE}}{\text{THE COMMITTEE}}$

# A. <u>LIST OF OFFICIAL WITNESSES</u>

Sl. No.	Name of Ministries/State Governments/Union Territories
1	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
2	Ministry of Law & Justice- Department of Legal Affairs
3	Ministry of Law & Justice- Legislative Department
4	Ministry of Home Affairs
5	Ministry of Defence
6	Ministry of Tribal Affairs
7	Government of Chhattisgarh
8	Government of Maharashtra
9	Government of Telangana
10	Ministry of Railways
11	Ministry of Road, Transport and Highways
12	Ministry of Rural Development
13	Ministry of Drinking Water and Sanitation
14	Ministry of Mines
15	Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER)
В.	LIST OF OFFICIAL WITNESSES WHO TENDERED ORAL EVIDENCE DURING STUDY TOUR TO SRINGAR, GUWAHATI AND BHUBANESWAR FROM 2ND TO 7TH JUNE, 2023
Sl. No.	Name of State Governments/Union Territories and other organizations
1.	Border Road Organization (BRO)
2.	Border Security Force (BSF)
3.	Defence Research and Development Organization (DRDO)
4.	Army Northern Command (XV Corps)
5.	Union Territory of Jammu & Kashmir
6.	Union Territory of Laddakh
7.	Government of Himachal Pradesh
8.	Government of Punjab
9.	Government of Uttarakhand
10.	Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
11.	Oil and Natural Gas Company (ONGC)
12.	Government of Tripura
13.	Government of Sikkim
14.	
14.	Government of Nagaland

- 16. Government of Meghalaya
- 17. Government of Mizoram
- 18. Government of Arunachal Pradesh
- 19. Indian Bureau of Mines
- 20. Government of Odisha
- 21. Government of Andhra Pradesh

# C. <u>LIST OF NON-OFFICIAL WITNESSES</u>

# Sl. No. Name of Experts/Stakeholders/Organizations

- 1. Smt. Brinda Karat, Ex. MP (Rajya Sabha) 2005-2011
- 2. Dr. Prashant Kumar Jha, Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) (Retd.), Telangana Forest Department
- 3. Shri R.D. Kamboj, Addl. Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) (Retd.), Gujarat Forest Department
- 4. Shri Suresh Chopane, Member- Regional Empowered Committee (REC), Nagpur and Raipur (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), President Green Planet Society
- 5. Shri K. Ravichandran, Director- Indian Institute of Forest Management (IIFM)
- 6. Dr. Ravindra Kumar Singh, Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) (Retd.), Chhattisgarh Forest Department
- Shri Shahbaz Ahmad, Indian Forest Service (IFS) (Retd.)
   Ex-Principal Chief Conservator of Forests & Chief Wildlife Warden, MP
- 8. Debi Goenka, Executive Trustee, Conservation Action Trust
- 9. Shri Abhinav Gaur, AdvocategAllahabad High Court.
- Shri Praveen Bhargav, Trustee Wildlife First Former Member-National Board for Wildlife
- 11. Shri Manoj Patil, Convener, Vibrant India Economic Council (VIEC), Mumbai
- 12. Shri Bijay Convener, Bharat Jan Andolan(Chhattisgarh Bachao Andolan)

### **APPENDIX-VII**

#### MINUTES OF THE SITTINGS

### Minutes of the 1<sup>st</sup> Sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation)

#### Amendment Bill, 2023

The 1<sup>st</sup> sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 25<sup>th</sup> April, 2023 from 1100 hrs. to 1235 hrs. in Committee Room No.62, Parliament House, New Delhi.

### **PRESENT**

### Shri Rajendra Agrawal — Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Dr. Dhal Singh Bisen
- 3. Shri Suresh Kumar Kashyap
- 4. Smt. Gomati Sai
- 5. Shri Sudarshan Bhagat
- 6. Shri Pallab Lochan Das
- 7. Km. Diya Kumari
- 8. Shri T.R. Baalu
- 9. Smt. Agatha K. Sangma
- 10. Shri Kotagiri Sridhar
- 11. Dr. Alok Kumar Suman
- 12. Shri Girish Chandra
- 13. Shri Pradyut Bordoloi
- 14. Ms. Geeta Kora

### **RAJYA SABHA**

- 15. Shri Jawhar Sircar
- 16. Shri Birendra Prasad Baishya
- 17. Smt. Phulo Devi Netam

# **SECRETARIAT**

1. Shri J.M.Baisakh - Joint Secretary

2. Shri C. Kalyanasundaram - Director

3. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Smt. Leena Nandan
 Secretary
 Shri S P Yadav
 ADG

3. Shri Ramesh Kumar Pandey - Inspector General of Forests

4. Dr. Dheeraj Mittal - Assistant Inspector General of Forests

5. Shri Charan Jeet Singh - Scientist 'D'

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

6. Shri Rajveer Singh Verma - Additional Secretary

7. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the first sitting of the Joint Committee. Thereafter, he drew the attention of the Member son the motion to refer the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 to Joint Committee which was adopted by Lok Sabha and concurred by Rajya Sabha on 29 March 2023. He further apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairpers on invited the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) to brief the Committee on various aspects related to the Forest (Conservation) Amendment bill, 2023. He then drew the attention of the representatives from the Ministries to Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
- 4. The representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change then made a Power Point presentation to the Committee illustrating the proposed Amendments in the Bill and the rationale behind them.
- 5. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill which were briefly replied by the representatives of the nodal Ministry. The Chairperson then directed the Ministry to provide written replies to all the points raised during the sitting.

### The representatives of the Ministries then withdrew

6. The Committee, thereafter, briefly deliberated on future course of action by the Committee and decided to hold the next sittings of the Committee on 16th and 17th May, 2023 for taking oral evidence of the representatives of the other concerned Ministries and State Governments. The Committee also decided to invite memoranda containing views/suggestions from the public in general and NGOs/experts/stake holders and institutions in particular by issue of a Press Communiqué.

The Committee then adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

# Minutes of the 2<sup>nd</sup> sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

The 2<sup>nd</sup> sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 16<sup>th</sup> May, 2023 from 1100 hrs. to 1230 hrs. in Committee Room No. 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

### **PRESENT**

### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Dr. Dhal Singh Bisen
- 3. Shri Raju Bista
- 4. Shri Tapir Gao
- 5. Shri Ajay Tamta
- 6. Smt. Gomati Sai
- 7. Shri Pallab Lochan Das
- 8. Shri T.R. Baalu
- 9. Smt. Agatha K. Sangma
- 10. Smt. Sajda Ahmed
- 11. Shri Kotagiri Sridhar
- 12. Dr. Alok Kumar Suman
- 13. Shri Girish Chandra
- 14. Ms. Geeta Kora

# **RAJYA SABHA**

- 15. Shri Jawhar Sircar
- 16. Shri R. Girirajan
- 17. Smt. Phulo Devi Netam

# **SECRETARIAT**

Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
 Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Smt. Leena Nandan - Secretary
 Shri Chandra Prakash Goyal - DGF&SS

3. Shri Ramesh Kumar Pandey - Inspector General of Forests

#### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE

### (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

4. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF HOME AFFAIRS

5. Shri Dharmendra Singh Gangwar - Secretary (BM), MHA

6. Shri Nishant Kr. Mishra - DS (LWE), MHA

### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF DEFENCE

7. Smt. Dipti Mohil Chawla - Additional Secretary

8. Shri Manish Tripathi - Joint Secretary

9. Brig Praveen Badrinath - Brig MO (C)

10. Shri C P Meena - Sc 'E', DRDO

#### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Shri Anil Kumar Jha - Secretary (TA)
 Shri Naval Jit Kapoor - Joint Secretary

13. Smt. Samidha Singh - Director

14. Shri Nadeem - Under Secretary

- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the second sitting of the Joint Committee. He further apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Home Affairs, Ministry of Defence and Ministry of Tribal Affairs to brief the Committee on various aspects related to the Forest (Conservation) Amendment bill, 2023. The representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice (Department of Legislative Department) were also present to assist the committee during deliberations. The Chairperson then drew the attention of the representatives from the Ministries to Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
- 4. The representatives of Ministry of Home Affairs, Ministry of Defence and Ministry of Tribal Affairs explained their views on the amendments proposed in the Bill.
- 5. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill and views of Ministry of Home Affairs, Ministry of Defence and Ministry of Tribal Affairs which were briefly replied by the representatives of Ministry of Home Affairs, Ministry of Defence and Ministry of Tribal Affairs. The Chairperson then directed the Ministry *viz.* Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting.
- 6. The Committee also decided to undertake a study tour to Srinagar, Guwahati and Bhubaneswar from 2<sup>nd</sup> June, 2023 to 7<sup>th</sup> June, 2023 to hold informal discussion with Chief Secretaries/representatives of various States/UTs and organizations regarding their views on provisions made in Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

The representatives of the Ministries then withdrew

The Committee was adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

# Minutes of the 3<sup>rd</sup> sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The 3<sup>rd</sup> sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 16<sup>th</sup> May, 2023 from 1315 hrs. to 1430 hrs. in Committee Room No. 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

#### **PRESENT**

#### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Dr. Dhal Singh Bisen
- 3. Shri Raju Bista
- 4. Shri Tapir Gao
- 5. Shri Ajay Tamta
- 6. Smt. Gomati Sai
- 7. Shri Pallab Lochan Das
- 8. Shri T.R. Baalu
- 9. Smt. Agatha K. Sangma
- 10. Dr. Alok Kumar Suman
- 11. Shri Girish Chandra
- 12. Ms. Geeta Kora

#### **RAJYA SABHA**

- 13. Shri Jawhar Sircar
- 14. Shri R. Girirajan
- 15. Smt. Phulo Devi Netam

#### **SECRETARIAT**

- 1. Shri J.M. Baisakh Joint Secretary
- 2. Shri C. Kalyanasundaram Director
- 3. Ms. Rachna Saxena Deputy Secretary

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

- Smt. Leena Nandan Secretary
- 2. Shri Chandra Prakash Goyal DGF&SS
- 3. Shri Ramesh Kumar Pandey Inspector General of Forests

#### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE

# (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

4. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

# REPRESENTATIVES OF GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

- 5. Shri Amitabh Jain Chief Secretary
- 6. Shri V. Sriniwas Rao Principal Chief Conservator of Forest
- 7. Shri Sunil Mishra Additional Principal Chief Conservator of Forests

(Land Management) and Nodal Officer,

Forest Conservation Act, 1980

#### REPRESENTATIVES OF GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

8. Shri Venu Gopal Reddy - Principal Secretary (Forests)

9. Shri Y.L.P. Rao - Principal Chief Conservator of Forests(Head of Forest Force)

#### REPRESENTATIVE OF GOVERNMENT OF TELANGANA

10. Shri Mohan Chandra Pargaien, IFS - Prl. Chief Conservator of Forests (FCA) and Nodal Officer, Telangana

- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the third sitting of the Joint Committee. He further apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Government of Chhattisgarh, Government of Maharashtra and Government of Telangana to brief the Committee on various aspects related to the Forest (Conservation) Amendment bill, 2023. The representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice (Department of Legislative Department) were also present to assist the committee during deliberations. The Chairperson then drew the attention of the representatives to the Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
- 4. The representatives of the Government of Chhattisgarh, Government of Maharashtra and Government of Telangana explained their views on the amendments proposed in the Bill.
- 5. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill and views of Government of Chhattisgarh, Government of Maharashtra and Government of Telangana, which were briefly replied by the representatives of Government of Chhattisgarh, Government of Maharashtra and Government of Telangana. The Chairperson then directed the Nodal ministry *viz*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting.

The representatives of the Ministries then withdrew

The Committee was adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

# Minutes of the 4<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The 4<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee was held on Wednesday, the 17<sup>th</sup> May, 2023 from 1100 hrs. to 1215 hrs. in Committee Room No. 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

#### **PRESENT**

#### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Shri T.R. Baalu
- 3. Dr. Dhal Singh Bisen
- 4. Shri Raju Bista
- 5. Shri Tapir Gao
- 6. Shri Sudarshan Bhagat
- 7. Shri Pallab Lochan Das
- 8. Smt. Agatha K. Sangma
- 9. Smt. Sajda Ahmed
- 10. Shri Kotagiri Sridhar
- 11. Dr. Alok Kumar Suman
- 12. Shri Girish Chandra

#### **RAJYA SABHA**

- 13. Shri Jawhar Sircar
- 14. Shri R. Girirajan
- 15. Smt. Phulo Devi Netam

#### **SECRETARIAT**

- 1. Shri J.M. Baisakh Joint Secretary
- 2. Shri C. Kalyanasundaram Director
- 3. Ms. Rachna Saxena Deputy Secretary

# REPRESENTATIVE OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Shri Chandra Prakash Goyal - DGF&SS

### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE

#### (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

2. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

#### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

3. Shri Roop N. Sunkar - Member (Infrastructure)

Shri Anil Kumar Khandelwal - Principal Executive Director (Gati Shakti)
 Shri Dhananjaya Singh - Executive Director/Gati Shakti (Civil)-II

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ROAD, TRANSPORT AND HIGHWAYS

6. Shri Anurag Jain - Secretary

Shri Amit Kumar Ghosh
 Shri Kamlesh Chaturvedi
 Joint Secretary

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

9. Shri Shailesh Kumar Singh - Secretary

10. Shri Praveen Mahto - Chief Economic Adviser

11. Shri Amit Kataria - Joint Secretary (MGNREGA)

- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the fourth sitting of the Joint Committee. He further apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Railways (Railway Board), Ministry of Road, Transport and Highways and Ministry of Rural Development to brief the Committee on various aspects related to the Forest (Conservation) Amendment bill, 2023. The representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice (Department of Legislative Department) were also present to assist the committee during deliberations. The Chairperson then drew the attention of the representatives from the Ministries to Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
- 4. The representatives of the Ministry of Railways (Railway Board), Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Rural Development explained their views on the amendments proposed in the Bill.
- 5. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill and views of Ministry of Railways (Railway Board), Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Rural Development which were briefly replied by the representatives of Ministry of Railways (Railway Board), Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Rural Development. The Chairperson then directed the Ministries including Nodal ministry *viz.* Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting.

The representatives of the Ministries then withdrew

The Committee then adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

# Minutes of the 5<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The 5<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee was held on Wednesday, the 17<sup>th</sup> May, 2023 from 1215 hrs. to 1315 hrs. in Committee Room No.'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

#### PRESENT

#### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Shri T.R. Baalu
- 3. Dr. Dhal Singh Bisen
- 4. Shri Raju Bista
- 5. Shri Tapir Gao
- 6. Shri Sudarshan Bhagat
- 7. Shri Pallab Lochan Das
- 8. Smt. Agatha K. Sangma
- 9. Smt. Sajda Ahmed
- 10. Shri Kotagiri Sridhar
- 11. Dr. Alok Kumar Suman
- 12. Shri Girish Chandra

#### **RAJYA SABHA**

- 13. Shri Jawhar Sircar
- 14. Shri R. Girirajan
- 15. Smt. Phulo Devi Netam

### **SECRETARIAT**

1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary

2. Shri C. Kalyanasundaram - Director

3. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Shri Chandra Prakash Goyal - DGF&SS
 Shri S P Yadav - ADG

3. Shri Ramesh Kumar Pandey - Inspector General of Forests

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

4. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF JAL SHAKTI (DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION)

5. Ms. Vini Mahajan - Secretary

Shri Samir Kumar - Economic Advisor

#### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF MINES

7. Shri Sanjay Lohiya - Additional Secretary

8. Shri Mustaq Ahmad - Director

9. Shri Pradeep Singh - Director (Technical)

#### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (DoNER)

10. Shri Lok Ranjan, IAS (TR:1989) - Secretary

1. Shri Angshuman Dey, IFS (TR:1997) - Joint Secretary

- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the fifth sitting of the Joint Committee. He further apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of Ministry of Jal Shakti (Department of Drinking Water and Sanitation), Ministry of Mines and Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER) to brief the Committee on various aspects related to the Forest (Conservation) Amendment bill, 2023. The representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice (Department of Legislative Department) were also present to assist the committee during deliberations. The Chairperson then drew the attention of the representatives from the Ministries to Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
- 4. The representatives of Ministry of Jal Shakti (Department of Drinking Water and Sanitation), Ministry of Mines and Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER) explained their views on the amendments proposed in the Bill.
- 5. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill and views of Ministry of Jal Shakti (Department of Drinking Water and Sanitation), Ministry of Mines and Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER) which were briefly replied to by the representatives of Ministry of Jal Shakti (Department of Drinking Water and Sanitation), Ministry of Mines and Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER). The Chairperson then directed the Ministry *viz*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting.

The representatives of the Ministries then withdrew

The Committee was adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

# Minutes of the $6^{th}$ sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The 6<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 30<sup>th</sup> May, 2023 from 1030 hrs. to 1230 hrs. in Committee Room No. 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

#### **PRESENT**

#### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Shri T.R. Baalu
- 3. Dr. Dhal Singh Bisen
- 4. Shri Tapir Gao
- 5. Shri Ajay Tamta
- 6. Shri Sudarshan Bhagat
- 7. Smt. Agatha K. Sangma
- 8. Shri Rajendra Dhedya Gavit
- 9. Shri Girish Chandra
- 10. Shri Pradyut Bordoloi

#### **RAJYA SABHA**

- 11. Dr. Ashok Bajpai
- 12. Dr. Prashanta Nanda
- 13. Shri Birendra Prasad Baishya
- 14. Shri R. Girirajan
- 15. Smt. Phulo Devi Netam

#### **SECRETARIAT**

Shri J.M. Baisakh
 Ms. Rachna Saxena
 Deputy Secretary

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Shri Chandra Prakash Goyal - DGF&SS
 Shri S P Yaday - ADG

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

3. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

## EXPERTS/ STAKEHOLDERS/ORGANIZATIONS

4. Smt. Brinda Karat - Ex-Member of Parliament, Rajya Sabha

5. Dr. Prashant Kumar Jha - Principal Chief Conservator of Forests (PCCF).

(Retd.), Telangana Forest Department

6. Shri R.D. Kamboj - Addl. Principal Chief Conservator of Forests

(PCCF) (Retd.), Gujarat Forest Department

7. Shri Suresh Chopane - Member, Regional Empowered Committee

(REC), Nagpur and Raipur (Ministry of Environment, Forest & Climate Change)

President - Green Planet Society

8. Shri K. Ravichandran - Director- Indian Institute of Forest

Management (IIFM)

9. Dr. Ravindra Kumar Singh - Principal Chief Conservator of Forests

(PCCF) (Retd.) Chhattisgarh Forest Department

- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the sixth sitting of the Joint Committee. He further apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairperson invited the experts to brief the Committee on various aspects related to the Forest (Conservation) Amendment bill, 2023. The representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice (Department of Legislative Department) were also present to assist the committee during deliberations. The Chairperson then drew the attention of the witnesses present to the Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
  - 4. Then, the experts, one by one, explained their views on the amendments proposed in the Bill.
- 5. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill and views of the experts which were briefly replied to by the experts. The Chairperson then directed the Ministry *viz*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting.

The witnesses then withdrew.

The Committee was adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

# Minutes of the 7<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The 7<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 30<sup>th</sup> May, 2023 from 1230 hrs. to 1400 hrs. in Committee Room No.'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

#### **PRESENT**

#### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Shri T.R. Baalu
- 3. Dr. Dhal Singh Bisen
- 4. Shri Tapir Gao
- 5. Shri Ajay Tamta
- 6. Shri Sudarshan Bhagat
- 7. Smt. Agatha K. Sangma
- 8. Shri Rajendra Dhedya Gavit
- 9. Shri Girish Chandra
- 10. Shri Pradyut Bordoloi

#### RAJYA SABHA

- 11. Dr. Ashok Bajpai
- 12. Dr. Prashanta Nanda
- 13. Shri Birendra Prasad Baishya
- 14. Shri R. Girirajan
- 15. Smt. Phulo Devi Netam

#### **SECRETARIAT**

Shri J.M. Baisakh
 Ms. Rachna Saxena
 Deputy Secretary

## REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Shri Chandra Prakash Goyal - DGF&SS
 Shri S P Yadav - ADG

### REPRESENTATIVE OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE

### (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

3. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

#### EXPERTS/ STAKEHOLDERS/ORGANIZATIONS

4. Shri Shahbaz Ahmad - Indian Forest Service (IFS) (Retd.)
Ex-Principal Chief Conservator of
Forests & Chief Wildlife Warden, MP

5. Shri Debi Goenka - Executive Trustee, Conservation Action Trust

6. Shri Abhinav Gaur - Advocate, Allahabad High Court

7. Shri Praveen Bhargav - Trustee Wildlife First,

Former Member – National Board for Wildlife Author – Wildlife Law for Rangers

8. Shri Manoj Patil - Convener, Vibrant India Economic

Council (VIEC), Mumbai

9. Shri Bijaya K Panda - Convener, Bharat Jan Andolan

(Chhattisgarh Bachao Andolan)

- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the seventh sitting of the Joint Committee. He further apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairperson invited the experts to brief the Committee on various aspects related to the Forest (Conservation) Amendment bill, 2023. The representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Law & Justice (Department of Legislative Department) were also present to assist the committee during deliberations. The Chairperson then drew the attention of the witnesses present to the Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
  - 4. Then, the experts, one by one, explained their views on the amendments proposed in the Bill.
- 5. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill and views of the experts which were briefly replied to by the experts. The Chairperson then directed the Ministry *viz*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting.

The witnesses then withdrew.

The Committee was adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

# Minutes of the 8<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The 8<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 26<sup>th</sup> June, 2023 from 1100 hrs. to 1300 hrs. in Committee Room No.'1', Extention to Parliament House Annexe, New Delhi.

#### PRESENT

### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Shri T.R. Baalu
- 3. Dr. Dhal Singh Bisen
- 4. Shri Raju Bista
- 5. Shri Tapir Gao
- 6. Shri Suresh Kumar Kashyap
- 7. Smt. Gomati Sai
- 8. Shri Sudarshan Bhagat
- 9. Km. Diya Kumari
- 10. Smt. Agatha K. Sangma
- 11. Shri Rajendra Dhedya Gavit
- 12. Dr. Alok Kumar Suman
- 13. Shri Pradyut Bordoloi

#### **RAJYA SABHA**

- 14. Dr. Ashok Bajpai
- 15. Shri Samir Oraon
- 16. Dr. Prashanta Nanda
- 17. Shri Birendra Prasad Baishya
- 18. Shri R. Girirajan

#### **SECRETARIAT**

Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary

2. Shri C. Kalyanasundaram - Director

3. Ms.Rachna Saxena - Deputy Secretary

#### REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Smt. Leena Nandan - Secretary
 Shri Chandra Prakash Goyal - DGF&SS

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

1. Shri Udaya Kumara - Joint Secretary & Legislative Counsel

# REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

- 1. Dr. Padmini Singh Joint Secretary & Legislative Adviser
- 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the eighth sitting of the Joint Committee and apprised the Members about the agenda of the sitting.
- 3. Thereafter, the Chairperson also welcomed the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Ministry of Law & Justice and initiated the deliberations on the Clause by Clause consideration of the proposed

amendments in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023. The representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change assisted the Committee during deliberations.

- 4. The Members of the Committee put forth their views on the proposed amendments in Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 and the representatives of Ministry explained the queries raised by the Members.
- 5. After detailed deliberations, the Committee accepted all the proposed amendments in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

The sitting of the Committee then adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.

# Minutes of the 9<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

The 9<sup>th</sup> sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 11<sup>th</sup> July, 2023 from 1500 hrs. to 1530 hrs. in Committee Room No. 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

#### **PRESENT**

#### Shri Rajendra Agrawal - Chairperson

#### LOK SABHA

- 2. Shri Tapir Gao
- 3. Shri Sudarshan Bhagat
- 4. Shri Pallab Lochan Das
- 5. Km. Diya Kumari
- 6. Smt. Agatha K. Sangma
- 7. Dr. Alok Kumar Suman
- Shri Girish Chandra

#### RAJYA SABHA

- 9. Shri Samir Oraon
- 10. Dr. C.M. Ramesh
- 11. Dr. Prashanta Nanda
- 12. Shri Birendra Prasad Baishya
- 13. Shri R. Girirajan
- 14. Smt. Phulo Devi Netam

#### **SECRETARIAT**

1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary

2. Shri C. Kalyanasundaram - Director

3. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary

- 2. At the outset, Chairperson welcomed the Members of the Joint Committee to the sitting of the Committee convened for consideration and adoption of Draft Report of the Committee. The Committee considered the Draft Report in entirety and adopted the same. The Committee also authorised the Hon'ble Chairperson to finalize and present the Report in Lok Sabha and lay the same on the table of the Rajya Sabha.
- 3. The Chairperson also announced that if any member desired to give any dissent note, the same may be submitted to the Secretariat by 4:00 pm on 13 July 2023.
- 4. Thereafter, the Chairperson in his concluding remarks thanked all the members of the Joint Committee for their unstinted support and cooperation which enabled the Committee to examine and finalize the report on an important legislation within defined time frame of time. The Chairperson, also placed on record the appreciation for the relentless assistance rendered to the Committee by the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat.

#### The Committee then adjourned.

### **APPENDIX-VIII**

### Notes/Minutes of dissent received from the Members of the Joint Committee

#### PRADYUT BORDOLOI

#### MEMBER OF PARLIAMENT (LOK SABHA)

# MEMBER, STANDING COMMITTEE OF PETROLEUM & NATURAL GAS MEMBER. COMMITTEE OF RULES. LOK SABHA

#### MEMBER, CONSULTATIVE COMMITTEE OF MINISTRY OF POWER, NEW AND RENEWABLE ENERGY

D.O. No. MP: Nowgong: 03 Date: 26th June, 2023

Shri Rajendra Agarwal,

Chairperson,

Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

Respected Shri Agarwal ji,

# Subject: Comments of dissent on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 (TBD) for inclusion in the JPC Report.

At the outset, I would like to appreciate efforts being undertaken to conduct vital public consultation as a part of the Committee's examination of the Forest (Conservation) Amendment Bill 2023. This is crucial for strengthening environmental protection mandate and building collective responsibility around forest conservation in India. I am thankful to you for allowing me to interact extensively during the hearings.

While the preamble of the proposed Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 invokes India's rich tradition of preserving forests and their importance in achieving net zero emission targets, there is reason to believe that the substance of the proposed changes will, however, emasculate the original Forest Conservation Act (FCA), thereby subverting the FCA's primary objective of providing for conservation of forests and checking further deforestation. The following are my detailed clause-wise comments, which are put forward for the Committee's consideration and if necessary, regarded as comments of dissent for the record.

# 1. Clause 3: Changing title of the Act from "Forest (Conservation) Act" to "Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam

Given that the FCA is of great importance to people across the country, 60% of which are dependent on forests and other ecosystems directly for their sustenance and livelihood, it is vital that is inclusive in its terminologies, not leaving out population in non-Hindi speaking regions, including the South and the North-East regions.

#### 2. Clause 4: Insertion of Section 1A (subsection 1) regarding lands to be covered under the FCA

a. By proposing to include only those lands within the ambit of the FCA which are recorded as the forest on or after 25th October 1980, a significant section of forest land area will be exempted, especially because large tracts of forest land in India were recorded as 'forest' during transfer of lands to the forest department while abolishing the Zamindari system in respective states after independence (in 50s-70s). A large section of such transferred land could not be notified as forest under the Indian Forest Act, 1927, or state forest legislations because of improper demarcation, ownership disputes and administrative lethargy. However, such lands continue to be protected as forests under the FCA, irrespective of their ownerships. Such forests can be easily found in ecologically rich landscapes like the Aravallis, central Indian plateaus, western ghats, etc and are important as wildlife habitats providing critical ecological services. These biodiversity hotspots will no longer be considered 'forest' and can potentially be sold, diverted, cleared, felled, utilized, exploited without any regulatory oversight, if the bill is passed in its current form.

b. Such an amendment would dilute the Hon'ble Supreme Court's 1996 landmark Godavarman judgment which widened the scope of the FCA to apply to any land recorded as forest by the government irrespective of its ownership. The proposed amendment would in effect limit the scope of the forest clearance mandate under the FCA at a time when India is rapidly losing essential forest cover.

#### Clause 4: Insertion of Section 1A (subsection 2) regarding lands to not be covered under the FCA:

The proposition to exempt certain categories of land from provisions of forest clearance bears the following grave implications:

a. <u>Threat to bio-sensitive areas</u>: Significant forests in Himalayan. Trans- Himalayan and **North Eastern regions**, which are rich with endemic biodiversity will be exempted because of their proximity to international borders. Clearing

of such forests without any assessment and mitigation plan will not **only threaten the biodiversity but will also increase the vulnerability of the ecologically and geologically sensitive areas, which are already threatened by unsustainable infrastructure developments and extreme weather events**. Blanket exemptions for border
infrastructure projects are problematic as they have significant impact on sensitive landscape and biodiversity, and may
adversely impact the infrastructures themselves, due to resultant environmental hazards in case of extreme weather
events.

- **b.** Wide scope of terminology: The usage of forest land for 'security-related infrastructure' and 'public utility' is also very wide and can be used to establish a variety of infrastructure projects on forest lands without applying for forest clearance. For example, public utility services are commonly understood as services provided by the government essential to citizens' requirements. This includes transport, postal, telephone, power, water, etc. This virtually allows the construction of any project on forest land.
- **c.** Further, in Amendment of Section 2, further exemptions are provided using **vague terminology** like **'proposed'**, **'ecotourism facilities', and 'any other purposes'** which can be exploited or misused for activities damaging forests and ecosystems in forest lands. Bringing all zoos, safaris and forest training infrastructures within the ambit of forestry activities, is inconsistent with the FCA and the FCA Guidelines, 2019 which clearly differentiate low footprint conservation establishments from exhibition-oriented outreach centers. Further, this may disproportionately commercialize forests and disturb forest ecosystems.
- **d.** The exemptions provided for are bound to **promote commercialisation of forests** (including notified forests) and **cause irreversible disturbance to wildlife**. It is a common misconception that wildlife only occurs inside Protected Areas (PA). On the contrary, areas outside PA are considered to support essential habitats and biodiversity.

The proposed Bill makes no provision for any impact assessment or any kind of regulatory oversight on the loss of habitats and species, nor would there be any remedies available for interventions to raise concerns. Roads, railway lines and such linear intrusions have a disproportionately vast impact on wild habitats and wildlife as it fragments, erodes natural forests. Removing safeguards in such a blanket manner will only further jeopardise, degrade and destroy forests.

#### 4. Clause (1) (a) (2) (c)

Blanket exemption of 100 km from international border is of particular concern in the North East region, due to proximity to international borders & small size of state as a result, will subsume the entire state and open up pristine forest areas along with its biodiversity for non-forestry uses without FCA regulation. Further, the ecologically fragile landscape along the LAC has the majority of the Protected Areas with critically threatened endemic species of flora and fauna, whose conservation will be threatened.

#### 5. Clause 5: Insertion of sub-section 2 of Section 2:

This section which exempts survey activities, such as, reconnaissance, seismic survey and drillings by Oil Companies, prospecting, investigation or exploration from FCA clearance, would open vast tracts of biodiversity rich forest across the country for scoping, prospecting and surveys for coal, iron ore, diamond and other mining, as well as for oil with no environmental safeguards Also at risk is our 7,517 kilometers long coastline and 1,382 islands from deep sea mining for deposits of minerals which will pave the way for commercial exploitation. Once scoping is done, analysis indicates that clearances for projects is usually a fait accompli. The proposed exemptions for all surveys and investigations are arbitrary in nature, and such exemptions should instead depend on the underlying project and its implications on the forest and associated wildlife.

#### 6. Critically assessing emphasis on carbon neutrality through plantations:

The Bill's focus on raising tradeable vertical repositories of carbon, i.e achieving carbon neutrality through a push for plantations, can jeopardize the very purpose of the Act to protect and conserve India's forests. While India's commitments to meeting national Net Zero Emission targets are important, experts have long argued that **creating carbon sinks via plantations and increasing tree cover is counter intuitive**, and multiple studies, including in India show that these are poor in sequestering carbon, as well as in other ecosystem services such as containing soil erosion, biodiversity conservation, water retention etc. Research has shown that **natural forests are far more effective in this regard**, considering that the carbon sequestration potential of natural forests is 40 times greater as compared to plantations. Further, it is important to consider that the destruction and degradation of forests in itself **contributes to climate change through the release of carbon dioxide (CO<sub>2</sub>).** 

7. Need to foreground forest rights in forest conservation legislation: What remains an obvious gap, even in the statement and objects of the amendment, is the reconciliation of the forest conservation legislation with the forest rights question, which should have been important especially when almost all proposed amendments will necessarily come to bear on prevailing, pending or recognised forest rights. There is an absence of any perspective on how existing proprietary, customary, and livelihood use rights will be dealt with for net zero compliant lands or in the case of fresh forest land diversions.

While the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in its response (dated 19th June 2023) has attempted to clarify some of the above mentioned points, concerns persist as there is an overwhelming reliance on implied meaning of provisions rather than categorically laying out safeguards in the text of the amendment. Further, on the question of ensuring safeguards, one observes a tendency to leave terms & conditions to the discretion of the Executive at subsequent junctures, creating scope for misinterpretation and misuse.

India's ancient civilisation and culture is closely linked to nature. Millions of marginalized and indigenous people continue to depend on forests for their sustenance and livelihood and will be rendered even more vulnerable were the proposed amendments come to pass. I strongly believe that rather than weakening regulation, amendments to India's Forest Conservation Act must focus on ensuring more effective implementation of conservation practices, especially in view of the accelerating threat of climate change.

Regards,

(PRADYUT BORDOLOI)

Relevant Provisions of Principal Act	Provisions proposed in Amendment Bill	Comments of Shri Pradyut Bordoloi, MP Lok Sabha (Member JPC)	Suggestion for Redrafting
1(1) This Act may be called the Forest (Conservation) Act, 1980.	Amendment of section 1. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and brackets "Forest (Conservation) Act", the words and brackets "VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM" shall be substituted.	Should be amend to make it more acceptable to all across the country.  A separate Hindi translated version can be made available alongside the English version, for the purpose of improved accessibility.	English Translation of Bill: This Act may be called the Forest (Conservation) Act, 1980 Appropriate Hindi name can be inserted
Not applicable (provisions do not exist in the Principal Act).	Insertion of new section 1A-Act to cover certain land.  After section 1 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—  "1A. (1) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—	1) Subsection 1A(1)(b) along with the proviso can be potentially misinterpreted to create an exception to the Supreme Court's judgment in T.N. Godavaraman case dated 12.12.1996 (which imposed applicability of Section 2 of the Act to any area recorded as forest in the Govt record irrespective of ownership and date)  This has negative implications on the applicability of Section 2 of the Act, which mandates permission of the Central Government for any non-forest activity on lands recorded as forest in 'government record', which also includes lands that are not notified under a statute.  2) The new changes also omit the category of lands which are neither notified nor recorded as forests in any government records but qualify the characteristics of a natural forest including those proposed to be notified as forest.  As per the latest FSI's "India State of Forest Report" (2021), Unclassed Forests account for approximately 15% of India's total forest cover, and in some States and Union Territories Unclassed Forests are a massive portion of their total forest cover. Some of these states constitute some of India's most unique and endangered biodiversity-rich regions (biodiversity-rich regions (biodiversity-rich regions (biodiversity-hotspots).	

	I		
		For instance, in  Northeast India, 97.2% of Nagaland's, 88.2% of Meghalaya's, 75.6% of Manipur's, 53% of Arunachal Pradesh's and 33.4% of Assam's total forest are categorized as unclassed forest. There is a concern that most of such lands may be exempted from the FCA as they are recorded as forests much before 1980.	
		3) The new changes also exclude those forest lands which are proposed to be declared forests but yet to be notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 or other state laws. (For e.g in Assam, nearly 730 sq.km. of lands are in the process of notification as RF from the existing category of Proposed RF under Assam Forest Regulation Act, 1891.)	
Not applicable (provisions do not exist in the Principal Act).	The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—  (a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.  (b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October, 1980:		The following land shall be covered under this Act, namely: —  (b) the land that has been declared or notified or is under the process of being notified as a forest following the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.  (b) the land that is not covered under clause (a) but has been recorded in Government records as forest irrespective of their ownership.  (c) the land that is not covered under clauses (a) or (b) but is recognizable as forests by local communities or in terms of its ecological and cultural significance.  (d) the land that is not covered in clauses (a), (b), (c) but identified or used for compensatory afforestation in lieu of

			forest diverted under Section 2 of the Act.
	Proviso Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for non-forest purpose on or before the 12th December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf:	There have been many instances where the States have unlawfully diverted lands recorded as forests for nonforest activities in the violation of the Act. The proposed amendment attempts to legalize such diversions.  The Supreme Court has reiterated that the primary purpose of the FCA is to prevent further deforestation, and any interpretations must sub-serve and help implement the intention of the Act.	Recommend to be deleted from amendment
		Many of such forest lands were diverted on lease for activities such as plantations, mining etc., by the States before 12th December, 1996 or even before the enactment of the FCA in 1980. For instance, Gavi, a RF in the core area of the Periyar Tiger Reserve, was leased to Kerala Forest Development Corporation for the cultivation of cardamom before 1980. The lease is set to expire in 2026, after which new permission will be required to be obtained under Section 2 of the Act. However, if the proposed amendment is accepted, many of such leased forest areas may get permanently diverted for such non-forest activity. This may also allow the lessee to change the nature of such plantation for other non-forest purposes like tourism, infrastructure etc.	
Not applicable (provisions do not exist in the Principal Act).	1A. (2) (a) The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely:—  (a) such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by the Government, which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;	Exemptions for roadside amenities are regressive and ultra vires the FCA. The new changes will fragment forest areas and will be detrimental to wildlife habitats and corridors, especially with lack of specifics with respect to the frequency of these facilities along such linear projects makes vast forest areas susceptible.  Already many railway lines such as Rail line thro the Deepor Beel (a Ramsar Site) on the outskirts of Guwahati City and roads pass through sensitive biodiversity	Recommend to be deleted from the amendment

	rich areas. More road and railways infrastructure are proposed to be constructed in upcoming years, which are going to fragment forests and affect wildlife in other parts of the country.	
	Granting any exemptions to areas alongside the roads will not only lead to massive deforestation but create multiple disturbance to forests and put immense pressure on wildlife. Linear infrastructure significantly affects and reverses the decades old conservation efforts to protect endemic flora and fauna, in many cases roads and railways are one of the major reasons of fatalities of protected species. According to reports, 45 elephants died between 2019-2021 and 26 tigers died between 2010-2021 due to railway accidents.	
	For development of access roads to adjoining villages or human habitations, diversion of forest lands must be allowed judiciously following due procedure of forest clearance under Section 2 of the Act and in such a manner that it causes minimum disturbance to the forest and wildlife, rather than through blanket exemption.	
(1) (a) (2)(b) such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1); and	Need for clarity on definition of 'reafforestation' and whether it is different from 'reforestation' - planting of trees on non-forest land or planting of trees on land which was previously forest. Act must define the term 'reafforestation' to prevent ambiguity or misuse.	Definition of 'reafforestation' to be recommended for addition
(1)(a)(2)(c) such forest land,— (i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or	According to the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, between 1996-2016, defence projects have taken up the second largest amount of forest land (1,549 sq.km.), second only to mining (4,947 sq.km.).  Strategically important linear infrastructures are already given	Recommend to be deleted from the amendment

(ii) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure; or

(iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or **public utility projects**, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.

permissions expeditiously by the Central Government under 'general approval' scheme. In such circumstance, blanket exemption is unreasonable and unwanted.

Infrastructure and linear development projects Himalayan and North-Eastern India involve activities such as blasting and excavation, creating tunnels, damming of water streams etc.. which significant and irreversible damage to the ecologically sensitive landscape of these regions. Experts have pointed Out the role of such infrastructure development as a significant contributor in intensifying the impact of extreme weather events leading to landslides and severe floods.

As per (1)(a)(2)(c) (iii) the term 'public utility' remains ambiguous, open ended and open to interpretation - such exemptions blanket undesirable but are also inconsistent, and ultra vires to the purpose of FCA. Accordingly, permission for activities must be granted on a case-on-case basis following due procedure under Section 2 of the Act.

# (1)(a)(2)(c)

Blanket exemption of 100 km from international border is of particular concern in the North East region, due to proximity to international borders & small size of state - as a result, will subsume the entire state and open up pristine forest areas along with its biodiversity for non-forestry uses without FCA regulation. Further, ecologically fragile landscape along the LAC has the majority of the Protected Areas with critically threatened endemic species of flora and fauna, whose conservation will be threatened.

**Suggestion:** prior to availing exemption for security related infrastructure, in forest areas, it is proposed that listed agencies would consult stakeholders mainly local communities residing nearby. As these forest areas form multiple use areas accessed by the local communities - no blanket exemption, but case-by-case forest clearance based on stakeholder consultation.

#### While plantations may provide Recommend to be deleted (1)(a)(3)some benefits, they do not The exemption provided under subfrom the amendment section (2) shall be subject to such provide the same level of terms and conditions, including the ecological services as natural conditions of planting trees to forests. Plantations, however, compensate felling of can exacerbate soil erosion and undertaken on the lands, as the degrade soil quality, as they Central Government may, often require intensive by fertilization, pesticide use, and guidelines, irrigation. Further, plantations specify. do not provide habitat for the wildlife, as they do not contain the structural complexity and diversity of natural forests. Therefore, it is important to prioritize protection restoration of natural forests and to manage them sustainably, rather than relying on plantations as a replacement. Any afforestation operation must be undertaken with the objective of ecological restoration augmenting and native biodiversity. Section Section 2(1) (iii) The purpose of such leasing of (iii) that any forest land or (iii) that any forest land or any forest lands by the state must be any portion thereof may be 2(1) (iii) ensured for conservation of assigned by way of lease portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any forests and wildlife only. or otherwise to any private private person or to any authority, person or to any authority, corporation, agency or any other corporation, agency, or organization subject to such terms any other organization and conditions, as the Central unless it is in the interest Government may, by order, specify; of in situ conservation of forest and wildlife. subject to such terms and conditions, as the Central Government may with reason prescribe; purpose for all such Section 2 other The Any purpose other than Any purpose than must be to reafforestation, but does reafforestation, but does not include establishments (1)(b)any work relating to or ancillary to protect and conserve the forests not include any work conservation, development and and wildlife, and not for any relating to or ancillary to management of forests and wildlife, leisure or commercial purposes. conservation, development Thus, it is essential that and management of forests sufficient reasoning is provided and wildlife, which shall certified for such developments as a by necessity for forests and wildlife concerned Chief Wildlife conservation. Warden or Principal Under the provision Chief Conservator with exemption of works 'ancillary to reasons in writing. conservation', the Act must also specify the Certified Authority Need for Act to which would decide whether the define work falls under the category of 'reafforestation'. ancillary or related work. It is suggested that the Certified

		<b>Authority</b> with respect to conservation of wildlife should be the Chief Wildlife Warden or Principal Chief Conservator of Forest ("PCCF") with respect to forest conservation.	
Section 2(1) (b)	i. silvicultural operations including regeneration operations;	Silvicultural operations must be undertaken with the objective of ecological restoration and augmenting native biodiversity.	i. silvicultural operations including regeneration operations which are purported to restore the original flora of the area and do not include plantation of species exotic to the area in question or causing disturbance to the wildlife;
	ii. establishment of check-posts and infrastructure for the front-line forest staff;	Specify to prevent misuse (such as illegal collection of money allowing extraction of forest materials)	Establishment of check- posts and infrastructure for the front-line forest staff, that do not affect or disturb the movement of wild animals
	iii. establishment and maintenance of fire lines;		No change
	iv. wireless communications;	Specify to prevent misuse	iv. wireless communications which are required for the front-line forest staff;
	v. construction of fencing, boundary marks or pillars, bridges and culverts, check dams, waterholes, trenches and pipelines;	Specify to prevent misuse	v. construction of fencing, boundary marks or pillars, bridges and culverts, check dams, waterholes, trenches and pipelines, solely required for the purpose of forest and wildlife conservation and certified as such by the concerned Chief Wildlife Warden or Principal Chief Conservator of Forest.
	vi. establishment of zoo and safaris referred to in the Wild Life (Protection) Act, 1972, owned by the Government or any authority, in forest areas other than protected areas;	Allowing zoos and safaris within the scope of non-forest activities in the FCA will disproportionately commercialise forests and wildlife.  Such establishments not only come at the cost of	Recommend to be deleted from the amendment

	fragmentation and destruction of existing forest and wildlife habitats, but have a huge cumulative impact from associated infrastructure, access routes, public amenities and other disturbances which cannot be termed as beneficial to the forests and wildlife.	
vii. eco-tourism facilities included in the Forest Working Plan or Wildlife Management Plan or Tiger Conservation Plan or Working Scheme of that area; and	In recent years mushrooming of tourism facilities has led to overuse, disturbance and serious management problems in several PAs. The National Wildlife Action Plan defines eco-tourism as eco-friendly and regulated wildlife-based tourism and also states that in case of any conflict between tourism and conservationinterests of a PA, the paradigm for the decision must be that tourism exists for the Protected Areas and not vice versa, and that demands of tourism must be subservient to and in consonance with the conservation interests of Protected Areas.  The exemption of establishment of eco-tourism facilities be deleted, instead they may be regulated as per the existing procedure of forest clearance under Section 2 of the FCA and decided on a case-to-case basis keeping in view the local circumstances and species affected.	Recommend to be deleted from the amendment
viii. any other like purposes, which the Central Government may, by order, specify."]	Specify to prevent misuse	viii. any other like purposes necessary for conservation of forest and wildlife, which the Central Government shall by reason prescribe.
Section 2 (2) The Central Government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-forest purpose.	Exemption of permission for conducting such surveys will open the floodgates for conducting surveys for purely commercial activities like mining. Some of these surveys or investigations might require drilling/digging of surface, clearing of vegetation, levelling of ground, creating access roads and producing high decibel	Recommend to be deleted from the amendment

noise or use of light at night or any other activity which might be detrimental to the wildlife and the ecosystem. Recently, the Gauhati High Court stayed Environmental Clearance to Oil India Limited with respect to exploration and drilling through extended reach drilling for hydrocarbons at seven locations in Dibru Saikhowa National Park due to the absence of a Biodiversity Impact Assessment. Therefore, a blanket exemption to such surveys is not recommended. It is suggested that the exemption to survey,

Therefore, a blanket exemption to such surveys is not recommended. It is suggested that the exemption to survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation, or exploration be deleted, and the existing procedure for permission under Section 2 of the Act be continued for such activities.

Email		<b>Joint Committee on Forest Conservation</b>
From:	Pradyut Bordoloi pradyut.bordoloi@sansad.nic.in	Fri, Jul 14, 2023 01:36 PM
Subject:	Re: Sir/Madam, You have Received an Email from Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 (JCFCAB), Lok Sabha Secretariat	
To:	Joint Committee on Forest Conservation <jcfcab- iss@sansad.ni<="" td=""><td>ic.in&gt;</td></jcfcab->	ic.in>

Dear Chairman,

I as member of the JPC could not attend the last meeting held on the adoption of the report hereby confirm that I have read the report and already sent my letter of dissent to be recorded as per the Direction clause 87 by the Speaker.

Best regards,

Pradyut Bordoloi MP Lok Sabha

----Original Message-----

From: jcfcab-lss@sansad.nic.in

To: pradyut bordoloi <pradyut.bordoloi@sansad.nic.in>

Sent: Fri, 14 Jul 2023 13:14:34 +0530 (IST)

Subject: Sir/Madam, You have Received an Email from Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 (JCFCAB), Lok Sabha Secretariat

Madam/Sir,

Kindly see the attached documents on the above mentioned subject.

Regards

JCFCAB Cell



फूलोदेवी नेताम सांसद राज्य सभा (छत्तीसगढ़) PHULODEVI NETAM Member of Parliament Rajya Sabha-Chhattisgarh Member-Standing Committee on Railways

बंगला नं. 34, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़,

नई दिल्ली-110001

34, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-110001 E-mail: phulodevi.netam@sansad.nic.in

Mob.: +91-9425597472

दिनांक: 10.07.2023 MPRS/CG/2023-10

आदरणीय श्री अग्रवाल जी.

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 पर संयुक्त संसदीय सिमिति का गठन किया। गया था जिसकी मैं भी सदस्या हूँ। सिमिति ने सदस्यों की कई बैठकें की कई राज्यों का दौरा किया, कई मंत्रालयों के साथ चर्चा की, सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा की और उसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। मैंने भी अपने विचार सिमिति की बैठकों में रखे थे। वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने उचित है जिन्हें सभी बैठकों में प्रमुखता से उठाया गया है जो निम्नलिखित है

# 1. खंड 3: वन (संरक्षण) अधिनियम का शीर्षक बदलकर 'वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम' किया जाना ।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 में शीर्षक संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है कि इसका शीर्षक 'वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम रखा जाए। चूंकि वन संरक्षण से संबंधित अधिनियम हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां कि 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अपने भरण-पोषण और आजीविका के लिए जंगलों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों पर ही निर्भर है। अधिनियम की शब्दावली में सभी का समावेश होना आवश्यक है चाहे वो नॉर्थ-ईस्ट हो या दक्षिण भारत जहां गैर हिंदी भाषी आबादी रहती है इसलिए अधिनियम का शीर्षक नहीं बदला जाना चाहिए।

# 2. खंड 4: एफसीए के तहत कवर की जाने वाली भूमि के संबंध में धारा 1ए (उपधारा 1) को सम्मिलित किया जाना ।

बिल प्रावधान करता है कि दो प्रकार की भूमि अधिनियम के तहत आएगी (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित / अधिसूचित भूमि या (ख) पहली श्रेणी में न आने वाली भूमि, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद बन के रूप में अधिसूचित। इसके अलावा अधिनियम 12 दिसम्बर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग में गैर-वानिकी उपयोग में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा, जिसका आदेश किसी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत अथॉरिटी ने दिया है।

यहां एफसीए के दायरे में केवल उसी भूमि को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है जो 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद वन के रूप में दर्ज है, ऐसे में वन भूमि क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को विशेष रूप से छूट दी जाएगी क्योंकि भारत में वन भूमि के बड़े हिस्से को हस्तातरण के दौरान वन के रूप में दर्ज किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद संबंधित राज्यों में जमींदारी प्रथा को समाप्त करते हुए वन विभाग को भूमि का आवंटन हुआ। अनुचित सीमांकन, स्वामित्व, विवादों और प्रशासनिक सुस्ती के कारण ऐसी हस्तांतरित भूमि के एक बड़े हिस्से को भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य वन विधानों के तहत वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सका। हालांकि, ऐसी भूमि को एफसीए के तहत बनों के रूप में संरक्षित किया जाना जारी है, भले ही उनका स्वामित्व कुछ भी हो ऐसे वन अरावली मध्य भारतीय पठार, पश्चिमी घाट आदि जैसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध परिदृश्यों में आसानी से पाए जा सकते हैं और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने वाले वन्यजीव आवास के रूप में महत्वपूर्ण हैं।

यदि विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है, तो इन जैव विविधता वाले हॉटस्पाट का अब वन नहीं माना जाएगा और इन्हें संभावित रूप से बिना किसी नियामक निरीक्षण के बेचा जा सकता है, काटा एवं हटाया जा सकता है।

# 3. खंड 4: एफसीए के तहत कवर नहीं की जाने वाली भूमि के संबंध में धारा 1ए (उपधारा 2) को जोड़ा जाना।

इसके तहत कुछ श्रेणियों को वन मंजुरी के प्रावधानों से छट देने के प्रस्ताव के निम्नलिखित गंभीर परिणाम होंगे जैसे :-

- (a) जैव संवेदनशील क्षेत्रों पर खतरा: हिमालय में महत्वपूर्ण वन एवं पर्वतमालाऐ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो स्थानिक जैव विविधता से समृद्ध है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता के कारण छूट दी जाएगी। बिना किसी assessment और mitigation plan के ऐसे जंगलों को साफ करने से न केवल जैव विविधता को खतरा होगा, बल्कि पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की संवेदनशीलता भी बढ़ेगी, जो पहले से ही अस्थिर बुनियादी ढांचे के विकारा और चरम मौसम की घटनाओं से खतरे में हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूर्ण छूट समस्याग्रस्त है क्योंकि उनका संवेदनशील परिदृश्य और जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और चरम मौसम की घटनाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय खतरों के कारण बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- (b) शब्दावली का व्यापक दायरा: सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता के लिए वन भूमि का उपयोग भी बहुत व्यापक है वन भूमि पर सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं को बिना Forest clearance के स्थापित किया जा सकेगा। इसमें कई तरह की परियोजनाऐं आ जाती हैं जैसे परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि। यह वस्तुतः वन भूमि पर किसी भी परियोजना के निर्माण की अनुमित देता है।
- (c) इसके अलावा, धारा 2 के संशोधन में प्रस्तावित इकोटूरिज्म सुविधाओं और किसी अन्य उद्देश्य जैसी अस्पष्ट शब्दावली का उपयोग करके छूट प्रदान की जा रही है। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे वन भूमि में वनों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। चिडियाघरों, सफारी और वन प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को वानिकी गतिविधियों के दायरे में लाना एफसीए और एफसीए दिशानिर्देश, 2019 के साथ असंगत है जो स्पष्ट रूप से कम पदिचहन संरक्षण प्रतिष्ठानों को प्रदर्शनी उन्मुख आउटरीच केंद्रों से अलग करता है। इसके अलावा, यह वनों का असंगत रूप से व्यावसायीकरण कर सकता है और वन पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ सकता है।
- (d) विधेयक में प्रदान की गई छूट व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगी और ये वन (अधिसूचित वनों सहित) तथा वन्यजीवों के लिए अपरिवर्तनीय अशांति का कारण होगी। एक आम धारणा है कि वन्यजीव केवल संरक्षित क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते है। जबकि इसके विपरीत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र भी वन्यजीवों के आवास और जैव विविधता वाले क्षेत्र होते है।

प्रस्तावित विधेयक किसी प्रभाव मूल्यांकन या किसी भी प्रकार का अन्य कोई प्रावधान नहीं करता है। इससे वन्यजीवों के आवासों और प्रजातियों के नुकसान पर कोई नियामक निगरानी नहीं होगी। सड़कें, रेलवे लाइन आदि का वन्य जीवों के आवासों और वन्य जीवन पर असमान रूप से व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये प्राकृतिक वनों का क्षरण करते हैं। इस तरह व्यापक तरीके से सुरक्षा उपायों को हटाना केवल और केवल जंगलों को और अधिक खतरे में डालना और नष्ट करना साबित होंगे।

- 4. खंड 6, धारा 3सी: निर्देश जारी करने की शक्ति: विधेयक में सभी जगह यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार केन्द्र, राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण / संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी कर सकती है। चूंकि संविधान के तहत वनों की गणना राज्य सूची में की गई थी लेकिन 42वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे समवर्ती सूची के तहत लाया गया जो वनों पर कानून बनाने के लिए राज्य और केन्द्र की संयुक्त जिम्मेदारी बना देता है लेकिन विधेयक के माध्यम से राज्यों के पास कोई अधिकारी नहीं रह जाएंगे।
- 5. खंड 4 (2) (c) (iii): इस उपधारा के लिए 'जन सुविधा परियोजनाऐं' में निम्नानुसार कार्य शामिल होने चाहिए जिसकी छत्तीसगढ राज्य द्वारा लम्बे समय से मांग की जाती रही है। (1) मोबाईल टॉवर, (2) ओएफसी केबल (3) पैरामिलिटरी बलों और राज्य पुलिस के कैम्प के लिए पहुंच मार्ग और सुरक्षा बलों के लिए हेलीपेड (4) अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी हॉस्टल / आश्रम निर्माण (5) एकलव्य विद्यालयों की स्थापना (जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना) (6) 5 मेगावॉट तक के सौर्य ऊर्जा संयंत्र हेतु, जहां 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर से कम वाले वन भूमि वाले क्षेत्र या पहाड़ / चट्टान जैसे नैसगिक रूप से वृक्ष विहीन क्षेत्रों में
- 6. खंड (1) (a) (2) (c): अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास और उत्तर-पूर्व के छोटे क्षेत्रफल वाले राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 100 कि.मी. तक की पूर्ण छूट विशेष चिंता का विषय है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य को इसमें शामिल कर लिया। जाएगा और बिना एफसीए विनियमन के जैव विविधता के साथ प्राचीन वन क्षेत्रों को गैर वानिकी उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा एलएसी के साथ पारिस्थितिक रूप से नाजुक परिदृश्य में अधिकांश संरक्षित क्षेत्र है जहां गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवों की स्थानिक प्रजातिया है जिनके संरक्षण को खतरा होगा।
- 7. खंड 5: धारा 2 की उपधारा 2 जोडना: यह अनुभाग सर्वेक्षण गतिविधियों, जैसे तेल कंपिनयों द्वारा टोही, भूकंपीय सर्वेक्षण और ड्रिलिंग को एफसीए की मंजूरी, जांच या अन्वेषण से छूट देता है इससे कोयला, लौह के लिए स्कोपिंग, पूर्वेक्षण और सर्वेक्षण के लिए देश भर में जैव विविधता समृद्ध जंगल में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसके इसके साथ ही हमारी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 1,382 द्वीप भी खतरे में आ जाएँगे जहां वाणिज्यिक लाभ के लिए बिना पर्यावरणीय सुरक्षा के तेल और अन्य खिनज भण्डारी का दोहन किया जाएगा। ऐसी छूट जंगल, तटरेखा द्वीप पर रहने वाले वन्यजीवों पर होने वाले विपरीत प्रभाव पर निर्भर होनी चाहिए।

इसके साथ ही एक अन्य प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। किसी भी वन क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को किसी व्यक्ति या अधिकारी, निगम एजेंसी या किसी अन्य संगठन को लीज पर दिया जा सकता है या अन्यथा, जो कि संबंधित राज्य सरकार से परामर्श के बाद केन्द्र सरकार अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 8. वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन तटस्थता पर जोर देगे का आलोचनात्मक मूल्याकन : वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन तटस्थता प्राप्त किए जाने का उल्लेख बिल में किया गया है। यह भारत के जंगलों की रक्षा और संरक्षण के अधिनियम के मूल उद्देश्य को खतरे में डाल सकता है।

हालांकि राष्ट्रीय शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताए महत्वपूर्ण हैं। हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ तर्क दे रहे हैं कि वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक बनाना और वृक्ष आवरण बढ़ाने की दिशा में कई हानियां होंगी जैसे मिट्टी का कटाव होगा, जैव विविधता का संरक्षण नहीं होगा, जल संसाधन समाप्त हो जाएंगे आदि अन्य पारिस्थितिकी तंत्र बिगड जाऐंगे।

एक शोध यह बताता है कि प्राकृतिक वन इस संबंध में कहीं अधिक प्रभावी है और प्राकृतिक वनों की कार्बन अवशोषण क्षमता वृक्षारोपण की तुलना में 40 गुना अधिक है। यह भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि वनों का विनाश और क्षरण स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगा जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।

9. वनों की रक्षा के लिए कर्तव्य का अभाव: बिल में किए गए संशोधन में यह कहीं नहीं दिखता कि ये संशोधन वनों की रक्षा को प्रमुखता देने के लिए लाए गए हैं। संविधान ने सरकार को जंगलों का अभिभावक बनाया है और इस बिल के माध्यम से सरकार अपनी जिम्मेदारी का दुरूपयोग करने की कोशिश कर रही है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को अंधाधुंध वनों की कटाई को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था. जो एक प्रमुख चिंता थी। लेकिन बिल में दिए गए प्रावधानों से यह चिंता खत्म होती नहीं दिख रही।

आशा है उक्त आवश्यक संशोधनों को विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा।

सादर,

भवदीया, (फूलोदेवी नेताम)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल, सांसद अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023

# R. GIRIRAJAN MEMBER OF PARLIAMENT (RAJYA SABHA)



11th July, 2023

### **Dissent Note**

To.

The Chairman.

Joint Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

Sir,

I hereby give my dissent on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 due to the following:

1. The Title of the bill should be understood by all throughout the country as well as the all over the world. English language is known to all the stakeholders.

Therefore the word 'Forest Conservation Act' should be retained as it is understood well throughout the country... Sanskritic Terminology is untenable.

Let it be called the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023

- 2. Forests and conservation of forest is under Concurrent List. State Governments have administrative control over forests. Therefore assigning all powers to Central Government infringes on Federal rights of the State Governments. Any decision should be arrive at only after proper discussion with the State Governments.
- 3. The Proposed amendments are inconsistent and *ultra vires* to the principal Act, severely compromises the constitutional mandate of the State (Article 48A) to safeguard forests, and jeopardizes the access to information, public participation and access to justice, which are essential component of Rio Declaration 1992 and fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution.

Hence I oppose and dissent the Bill.

R. GIRIRAJAN MEMBER OF PARLIAMENT (RAJYA SABHA) TAMIL NADU

#### Point 1

The Title of the bill should be understood by all throughout the country as well as the all over the world. English language is known to all the stakeholders.

Therefore the word 'Forest Conservation Act' should be retained as it is understood well throughout the country... Sanskritic Terminology is untenable.

Let the it be called Forest (Conservation) Amendment Act, 2023

#### Point 2

Forests and conservation of forest is under Concurrent List. State Governments have administrative control over forests. Therefore assigning all powers to Central Government infringes on Federal rights of the State Governments... Any decision should be arrive at only after proper discussion with the State Governments.

### Point 3

The Proposed amendments are inconsistent and ultra vires to the principal Act, severely compromises the constitutional mandate of the State (Article 48A) to safeguard forests, and jeopardizes the access to information, public participation and access to justice, which are essential component of Rio Declaration 1992 and fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution.

Hence I oppose and dissent the Bill.

R. GIRIRAJAN MEMBER OF PARLIAMENT (RAJYA SABHA) TAMIL NADU

# NOTE OF DISSENT SUBMITTED BY SHRI JAWHAR SIRCAR, MP (RAJYA SABHA) AND SMT. SAJDA AHMAD, MP (LOK SABHA) TO THE JOINT COMMITTEE ON THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE FOREST (CONSERVATION) ACT.

#### Suggestion 1.

Please retain original title of the Forest (Conservation) Act and DO NOT include the new words, namely "Evam Samvardhan)"

#### Suggestion 2.

Under section 1A (1), please SUBSTITUTE amendment provision, namely,

"The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely: —

- (a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.
- (b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October 1980"

#### WITH THE WORDS:

"The following land shall be covered under this Act, namely: —

- (a) the land that has been declared or notified or is under the process of being notified as a forest following the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force.
- (b) the land that is not covered under clause (a) but has been recorded in Government records as forest irrespective of their ownership.
- (c) the land that is not covered under clauses (a) or (b) but is recognisable as forests by local communities or in terms of its ecological and cultural significance.
- (d) the land that is not covered in clauses (a), (b), (c) but identified or used for compensatory afforestation in lieu of forest diverted under Section 2 of the Act."

### Suggestion 3.

Again, in 1A (1), please DELETE this part of proposed amendment, ie,

"Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for nonforest purpose on or before the 12th December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf".

#### Suggestion 4

In1A. ((2) where roadside amenities are mentioned,

please SUBSTITUTE THE WORDS

"which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;"

#### WITH THE WORDS:

"which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 1000 square feet in each case;"

### AND ADD PROVISO

"provided there are not more than three such amenities in each cluster and every cluster shall be not less than 50 kilometres apart"

— in order to minimise the disturbance to forests.

#### Suggestion 5.

Again, in 1A (2) b) AFTER the words

"such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1);"

#### ADD PROVISO

"but shall not include compensatory afforestation"

#### Suggestion 6.

Further, in 1A (2), AFTER THE WORDS

"such forest land,-

(i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international", insert "Himalayan" BEFORE CONTINUING as "borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or".

#### Suggestion 7.

And, furthermore, in 1A (2), AFTER THE WORDS

"(3) The exemption provided under sub-section (2) shall be subject to such terms and conditions, including the conditions of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands, as the Central Government"

#### **INSERT**

"in consultation with concerned State Government"

#### THEN CONTINUE

"may, by guidelines, specify."

#### Suggestion 8.

Again, to continue with 1A (2)

the Act must limit the term "public utility projects" in the following phrase

"iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.",

BY CLEARLY STATING THAT such projects shall be directly under Government and it agencies and SHALL NOT BE

"privatised, leased or the operational control of which shall be handed over to any private company or entity".

### Suggestion 9.

In ALL PLACES ADD the words "in consultation with concerned State Governments"

after the words "Central Government" wherever issuing of orders and guidelines appears.

### Suggestion 10.

After Section 2(1) (iii)

"that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organisation subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify;"

### PLEASE INSERT PROVISO

"Provided there are wide public consultations before such assignment with environmentalists, wild life exports and the local community and it is in the interest of in situ conservation of forest and wildlife"

### Suggestion 1

In Section 2 (1) (b), after the words

"any purpose other than reafforestation, but does not include any work relating to or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife,"

### **INSERT THIS PROVISO**

"Provided concerned Chief Wildlife Warden or Principal Chief Conservator of Forests shall certify the same with reasons in writing."

# Suggestion 11.

In Section 2(1) (b) after the phrase

"i. silvicultural operations including regeneration operations;"

# INSERT THIS PROVISO

"Provided that the species shall retain and restore the original ones and shall not be exotic or invasive or disturb the wildlife therein"

Email

Joint Committee on Forest Conservation

From: Jawhar Sircar < jawhar.sircar@sansad.nic.in>

Thu, Jul 13, 2023 12:40 PM

Subject: Forest Conservation Act—Note of Dissent to Report of Joint Committee on Amendments to the Forest Conservation Act.

1 attachment

To: Joint Committee on Forest Conservation < jcfcab-Iss@sansad.nic.in>

Cc: raypurnendu@yahoo.in

Sir/Madam,

I could not attend the last meeting held on 11 July, 2023 but I certify (as per Direction 87 of the 'Directions by the Speaker') that I have read the said report before I file this 'Note of Dissent'.

Jawhar Sircar, MP RS Sent from my iPad Jawhar Sircar Sent from my iPad

Forest Conservation Act .docx 11 KB

**Email** 

### Joint Committee on Forest Conservation

### **Certificate for JCFB Report**

From: Sajda Ahmed <sajda.ahmed@sansad.nic.in>

Fri, Jul 14, 2023 12:31 PM

**Subject:** Certificate for JCFB Report

To: Joint Committee on Forest Conservation <jcfcab -Iss@sansad.nic.in>

Reply To: Sajda Ahmed <sajda.admed@nic.in>

To

The Chairperson

Joint Parliamentary Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill

Dear Sir,

I am writing to inform you that I was unable to attend the JCFB meeting that took place on July 11, 2023. I would like to state that, in accordance with Clause 87 of the "Directions by the Speaker," I have read the report.

With regards

Sajda Ahmed MP / सजदा अहमद

Lok Sabha / संसद सदस्य (लोकसभा)

Uluberia PC, Howrah, West Bengal

Member Department Related Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change

Member Consultative Committee Ministry of External Affairs Govt of India

C-II/5 Tilak Lane NEW DELHI-110001

Tel-011-23782786, FAX-011-23782779

Mob-9836390227, 9871436166(PS)

#### **ANNEXURE - I**

AS INTRODUCED IN LOK SABHA

#### Bill No. 80 of 2023

#### THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023

#### Α

#### **BILL**

further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

**1.** (1) This Act may be called the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

69 of 1980.

**2.** In the Forest (Conservation)Act, 1980 (hereinafter referred to as the principal Act), after the long title and before the enacting formula, the following preamble shall be inserted, namely:—

Insertion of Preamble.

"WHEREAS, the importance of forests is to be realised to enable achievement of national targets of Net Zero Emission by 2070 and maintain or enhance the forest carbon stocks through ecologically balanced sustainable development;

AND WHEREAS, Nationality Determined Contribution targets of the country envisage creating carbon sink of additional 2.5 to 3.0 billion tons of CO2 equivalent by 2030;

AND WHEREAS, the country envisages an increase in the forest and tree cover to one-third of its land area, which is to be given impetus with an enhanced growth trajectory;

AND WHEREAS, India has a rich tradition of preserving forests and their bio-diversity, and, therefore, enhancing forest based economic, social and environmental benefits, including improvement of livelihoods for forest dependent communities is envisaged;

ANDWHEREAS, it is necessary to provide for provisions relating to conservation management and restoration of forests, maintaining ecological security, sustaining cultural and traditional values of forests and facilitating economic needs and carbon neutrality.".

# Amendment of section 1.

**3.** In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and brackets "Forest (Conservation) Act", the words and brackets "Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam" shall be substituted.

# Insertion of new section 1A.

**4.** After section 1 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

# Act to cover certain land

'1A. (1) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—

- (a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force;
- (b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25<sup>th</sup> October, 1980:

Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for non-forest purpose on or before the 12<sup>th</sup> December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf:

Explanation.— For the purposes of this sub-section, the expression "Government record" means record held by Revenue Department or Forest Department of the State Government or Union territory Administration, or any authority, local body, community or council recognised by the State Government or Union territory Administration.

- (2) The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely:—
  - (a) such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by the Government, which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;
  - (b) such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1); and
  - (c) such forest land,
    - (i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or
    - (ii) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure; or
    - (iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.
- (3) The exemption provided under sub-section (2) shall be subject to such terms and conditions, including the conditions of planting trees to compensate felling of tress undertaken on the lands, as the Central Government may, by guidelines, specify.'.

# Amendment of section 2.

- **5.** In the principal Act, section 2 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and—
  - (a) in sub-section (1) as so renumbered,—

- (I) in clause (iii), for the words "not owned, managed or controlled by Government", the words ", subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify" shall be substituted;
- (II) in the Explanation, for the long line occurring after clause (b), the following shall be substituted, namely:—

"but does not include any work relating to or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife, such as—

- (i) silvicultural operations including regeneration operations;
- (ii) establishment of check-posts and infrastructure for the front line forest staff;
- (iii) establishment and maintenance of fire lines;
- (iv) wireless communications;
- (v) construction of fencing, boundary marks or pillars, bridges and culverts, check dams, waterholes, trenches and pipelines;
- (vi) establishment of zoo and safaris referred to in the Wild Life (Protection) Act, 1972, owned by the Government or anyauthority, in forest areas other than protected areas;
- (vii) eco-tourism facilities included in the Forest Working Plan or Wildlife Management Plan or Tiger Conservation Plan or Working Scheme of that area; and
- (viii) any other like purposes, which the Central Government may, by order, specify.";
- (b) after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—
- "(2) The Central Government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-forest purpose."
- **6.** In the principal Act, after section 3B, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 3C.

"3C. The Central Government may, from time to time, issue such directions, to any authority under the Central Government, State Government or Union territory Administration, or to any organisation, entity or body recognised by the Central Government, State Government or Union territory Administration, as may be necessary for the implementation of this Act.".

Power of Central Government to issue directions.

53 of 1972.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Forest (Conservation) Act, 1980 (the Act) was enacted to provide for the conservation of forests and for matters connected therewith or ancillary or incidental thereto. It provides that prior permission of the Central Government is required for dereservation of forest land, use of forest land for non-forest purposes, assigning of forest land by way of lease to private entities and for clearing of naturally grown trees for the purpose of reafforestation.

- 2. After its enactment, new challenges relating to ecological, social and environmental developments, such as, mitigating the impact of climate change, achieving the national targets of Net Zero Emission by 2070 and maintaining or enhancing the forest carbon stock have emerged at national and international levels. Further, keeping in view the aims and objective of the country to increase the forest or tree cover for creation of carbon sink of additional 2.5 to 3.0 billion tons of  ${\rm CO}_2$  equivalent by 2030, and to carry forward the rich tradition of preserving forests and their bio-diversity symbiotically by enhancing forest based economic, social and environmental benefits, including improvement of livelihoods for forest dependent communities, it is necessary to broaden the horizons of the Act.
- 3. Further, prior to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court, dated the 12th December, 1996 (in the matter of *T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India and others*), the provisions of the said Act were applied to notified forest lands and not to revenue forest areas, and non-forestry use in the revenue forest areas was allowed through permissions granted by the Government and various authorities. Subsequent to the said Judgment, the provisions of the Act were applied in the recorded forest areas including such recorded forests which had already been put to various type of non-forestry use, thereby restraining the authorities from undertaking any change in the land use and allowing any development or utility related work. Besides this, apprehensions prevailed regarding applicability of the Act in the plantations raised in private and Government non-forest lands. This situation resulted in misinterpretation of the provisions of the Act with respect to their applicability especially in recorded forest lands, private forest lands, plantations, etc. Therefore, it is considered necessary to prescribe the extent of applicability and non-applicability of the Act in various types of lands.
- 4. There is also a need to fast track the strategic and security related projects of national importance so as to ensure development of vital security infrastructures, especially along the international border areas such as Line of Actual Control, Line of Control and Left Wing Extremism affected areas. Similarly, small establishments, habitations on the side of public roads and railways also need to be facilitated by providing them access and connectivity to main arterial roads and other public utilities.
- 5. Since, there is change in the ecological, social and environmental regimes and policies relating to conservation and development of forests during the last four decades since the enactment of the Act, to keep its provisions in tandem with the dynamic changes in the ecological, strategic and economic aspirations of country, it is proposed to introduce the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 in Parliament. The salient features of the said Bill, *inter alia*, are to—
  - (i) insert a preamble to the Act to encompass the country's rich tradition of preserving forests, their bio-diversity and tackling climate change challenges within its ambit;
  - (ii) amend the short title of the Act to be called the *Van* (*Sanrakshan Evam Samvardhan*) *Adhiniyam*, 1980, so as to ensure that the potential of its provisions is reflected in its short title;
  - (iii) clarify the scope of applicability of the Act upon various lands so as to remove ambiguities and bring clarity;
    - (iv) exempt certain categories of lands from the purview of the Act—

- (a) to fast track strategic and security related projects of national importance;
- (b) to provide access to small establishments, habitations on the side of public roads and railways; and
  - (c) to encourage plantation on non-forest land;
- (v) provide for terms and conditions including the condition of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands while considering the proposed relaxations under the Act;
- (vi) include more activities, which are taken up for the cause of conservation of forest and wild life in to the array of forestry activities;
- (vii) bring uniformity in the applicability of the provisions of the Act in respect of both Government and private entities;
- (viii) empower the Central Government to specify, by order, the terms and conditions subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as nonforest purpose;
  - (ix) empower of the Central Government to issue directions.
- 6. The Bill seeks to achieve the above objectives.

NEW DELHI;

BHUPENDER YADAV.

The 27th March, 2023.

#### **ANNEXURE**

#### EXTRACTS FROM THE FOREST (CONSERVATION) ACT, 1980

(69 OF 1980)

\* \* \* \* \*

Short title, extent and commencement.

**1.** (1) This Act may be called the Forest (Conservation) Act, 1980.

Restriction on the dereservation of forests or use of forest land for non-forest purpose. **2.** Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in a State, no State Government or other authority shall make, except with the prior approval of the Central Government, any order directing—

\* \* \* \* \*

(*iii*) that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organisation not owned, managed or controlled by Government;

\* \* \*

*Explanation.*—For the purposes of this section "non-forest purpose" means the breaking up or clearing of any forest land or portion thereof for—

- (a) the cultivation of tea, coffee, spices, rubber, palms, oil-bearing plants, horticultural crops or medicinal plants;
  - (b) any purpose other than reafforestation,

but does not include any work relating or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife, namely, the establishment of check-posts, fire lines, wireless communications and construction of fencing, bridges and culverts, dams waterholes, trench marks, boundary marks, pipelines or other like purposes.

\* \* \* \* \* \*

# LOK SABHA

A BILL

further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980.

(Shri Bhupender Yadav, Minister of Environment, Forest and Climate Change and Labour and Employment)